

DUE DATE SLIP**GOVT COLLEGE LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

उपरोक्त साविधानिक उपबन्ध स्थिति का स्वयं हा नहुन कुछ स्पष्ट कर दते हैं। सविधान में जिन स्वतन्त्रताओं को मान्यता प्रदान की गई है वह सब निर्वन्धन साथ कि उनका प्रयोग समानीय जनता के हितों व अनुकूल होना चाहिए। सोमिन्त सभ में न्यायालया को सविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकार सर्वोच्च सोवियत व प्रेसीडियम का प्रात है। ऐसा दिवने म यह निणय कि कान सा कथन समानीय जनता के हितों व प्रतिबुल है प्रेसीडियम के द्वारा ही किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय क द्वारा नह। यदि प्रेसीडियम अपनी किसी आगति (decree) क द्वारा नागरिका क वाक् स्वातन्त्र्य क अधिकार पर प्रहार करता है तो नागरिका को अपने अधिकार का रक्षा करने का कोई उपाय शय नहर् रहा। इसी प्रकार यदि सर्वोच्च सविधन (विधान मन्ल) इस साविधानिक उपबन्ध की आइ में काइ ऐसा निधि पारित करती है तो नागरिका क वाक् स्वातन्त्र्य क अधिकार का अतिक्रमण करती है तो नागरिका का कोई उपचार उपलब्ध नहर् है। सोवियत सभ का काइ न्यायालय उमे सविधान क प्रतिबुल हान के कारण अवैध घोषित नह कर सकता। प्रेसीडियम तो सविधान की व्याख्या करने की शक्ति रखता है, स्वयं ही सर्वोच्च सविधन के प्रात उत्तरणीय है। इस कारण वह भी सर्वोच्च सोवियत का विरोध नहीं कर सक्ता।

राजनीतिक स्वतन्त्रताओं पर दूसरा साविधानिक निर्वन्ध यह है कि उनका प्रयोग समानीय जनता को सुलभ करने के लिए ही होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिकों को शासन और समाज व्यवस्था क मौलिक स्वरूप क विषय में किसी प्रकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इस निर्वन्ध क अनेक लाभ हैं। प्रिटेन म द्वितीय महायुद्ध क पश्चात् जन श्रम दल (Labour Party) की सरकार बना तो उसने अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। परन्तु उसक कुछ काल बाद ही चर्चिल के नेतृत्व में बनने वाली अनुत्तर सरकार ने श्रम दल की सरकार क द्वारा किए गए अनेक परिवर्तनों का निराकरण कर दिया। इससे अकारण ही बहुत से धन और शक्ति का अप्रयोज्य होत है। शासन का नीति क सध में मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होने से इस अप्रयोज्यता को रोका जा सकता है। परन्तु इसके कुछ महत्वपूर्ण दोर

सोवियत संघ का शासन



महेन्द्र प्रकाश अग्रवाल, एम० ए०



नि ता ब म ह ल
इलाहाबाद बम्बई

असहमति व्यक्त नही कर सकता। परन्तु इन सब सुविधाओं के होत हुए भी नागरिक विचार अभिव्यक्ति का स्वतन्त्रता से प्रचित रह सकते हैं। सोवियत संघ में जनतावियों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार दिया गया है। परन्तु उन्हें राजनैतिक स्वतन्त्रताएँ किस सीमा तक उपलब्ध हैं यह सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के मुख पत्र 'प्रवदा' (Pravda) की निम्न उक्ति से स्पष्ट हो जाता है "सोवियत के देश में न्यूना दल, मराजिका तथा क्रांतिकारी समाजवादियों (Revolutionary Socialists) के संग हुए प्रस का प्रजापत के साथ हा संग के लिए सुचल दिया गया है। राक् और प्रेस स्वातन्त्र्य समाजवादी शासन की सुल्ल करने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। ना के हा समाजवादी शासन परम्परा का उलटने का विचार करता है जनता का शत्रु है। यदि वह अपने उद्देश्य का पूरा करना चाहेंगा उस कागज का एक पत्रा भी नही मिलेगा वह किता सुप्यालय के द्वारा के अन्तर भी न जा सकता। उस अपने भाषण का विर फलाने के लिए एक भा हाल, एक भी कमरा या एक काना भी नही मिलेगा।" इसमें स्पष्ट हा जाता है कि यािकारिक विचारवादी का विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जनता का शत्रु माना जाता है। सोवियत संघ में जनता के शत्रुओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है यह सर्वविदित है। मावादी संगठन ने बर्लिन की मत है कि 'सोवियत नागरिका के नाना "अधिकारों का अर्थ यहां है कि वे साम्यवादी शासन द्वारा समानित "मान काओं का प्रस्ताव के ताल गा मन्त है, परन्तु उनका आवाजना नही कर सकते।" २

सोवियत संघ में विचारों का अभिव्यक्त करने की वास्तविकता नागरिका के समाधान द्वारा प्रदान की गई है जनता में यह कागजाना तथा सामूहिक

^१ Pravda Jan 22 1936 (ten days after the publication of the draft of Stalin Constitution)

^२ "The new rights of the citizens signify the liberty to sing the praises of the achievements of the soviet regime but not to criticize them — De Basily Russia under Soviet Rule p 182

प्रकाशक—विश्व मद्रास ५६ ए, चैरो रा इलाहाबाद ।
 मुद्रक—राधेश्याम नारायण रायन आर प्रेस बंगलूरु ।

विभिन्न जातियाँ का सांस्कृतिक मामलों में अधिनायिक स्वतंत्रता देने की नीति का कारण ही सोवियत संघ में कई प्रकार के एकक बनाये गये हैं, यथा संघ गणराज्य, स्वायत्तशासी गणराज्य, स्वायत्तशासी क्षेत्र आदि। यद्यपि इन संघ का समान मात्रा में शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, परन्तु माया एवं संस्कृति संबंधी मामलों में इन सबको पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है।

सुरक्षा की समस्या—सन् १९१७ की क्रांति के पश्चात् स्थापित सोवियत समाजवादी गणराज्यों ने शांति को न केवल आवश्यक शत्रुओं का ही सामना करना पड़ा बल्कि उन्हें पूँजीवादी देशों की सहायता से भी युद्ध करना पड़ा। पूँजीवादी देशों की सहायता को नकारा सोवियत गणराज्यों को नाटक करने में सफलता न मिली परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न सोवियत समाजवादी गणराज्यों ने शांति का यह निश्चय हो गया कि यदि वे परस्पर सन्धि नहीं होने तो पूँजीवादी देशों का घर न दीब उनका अग्रिम समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखना असम्भव होगा।^१ यह निश्चय उन्हें एक दूसरे के निकट लाया जिससे उन्होंने परस्पर सन्धियाँ कर साम्यवाद संघ का निर्माण किया।

क्रांति ने पूरे महाद्वीप के नेताओं का विश्वास था कि क्रांति का पश्चात् यूरोप के अन्य देशों में भी क्रान्ति होगी जिससे परिणामस्वरूप सोवियत संघ का पूँजीवादी देशों से भय न रहेगा। परन्तु उनकी यह आशा पूर्ण न हुई। क्रांति के पश्चात् सुरक्षा की समस्या इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि इस के नये शासकों को अपने निकटवर्ती सोवियत गणराज्यों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक हो गया। इसी कारण उन्हें संघान्तरण का आश्रय लेना पड़ा।

आर्थिक पुनर्निर्माण तथा आम निर्भरता की आवश्यकता—साम्यवाद नेताओं का समर्थन था या प्रयत्न न केवल प्रेरित करने वाला तीव्र

The nation lies perceived that in a hostile capitalist world and with the wave of counter revolution still flowing in unity lies strength the road to survival lies in their success to form a single and hence a strong state —R. K. Mishra *Soviet Federalism* p. 4

प्रस्तावना

सोवियत रूस का शासन प्रणाली का उद्देश्य का सामाजिक वृद्धि तथा आर्थिक व्यवस्था का ध्यान म रकत हुए सफल ग्राम्यन प्रस्तुत करना है। इस पुस्तक का उद्देश्य है। पुस्तक को विश्वविद्यालय के छात्रशास्त्र व विद्यालयों के लिए निशुल्क रूप से उपयोग बनाने का प्रयास किया गया है।

सोवियत रूस का शासन प्रणाली पर लिखा गया पुस्तक में हम प्रायः परस्पर पूरक विरोधी विचार मिलते हैं। इसका कारण यह है कि अविश्वसनीयता ने अनेक सामाजिक विचारों व अनुसार सोवियत शासन प्रणाली का प्रशंसा या बुरा सिद्ध करने का प्रयास किया है। जहाँ एक ओर सोवियत रूस साम्यवाद लाने उस 'समाधिक जनतान्त्रिक' प्रणाली है, जहाँ पारम्परिक देशों व अनेक लेवका ने उस पूरे अविश्वसनीय सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस कारण 'समाधिक' में निम्नलिखित भाग से लिखा गया अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। 'समाधिक' के प्रकार व अविश्वसनीयता बखाना व 'विश्वसनीय' के पुस्तक में सामाजिक तथ्य तथा उन पर प्रभावित निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सोवियत शासन प्रणाली व विभिन्न अर्थों का अन्य देशों के सामाजिक व यथास्थान तुलना का काम है। सोवियत शासन प्रणाली पर अनेक प्राधिकार विचारों व प्रथा से उद्धरण भी लिए गए हैं, जिससे पाठक को वास्तविकता का सामना करने में मदद कर सकें।

पुस्तक का उद्देश्य का अर्थ 'समाधिक' करने वाले पाठकों का लक्ष्य आभास होगा।

प्रकाश

महेंद्र प्रकाश अग्रवाल

२ अप्रैल १९५६

शासनाग गया है।^१ उनके इस कथन में हम सोवियत शासन व्यवस्था में प्रेसीडियम की महत्त्वपूर्ण स्थिति का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

प्रेसीडियम की स्थिति का तुलनात्मक निवेदन—प्रेसीडियम की शक्तियाँ पर एक दृष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेसीडियम ऐसे अनेक कार्य करता है जो अन्य देशों में नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, विधानमण्डल, प्रधानमन्त्रि और उच्च सदन, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। सामान्य सार्वधानिक राज्यों द्वारा किये जाने वाले कृत्यों हैं, विधानमण्डल और सदन बुलाना तथा उन नियमित करना, नये नियोजन करना, दैनिक प्रतिनिधित्व तथा संसद सेनाओं के उच्चाधिकारियों की नियुक्तियाँ करना तथा उनको पदभुक्त करना, पदों तथा उपाधियों को प्रितरि करना, प्राप्ति प्राप्त करना, तथा प्रमाण पत्रों तथा आस्तनपत्रों का प्रेषण करना प्राप्ति। सोवियत शासन व्यवस्था में ये सब कृत्यों प्रेसीडियम का ही अधिकार हैं। इसी कारण सोवियत लोकप्रतिनिधि (Prof Traino) ने प्रेसीडियम के कृत्यों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि अनुच्छेद ४८ में समाज सोवियत और प्रेसीडियम को दिये गए कृत्यों उन कृत्यों के समान हैं जो ताबूत राज्या में शासक अर्थात् नरेश या राष्ट्रपति, को दिये जाते हैं। परन्तु हमें यह यहाँ याद रखना चाहिए कि ब्रिटन के नरेश या अमेरिका के राष्ट्रपति की भाँति सोवियत सदन के प्रेसीडियम का किसी प्रकार का अभिव्यक्ति अधिकार (veto) प्राप्त नहीं है। सदैव शासन प्रणाली वाले देशों में राज और सार्वधानिक प्रभुत्व को सौंपे गये अधिकार कृत्यों मजिस्ट्रेट के परामर्श से संपादित होते हैं। प्रेसीडियम को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मजिस्ट्रेट के परामर्श लेना आवश्यक नहीं है इस कारण यह अन्य देशों में मजिस्ट्रेट द्वारा किये जाने वाले अनेक कृत्यों में आता है।

^१ "The Presidium or permanent committee is not only the nerve centre of the Supreme Council but also in reality the highest governing instrument in the USSR" de Basly Rivier et al. *Soviet People* p 179

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

१ सांख्यिक सङ्घ—देश और निवासो १

भौगोलिक स्थिति—जनघनत्व—जलवायु—आर्थिक साधन—
कृषि—‘कोलब्रोज तथा ‘साउथवुड—उद्योग धर्म—जनसंख्या—
धर्म—जातिवाद तथा भाषाएँ

२ बाल्शेविक क्रांति के पूर्व का समय ६

प्रारम्भिक इतिहास—मंगोला का आक्रमण—मास्को के नेतृत्व
में रूस का एकीकरण—यान्त्रिक मजदूरी—कथरीन महान्—अलेक्जेंडर
प्रथम के सुधार—दिसम्बरी क्रांति तथा निकोलस प्रथम का शासन—
अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन तथा सुधार—अलेक्जेंडर तृतीय—
सन् १८५५ की असफल क्रान्ति—अलेक्जेंडर (१८५५) का घोषणा
पत्र—प्रथम तथा द्वितीय रूसी—तृतीय और चतुर्थ रूसी—चारशाही
शासन के अन्य अंग—आत्मकलान शक्तियों का दुस्प्रयोग—
चारशाही रूप में सामाजिक जीवन—चारशाही का राजपूतक संसक्ति
का नाश—प्रथम विश्व युद्ध का रूस का राजनीतिक स्थिति पर
प्रभाव

३ मार्क्सवाद, बाल्शेविक क्रांति तथा सांख्यिक शासन व्यवस्था का विकास २८

मार्क्सवाद का सूत्र—द्वन्द्वीय भाविकता—ऐतिहासिक
भौतिकवाद—अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त—मानव के क्रांति तथा
राज्य सम्प्रदाय विचार—अंतराष्ट्रीय क्रान्तिकारी प्रणाली—मार्च
१९१७ की क्रांति—अस्थायी सरकार—बाल्शेविक क्रांति—सांख्यिक
विकास की पृष्ठभूमि—सन् १९२८ का संविधान—सन् १९२८ का
संविधान—सन् १९३६ का (स्थानिक) संविधान

मन्त्रिमण्डल का कार्य होता है। मन्त्रिमण्डल को संसद के बहुमत दल का, या ऐसे कई दलों का निहें संसद में बहुमत प्राप्त होता है, समर्थन प्राप्त होने के कारण अपनी भाति पर संसद का अनुमोदन करने में अधिक कम्तिनाई नहीं होता। सोवियत संघ में भी संदेव मन्त्रिपरिषद् का अपने समस्त प्रस्तावों तथा अपने समस्त नीतियों पर सर्वोच्च सोवियत का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। परन्तु यह प्रश्न शर रह जाता है कि क्या जो नातिया मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत करती है वे उसी के द्वारा निर्धारित का हुई होती हैं। क्या मन्त्रिपरिषद् शासन का नान निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है? यदि इस प्रश्न का उत्तर 'हां' होता निश्चय ही सोवियत संघ का मन्त्रिपरिषद् ग्राम संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों के मन्त्रिमण्डल के समान स्वीकार्य मानी जायगी।

सोवियत शासन प्रणाली के संरक्ष में अधिकृत जानकारी रखने वाले आधिकारिक सिद्धान्त उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 'नहीं' देता है। उनके मतानुसार सोवियत संघ के शासन का नाति के संबंध में समा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित करना कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रिय समिति के प्रसाधियम का कार्य है। मन्त्रिपरिषद् को उन सिद्धान्तों के प्रसार पर कार्य करना है और पात्र प्रसाधियम के निर्णयों को औपचारिक रूप दे देता है। आग और निक का कथन है कि नियंत्रण हा केवल औपचारिक दृष्टि से हा मन्त्रिपरिषद् को सहाय्य शर पालिसा माना जा सकता है। प्रस्तुत पालिटब्यूरो के रहते उस यह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता।^१ रूनिथन डाउस्टर ने भी इसके समान ही मत व्यक्त किया है। उन्होंने मन्त्रिपरिषद् के संस्था का ११ वगो में विभक्त किया है प्रथम व जो पार्टी के केन्द्र, विभागत पालिटब्यूरो,^२ के संस्था हैं, और दूसरे व जो उसके संस्था नहीं हैं। द्वितीय गम के मन्त्रियों के संरक्ष में उन्होंने लिया

^१ 'C'est only it is hardly the supreme executive authority in more than formal sense the Politbureau would leave it no room for such a role' — O.G. & Zink op cit p 82

^२ पालिटब्यूरो का स्थान ग्राम पार्टी का केन्द्रिय समिति के प्रसाधियम में ले लिया है।

४ स्तालिन मन्त्रिधान का प्रकृत तथा विशेषताएँ

८२

मन्त्रिधान का लिखित स्वरूप—राय का सम्मानना की आधार—
अनभ्य (18 d) राय का मन्त्राधिकार—सुदृढ़ कन्दयुक्त संधार
व्यवस्था—राज्यकारण का प्रवृत्ति नागरिका के मूल अधिकारों की
निशान्दता—नागरिकों के कर्तव्य—साहित्य प्रणाली—नेत्रान विधान
मन्त्र के द्वारा सन्तान का पूरा समानता—प्रेमाश्रित एक अनुपम
शासन मन्त्रा—मन्त्राधान मानविक प्रधानता—प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के
कारणों का प्रवृत्ति—निर्वाचित मन्त्रालय—योजनाइद एव
मुनियन्त्रित प्रथम प्रथम—राष्ट्रों का शासन पर कठोर नियन्त्रण
—जनताधिकार के कारण

५ नागरिकों के मूल अधिकार तथा कर्तव्य

८३

सन् १९४६ का परिनिर्णित परिनिर्णित—स्तालिन सन्विधान द्वारा
प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार—काम पाने का अधिकार—भाषिक
सुरक्षा का अधिकार—निर्वाचन तथा अन्तर्गत का अधिकार—शिक्षा
पाने का अधिकार—समानता का अधिकार—धार्मिक आस्था तथा
धर्म निर्यात प्रचारकों के अधिकार—नागरिक स्वतन्त्रताएँ—साधननिष्ठ
संस्थाओं के सम्मान होने का अधिकार—व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का
अधिकार—व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार—प्राप्त्य का
अधिकार—नागरिकों के मूल कर्तव्य

स्तालिन सन्विधान / ९० (federal m)

८४

सन् १९४६ का परिनिर्णित परिनिर्णित—संधार प्रवृत्ति अपनाए जाने
के कारण—साहित्य संधार एक—सन् १९४६ का संधार संधार
हानि का आधार—सन् १९४६ का संधार संधार संधार संधार
शासन मन्त्रालयों का पन्नातान—संधार संधार संधार संधार
निर्यात—राज्यकारण का प्रवृत्ति—सन् १९४६ के संधारों का
मन्त्र शासन का शक्ति पर प्रभाव—सन् १९४६ का शक्तिशासन
नाना—सन् १९४६ का शक्तिशासन तथा एकता के शक्ति शासनिक
मन्त्रा—साहित्य संधार की संधार संधार संधार संधार

सब गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों का किया गया है। सोवियत सभ के सब गणराज्यों में मवाधिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या वाले सब गणराज्य रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य (R S F S R) का प्रथम संविधान जून १९१८ में अंगीकृत किया गया था। अन्य सब गणराज्य तथा सोवियत सभ का प्रथम संविधान (१९२३) इसी संविधान का अनुरूप थे। सन् १९३७ में सोवियत संविधान ने प्रशस्त किए जाने के पश्चात् रूसी गणराज्य तथा अन्य सभी सब गणराज्य में उसी के उपबन्धों के आधार पर नवीन संविधान बनाए गये। आनकन उन्हां संविधानों के अनुसार सब गणराज्य का शासन संचालित होता है।

सब गणराज्यों का विधानांग सर्वोच्च सोवियत—प्रत्येक सब गणराज्य में शासन ने विधानांग (Legislature) का रूप में एक सर्वोच्च सोवियत कार्य करता है, जिसका निर्वाचन गणराज्य के समस्त नागरिकों द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। सर्वोच्च सोवियत की संसद-सभा तथा प्रतिनिधिसभा का आधार गणराज्य के संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। संविधान में सब गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों को गणराज्य का “राजसत्ता का सर्वोच्च अंग तथा “एकमात्र विधायक अंग बताया गया है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जहां सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत में दो सभ हैं, वहां सब गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतें एकसंनानामक हैं। सोवियत लेखक सब गणराज्यों के लिए द्विसदनत्मक विधानमण्डल का आनामन्नक उठाते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न एककों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता नहीं होती।

सोवियत संविधान के अनुच्छेद ६ में सब-गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों की शक्ति तथा कृत्या का उल्लेख है। सर्वोच्च सोवियत सोवियत सभ के संविधान के अनुरूप गणराज्य के संविधान को अंगीकृत करती है तथा उसमें संशोधन करती है। वह गणराज्य के क्षेत्र में अस्तित्व स्थापित सभी गणराज्यों के संविधानों की पुष्टि करती है और उनमें सुधारों की सीमाएँ निर्धारित करती है। गणराज्य के आर्थिक तथा राजनीय आर्थिक योजना पर भी स्वीकृति देती है। सब-गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत गणराज्य के किसी

अध्याय १

सोवियत संघ देश और निवासो

भूमण्डल के सम्पूर्ण स्थल भाग के पन्द्राश में पैना हुआ सोवियत संघ संसार का सबसे बड़ा देश है। योगेश का पृथ्वी तथा एशिया का तृतीयवां सोवियत संघ के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है। इसका सीमाएँ पाल्टिक सागर से प्रशान्त महासागर तक तथा श्वेत सागर और उत्तरा ध्रुव महासागर से कैस्पियन सागर और काला सागर तक फैली हुई हैं। इसका सीमा रेखा की लम्बाई साठ हजार किलोमीटर है तथा उस पर गारह सागर और बारह देश अवस्थित हैं। इन्हे अन्य सभी देशों से अधिक परन्तु साब हा सर्वाधिक अनर्थक, समुद्रतट उन्मुख है। इसका कारण यह है कि उत्तरा ध्रुव महासागर, जो सोवियत संघ का उत्तरा भाग पर स्थित है, यह एक अविश्वस्य भाग में प्रखन चला रहता है। सोवियत संघ के अधिकांश प्रमुख नगरों, जैसे लाननग (Leningrad) क्रानस्टा (Cronstadt) रेगा (Riga) तथा पश्चिम में पाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। दक्षिण में काला सागर पर स्थित ओडसा (Odessa) पूर में चारान सागर पर स्थित व्लादावास्तोक (Vladivostok) तथा उत्तर में श्वेत सागर पर स्थित आर्केंजल (Archangel) सोवियत संघ के अन्य प्रमुख नन्दरगाह हैं।

भौगोलिक स्थिति—सोवियत संघ की उत्तरी सीमा पर उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी सीमा पर लाक-गणराज्य चीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान आदि राज्यों, पूर में प्रशान्त महासागर तथा पश्चिम में पोलैंड, जेकमानोवाकिया, रूमानिया आदि देश हैं। दक्षिणी सीमा पर कार्पेथियन, कारथियन, पामार और आल्पाइ पर्वतमालाएँ हैं, जो इस अन्तराल से पृथक करती हैं। सोवियत संघ का दक्षिणी सीमा एक स्थान पर भारत का सीमा से केवल साठ मील अंतर पर है।

गणराज्यों के मन्त्रालय दो प्रकार के होते हैं—(१) संघ-गणराज्यिक (Union Republican), तथा गणराज्यिक (Republican) संघ-गणराज्यिक मन्त्रालय केनीन संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों के अनुसृत होते हैं तथा संघ और संघ गणराज्य दोनों की मंत्रिपरिषदों के अधीन होते हैं । गणराज्यिक मन्त्रालय केवल संघ गणराज्य की मंत्रिपरिषद के हा अधीन होते हैं । सब संघ-गणराज्यों में मंत्रियों अथवा मन्त्रालयों की संख्या समान नहीं है । फरवरी, १९४७ के संशोधन के पूर्व संविधान में संघ-गणराज्यों के मन्त्रालयों का भा उल्लेख था परन्तु अब अपना आवश्यकतानुसार मन्त्रालयों का संख्या निर्दिष्ट करने का अधिकार संघ-गणराज्यों को दे दिया गया है ।

संघ-गणराज्यों की मंत्रिपरिषदें संघ गणराज्य की पूर्व प्रवर्तित विधियों एवं सांविधान संघ की मंत्रिपरिषद — विनिश्चया और आदेशों का आधार पर “विनिश्चय और आदेश” जारी करता हैं । इन विनिश्चयों और आदेशों ने कार्यशासन का परावृत्त करना या उद्घाटन का कार्य है । गणराज्यों की मंत्रिपरिषदों को अपने क्षेत्र के स्वायत्तशासी गणराज्यों की मान्य परिषदों के विनिश्चयों तथा आदेशों को निलम्बित (suspend) करने तथा प्रस्ताव, क्षमों और स्वायत्तशासी क्षेत्रों का सौमित्रता की कार्यकारिणी समिति का विनिश्चयों और आदेशों को रद्द (annul) करने का अधिकार दिया गया है । संघ गणराज्यों के मन्त्री राज्य प्रशासन की उन शाखाओं का निरीक्षण करते हैं जो संघ-गणराज्य के क्षेत्राधिकार में आता हैं तथा आदेश और अनुदेश (instructions) जारी करते हैं । यह आदेश और अनुदेश उन मन्त्रालयों के क्षेत्राधिकार का सामाज्य और अन्वयन होना चाहिये तथा सौमित्र संघ तथा संघ-गणराज्य का विनिश्चय सांविधान संघ तथा संघ गणराज्य की मंत्रिपरिषदों के विनिश्चय और आदेशों, एवं सौमित्र संघ संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों के आदेशों और अनुदेशों पर आधारित होना चाहिये । संविधान के इन उपबन्धों में यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ-गणराज्यों का “संघभूता” संघ में किन्ती सम्मिलित है ।

संघ-गणराज्यों के कार्यक्षेत्र तथा विधानात्मक के बीच सम्बन्ध—
उपरोक्त सांविधानिक उपबन्धों पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि संघ

यूराल पर्वतमाला (Ural Mountains) को सोवियत संघ के योरोपीय और एशियाई भागों के बीच की सीमा माना जाता है। यह पर्वत माना अनुल्लंघनीय नहीं है। इसमें ऐसे अनेक दर्रे हैं जिनसे एक भाग से दूसरे भाग में जाया जा सकता है। यूराल पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर की ऊँचाई लगभग ६ फुट है। यह शिखर पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में है।

क्षेत्रफल—सन् १९४६ में लगाये गये अनुमान के अनुसार सोवियत संघ का पूर्ण क्षेत्रफल ८,७ ८, ७ वर्गमाइल है।^१ अन्य देशों के क्षेत्रफल से तुलना करने पर हम पाते हैं कि सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग दस गुना, भारत से आठ गुना और युक्त राज्य (United Kingdom) से लगभग सौ गुना बड़ा है। इसके आकार का अनुमान हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ६ मील प्रति दिन की गति से चलने वाली रेलवे ट्रेन को सोवियत संघ की पूर्वा सीमा से पश्चिमी सीमा तक पहुँचने में दस दिन लगेंगे। यह एक रोचक तथ्य है कि सोवियत संघ की पूर्वी सीमा पर सूर्य पश्चिमी सीमा की अपेक्षा ६ घंटे पहले उदय होता है।

जलवायु—सोवियत संघ के बृहत्कार का प्यास में रखने पर उसके विभिन्न भागों में भिन्न जलवायु होना आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होता। उत्तरी भाग टुंड्रा (Tundra) में वर्ष भर फँस जाता है। यहाँ वर्ष में दस महीने शीत ऋतु रहती है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश में लम्बी ग्रीष्म ऋतु होती है और तापमान बहुत ऊँचा पहुँच जाता है। याना नदी पर स्थित वेरखोयान्स्क (Verkhoyansk), जहाँ जनरल म निम्नतम तापमान—६० फा तक पहुँच जाता है विश्व का शीतलतम स्थान है।

सागर—अधिकांश भाग में लम्बे तथा कठोर शीत एवं ऊँचे तार की ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। कश्मिर सागर के तट पर स्थित अस्त्राखान (Astrakhan) में वर्ष में सात पांच महीने, मास्को में साढ़े छ महीने तथा श्वेत सागर (White Sea) पर चार आर्कान्जेल (Archangel) में आठ महीने तक तापमान शिबिन्दु से नीचे ही रहता है। इससे हम रुष के शीत की

^१ The Statesman's Year Book 1955 ■ 1434

के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर विधियाँ बनानी हैं तथा अपना प्रेसीडियम निर्वाचित करती है। स्वायत्तशासी गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतें अपने अपने गणराज्यों के लिए मंत्रि परिषद् तथा सर्वोच्च न्यायालय को भी निर्वाचित करती हैं। सर्वोच्च सोवियत व सत्रावकाश काल में उसके आवेकाश कार्य उसका प्रेसीडियम करता है। स्वायत्तशासी गणराज्यों की मंत्रि परिषद् पूरा प्रवर्तित विधियाँ व आधार पर निनिश्चय और आदेश जारी कर सकता है, परन्तु सत्र गणराज्य की मंत्रि परिषद् उन्हें निलम्बित कर सकती है। अपना इस विधि के द्वारा सत्र-गणराज्य की मंत्रि परिषद् स्वायत्तशासी गणराज्यों पर प्रभुत्व प्रदर्शित रखती है।

स्वायत्तशासी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था

सत्र गणराज्यों के नाताय आधार पर किए गए उपविभागों में स्वायत्तशासी गणराज्यों व पश्चात् स्वायत्तशासी क्षेत्र (Autonomous Regions) तथा राष्ट्रीय क्षेत्र (National Areas) का स्थान आता है। इन उपविभागों की जनसंख्या बहुत कम होती है। प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र में नागरिकों के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 'कामचीवी जन' व 'सोवियत' (Soviet of Working People's Deputies) होता है जो अपने अधीन शासनांगों के कार्यों का निर्देशन करती है, सामाजिक जीवन को बढ़ावा देने का प्रयत्न करता है, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखती है तथा विधियों व कानूनों का अधीक्षण करती है। इन क्षेत्रों की सोवियतों को स्थानीय प्राथमिक तथा सांस्कृतिक मामलों का निर्देशन करने तथा स्थानीय योजनाएँ तैयार करने का अधिकार भी दिया गया है। सोवियत सत्र तथा सत्र-गणराज्यों की विधियाँ द्वारा जो शक्तियाँ इसमें गिनी हैं उनकी सीमाओं व अन्तर्गत वह निनिश्चय अंगीकृत करती है तथा आदेश जारी कर सकती है। 'कामचीवी जनता' के प्रतिनिधियों की सोवियत क्षेत्र व कार्यपालिका तथा प्रशासनिक अंग कार्यकारिणी समिति, को निर्वाचित करती है जिसमें एक समारोह उपसमारोह एक मंत्री तथा कुछ सदस्य होते हैं, यह कार्यकारी समिति क्षेत्र का समस्त व प्रति उत्तरदायी होती है तथा उसके समक्ष अपने कार्यों व सत्र में आका प्रस्तुत करती है। सत्र गणराज्यों की मंत्रि परिषद् स्वायत्तशासी क्षेत्रों

कठोरता का अनुमान लगा सकते हैं। रूस पर आक्रमण करने वाली सभी सेनाओं को इस कठोर शीत ऋतु का कारण असमर्थता काट उठाने पड़े हैं। इसी प्रकार सोवियत संघ के आधिकारिक भाग में गमाम १० फा से अधिक ठान कम रहता है।

सोवियत संघ के कुछ बड़े गिने प्रदेशों में हा प्रति वर्ष २ इंच से अधिक वर्षा होती है। मध्य एशिया और उत्तर पूर्वी साइबेरिया में तो वर्ष में आठ इंच से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी भाग में जलवायु भी कभी व कारण बहुधा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्राकृतिक साधन—वर्तमान युग में औद्योगिक क्रान्ति के कारण प्राकृतिक साधनों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। किसी देश की प्राकृतिक शक्ति के लिए उनका प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक माना जाता है। सोवियत संघ प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से संसार के अत्यन्त समृद्ध देशों में है। यूक्रेन (Ukraine) में पर्याप्त मात्रा में कोयला, लोहा और मंगनीज पाया जाता है। यूराल पर्वत में कोयला, सोना, प्लैटिनम, पारा, एल्यूमिनियम, आभियम, निकल तथा तल के भण्डार हैं। कनाकमन में कागला, तांग तथा अन्य धातुएँ पाई जाती हैं। पूर्वी साइबेरिया में भी कोयला, लाहा, सोना तथा अन्य धातुएँ पायी जाती हैं। काकशस क्षेत्र में तेल, मंगनीज, ताम्र तथा सीसा मिलता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ अधिक कार्बल और कच्चे लोहे का उत्पादक सोवियत संघ ही है। संसार में स्वयं अधिक मंगनीज सोवियत संघ में ही मिलता है। यूरोप पर्वत में अन्य खनिज पदार्थों के अतिरिक्त प्लेटिनम नामक बहुमूल्य धातु भी मिलती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक 'किसी अन्य देश में इतना अधिक प्रकार के खनिज पदार्थ नहीं हैं, और वरन् संयुक्त राज्य अमेरिका ही (सोवियत संघ से) अधिक समृद्ध है।'

'No other land has so great a variety of minerals and only the United States is richer'—George B. Cressey
Asia's Lands and Peoples p. 290

नष्ट हो सकती है। ग्रामिकों की अनुशासनहीनता भी राज्य और समाज की पराजित हानि कर सकती है। इन सब से सावजनिक समाजवादी सम्पत्ति का हानि न होने देना महान्यायवादी का प्रधान कर्तव्य है।

महान्यायवादी का दूसरा प्रधान कर्तव्य, जहाँ कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, नागरिकों, पदाधिकारियों शासन विभाग तथा सावजनिक सम्पत्तियों द्वारा निधि व वायपानन का अधीक्षण करना है। यह कर्तव्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विधियों का समुचित पालन नहीं किया जाता तो राज्य में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विधियों का उल्लंघन न करना इच्छा में हो किया जा सकता है, परन्तु उनका गलत अर्थ समझने व कारण अनिच्छा से भी हो सकता है। महान्यायवादी तथा उसका विभाग के अन्य पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी कारण से विधियों का उल्लंघन न होने दें और जान ऐसा होना है तो अपराधियों का समुचित दण्ड मिलाने जिससे अन्य लोगों व मरिचक से विधियों का अतिक्रमण करने का परिणाम भला भाति अंकित हो जाय।

महान्यायवादी का तालिम सन्निधान व अन्तर्गत शासन के अन्य सभी विभागों से स्वतन्त्र रहना है। इसका कारण यही है कि यह शासन न किसी भा अग द्वारा विधियों का अतिक्रमण न होने दे सकें लिए यह स्वतन्त्र अथवा आनुरूप है। परन्तु यहाँ हम यह जान रखना चाहिए कि महान्यायवादी शासन व विभिन्न अग व प्रभाव से मने ही मुक्त हो परन्तु वह कभी निरुद्ध पाठों व समन्वया प्रभाव से कठोर मुक्त नहीं है। महान्यायवादी व पर पर ऐसा ही प्रकृति का नियुक्त किया जाता है जो पाठों की आशाओं का अक्षर पालन करे। ऐसा न करने पर उस पर पण्युन मा किया जा सकता है। महान्यायवादी व विभाग व समस्त कर्मचारियों का कार्यवाहियों का संचालन तथा निर्देशन कन्द्र से होता है, इस कारण यह विभाग वन्दनीकरण में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है।

राजनीतिक पुलिस

सावित्र राज्य व्यवस्था का बल राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं हो सकता। राज विरोधी पण्युन एवं कार्यवाहियों

शक्ति सम्पत्ति के मन्दार की दृष्टि से भी सोवियत संघ बहुत समृद्ध है। सोवियत संघ के कोयले के मझारों का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। काकेशिया जार्जिया तथा यूराल पवनमाला के क्षेत्र में तेल पाया जाता है। सवालिन द्वीप में भी तेल निकाला जाता है। वाल्गा नदी की उपत्यका में भी तेल मिलता है। अन्य क्षेत्रों में भी तेल की खोज हो रही है। शक्ति का तीसरा साधन है जल विद्युत्। सोवियत संघ में तेज धारा वाली नदियाँ का आधिक्य नहीं है, परन्तु वाल्गा तथा अन्य उड़ी नदियों पर बांध बना कर विद्युत् उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सान्बेरिया की अगारा नदी से भा बनी मात्रा में विद्युत् उत्पन्न की जाती है।

उपरोक्त बखान से स्पष्ट हो जाना है कि सोवियत संघ में देश के औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक सभी साधना का बड़ा भण्डार है। यही कारण है कि सोवियत संघ ने पिछले वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है।

कृषि कोरसोज तथा सोरखोज—सोवियत संघ की जनता का एक बड़ा भाग कृषिकार्य करता है। यही कारण है कि सोवियत संघ संसार के प्रमुख कृषि प्रधान देशों में है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ सोवियत भूमि में ही पैदा होता है। राब जो और जल उत्पादन में भी सोवियत संघ संसार के अन्य सभी देशों से आगे है। सुन्दर जिससे चीनी बनती है, और आलू तथा सब्जियाँ भी सोवियत संघ में ही सर्वाधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। पशु-पालन के क्षेत्र में सोवियत संघ में काफी प्रगति हुई है। वहाँ कई करोड़ गाँवें तथा मुँदर पाले जाते हैं।

वर्त्तमानिक क्रांति के बाद सोवियत संघ में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पुराने छोटे-छोटे खेतों का स्थान अब बड़े बड़े सोखोज (Sovkhoz) तथा काल्खोज (Kolkho) ने ले लिया है। सोखोज उन खेतों का नाम है जिनका प्रबंध राज्य की ओर से होता है और जिनमें उत्पादित अन्न पर राज्य का अधिकार होता है। काल्खोज उन खेतों को कहते हैं जिनका प्रबंध कृषकों का एक सहकारी संस्था द्वारा होता है। काल्खोज राज्य की देख रेख में कार्य करते हैं और अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग उन्हें राज्य को देना पड़ता है। राज्य का अधिकार यह है कि वेक्टर तथा अन्य यंत्र उपकरण के लिए

प्रदान किये जाते हैं जिसके लिए इन्हें राय को किराया देना होता है। सोवियतों में कृषक को पारिवारिक दिना जाता है। कोल्लोजा में उन्हें काम के अनुपात से उत्पादित अन्न का एक भाग दिया जाता है।

उद्योग धरो—लनिन ने एक बार कहा था कि उद्योग का दृष्टि से जार शाही रुम “इङ्गर्लैंड” से चार गुना, जर्मनी से पांच गुना तथा अमेरिका में दस गुना पीछे था।^१ परन्तु सोवियत शासन में रुस ने औद्योगिक क्षेत्र में अत्यन्त जनक उन्नति की है। लोहे तथा स्थापन के उत्पादन में अब सोवियत संघ अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है। कृषि के यंत्राकरण के लिए ट्रैक्टरों और बड़े-बड़े यंत्रों तथा यातायात के साधनों के लिए इन यंत्रों का महत्व आवश्यकताओं की पूर्ति इसी उद्योग के द्वारा की जा रही है। न केवल इतना ही, धर्म राय देशों को यंत्र तथा कल पुर्जा का यही माना है सोवियत संघ द्वारा निर्यात भी किया जाता है। सोवियत संघ के अन्तर्गत उद्योगों में सूती कपड़े का उद्योग, चीनी बनाने का उद्योग तथा कागज और रियासलाह बनाने के उद्योग प्रमुख हैं।

उद्योग धर्मों के प्रसार के साथ साथ बढ़ रहा है। न निर्माण होना आवश्यकता है। सोवियत संघ के प्रमुख नगर मास्को, लेनिनग्राद, मोस्को, लार्नोफ, बार्कु, स्लाविनग्राद, कोय आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं।

जनसंख्या—सन् १९४९ के अनुमान के अनुसार सोवियत संघ की पूर्ण जनसंख्या १६ करोड़ ३२ लाख है।^२ सोवियत संघ के अद्भुत क्षेत्रफल, प्राकृतिक साधनों के भण्डार, शक्ति के स्रोत तथा खाद्यान्नाभ्यासन को ध्यान में रखते हुए यह जनसंख्या बहुत अधिक नहीं प्रतीत होती। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, सोवियत संघ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम गुना बड़ा है। प्राकृतिक तथा शक्ति साधनों एवं खाद्यान्नोत्पादन का दृष्टि से भी सोवियत संघ भारत की अपेक्षा बहुत अधिक समृद्ध तथा समुन्नत है। परन्तु वहाँ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का केवल १.४ प्रतिशत है।

^१ V I Lenin as quoted by George B Cressley in *Asia's Land and Peoples* p 291

^२ *The Statesman's Year Book* 1956

सन् १९२६ का जनगणना के अनुसार सावित्र संध की जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग (११ करोड़ ४६ लाख) ग्रामीणों में तथा एक तिहाई भाग (५ करोड़ ५६ लाख) नगरों में रहता है। पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या १७२ है। इनमें से मास्को तथा लेनिनग्राद की जनसंख्या क्रमशः ४१ लाख ७ हजार तथा २१ लाख ६१ हजार है। शहरों में पचास हजार से एक लाख तक का जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ६२, एक लाख से पांच लाख तक का जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ७, और पांच से दस लाख तक का जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ६ है। जनसंख्या संख्या एक अरब तक केवल यह है कि सन् १९२६ की जनगणना के अनुसार सावित्र संध में पुरुषों में नारियों की संख्या अधिक थी। पुरुषों की संख्या उस समय ८ करोड़ १६ लाख थी जबकि नारियों की संख्या ८ करोड़ ८८ लाख थी। नारियाँ इसकी प्रवृत्ति श्रम के द्वारा लाभ-स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने वाली तथा जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि होने के कारण सावित्र संध का जनसंख्या निरंतर बढ़ता जा रहा है। राज की ओर से भी जनसंख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

धर्म—कति (१९१७) — पूर्ण रूप में प्रथोथोक्स चर्च (Orthodox Church) का राजभार प्राप्त था। मास्कोवाणी अनाथशालाएँ हान हैं जहाँ कारण नान्थानिक धर्म — पश्चात् प्रथोथोक्स चर्च का भी राजभार से वंचित कर दिया गया। यह प्रवृत्ति २३ जनवरी १९१८ का एक प्राज्ञापन के द्वारा का गई। वर्तमान सावित्र संधिधान समस्त नागरिकों की धार्मिक उत्पत्ति की स्वतंत्रता तथा धर्म विरोध प्रचार का स्वतंत्रता का मान्यता प्रदान करता है।^१

सावित्र संध में मुन्त नार धर्मों के अनुयायी हैं। ये धर्म हैं—रूढ़ि धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और यहुदा धर्म। इससे भी अधिक मानने वाले के धर्मों में विभाजित हैं जैसे प्रथोथोक्स चर्च के अनुयायी, शैख-गट, लूथरान्, बालिगनगान्, खन्त कथानिक धर्म। यन्त्रि प्रव प्रथोथोक्स चर्च का प्राधान्य

^१ Freedom of religious worship and freedom of anti religious propaganda is recognised for all citizens —Article 124 of the Constitution of the U. S. S. R.

समाप्त हो गया है परन्तु उसके अनुयायी अभी भी पर्याप्त संख्या में हैं। मास्को तथा अखिल रूस का पट्रिआर्क (Patriarch) उनका प्रधा धर्माधिकारी है। इस्लाम के अनुयायियों का संख्या ईसाइयों के बाद सर्वाधिक है। इनमें मुख्यतः तुर्को हैं। बौद्ध धर्मावलम्बियों की मुख्य संस्था केन्द्रीय बौद्ध परिषद है, जिसके प्रभु एक लामा हैं। यहूदियों के भी सोवियत संघ में अनर्क सम्प्रदाय हैं।

बाल्यशक्ति शक्ति के पश्चात् रूसी साम्राज्य में धर्म विरोधी आन्दोलन की लहर दौड़ गयी थी। उस समय धर्माधिकारियों के साथ निरन्तरीय व्यवहार भी किया गया था और विरजा के स्थान पर सहाय (म्युनिस्म) आदि भी उठा लिए गए थे। आज भी साम्यवादी दल (Communist Party) का सन्त्य होना किसी ऐसे शक्त के लिए समझ नहीं है जो पूर्णरूपेण श्रीनीश्वरगदी न हो। परन्तु आज की ओर से अब पहले की अपेक्षा कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न नाति का पालन किया जा रहा है। सन् १९३६ के संविधान ने धर्माधिकारियों का राजनातिक अधिकार प्रदान कर दिया है, जो उन्हें पिछले संविधानों द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे।

जातियाँ तथा भाषाएँ—सोवियत नेता नारशाही रूस को जातियों का कारागार^१ के नाम से संबोधित करते हैं। उनके कारण यह है कि नारशाही रूस में विभिन्न जातियों के लोगों का लड़कन रूसी साम्राज्य के अन्दर रहने के लिए विवश किया जाता था और उनका शासन किया जाता था। जाति के पश्चात् जाति की समस्या का अन्त नहीं था। आज क्योंकि वर्तमान सोवियत संघ में लगभग वह सभी प्रदेश सम्मिलित हैं जिन पर रूस का प्रभुत्व था परन्तु साम्यवादी शासन ने जाति की समस्या का दूसरे प्रकार से मुलभूतने का प्रयत्न किया है। निश्चय साम्राज्य के अन्दर सोवियत शासन प्रणाली में सभी जातियों को अपनी भाषा और संस्कृति के विकास का अवसर प्रदान किया गया है। यद्यपि कि संविधान में सोवियत संघ के प्रत्येक एकक (Unit) को अपने-अपने पृथक होने का अधिकार मान्यता दी गयी है।^२ व्यवहार में इस अधिकार का प्रयोग कदा तक समय है इस पर हम आगे विचार करेंगे।

The prison of peoples

^१ The right freely to secede from the U S S R, is reserved to every Union Republic — Art 17 of the Constitution of the U S S R

सोवियत संघ की जनता का एक बड़ा भाग स्लाव (Slav) जाति के लोगों का है, जो कार्पेथियन पर्वत माला के उत्तर पूर्व से पूर्वी योरोप के विभिन्न भागों में फैल गए थे। प्रारम्भ में इनका जीवन खानाबदोशों जैसा था। रूस के महान रूसी (Great Russians), यूक्रेन के लघु रूसी (Little Russians) और बेलोरूस (Byelorussia) के श्वेत रूसी (White Russians) इन्हीं स्लाव जातियों के हैं। सोवियत संघ का अन्य जातिवासी मंगोल, फारसी, तथा तुर्क जाति-समूह मुख्य हैं। स्लाव जातिवासी के साथ ही पोल (Poles) भी हैं। परन्तु इनमें अधिकांश रोमन कैथोलिक हैं, जब कि उपरोक्त तीनों प्रकार के रूसी ग्रिगोरियन चर्च के अनुयायी हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व में फिनलैंड (Finns) के लोग हैं, परन्तु अब उनका संख्या अधिक नहीं है। जर्मन और यहूदों भी सोवियत संघ के कुछ भागों में रहते हैं। सोवियत संघ में १६६ जातीय समूहों का अस्तित्व स्थापित किया जाता है परन्तु, २, से अधिक संख्या वाले समूहों का संख्या ५ है।^१ उपरोक्त जाति समूहों का अपनी अपनी भाषाएँ हैं। १९२६ की जनगणना के अनुसार लगभग ७८ प्रतिशत जनता स्लाव जातियों की थी और शेष २२ प्रतिशत अन्य जातियों की।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राजा के ग्राम निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर धरोर में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का स्थानांतरण हुआ। उस समय एक राज एक राज्य के सिद्धान्त का बहुत प्रचार हुआ। परन्तु सोवियत नेताओं ने राष्ट्रीयता और अथवा जातियों के ग्राम निर्णय के सिद्धान्त का स्वीकार करते हुए भी एक राज एक राज्य के सिद्धान्त को स्थापित नहीं किया। सन् १९२३ में स्थापित सोवियत समाजवादी गणराज्य अब एक बहु जातीय राज्य है। सोवियत नेताओं ने जातियों की समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए, इस पर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे।

अध्याय २ काति के पूर्व का रुम

प्रारम्भिक इतिहास— उस समय पश्चिमी याशप में पवित्र रोमन साम्राज्य का उदय हो रहा था, उस समय उनमान रुम के प्रदेश में मध्य एशिया से आए हुये स्लाव जातियाँ के टानाबदोश लोग निवास करते थे। यह लोग एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते थे इस कारण इनमें कुछ सामाजिक तथा राजनैतिक संगठन का अभाव था। नवी शलाज्मा में स्क्विनितिया निवासी (Norsemen) इस प्रदेश में आकर बसने लगे। सन् ८२८ ई में कुछ तीन राजकुमारों ने तीन छान छोट राजा की नींव रखी। कालान्त में इन तीनों राजा का हारक (Rusik) नामक राजकुमार ने, जो उल्लेख तीन राजकुमारों में से ही एक था एक में मिला लिया और एक स्लाव राज की स्थापना की। इस राज का राजधानी काव् (Kiev) नगर था डा नायर (Dnieper) नदी के तट पर स्थित है।

काव् (Kiev) राज का रुम के अन्तर्गत समा राजा पर काला समय तक प्रभाव रहा। इस राज्य का सम्बन्ध शीघ्र ही कन्स्तान्टिनोपल (Constantinople) में स्थापित हो गया, जो उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का राजधानी थी। वहाँ से ईसाई धर्म प्रचारका का इस प्रदेश में आना प्रारम्भ हो गया। उन्होंने राजा के अधिनिरासी तथा अनेक देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी में तातार आक्रमणों के समय तक काव् का अन्त राजा पर प्रभाव बना रहा, परन्तु किसी संगठित तथा सशक्त राज्य की स्थापना नहीं हो सकी।

मंगोलों का आक्रमण—सन् १२२४ में जंगज खा (Jenghiz Khan) के मंगोल दला ने रूसी प्रदेश पर आक्रमण किया। स्लाव सेनाएँ उनके सामने नहीं टिक सकी और पराजित हुई। सन् १२३७ में दूसरा बार आक्रमण हुआ और इस बार आक्रानका ने रुस के समस्त मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।

लगभग दो शताब्दियों तक रूस पर मंगोलों का प्रभुत्व रहा। आक्रमण के समय मंगोलों ने अत्यन्त क्रूरता से काम लिया परन्तु शासन में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। उन्हें ज्वलन अग्नि कर प्राप्त करने की ही उद्युक्ता रहती थी। मास्को का ड्यूक उनका एकत्र करने वाला प्रथम अधिकारी था। उसने इस स्थिति से लाभ उठा कर अपने निकटवर्ती राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। सन् १२८८ में एक बड़े युद्ध में मास्को के प्रमुख ड्यूक ने मंगोलों को पराजित कर दिया। मंगोलों का साम्राज्य उस समय प्राणिकी प्रेर या प्रैर उनकी शक्ति का हास हो चुका था। पन्ध्रवीं शताब्दी के मध्य काल तक रूसी प्रदेशों में तातार शासन का रंग रहा अंग्रेजों भी नष्ट हो गया।

मास्को के महत्त्व में रूस का पर्यवर्तन—रूस में ग्रामीणी बहुत से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों थे परन्तु उस समय तक मास्को के शासकों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। मंगोलों पर विजय होने के कारण मास्को के ड्यूक को रूस की एकता की स्थापना रखने वाले सभी वर्गों का नेतृत्व प्राप्त हो गया। साथ ही साथ गारसी दिनाग के कारण बहुत से जमींदार सामंता तथा धर्माधिकारियों की सहानुभूति भी उसे प्राप्त हो गई थी। सन् १४५३ में कन्स्टान्टिनोपल (Constantinople) पर तुर्कों (Turks) ने अधिकार कर लिया। उस समय मास्को का शासक वसिल द्वितीय (Vasil II) था जिसने कई भीषण युद्ध लड़ कर दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सन् १४६२ में इवान तृतीय (Ivan III) मास्को का शासक हुआ और उसने योरोप के अन्य शासकों को सूचित किया कि उसका राज्य拜जान्टीन साम्राज्य (Byzantine Empire) का उत्तराधिकारी है। इवान चतुर्थ ने, जिसे इवान भयंकर (Ivan the Terrible) भी कहते हैं, पार (Ivan) के विजय प्राप्त किया। पार शब्द सीज़र (Caesar) शब्द का अनुवर्तन है। मास्को के शासक अपने निकटवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार कर रहे। मनरा के क्षेत्रों में 'सालहदी' शताब्दी के अंत में मास्को रूस बन गया था और उसका शासक पार। उनका राज्य क्षेत्र में यूरेन और वोल्गा की उपनद्या (Volga Valley) सम्मिलित थे, और वह वसिलो सागर और सान्बेरिया तक फैला हुआ था।^१ बायजान्टीन साम्राज्य

^१ 'By the end of the sixteenth century Moscow had

सेना से पाटर की सेना का युद्ध हुआ और उसमें विजय के फलस्वरूप रूस का कई प्रदेश प्राप्त हुये।

पाटर ने राल्टिक क्षेत्र में सेंट पाटर्सबर्ग (St Petersburg) नामक नगर का निर्माण किया और उसी का अपना राजधानी बनाया। उसने अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दों पर किया और रूस को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिये स्वयं, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय बनवाये। रूस में औद्योगिकीकरण के लिये भी उसने पूर्ण प्रयत्न किया और विशेषांश उद्योगिक तथा कृषिकारों को रूस आने के लिये प्रोत्साहित किया। उसका मुद्दा अपने महत्वपूर्ण तथा मानक थे कि अब बाल्शेविक नेता भी उस सामंतिक शासक मानने लगे हैं। परन्तु सामान्य जनता का उसका मुद्दा अधिक प्रभावित न कर सका। उसने एक प्रयत्न बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने राजसत्ता तथा धर्माधिकारिता के बीच द्वन्द्व का स्थिति न उत्पन्न होने देने के लिये अर्थशास्त्र के पूर्ण अन्वेषण करने अधिनियम कर दिया और स्वयं उसका प्रधान बन गया। इस रूस में पूर्ण एकतन्त्र (Aocracy) स्थापित हो गया। सन् १७२१ में पाटर ने रूस का सम्राट (Emperor) घोषित किया जिस से रूस का शासक का सम्मान और अधिक बढ़ गया।

कैथरीन महान्—पाटर की मृत्यु के पश्चात् अन्तरहर्षा शताब्दी में रूस की शासन प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु रूस साम्राज्य का विस्तार बढ़ता ही गया। रूस का सम्राट कैथरीन महान् (पीटर महान् की पत्नी) के समय में रूस का काले सागर (Black Sea) का हिम विह्वल तट प्राप्त हुआ। रूस के शासक बहुत समय से ऐसे तट का प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे थे। कैथरीन महान् के शासन काल में ही रूस को पार्लै के विभाजनों में उसके राज्य क्षेत्र का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ परन्तु राज क्षेत्र में विस्तार होने के साथ ही नए समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं। इन्होंने यह साम्राज्य का समुचित प्रशासन सरल करने का प्रयत्न किया।

अलेक्जेंडर प्रथम के मुद्दों—उत्तरावर्ती शताब्दी के प्रथम वर्ष (१८०१) में अलेक्जेंडर प्रथम (Alexander I) रूस का शासक बना। वह उत्तर विचारों वाले युवा था और स्वयं से निरंकुश शासन का अन्त कर एक संवैधानिक राजतन्त्र (Constitutional monarchy) का स्थापना करना चाहता था। रूस

में निवाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान प्रवर्तित करने की भी उसकी योजना थी।^१ उसका शासनकाल (१८११-१८२५) में संविधानिक सुधारों की कई योजनाएँ बनाई गईं, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना स्पेरान्स्की (Speransky) का योजना है। यह योजना सन् १८१६ में प्रस्तुत की गई थी। स्पेरान्स्की की योजना शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धान्त पर आधारित थी और इसमें सम्राट को आवश्यक निमाण कान में सहायता देने के लिये चतुर्ता द्वारा निर्वाचित राज्य परिषद (State Council) तथा शासन के प्रत्येक विभाग के लिये एक मंत्री की व्यवस्था का गढ़ था। सन् १८११ और १८१२ में राज्य परिषद का स्थापना तथा मनाने का प्रस्तावन के रूप में स्पेरान्स्की की योजना के कुछ भागों का कार्य भी दिया गया। परन्तु नेपालियन के विरुद्ध पुनः युद्ध आरम्भ हो जाने तथा स्पेरान्स्की के पद-च्युत किए जाने के कारण प्रस्तावित सुधारों का अधिकांश भाग प्रभावित नहीं किया जा सका। राज्य परिषद के संस्थापकों का स्वयं सम्राट नानाकिन करता था तथा वह उनके सुझावों तथा प्रस्तावों का मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस कारण इन सुधारों से रूस के शासन के एकतात्मक स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। सत्तेर में इसका कारण यही है कि तब तक रूस के बाद अन्तर्देशीय के विचारों में प्रतिक्रिया परन्तु महान् परिवर्तन हो गया था।

दिसंबर क्रांति (December Revolution) तथा निकोलस प्रथम का शासन—निकोलस प्रथम के पश्चात् निकोलस प्रथम (Nicholas I) रूस का तब राजा था। उसका शासन काल (१८२५-१८५५) के प्राथमिक वर्षों में ही असफल दिसम्बरी क्रांति हुई। उस क्रांति के प्रयत्नों का नेतृत्व आभिजात्य वर्ग के तथा उदारवादी विचारों के व्यक्तियों के हाथ में था। इस विद्रोह का दूरता के साथ दमन किया गया। जार निकोलस के शासन-काल में उन्नीसवीं शताब्दी का ही प्रधानता रही। उस काल में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ और वह था स्पेरान्स्की के द्वारा 'रूसी साम्राज्य की विधियाँ की संहिता' का संकलन। प्रोक्सिन्सकी के शब्दों में, "देश के इतिहास में प्रथम बार यह अभि

^१F A Ogg and Harold Zink, *Modern Foreign Governments* p 797

निश्चित करना सम्भव हो गया कि वालन में साम्राज्य का शासन किन विधियों के अनुसार संचालित होता है^१।

निकोलस प्रथम ने काले सागर का पूरा उपयोग करने लिए १८५२ में टर्की से युद्ध आरम्भ कर दिया। युद्ध का कारण टर्की के सुलतान की अर्धों डाक्स ईसाई प्रजा की रक्षा माना गया। इसी युद्ध को क्रिमेयन युद्ध के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ईंग्लैंड और फ्रांस रुस के इस पक्ष में होते हुए प्रभुत्व को सहन नहीं कर सके थे, इस कारण उन्होंने टर्की के सुलतान की सहायता के लिए अपनी सहायता भर्त्ता। सन् १८५५ में निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई। सन् १८५६ में पेरिस में संधि हुई जिसमें काले सागर में युद्धपोत (Warships) के ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस प्रकार रुस का भूमध्य सागर की ओर विस्तार रोक दिया गया।

अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन तथा उसके सुधार—सन् १८५५ में अलेक्जेंडर द्वितीय रुस के जारशाही सिंहासन पर आरुढ़ हुआ। उसके शासन काल (१८५५-१८८१) में रुस ने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। सन् १८६४ में तुर्का और किर्गिज सरदारों के पारस्परिक वैमनस्य का लाभ उठा कर रुस ने ताशकन्त (Tashkent) पर अधिकार कर लिया। चार-पाँच सन् १८६८ में रुसी सेनायाँ न ताशकन्त की राजधानी समरकन्त पर अधिकार कर ली। उस पश्चात् ताशकन्त के ज्ञान ने समरकन्त का पूरा प्रांत रुस का दे दिया।

तर्की रुसी साम्राज्य के क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा था वहा आन्तरिक परिस्थिति दिन प्रति दिन गिरावटी जाता था। रुसी राजनीतिज्ञ यह अनुभव करने लग थे कि अत्र सुधार का अधिक समय न मिले स्थिति नहीं किया जा सके। क्रिमिया के युद्ध (Crimean War) में रुस की पराजय के पश्चात् सुधार का धोरण किया जाना आवश्यक समझा गया। सन् १८६१ में अलेक्जेंडर

^१ "For the first time in the history of the country it became possible to ascertain what actually were the laws governing the Empire" Michael T. Florinsky *The Govt & Politics of the U S S R in Governments of Continental Europe* edited by Shotwell

रूसी द्वितीय ने कृषका की अर्द्धदासता (Serfdom) का अंत करने की घोषणा की। उसी कृत्य के कारण उसे 'उद्धारक तार' (the Tsar Emancipator) के नाम से संबोधित किया जाता है। कृषका का एक निश्चित परिमाण में भूमि देने की व्यवस्था की गई परन्तु इसने बंले में उन्हें जमीन को प्रतिकर के रूप में धन देना होता था। इन सुधारों से जहाँ एक ओर जमीनी मालिकों का भावना फल गई वहाँ दूसरी ओर कृषकों को भी निराशा हुई। उनसे प्राप्त जमीन को प्रतिकर देने के लिए यह नहीं था और इस कारण उन्हें सुधार से विशेष लाभ नहीं हुआ।

अलेक्जेंडर के अन्य प्रमुख सुधार स्थानाय स्वशासन संस्थाओं का पुनर्गठन, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, ग्राम पंच का एकाकरण, विश्वविद्यालयों का आन्तरिक संगठन के सम्बन्ध में स्वायत्तता प्रदान करना आदि थे। परन्तु जिस सुधार का सर्वाधिक मांग थी वह स्वीकृत नहीं किया गया। अलेक्जेंडर द्वितीय जनता द्वारा निर्वाचित विधान सभा स्थापित कर अपना एकात्मिक सत्ता को सीमित करने का सदैव विरोधी रहा। साम्राज्य के अधिकारी उदारतावादी विचारों से इतने भयभीत थे कि वे समाचारों में 'संविधान' और 'संसद' शब्दों को भी सेंसर कर देते थे।^१

तार अलेक्जेंडर के द्वारा किये गये सुधार महत्वपूर्ण तथा प्रगतिशील माने जाते थे भी जनता को संतुष्ट नहीं कर सका। तारशाह के प्रांत जनता के हृदय में सद्भाव उत्पन्न करने के स्थान पर उनके मिल्कुल उलट ही प्रभाव हुआ। उनके कारण उदारतावादी आन्दोलन (Liberal movement) का धग धोर भाव अधिक बढ़ गया। मनरो के मतानुसार "कृषकों के उद्धार का एक परिणाम यह हुआ कि कृषकों के नगरों का जाने का प्रोत्साहन मिला गया कन मन्त्री पर तथा औद्योगिक शक्ति के प्रारम्भिक वर्षों की नूतनापूरा कार्य का प्रशासन में कारखानों में काम निभाना था। कारखानों के यही श्रमिक पाल्सेविकों के सत्ता प्राप्त करने के साधन बने।^२ जनता में पैदा निराशा और असन्तोष सन् १८८१ में

^१ Sergius A. Korff *Autocracy and Revolution in Russia* p 7-8

^२ W B Munro and M Aycarst *The Governments of Europe* p 637

अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या का कारण बना। उसका शासन-काल के अन्तिम वर्षों में रूस में निहिलिस्ट (Nihilist) दल का जार बहुत बढ़ा था। जारशाही पुनित्त ने दमन से निहिलिस्टों का गुप्त सन्स्थापना को समाप्त करने का प्रयत्न किया। स्वयं अलेक्जेंडर द्वितीय पर गम फैक कर उनकी हत्या करने वालों को निहिलिस्ट माना जाता है।

अलक्जेंडर तृतीय—अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के पश्चात् अलेक्जेंडर तृतीय उनका उत्तराधिकारी बन कर मजबूत हुआ। उसने समस्त उत्तराचारवादी आन्दोलनों (Liberal movements) का कुचनने तथा पूर्णरूपण निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। अलेक्जेंडर द्वितीय ने अपनी मृत्यु के दिन मुधारा की एक योजना पर अपनी स्वाकृति दे दी थी। इन योजना को “लारिस्-मेलिकोव संविधान (Lois Melikov Constitution)” कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माता काउन्ट एन. डी. लारिस् मेलिकोव था। उस योजना में एक ऐसा परामशान्ता परिषद् का बनाने का प्रस्ताव था जिसके कुछ सदस्य जार द्वारा नामांकित किये जाते तथा कुछ अन्य स्थानाय संस्थाओं द्वारा चुने जाते। यह परिषद् बस परामशान्ता होता और इससे निश्चय को मानना सम्राट के लिये आवश्यक न था। परन्तु अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद उसका उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर तृतीय ने इस योजना का प्रवर्तन नहीं किया। उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह समस्त आतिकारी तथा उत्तराचारवादी आन्दोलनों का उन्मूलन कर पूर्णरूपण एकीकृत शासन बनाए रखेगा और अपने सम्पूर्ण शासन काल में वह अपने निश्चय पर अग्रिम रहा। उसने अपने शासन-काल में अपने सम्राट की रुखियों से भिन्न सभी जातियों का रूसीकरण (Russification) करने का भी प्रयत्न किया।

सन् १९०५ का असफल क्रांति—सन् १९०५ में अलार्जेंटर तृतीय की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र निकोलस द्वितीय (Nicholas II) ने उसका स्थान लिया। उसने पिचार अपने पिता से समान ही थे। उसने अपने पिता की प्रतिक्रियाशील नीति का ही पालन किया और सुधार के लिए आन्दोलन करने वालों का बहुत से दमन किया। इस नीति के परिणामस्वरूप जनता का असंतोष बढ़ने लगा और क्रांतिकारी संस्थाओं का कार्यवाहियों भी और अधिक

न गई। निकोलस द्वितीय ने सन् १९४ में जापान के साथ अपने मित्रों का तय करने व सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसे दृढ़ विश्वास था कि जापान युद्ध में रूस के सामने नहीं टिक सकता। परन्तु युद्ध का परिणाम उसकी आशा के विपरीत हुआ। पराजित जार को जापान से संधि करने के लिए विवश होना पड़ा जिसमें उस दक्षिणी मंचूरिया और कोरिया में अपने समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। सखालिन् द्वीप का आधा भाग रूस ने जापान को दिया। यह संधि जारशाही के लिये अत्यन्त लाजानक थी और इससे उसने सम्मान को बहुत ठेस लगी।

जनवरी १९५ में जब कि रूस जापान युद्ध जारी था पाटर्सबर्ग व एक नये कारगाने र श्रमिकों ने हड़ताल की। व लोग जुलूस बना कर जार के 'शहर' प्रसाद व सामने अपनी मार्ग को प्रस्तुत करने के लिये गये। परन्तु जारशाही पुलिस ने उन पर गाली चलाई जिसमें मैक्रय श्रमिक हताहत हुए। इससे जनता र सभी भागों में तीव्र असंतोष की भावना गहृत हो गई। जार को अभी तक जार का जनता का हितचिन्तक समझत था, जार के मित्रों ही हो गये। समस्त रूस में विद्रोह की एक लहर लौढ़ गई और श्रमिकों और किसानों ने स्थान स्थान पर हड़तालें और आन्दोलन दिये। इसी समय पोतेम्किन (Potemkin) नामक युद्ध पाव (battleship) र नारिका ने विद्रोह किया। रूसी साम्राज्य की राजधाना सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों की सोवियत (Workers Soviet) का स्थापना का गई। इसी व अनुरूप सोवियत या परिषद अन्य स्थानों पर स्थापित का गई। इस समय तक आन्दोलन का नेतृत्व मार्क्सविक नेताओं के हाथ में आ चुका था। सेंट पीटर्सबर्ग की सोवियत का सम्पादन जास्का था। जार ने विद्रोह का दमन करने का पूर्ण प्रयत्न किया परन्तु जापान से पराजित होने के कारण उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुका थी। ऐसी स्थिति में उसने कुछ सुधारों की घोषणा कर स्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न किया।

३० अक्टूबर का घोषणापत्र^१—३ अक्टूबर, १८५ का जार ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसमें कई सांविधानिक सुधारों का उल्लेख किया

^१ उस समय रूस में जा सवत् (calendar) प्रचलित था उसका अनुसार यह

गया था। इस घोषणापत्र के द्वारा जनता की मूल स्वतन्त्रताओं का प्रत्याभूति प्रदान की गई थी। यह मूल स्वतन्त्रताएँ अकारण बन्दी न बनाये जाने की स्वतन्त्रता, विचारों की स्वतन्त्रता, समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, एकत्र होने का स्वतन्त्रता तथा संगठित होने या संघ बनाने की स्वतन्त्रता थीं। घोषणापत्र में एक द्विसप्ताह नामक विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। इसके उच्च सदन के आधे सदस्यों को जार द्वारा नामांकित किये जाने तथा आधे के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गई थी। निम्न सदन जिसका नाम राय ड्यूमा था, के सदस्यों का निर्वाचन जिला समूहों के द्वारा किया जाता था। पुरुष-मतधिकार के आधार पर चुनी जाता। घोषणापत्र में यह नियम स्वीकृत किया गया था कि कोई विधि (law) राय ड्यूमा के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगी तथा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्राट् द्वारा नियुक्त अधिकारियों की कार्यवाहियों पर नियंत्रण में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा जिससे उनकी कार्यवाहियाँ विधि के अनुकूल हों।

सन् १९५ और १९६ में उद्घाटित घोषणापत्र को प्रवर्तित करने के लिये आवश्यक विधियाँ बनाई गईं, तथा पूर्ण प्रवर्तित विधियाँ में संशोधन किये गये। अन्तर्राष्ट्रीय समय में मातिसारा आन्दोलन भा शिथिल हो कर समाप्त हो गया। अभी रूस की जनता में यह राजनीतिक चेतना और सगर्भता है कि कार्य करने का भावना नहीं था जो क्रांति को सफलता प्रदान करती है। अक्टूबर १९५ के घोषणापत्र पर विचार प्रकट करते हुये मारा ने लिखा है कि "सन् १९५ में रूस अत्यंत राजनीतिक निरास की उस स्थिति तक पहुँच गया जो इंग्लैंड का सन् १२१५ में मगना कार्टा के द्वारा प्राप्त हुआ था।"

घोषणा १७ अक्टूबर को की गई। राय ड्यूमा में भी अन्तर्राष्ट्रीय संवत् स्वीकार कर लिया गया।

“Russia in 1905 had at least reached the stage in political development attained by England in 1215 with Magna Carta—W. M. M. and Morley Aycarst *The Conventions of Europe* p 639

प्रथम तथा द्वितीय ड्यूमा—अक्तूबर १६ ५ व घोषणापत्र व अनुसार सन् १८ ६ म प्रथम राय ड्यूमा ने निर्वाचन कराए गए । राय ड्यूमा म सभी सत्स्य निवाचित थ । यद्यपि स्त्रिय का मतान्तर नह्य िया गग था परंतु पुरुषा की एक बड़ी सग्या का मतधिकार प्राप्त हो गया था । समाजवाणी विचारा व उग्र ल सन् १६ ५ व साविनिक सुधार स सतुट नह्य थ, ंस कारण उहाने निर्वाचन न रायकाट किया । प्रथम ड्यूमा र अधिकांश सत्स्य साविनिक प्रजातन्त्रवाणी (Constitutional Democrats) दल थ ये, परंतु कुछ सत्स्य उग्र विचारा वाले भी थ । म १६ ६ म इसका प्रथम सत्र हुआ और इसने एक ऐले विधेयक पर ाचार करना आरम्भ किया जिस र द्वारा ाबी जमादारिया का समाप्त कर भूमि का कृषका म वितरित करने का प्रस्ताव रपा गया था । ड्यूमा ने मन्त्रिमल व कारों र सम्ब म एक सप्तर का प्रस्ताव पारित करने का प्रयत्न भी किया । इस समय तक रूस और जापान म संधि हा चुकी थी, और इस कारण जिस दवाव र कारण चार न साविधानिक सुधा की घोषणा की थी वह अत्र समाप्त हो गया था । जार ने जून १६ ६ म ड्यूमा का भग कर िया और ंस प्रकार ंस में साविधानिक शासन का प्रथम प्रयाग हा असफल रहा ।

प्रथम ड्यूमा व विघटन र पश्चात् पुन निर्वाचन कराए गए । उ समाजवाणी और क्रान्तिकारी दला ने, बिहाने पिछले निर्वाचन का रायकाट किया था, इस बार निर्वाचना म भाग लिया । इस परिणामस्वरूप ड्यूमा और जार व नीच की लाइ और र गइ । निर्वाचन व कुछ ही माह पश्चात् जून १६ म जार ने द्वितीय ड्यूमा का भी भग कर िया । जार तथा उग्र मन्त्रियों को यन् निग्रह हा गया कि त्र तक निर्वाचा सम्प्रधा नियमा म पारवतन नही किया जाएगा तत्र तक ड्यूमा व साथ काय करना असम्भव हे । ंसी कारण जिस िन ितीय ड्यूमा को भग किया गया उसी िन चार की सरकार ने एक नई विधि का प्रवर्तित किया जिसम निर्वाचन तथा मतधिकार सम्प्रधी नियमा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए ।

जून १६०७ के निर्वाचन नियम तथा तृतीय और चतुर्थ ड्यूमा— निर्वाचन सम्प्रधी नए नियमों र द्वारा मतधिकार को बहुत अधिक सीमित कर

लिया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया कि क्यूमा में जार व समर्थकों का बहुमत हो। निर्वाचन सम्बंधी इस नई विधि का प्रवर्तित कर जार ने अक्टूबर १९ ५ के घोषणापत्र का अतिरिक्त किया था, क्योंकि घोषणा में कहा गया था कि प्रत्येक विधि क्यूमा की स्वीकृति से बनाई जावेगी। इस विधि को प्रवर्तित करने के साथ ही जार की सरकार ने क्रान्तिकारी तथा सामाजिक जनतन्त्रवादी दलों के बहुत से सदस्यों को निर्वासित कर दिया।

निर्वाचन सम्बंधी नई विधि का प्रवर्तित करने से जार का उद्देश्य पूरा हो गया। सन् १९ ७ में तृतीय क्यूमा के निर्वाचना में जारशाही के समर्थकों को बहुमत प्राप्त हुआ। अनुमान किया गया है कि इस निर्वाचन में करीब १५ प्रतिशत नागरिकों को मतार्थिकार प्राप्त था^१। निर्वाचन विधि की बदलिता के कारण कृषकों और श्रमिकों के वास्तविक प्रतिनिधित्व का निर्वाचित होना अत्यंत दुष्कर था। तृतीय और चतुर्थ क्यूमा में क्रमशः पैताचीस और पैंतालीस धमाधिकारी (electors) चुने गए थे। यह बहुत बड़ी संख्या है। यह सभी मतार्थिकारी जारशाही के समर्थक थे क्योंकि पिछले काफी समय से जारशाही और धमाधिकारियों में परस्पर गठनघन था। तृतीय और चतुर्थ क्यूमा में जार की सरकार का किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं किया और उसका व्यावहारिक कार्य किया। इस कारण इन दोनों में पूरे पांच पांच वर्ष काय किया जा कि उनका निश्चित कायमान था।

जारशाही शासन के अर्थ अंग—सन् १९ ५ के सामाजिक परिवर्तनों के पश्चात् रूस के शासन का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझने के लिए क्यूमा के अतिरिक्त शासन के अर्थ अंग तथा उनसे जुड़ा वे शक्तियाँ का समझना आवश्यक है। यद्यपि इन परिवर्तनों ने जार की शक्तियों पर पराप्त प्रतिरोध लगा दिए थे परन्तु अभी भी शासन में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। अप्रैल १९ ६ में अक्टूबर १९ ५ के घोषणापत्र के अनुसार संस्थापित व परिवर्तित मूल विधियाँ (Fundamental Laws) में उल्लेख था “रूस के सम्राट में सर्वोच्च एकवर्ती शक्ति निहित है। उसकी आज्ञाओं का न केवल भय के कारण बल्कि अनिवार्य

से मानने की आज्ञा स्वयं ईश्वर ने दी है।^१ प्रत्येक विधेयक पर उसके विधि का रूप लेने व पूर्व-सम्राट का स्वीकृति आवश्यक थी। मूल विधियां व सशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार वरुन सम्राट को ही था। विधान मण्डल व उच्च सदन, राज्य परिषद (State Council), ने प्राप्ते सम्बन्ध सम्राट् द्वारा नामांकित किए जाते थे। इससे अतिरिक्त सम्राट् को विधान मण्डल व दोनों सदन व सत्र बुलाने, उन्हें स्थगित करने तथा उन्हें विघटित करने का अधिकार भी प्राप्त था। इस सम्बन्ध में केवल यही प्रतिबन्ध था कि यह व एक बार उनका सत्र बुलाया जाना आवश्यक था।

शासन व उच्च अधिकारियां तथा मंत्रियों को सम्राट स्वयं नियुक्त करता था। मंत्री केवल सम्राट् व प्राप्त उत्तरदायी होते थे। विधान मण्डल व प्रति नहीं। वैदेशिक सम्बन्ध, युद्ध तथा शान्ति का घोषणा करना तथा अन्य देशों से सन्धियां करना, ये सब सम्राट् व परमाधिकार (prerogatives) थे। सम्राट् को आप्रकालीन स्थिति (State of Emergency) की घोषणा करने का भी अधिकार था। ऐसा घोषणा व पश्चात् तत्कालिक स्वतन्त्रताएँ निलम्बित (suspend) हो जाता था।

सन् १८६४ में अलेक्जेंडर द्वितीय ने न्याय व्यवस्था सम्बन्धी बहुत स महत्वपूर्ण सुधार किए थे जिनसे द्वारा न्यायाधीशों को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। परन्तु धीरे धीरे न्याय व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए जिनमें सन् १८७४ व सुधारों का प्रधान काफी सीमा तक नष्ट हो गया। सन् १८८८ में एक विधि व द्वारा कृषकों द्वारा किए जाने वाले हृत व छोटे अपराधों व सत्र में विचार करने का अधिकार न्यायाधीशों से छीन कर राजकीय अधिकारियों को दे दिया गया। यह अधिकार सन् १९१२ में विधान मण्डल व दोनों सदन द्वारा पारित विधि द्वारा न्यायाधीशों को वापस लिया गया।

आप्रकालीन शक्तियों का दुरुपयोग—अलेक्जेंडर द्वितीय की क्रांति

^१ "To the Emperor of all the Russias belongs the supreme autocratic power. To obey his commands not merely from fear but according to the dictates of one's conscience is ordained by God himself —Art 4 of the Fundamental Laws

कारिया द्वारा हटा किये जाने (१८८८) के पश्चात् से रूस में “आपराधिक उपाय (exceptional measures) का प्रयोग प्रारम्भ किया गया था। इनके अन्तर्गत प्रशासनीय अधिकारियों को अत्यन्त विस्तृत अधिकार दे दिये जाते थे। एक विशेष राजनैतिक पुलिस ओब्राना (Okhrana) का संगठन किया गया था जिस का कार्य उन राजनैतिक कार्यवाहियों का पता लगाना तथा अतिकारियों को पकड़ना था। अस्तु यह पुलिस जारशाही द्वारा किये जाने वाले दमन का प्रमुख साधन थी। “आपराधिक उपायों से संबंधित विधि पहले केवल ताना बंध के लिये प्रयुक्त की गयी थी परन्तु वह फिर सदेन ही लागू रहा। प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उसका नवीनीकरण कर दिया जाता था। उनका नगर या ग्राम विशेष सरक्षण के अन्तर्गत शासित होता था नागरिका का प्रशासनीय प्रक्रिया में सम्मेलित किया जा सकता था किसी विशेष नगर में उनका निवास पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था, किसी विशेष प्रमाणा पर करने से रोका जा सकता था, उन्हें पुलिस की देख रेख में रखा जा सकता था और केवल शराब का व्यापार पर उन्हें रोकना जा सकता था या उनकी तलाशी जा सकती थी।” सन् १९५५ में सामाजिक शासन की स्थापना किये जाने के बाद भी आपराधिक उपायों का प्रयोग जारी रहा। फरान्सिसकी के शब्दों में “आपराधिक स्थिति ही सन् १९५५ के समय के रूस की सामान्य स्थिति थी।”^१

जारशाही रूस में सामाजिक जीवन

जनता का दयानिष्ठ वर्गीकरण—जारशाही रूस का एक विशेषता यह थी कि जनता का विविधता के द्वारा चार वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। इन वर्गों का निर्माण स्वयं जारशाही के द्वारा किया गया था और वहाँ इसका शासन करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती थी। प्रत्येक वर्ग के

^१ Harper S N, *The Government of the Soviet Union* p 14

^२ A state of emergency was the normal regime in the Russia of 1905-1914 — M T Florinsky *op cit* p 673

नागरिक न उच्च निश्चित अधिकार और कर्तव्य होत थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में यह वर्गीकरण शिथिल होता जा रहा था और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ता जा रहा थी जो किसी वर्ग में जा रहे जा सकते थे। परन्तु चारशाही वर्ग व्यवस्था को बनाए रखने में ही अपना हित समझती थी और इस कारण उम प्रस्तावहन देता थी।^१ १६१७ की श्रावत तक जिगिया द्वारा इस वर्गीकरण का मान्यता प्राप्त थी। जनता को निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त किया जाता था —

- १ आभिजाय वर्ग (the nobility)
- २ समाधिकारी वर्ग (the clergy)
- ३ नगर निवासी (burghers)
- ४ सामान्य या कृषक (the peasantry)

आभिजाय वर्ग—आभिजाय वर्ग चारशाही रूस का सर्वाधिक प्रभावशाली तथा समृद्ध वर्ग था। राज्य न उच्च पदा पर अधिकतर इसी वर्ग के लोगों का नियुक्त किया जाता था। यद्यपि सन् १८६१ में कृषक न “उद्धार” के पश्चात् उन्हें भूमि का स्वामत्त्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, परन्तु अग्रेसर भूमि पर आभिजाय वर्ग के लोग न ही अधिकार था। इस वर्ग के लोगों का दो भाग में विभाजित किया जा सकता है (१) वे जिन्हें वंश परंपरा से इस वर्ग में सम्मिलित माना जाता था, तथा (२) वे जिन्हें “यत्किन्तु” के त इस वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया था। उच्च राजकीय पदों पर पहुँच जाने से आभिजाय वर्ग की संख्या प्राप्त हो जाती थी। स्थानीय सभाया तथा राज्य द्यूमा के निर्वाचना में आभिजाय वर्ग के व्यक्तियों के मत का अधिक महत्व होता था। इस वर्ग के व्यक्तियों का श्रम ऐस गहन से विशेषाधिकार प्राप्त थे जो अन्य वर्गों के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं थे।

^१ 'Tsarism rested on a system of legal classes that had its roots in the past but was consciously fostered as part of the policy of self defence of autocracy'—S N Harper op cit p 16

धर्माधिकारी वर्ग—जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है रूस में अर्थोक्स चर्च को राजाज्य प्राप्त था। चर्च के पास पर्याप्त संपत्ति तथा भूमि एकत्र हो गई थी। इस कारण धर्माधिकारियों के हाथ भी जारशाही और आभिजात्य वर्ग के हिस्से के साथ सन्तुष्ट हो गये थे। यह वर्ग बिना चार और उसकी सरकार के अधिकारियों के निकट होता जाता था उनका ही जनसाधारण से इसका सम्पर्क टूटता जाता था। धर्माधिकारियों को भी उनके विशेषाधिकार प्राप्त थे।

नगर निवासी वर्ग—नगर निवासी वर्ग का आशय ऐसे लोगों से था जो नगरों में रहने थे तथा छोटे-बड़े कारखानों में कार्य करते थे अथवा दस्तकारी के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुत से ऐसे श्रमिकों को भी 'सब वर्ग' में सम्मिलित माना जाता था जिन्होंने ग्रामीण प्रपना एण सम्बंध निच्छेद कर लिया था। परन्तु रूस के औद्योगिक विकास के साथ कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती ही जाती थी। ये श्रमिक नगरों में रहते अथवा वे परन्तु यह नगर निवासी वर्ग का सदस्य नहीं माना जाता था। इन्हें अपने सम्पत्ति नगरीय अधिकारों में प्राप्त नहीं था।

कृषक वर्ग—अन्तिम, परन्तु संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग, कृषकों का था। रूस कृषि प्रधान देश है इस कारण इस वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक ही है। सन् १८६१ में अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा प्रवर्तित सुधारों के परिणामस्वरूप कृषकों का अर्थोक्स का आर्थोक्स हो गया था, परन्तु उन्हें अभी भी अन्य वर्गों के लोगों से हानि समझा जाता था। इनके अधिकतर अक्षितपूर्ण और दुर्गा जानने-बुझने करने थे और उन्हें अपने-अपने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्कूलों में भर्ती के समय उनके बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था और कुछ विशेष शर्तें पूरा करने पर ही उन्हें स्कूल में प्रविष्ट किया जाता था। निर्वाचना में वे अन्य वर्गों से अलग मतदान करते थे। सन् १९५५ के सुधारों के द्वारा उनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। परन्तु फिर भी उनका वैधानिक अधिकारों (legal disabilities) का पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ।

बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव—यद्यपि जनता के वर्गीकरण सम्बंधी विधि सन् १९१७ तक रूढ़ नहीं की गई थी परन्तु उसका प्रभाव सन् १९६६ में किए गए

संविधानिक परिवर्तना के कारण बहुत कुछ समाप्त हो गया था। उनके द्वारा दो मुख्य अधिकार जो केवल उच्च वर्गों का ही प्राप्त थे अब वर्गों को भी प्राप्त हो गए। ये अधिकार थे—अपना निवास स्थान चुनने एवं देश में स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार तथा राजसत्ताओं में प्रविष्ट होने का अधिकार। शिक्षा का प्रसार और प्रजातांत्रिक विचारों का प्रचार के कारण गीसवा शताब्दी के प्राथमिक वर्षों तक रूस में एक नए युग का सृष्टि हो चुकी थी। यह था बुद्धिमानों का युग (the Intellectuals)। इस युग में सभी वर्गों के व्यक्ति थे। बुद्धिवादी वर्ग जारशाहों, समाकरण प्रणाली तथा उच्च वर्गों के यंत्रियों के शिक्षाधिकार का विरोधी था। राजनीतिक ग्लोब के नेता अधिकतर इस युग के अंगी होते थे।

जारशाहों की बलपूर्वक समाकरण का नाति—रूसी साम्राज्य के विस्तार में जार का सरकार के समस्त एक अंगिन समन्वय करने का था। उस समय विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के प्रति अमान्यताएँ बाली नाति से सम्बन्धित थी। यदि हम श्वेत रूसिया और लाल रूसिया का भाग गौर रूसिया में हाँ गिनता रूसी साम्राज्य की लगभग आधा प्रजा गौर रूसी थी। जारशाहों ने अल्पसंख्यकों के प्रति अपमानपूर्ण समाकरण का नाति अमान्य। अल्पसंख्यकों का संस्कृति भाषा, धर्म और परम्पराओं का कुचल कर उन्हें रूसी भाषा, रूसिया के धर्म और रूसी संस्कृति अपमान के लिए विवश किया जाता था। यंत्रियों के प्रति जार का सरकार का नीति विशेष रूप से कठोर थी। उन्हें अखिली और अखिली परिवर्तनाओं में कुछ क्षेत्रों का हस्तगत कर अन्य किसी क्षेत्र में बसने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। केवल कुछ वर्ग यंत्रियों, विचारकों, और चिकित्सकों को ही इस नियम से अपवाद थे। यंत्रियों का इतनी घातनाई दी जाती थी कि वे बहुत से यंत्रियों को छोड़ कर अन्यत्र चले गए। अन्य जातियों और समाजिकविविधता का स्थिति में बहुत सावधानी थी। सन् १९५ के आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने के कारण जारशाही सरकार ने उसके बाद गौर रूसिया में और भाग बुरा प्रहार किया। जितना ही जार की सरकार रूसीकरण के द्वारा साम्राज्य के एकीकरण का प्रयत्न कर रही थी उतना ही वह विपन्नता का अन्त अग्रसर होता जा रहा था।

प्रथम विश्व युद्ध का रूस की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव

१ जुलाई, १९१४ का रूस युद्ध में प्रविष्ट हुआ। कहा जाता है कि जार की सरकार को यह विश्वास था कि युद्ध में प्रवेश करने से जनता में देश प्रेम की भावना को जागृत किया जा सकेगा और पितृभूमि की रक्षा करने के लिए वह जारशाही से अपने विरोधों का भुला देगा। उस समय तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि रूसी साम्राज्य के विपक्षन के लक्षण स्पष्ट दीप्त रह रहे थे। राजनीतिक दल का प्रभाव कम रहा था और स्थान स्थान पर क्रमिकता का हस्तान्तरण जारी था। जारशाही जिस प्रकार अपने आपत्कालीन त्रिकोण का दुर्न्याय कर रही थी उसका रूस ने विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था। रूस ने ग्लोबलनीय है कि उस समय रूस ने अधिकार सम्पन्न जार के मनधन प्रत्युत्तर नहीं दिया। जारशाही की उत्पन्नक रूसीकरण की नीति के कारण रूस का समाज रूसी नागरिकों में घोर असन्तोष फैला हुआ था। रूसी कारण से यह कहा जाता है कि जार ने अपने सिंहासन की प्राप्ति की लपटों में अपने लिए ही युद्ध में प्रवेश किया।

युद्ध के प्रारम्भिक काल में जार का सामाजिक जनतन्त्रवादी दल के राजनीतिक दल — अनिर्दिष्ट जनता के अन्तर्गत सभी भागों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। देश के सभी भागों और जनता के सभी वर्गों में देशभक्ति की भावना प्रबल हो उठी। परन्तु यह उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। युद्ध में होने वाली जन जन का अपार क्षति वर्धना का रूसी साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय और युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली अकाल की स्थिति से जनता में घोर असन्तोष उत्पन्न हुआ। जार सरकार ने इस स्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं थी। रूस ने रूसी साम्राज्य के भी सामाजिक सुधारों और संसदीय शासन स्थापन करने का नाग प्रत्युत्तर का। सन् १९१५ की अगस्त में जार निकोलस स्वयं राजा का सर्वोच्च कमान्डर बन गया और उसके राजधानी से चले जाने के बाद उसकी पत्नी (सारा) ने शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया। वह एक

अग्निनि काक, ग्रस्य सपुतिन (Gregory Rasputin) स हुत प्रधि
प्रभाति या त्रोर न देव (man of God) मानती या। अरान र
हुधा कि पेरा विकट परिस्थिति में देश का गलविज शासक सपुतिन न
गा। जनता का प्रसन्नता हा गा और युद्ध में लड़ने वाला सनाई भा
सुद का सभाति दबने का कामना करने गा। नानक, कागागास गा
प्रभाति न कार प्रकाति जिन क कट त हा ग। फल त
र गा हुत भी प्रभाव न गा। उने शासकता में किना प्रका का
सुार कन स त गा कर ति और अमानकता का सदन क हा
प्रता प्रान लन ना ति। १९१७ क प्रान्न में जनता न अरान न
प्रता ना गा कर ति या कि चारगा शासन भाति में किना
प्रकार का शुका जे नगा त गा था। जन हा प्रश्न हा या कि स
नगाविकार किम हाना चाणि।^१

इस प्रश्न — उत्तर का लपन भाव और नवर १८१७ का प्रवि
दारा हुधा।

^१ By 1917 there was no question whatever as to the fate of the Tsarist regime. The only question was as to who should be its heir — W. B. Munro & Morley Ayeasist *The Government's of Europe* p 641

अध्याय ३

माक्सवाद, बोलशेविक क्रान्ति तथा सोवियत शासन व्यवस्था का विकास

जिस समय समस्त विश्व का १०० वें प्रथम महायुद्ध के परिणाम का उद्भुक्ता पृथक् प्रस्ताव कर रहा था उस समय एक ऐसा नया घटा जिसने सभी देशों में निराशा, निराशा, निराशा का एक अजीब और अजीब ज्वार फैला दिया था। यह घटना था रूस की राजनीतिक क्रान्ति। राजनीतिक क्रान्ति में न केवल रूस की राजसत्ता ही परिवर्तित हुई बल्कि समस्त विश्व में भी प्रचलन परिवर्तित हुआ। इस घटना से यह क्रान्ति सिद्ध हो गई कि यह क्रान्ति का नेतृत्व राजनीतिक क्रान्ति ने किया कि एक सिद्धांत का नाम मार्क्स (Karl Marx) और फ्रेडरिक एंगेल्स (Friedrich Engels) द्वारा प्रतिपादित विचारों पर आधारित था। क्रान्ति के पश्चात् राजनीतिकों ने देश में जिस शासन व्यवस्था का स्थापना के यह भाव मार्क्सवादी सिद्धांतों का कायम करना का प्रयास था। इसलिए राजनीतिक क्रान्ति तथा सशस्त्र शासन व्यवस्था का अन्त आरम्भ करने के पूर्व मार्क्सवादी सिद्धांतों में परिवर्तित होना आवश्यक है। यहाँ अति संक्षेप में हम उस पर विचार करेंगे।

माक्सवाद के मूल तत्व—कान मार्क्स (१८१८-१८८१) द्वारा लिखित गतक प्रथम में मार्क्स और एंगेल्स का उद्घरण करने वाले प्रथम प्रकरण हैं। यह प्रथम है—

(१) 'द कैपिटल' (The Capital) तथा (२) 'मनफेस्टो ऑफ़ द कम्युनिस्ट पार्टी' (Manifesto of the Communist Party)। द्वितीय प्रथम कान मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स दोनों ने लिख कर लिखा था। यह प्रथम प्रथम (१८४८ कैपिटल) में पूर्ण लिखा गया था, और इसमें मार्क्स के द्वारा का मार्क्स इतिहास की व्याख्या और मार्क्स और एंगेल्स द्वारा संक्षेपित विश्व का

समस्याओं का हल का सङ्ग्रह में उल्लेख है। 'नि' कैपिटल माक्स की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसे उस प्रथम काटि व दार्शनिकी में स्थान मिला। इस ग्रन्थ में माक्स का विचार का सविस्तार वर्णन है।

माक्सवादी दर्शन में तीन मूल तत्व हैं जिन पर माक्स का राय सम्बन्धी विचार आधारित हैं। ये तत्व हैं —

- (१) द्वैतमक भौतिकवाद (Dialectical Materialism)
 - (२) ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism), तथा
 - (३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value) ।
- इन सिद्धान्तों का यहाँ सञ्चय में स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

(१) द्वैतमक भौतिकवाद—काल माक्स द्वैतमक पद्धति (Dialectical method) का प्रयोग करने वाला प्रथम विचारक नहीं था। उसके पूर्व हागल (Hegel) ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया था। परन्तु माक्स ने हागल की द्वैतमक पद्धति का प्रयोग भिन्न उद्देश्य से किया। माक्स का विचार था कि भौतिक पदार्थ ही वास्तविक चरित्र जगत या प्रकृति का मौलिक आधार है। पदार्थ ही प्रथम सत्य है। जबकि कथन है कि पदार्थ तब के विकास का माहा चेतना तब उपन होना है। यह भौतिक पदार्थ को प्राथमिक महत्त्व देता है और चेतना का द्वितीय। मनुष्य का चेतना का निमाण उसकी भौतिक परिस्थितिना करता है, न कि भौतिक परिस्थितिया का निमाण चेतना करता है।^१ माक्स का अनुसार ससार की प्रत्येक वस्तु गतिमान है प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन का हर्म्य यह है कि प्रत्येक वस्तु में कुछ अपने निमित्त विरोधी तत्व (Inherent contradictions) होते हैं। इन विरोधी तत्वों का बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष का परिणाम स्वरूप एक नए तत्व का सृष्टि होती है। परन्तु इस नए तत्व में भी विरोधी तत्व निहित रहते हैं, जिससे पुनः यहाँ चक्र चलता रहता है। इस प्रकार

^१ 'It is not the consciousness of men that determines their being but on the contrary their social being that determines the r consciousness' —K. Marx *Selected Works* Vol I p 269

द्वन्द्वगत वस्तुओं का निहित संघर्षों का अंगन है। विरोधी तन्त्रों का सङ्घर्ष ही विकास है।^१

द्वन्द्वगत भौतिकशास्त्र हम प्रतीतिता है कि संसार में कोई प्राकृतिक घटनाएँ एकाकी नहीं होती। सभी प्राकृतिक घटनाएँ परस्पर सम्बद्ध और अन्यायप्रति होती हैं। यदि ऐसा है तो हम इतिहास की हर एक सामाजिक व्यवस्था और प्रत्येक सामाजिक शासन का उन विधियों के दृष्टिकोण से अंगन चाहिए जिनसे वे सम्बद्ध हैं। उदाहरणार्थ पूँजीवादी व्यवस्था आज अत्यंत हानिकार और अस्वाभाविक व्यवस्था प्रतीत होती है, परन्तु यह सामन्तवादी व्यवस्था के आगे का आवश्यक चरण था। मार्क्स का विचार था कि सामन्तवादी व्यवस्था में निहित विरोधी तन्त्रों ने पूँजीवादी व्यवस्था को स्थापन किया। परन्तु पूँजीवादी व्यवस्था स्वयं अपने निहित विरोधी तन्त्रों के कारण समाजवादी व्यवस्था का स्थापन देकर लुप्त हो जाएगी।

(२) ऐतिहासिक भौतिकशास्त्र—मार्क्स ने न केवल द्वन्द्वगत भौतिक शास्त्र के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया बल्कि उसमें आधार पर इतिहास की व्याख्या भी की। इसी व्याख्या को इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Materialistic interpretation of History) कहते हैं। मार्क्स का विचार था कि समस्त इतिहास ही उत्पात्कीय शक्तियाँ (Productive forces) और उत्पात्कीय सम्बन्ध (Productive relations) का इतिहास होगा। उत्पादन के साधनों का निरन्तर विकास होता रहता है और इस कारण वे अलग परिस्तरनशील रहते हैं। इससे परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन यापन की पद्धति में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। फल मार्क्स के शास्त्र में सामाजिक संघर्षों का उत्पात्कीय शक्तियों के प्रतिपादन होता है। नई उत्पात्कीय शक्तियों को पालाने पर मनुष्य अपने उत्पादन

^१ It is popular meaning dialectic is the study of the contradiction within the very essence of the things. Development is the struggle of opposites —Lenin as quoted by J. Stalin in his *Essay on Historical and Dialectical Materialism* p. 14

का पदवी को बदल देते हैं और अपनी उत्पात्ता पद्धति को बदलने पर, अर्थात् अपने आर्थिकोपाजन के शस्त्रों को बदलने पर, वे अपने सार सामाजिक सम्बन्धों का प्रभाव देते हैं। माप की मित ने तुम्हें पेंचीमानिया जाले समान का दिया।^१ समान की विधियों (laws) और मर्यादाओं में हम सामाजिक-सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब देखने को मिलता है। इस कारण उत्पात्काय शक्ति का ही निहाय का गति को निर्धारित करता है।

ऊपर हमने देखा कि उत्पात्काय शक्ति का प्रभाव पर उत्पात्काय व्यवस्था का निर्माण होता है। आरम्भिक काल से लेकर वर्तमान काल तक के समाज का विवर्चन कर मार्क्स ने इस प्रकार के पांच सम्बन्धों का उल्लेख किया है। ये सम्बन्ध हैं—

आरम्भिक समाज दासता का युग, सामन्तशाही, पचीमाणी तथा प्रारंभिक समाजवादी व्यवस्था।

आरम्भिक समाज में मनुष्य में सम्पत्ति का भावना प्रधान थी। उस समय उत्पात्कीय शक्तियाँ (उत्पात्ता के शक्तियाँ) पर अनिश्चित अधिकार नहीं होता था और और इस कारण समाज में यह सङ्घर्ष नहीं था। उस समय न शोषण था और न शक्ति। परन्तु कुछ मरगल समाज के कुछ व्यक्तियों ने उत्पात्काय शक्ति पर अधिकार कर लिया। आरम्भिक समाज में 'मनुष्य के पतन' (Fall of man) का नैसर्गिक उल्लेख मिलता है यह कुछ बंसा ही घटना है। उत्पात्काय के अंगों पर कुछ शक्तियों का प्रभुत्व ही माने का यह परिणाम हुआ कि समाज में व्याप्त यह विचार प्रचलित हो गया। यह सङ्घर्ष का आरम्भ इस से होता है। स्वयं यह मार्क्सवादी युग प्रारंभ है जिसमें उत्पात्कीय शक्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व और भागिदारी का प्रभाव है। सामन्तशाही युग के प्रारंभिक युग प्रारंभ। यह युग में पेंचीमानिया के साम्राज्य के स्थायी हैं और वैयक्तिक शक्ति का रूप में स्वतन्त्र हो गए भागिदारी के हाथ अपना नाम बचाने तथा शोषण के कारण का प्रभाव करने के लिए विवर्धित हैं। पेंचीमानिया के आर्थिक विचारों के अनुसार उस स्वयं प्रभाव का प्रभाव ले जा रहे हैं जिसके माध्यम समाजवादी व्यवस्था का युग आणगा। काल मार्क्स

और एंगिल्स ने लिखा है कि 'तब तक व सभी सम्राज्ञा का इतिहास मग सहूनों का इतिहास है। उनका निश्चित मत है कि वर्तमान पूँजीवादी स्वयं अपने विनाश के साधन एकत्र कर रहा है। पूँजीवाद का पतन और श्वहारा मग की विजय होना अवश्यभावी है।

मार्क्स के इन्द्रामक मौलिकवाद को मान लेने से जो उनसिद्धियाँ (corollaries) हमारे सामने आती हैं, उन पर स्टालिन ने अपने एक निबंध में प्रकाश डाला है। उनमें से मुख्य उनसिद्धियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) इतिहास कुछ राजनीतिक घटनाओं की कहानी नहीं है। उसकी गात कुछ निश्चित विधियों द्वारा स्थिर होता है और ये विधियाँ उतनी ही दृढ़ हैं जितनी वैज्ञानिक विधियाँ।

(२) क्योंकि इतिहास एक विज्ञान है और उसकी निश्चिता निश्चिता हैं, तथा उन विधियों का अध्ययन कर उन्हें समझा जा सकता है, इसलिए इतिहास की भावी गति के सम्बन्ध में भा भविष्यवाणियों की जा सकता है।

(३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त—पूँजीवाद के विकास उसका वर्तमानस्था और उसके पतन पर मार्क्स ने इन्द्रामक मौलिकवाद और उसके द्वारा की गई इतिहास की व्याख्या द्वारा प्रकाश डाला है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त वह सिद्धान्त है जिसके द्वारा मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था के आधार पर प्रकाश डाला है।

मार्क्स के मतानुसार किसी वस्तु का मूल्य इस तथ्य द्वारा निर्धारित होता है कि उसके बनाने में सामाजिक आवश्यकता का पूर्ति की दृष्टि से कितना समय (Socially necessary labour time) लगता है। परन्तु प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में माननीय मजदूरी अतिरिक्त कुछ उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। उन उपकरणों के साधनों पर जिस काम का अधिकार है वह पूँजीपति

‘The history of all hitherto existing society is the history of class struggle —K. Marx & F. Engels *Manifesto of the Communist Party* p 45 (According to Engels ‘history of all hitherto existing society is the history of class struggle’)

है। उत्पादन के साधनों का स्वाम्य होने के कारण पूँजीमति शक्तिशाली होता है, और श्रमिक वर्ग उनका श्रमदान के कारण दान और असहाय। श्रमिक वर्ग के पास केवल एक वस्तु होती है जिसका विनिमय कर वह जीविकोपार्जन करत है। यह वस्तु है श्रम। बाज़ार में उनका श्रम हा प्रत्येक वस्तु का उपयोगिता वर्ग कर उसका मूल्य में वृद्धि करता है। परन्तु पूँजीमति उन्हें उनका श्रम का परा मूल्य नहीं देते। वे उन्हें केवल उनका हा मजदूर देते हैं जिनमें से वे जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का पूर्ति कर सक। यह श्रमिक का असहायता-स्थिति के कारण सम्भव होता है क्योंकि जीवित रहने के लिए श्रमिकों को इतना कम मजदूर पर माँ कान करना पड़ता है। माक्स के मतानुसार उत्पादित वस्तु के विनिमय मूल्य (Exchange Value) और श्रमिक का लिये गये पारिश्रमिक का अन्तर हा अतिरिक्त मूल्य है जो पूँजीमति स्वयं हथक कर जाता है। पूँजीमति द्वारा इस अतिरिक्त मूल्य का उस प्रकार हथक कर जाना श्रमिक वर्ग का शोषण है। परन्तु प्रत्येक पूँजीमति इस प्रकार का शोषण करने के लिए बाध्य है। यदि वह ऐसा न करता वह अन्य पूँजीमति से प्रतिस्पर्धा में कर सकगा और उस प्रकार स्वयं अपना नाश करगा। पूँजीमति का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकता का पूर्ति करना नहा बल्कि स्वयं अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। इस कारण वह ऐसे पन्थों का उपयोग करता है जिनमें उस अधिनाशिक लाभ हा। इसी कारण है कि पूँजीमति सामाजिक आवश्यकता का वस्तुओं का उत्पादन न कर शोषण का उत्पादन करत हैं, जिसे ऐसा करने से उन्हें अधिक लाभ होता है।

माक्स के राज्य तथा क्रांति सम्बन्धी विचार

राज्य—माक्स के पूरा समा प्रमुख राजनैतिक विचारक यह मानत आते थे कि राज्य नागरिकों के हित के लिये बना और इस कारण उसे बने रहना चाहिये। परन्तु माक्स ने इस सम्मान्य सिद्धांत का मा सिप्पा और भ्रातृव्य स्मरण कर लिया। हम इसके पूर्व उल्लेख कर चुके हैं कि माक्स के मतानुसार उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होने पर सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। राज्य और व्यक्ति के सम्बन्ध में इस निम्न के अन्तर्गत नहीं हैं।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऐंटी डूबिंग (Anti Duhring) में एंगिल्स ने लिखा है कि राय स्वाभाविक सस्था नहीं है। इसका प्रादुर्भाव तभी होता है जब समाज परस्पर विरोधी तत्वों में विभक्त होता है जिन्हें दूर करने की उसमें शक्ति नहीं होती। उस प्रकार राय वर्ग संघर्ष द्वारा उत्पन्न होता है। जब समाज से वर्ग संघर्ष का अन्त हो जायगा तो राय भी नाश हो जायेगा। एंगिल्स के मतानुसार राय सदैव "दमन का साधन" होता है जिसका प्रयोग समाज का शक्तिशाली वर्ग शक्तिहीन वर्ग के विरुद्ध करता है। कम्यूनिस्ट मनिफेस्टो में मार्क्स और एंगिल्स ने राय को 'बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणा समिति' (Executive Committee of the Bourgeoisie) की सलाह दी है।

समहारा वर्ग की क्रांति—मार्क्स के अनुसार किसी ऐसे समाज में जो विरोधी वर्गों में विभक्त है प्रजातन्त्र की स्थापना होना असंभव है। वर्तमान पूँजीवादी देशों में जिस व्यवस्था को प्रजातन्त्र कहा जाता है वह मार्क्स के मतानुसार प्रजातन्त्र नहीं है। जैसा ऊपर कहा गया है, राय सदैव शक्तिशाली वर्ग के हाथ में दमन का साधन होता है। इसलिये पूँजीवादी व्यवस्था वाले देशों में पूँजीपतियों के हाथ में ही राय का वास्तविक शक्ति रहती है। परन्तु उस तथाकथित प्रजातन्त्र में समहारा वर्ग (Proletariat) को कुछ सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनका उपयोग वह अपने को संगठित कर अपना शक्ति वृद्धि करने में और अन्तिम संघर्ष में विजय प्राप्त करने की तैयारी करने के लिये कर सकता है। पूँजीपतियों से यह आशा करना मूर्खता है कि वे कभी स्वच्छा से अपनी स्थिति में परिवर्तन स्वीकार कर लेंगे। इसलिये मार्क्सवाद्या का यह निश्चित मत है कि शक्ति के प्रयोग में ही वर्तमान व्यवस्था का अन्त कर समाजवाद की स्थापना का जा सकता है। मार्क्स और एंगिल्स ने लिखा है—“साम्यवादी अपने विचारों और उद्देश्यों का छिपाने से घृणा करते हैं। वे खुले रूप में घोषणा करते हैं कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को शक्तिपूर्वक नाश करने से ही होगी।

“The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social

माक्सवाद्, मार्शेविक क्रान्ति तथा सावियत शासन-व्यवस्था का विकास ५

पेंजीवादी व्यवस्था स्वयं ही क्रान्ति का माग प्रशस्त करती है। इस व्यवस्था का परिणाम यह होता है कि सारी सम्पत्ति सिर्फ़ कर कुछ व्यक्ति-वाँ हाथ में आ जाता है और इस कारण अधिकांश लोग निबन हो जात हैं। माक्स वं अनुसार सनहारा वग क प्रत्येक ट्रान्ज़िशन का बुरी तरह दमन किया जाएगा जिससे उसका सदस्यां में एकता स्थापित होगी। बड़े-बड़े कारखानों में हज़ारों अधिक एक साथ कार्य करने हों और इस प्रकार पेंजीवाद् ने स्वयं उई अपना सग्न करने की सुविधा प्रदान कर दी है। यही अधिक एक दिन पेंजीवाद् की कबर खान्दन वाले सिद्ध होगी। पर वह यह समझ नाथगी कि पेंजीवादी व्यवस्था में उनका दशा कभी नहीं सुधर सकना तो वे सशस्त्र क्रान्ति करेंगे। इस क्रान्ति का परिणामस्वरूप पेंजीवाद तथा उसका साथ ही शोषण की समाप्ति होगी।

सनहारा वग का अधिनायकत्व—क्रान्ति के पश्चात् समाज और शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा इस पर भी मार्क्स ने अपने ग्रंथों में प्रकाश डाला है। क्रान्ति के पश्चात् के काल का दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—सक्रांति काल और सामान्य काल। सक्रांति काल में समाज और शासन व्यवस्था का स्वरूप सनहारा वग का अधिनायकत्व होगा। इस अधिनायकत्व का होना इस लिये आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धावादी और क्रान्ति विरोधी शक्तियाँ पुनः अपना सर उठाने का प्रयत्न करेंगी। उनके ऐसे सभी प्रत्यर्था का पूरी तरह निष्काश कर पेंजीवाद् के समस्त तत्त्वों का उन्मूलन करना होगा। उत्पत्ति के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होगा। राज्य सधय की समाप्ति हो जाने के कारण शासनवादी वग और शासितवर्ग के हितों में कोई विराध शेष न रह जाएगा और इसी कारण इस व्यवस्था का सनहारा वग के जो कि ऐसे समाज का एक मात्र वग होगा, अधिनायकत्व का सञ्चालन दी गई है। इस समाज का यह सिद्धांत होगा कि 'जो कार्य नहीं करता वह खाना भी न पावे। बचल बृद्ध, बालक और अगहीन या अरवस्थायी व्यक्ति ही बिना काम किये भोजन पाने के अधिकारी होंगे। इस समाज और पेंजीवादी समाज में एक महत्वपूर्ण अंतर यह होगा कि इसमें वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया

जाएगा, मुनाफा कमाने के लिये नहीं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन (Over production) की समस्या, जो कि पूँजीवादी व्यवस्था का एक आवश्यक परिणाम तथा लक्षण है, उत्पन्न ही न होगा।

राज्य को माक्सवादी सैन्य ही शासकीय ढंग का अभिनायकत्व मानते रहे हैं। पूँजीवादी अर्थसंस्था साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होने तक राज्य का यही स्वरूप विद्यमान रहेगा। एंगिल्स के शब्दों में “जब तक सचहारा को राज्य की आवश्यकता है उसे उसकी आवश्यकता स्वतन्त्रता का हस्त में नहीं है, वरन् अपने विरोधियों का कुचलने के लिये है। जब स्वतन्त्रता की बात करना सम्भव हो जायगा तब राज्य समाप्त हो जाएगा। जब तक शोषण की पूर्ण समाप्ति नहीं हो जाती और सचहारा बग के सभी विरोधी समाप्त नहीं हो जाते तब तक स्वतन्त्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्गहीन समाज की स्थापना तथा राज्य की समाप्ति—सक्रांति काल का अतः उस समय होगा जब नूना वर्ग और पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तिम अवशेष भी मिट जाएंगे और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव शेष न रहेगा। वर्गहीन समाज में व्यक्तिगत साहचर्य की भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण राज्य के नियंत्रण की कोई आवश्यकता शेष न रहेगी। ऐसी व्यवस्था में राज्य स्वतः लुप्त हो जाएगा। माक्स ने साम्यवादी समाज का जो विचार अंकित किया है उसमें उसकी भाषा बहुत कुछ स्वप्नचोकीय विचारकों (Utopian thinkers) जैसी हो गई है। माक्स के अनुसार उस समाज का आधार यह सिद्धान्त होगा प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक का उसकी आवश्यकता के अनुसार^१ अर्थात्, प्रत्येक याक अपना योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा।

सक्रांति काल के अन्त होने और उत्प्रेरणात्मक राज्य के लुप्त होने में कितना समय लगेगा इस सम्बन्ध में न तो माक्स ने ही कोई निश्चित उत्तर दिया है और न उसके अनुयायियों ने। आधुनिक सोवियत प्रवक्ता इस सम्बन्ध में यही

^१“From each according to his ability to each accords to his needs —K. Marx in his Critique of the Gotha Programme

कहते हैं कि जब तक संसार के सभी देशों में समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक शांति छुट नहीं सकती। इसका कारण यह बातलाने है कि पूँजीवादी राज्य सदैव समाजवादी राज्य का नष्ट कर रहा पुन पूँजीवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस कारण समाजवादी राज्य को भी आत्मरक्षा के लिये शक्ति साधना करना आवश्यक है।

एक प्रश्न शेष रह जाता है जिसका मार्क्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह कि बग़हान या साम्यवाद समाज के जहाँ ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुसार कौन सा अवस्था आता। मार्क्स ने कहा कि समाजवादी समाज समाजवादी युग के समाजों में ही होगा, क्योंकि उसमें बग़ सदैव नैतिकता के निहित अन्तर्भाव नहीं होता।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन

प्रथम इंटरनेशनल—मार्क्स ने कहा कि एक देश में शांति तक काय रूप देने का सफल प्रयास सबसे प्रथम स्तर में किया गया परन्तु उसमें पुन भी कुछ असफल प्रयत्न किए गए थे। सन् १८४५ में मार्क्स और एंगेल्स के प्रयत्नों से लन्दन में 'नमन' एक संयुक्त एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना हुआ। ऐसा ही संस्थाओं का स्थापना पेरिस और ब्रुसेल्स में भी की गई। सन् १८४७ में लन्दन में इनका एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। यहां इंटरनेशनल कम्युनिस्ट लीग का स्थापना की गई। कुछ ही माह पश्चात् 'नमन' और फ्रांस में उस संस्था का अवैध घोषित कर दिया गया। इस पश्चात् सन् १८४५ में स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में प्रथम इंटरनेशनल (First International) का स्थापना हुआ। इस संस्था में पारस्परिक मतभेद बहुत अधिक थे।

सन् १८७१ में फ्रांस और प्रुशिया (Prussia) के युद्ध के समय पेरिस में क्रान्ति का प्रयत्न किया गया। इस प्रयत्न में प्रारम्भ में कुछ सफलता मिली और पेरिस कम्यून का स्थापना हुई, परन्तु शीघ्र ही इस आन्दोलन को कुचल दिया गया। इस प्रथम इंटरनेशनल में मार्क्सवादी और अराजकतावादी में विरोध इतना अधिक बढ़ गया कि सन् १८७२ में अराजकतावादी को इससे निकाल दिया गया। सन् १८७६ में प्रथम इंटरनेशनल का अन्तिम बैठक हुई।

द्वितीय इंटरनेशनल—सन् १८८६ में एगिन्स क नेतृत्व में पेरिस में प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना हुई। परन्तु उसमें मात्र आन्तरिक मतभेद उत्पन्न हो गये। जिस समय प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय इंटरनेशनल ने महायुद्ध का समर्थन नहीं किया। अतः प्रारंभिक मतभेदों से युद्ध कार्यों में भाग न लेने की अपाव की गई। परन्तु देश प्रेम का भावना अन्तर्राष्ट्रीयता का भावना न प्रबलित होकर सिद्ध हुई। और सभी देशों ने सन्तानसंगी नहीं और न कि नृजाओं ने अपनी सरकारों का साथ दिया। नरल सेनित और उसके बाल्शविक अनुयायियों ने महायुद्ध का विरोध करने लगे। इस प्रकार द्वितीय इंटरनेशनल स्वयं ही भंग हो गई।

इस पूर्व रूस में लेनिन ने अधिक प्रयत्न के पक्षस्वरूप मार्क्सवादी बाल्शविक दल के रूप में संगठित हो चुके थे। पहले ये रूसी समाजवादी जनताधिकारिक दल के एक गुट के रूप में कार्य करते थे, परन्तु सन् १९१२ में उन्होंने अपना संगठन बना लिया। इस वर्ष प्रागा (Prague) में आंतर-दलिक समिति (Inter-dal Communist Central Committee) की स्थापना हुई और प्रागा (Prague) नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। बाल्शविकों ने सुवर्ण के रूप में इस पत्र ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके प्रारंभिक संपादकों में जॉसफ स्टालिन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है।

मार्च १९१७ की क्रांति तथा जारशाह का अन्त—पिछले अन्तर में हम प्रथम विश्व युद्ध के रूस का राजनैतिक स्थिति पर प्रभाव का उल्लेख कर चुके हैं। सन् १९१७ के प्रारंभिक महीनों तक यह निश्चित हो चुका था कि जारशाह का पतन अवश्य-भावी है। परन्तु जारशाही का लक्ष्य प्राप्त करना शीघ्र यथायक गिर जायगा यह किसी का आशा नहीं थी। सन् १९१७ की मार्च में विद्रोह का प्रारंभ पेत्रोग्राद (Petrograd) की सड़क पर हुआ। इससे पूर्व राजा की कमी के कारण पेत्रोग्राद का जनता को मिलने वाले राजस्व में और कमी हो गई थी जिससे कारण जनता में भावना प्रसृत हो गया था। जारशाह ने सत्ता का भाति दमन का आश्रय लिया।

हत्याया अभिकों का दमन करने के लिये उनका बुलाया गया, परन्तु सैनिका ने विद्रोह कर दिया। उसके पुत्र छपूना ने, जिसके अधिकांश सम्पत्ति वारशाही के समर्थक थे, चार की आगामी सरकार का सूचना दी था परन्तु उसका चेतावनी का उल्टा ही परिणाम हुआ। चार ने छपूना का भग करने का धमका कर दिया। सैनिका के विद्रोह के कारण हत्यालिया के अन्तिम ने चार पकड़ लिया और शान्त हो यह दूसरे नगर में भाग गया। दूसरे नगर में भी सैनिका ने विद्रोह जनता का साथ दिया, जिसके परिणामस्वरूप बिना अधिक रक्तपात के ही वारशाही का अन्त हो गया। १२ मार्च (वर्तमान रूसी सन के अनुसार २७ फरवरी) को छपूना ने एक अध्यायी समिति नियुक्त की। कुछ ही दिनों में इस में एक नवान सरकार की स्थापना हो गई जिसका प्रधान प्रिंस ल्योव (Prince Lvov) था। इसी सरकार के प्रतिनिधाय सेना के प्रधान कारालय पर गए। चार निकोल्स द्वितीय ने राज सिंहासन त्याग कर अपने भ्राता ग्रेगोरि माइकल का प्रथम उत्तराधिकार ग्रहण किया। परन्तु जनता वारशाही के इतना ऊपर चुका था कि वह अब किसी चार का अपना शासक स्वीकार करने का प्रसन्न नहीं था। इस कारण यह निश्चय किया गया कि इस की शासन प्रणाली का निष्पन्न करने का काम जनता द्वारा निर्वाचित सावियत जनता का सौदा चार। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस समय लेनिन विदेश में था और स्टांलिन साइबेरिया में निवासित था। प्रथम सरकार पर उत्तर (Liberal) नेताओं और अनुयायियों का प्रभुत्व था न कि बाल्शेविकों का।

अस्थायी-सरकार ने देश का मुद्रा सम्पत्ति नाति में कोई परिवर्तन नहीं किया, ना कि जनता की कठिनाइयाँ का मुख्य कारण थी। यद्यपि वारशाही का अन्त हो चुका था, परन्तु हम पर कौन शासन करेगा इस प्रश्न का निश्चय होना अभी शेष था।

अस्थायी सरकार तथा पेत्रोग्राद सावियत में संघर्ष—क्यान्ति के प्रारम्भिक दिनों में ही पेत्रोग्राद सैनिक तथा जनिक प्रतिनिधि सोवियत (Petrograd Soviet of Soldiers & Workmen's Deputies) की स्थापना हो गई थी। इसका प्रधान सभ्यजिक जनताजिक ग्ल का एक सदस्य तथा जन प्रधान भन दल (Labour Group) का नेता करन्सकी था। इस सोवियत को

सावियत सघ का शासन

अमिका और सैनिका दाना का विश्वास जात था, और इस कारण वह अस्थायी सरकार से अपनी मांगें मनवाने में सफल हो जाता था। इस समय रूस पर एक प्रहार का द्वैर शासन था। सावियत तथा अस्थायी सरकार दोनों ही आजातियां निपालते थे और कभी कभी तो इन दाना का आजातियां एक दूसरे की विरोधी होती थीं। यद्यपि प्रारम्भ में सावियत में बाल्शेविका का बहुमत न था, परन्तु इसकी नीति सदैव अस्थायी सरकार की नीति से अधिक उग्र रही। यही कारण था कि मात्र से अस्तूर तक के काल में सावियत और अस्थायी सरकार में सत्ता हस्तगत करने के लिए निरन्तर सङ्घर्ष चलता रहा। अस्थायी सरकार का दुर्बलता का ज्ञान हमें इसी तथ्य से हा जाता है कि अपने आठ मास के सक्षिप्त जीवन काल में इसकी रचना में छ बार महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जुलाई में अस्थायी सरकार के प्रधान पद का कार भार करेन्सकी के हाथ में आ गया जो 'सज (प्र) पैराग्राफ सोवियत का उपायक्ष तथा अस्थायी सरकार में न्याय मंत्री था।

अप्रैल १९१७ में लेनिन स्टिट्जरलैण्ड में रूस पहुँच गया। विश्वास किया जाता है कि उसकी इस यात्रा का प्रबंध जर्मनी का सरकार द्वारा किया गया था। उसने रूस में आते ही युद्ध का अन्त करने और राजसत्ता सोवियतों को दिए जाने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। बाल्शेविक दल के प्रमुख पत्र 'प्रोब्लेम' का प्रकाशन पुन प्रारम्भ हुआ। लेनिन रूस में सदस्य प्रजातन्त्र स्थापित किए जाने का प्रयत्न विरोधी था और मार्क्स के सिद्धान्त के आधार पर रूस में सोवियत समाजवादी राज स्थापित करना चाहता था। प्रारम्भ में उसे अपने ही दल के सन्स्था का सामना करना पड़ा। उसकी तत्कालीन नीति का विरोध करने वालों में स्यालिन का नाम उल्लेखनीय है। परन्तु धीरे धीरे उसे समर्थन प्राप्त होने लगा। जुलाई में बाल्शेविका ने विद्रोह का सन्हा हस्तगत करने का असफल प्रयास किया। उनका विद्रोह दबा दिया गया और उनके नेताओं का भूमिगत हो जाना पड़ा। लेनिन फ़िनलैंड चला गया। परन्तु जारशाहों का अन्त होने पर जिस सुरक्षित स्वप्न के कार्यान्वित होने का कल्पना रूस की जनता ने की था वह अभी भी स्वप्न मात्र ही था। करेन्सकी की सरकार ने तो देश की आर्थिक समस्या में कोई आमूल परिवर्तन करने को हा प्रस्तुत थी और न मित्र

राष्ट्रा का साथ छोड़कर जर्मनी से पृथक् संधि करने को। रूस के कृषक जमींदारी का अंत और भूमि का अपने बीच पुनर्वितरण चाहते थे। बाल्शेविक उह 'रेडी, भूमि और शांति' देने का वादा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अस्थायी सरकार ने देश की भारी शासन प्रणाली का निगमन करने के लिए सविमान सभा बनाने की घोषणा की। ऐसी घोषणाओं से जनता सतुष्ट नहीं हो सकती थी। परिणाम हुआ नवम्बर क्रान्ति तथा बाल्शेविक शासन की स्थापना।

बाल्शेविक क्रान्ति—माच की क्रान्ति के पश्चात् वाक् स्वातंत्र्य समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, संधि बनाने तथा सभा बनाने की स्वतंत्रता आदि जो सुविधाएँ रूस में नागरिकों को उपलब्ध हो गई थी, नारेशविका ने उनका परा उपयोग किया। उन्होंने सोवियतता में अपना प्रतिनिधित्व बनाने का धार प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें रूस के दो प्रमुख नगरों की सोवियतता प्रोत्साहित करने तथा मास्को सोवियत में, बहुमत प्राप्त हो गया। उन्होंने प्रथम दल के समस्या को बड़ी सरलता से लेना में भी भरती किया। उनके द्वारा जनता की आकांक्षाएँ प्रतिबिम्बित होती थी, इस कारण जनता भी उनकी ओर आकर्षित हुई। ७ नवम्बर, १९१७ का सोवियत की अग्निलक्ष्मी का प्रसंग हुआ। रूस कांग्रेस में बाल्शेविकों का बहुमत प्राप्त था। इससे पूर्व ही कृषक ने भूमि के पुनर्वितरण के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। बाल्शेविक दल ने नेताओं ने समझा कि यही समय है जब वे अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं। लेनिन और उसके सहकारी त्रांसकी (Trotsky) ने ७ नवम्बर को विद्रोह प्रारम्भ करने का कार्यक्रम बना रखा था। उन दिनों बाल्शेविक सेनाओं ने समस्त राजकीय भवन और महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। जनता ने उन्हें मुक्तिदूत समझ कर उनका साथ दिया। क्रोसकी के अतिरिक्त उसकी सरकार ने सभी सम्पत्ति जन्दी बना लिए गए। क्रोसकी बच कर भाग निकलने में सफल हो गया। जिस प्रकार माच में जारशाही का अंत करने के लिए अधिक रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उसी प्रकार अस्थायी सरकार का भी बिना अधिक संघर्ष के अंत हो गया। अब मास्को, पेरोग्राद तथा कुछ अन्य बड़े नगरों में ही युद्ध हुआ।

क्रोसकी की सरकार के पतन के पश्चात् रूस में एक नए शासन की

स्थापना की गई। इस सरकार को 'जन कमिस्सार परिषद्' (Council of People's Commissars) का नाम दी गई। इस सरकार का श्रमजीव लेनिन ने, पर राष्ट्र मंत्रिषद् नासकी ने और उपराष्ट्र मंत्रिषद् स्तालिन ने ग्रहण किया। सोवियतों का काग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर रूस का नवीन नाम रूसी समाजवादी संघात सोवियत गणराज्य (Russian Socialist Federated Soviet Republic) घोषित किया।

सोवियत शासन व्यवस्था का विकास

सांविधानिक विकास का प्रारम्भ

नवम्बर की बाल्शेविक क्रांति के परिणामस्वरूप राजसत्ता सोवियतों के हाथ में आ गई। बाल्शेविकों में शासन व्यवस्था के भागी स्वरूप के सम्बन्ध में इन समय तक कोई निश्चित विचार न था। कुछ बाल्शेविक विश्व के सभी देशों में क्रांति होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ अन्य बाल्शेविकों का यह विचार था कि शासन का वर्तमान स्वरूप प्रस्थायी है, तथा शान्ति के व्यवस्था स्थापित हो जाने पर देश की भागी शासन व्यवस्था का निश्चय जनता के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन के द्वारा किया जायेगा।^१ निदेशों में भी तरह-तरह के विचार पनप रहे थे। कुछ लोगों का विचार था कि रूस में साम्यवादी शासन स्थापित होने से अन्य देशों में भी साम्यवाद का प्रसार होगा, जबकि कुछ लोगों का मत था कि सोवियत शासन का शीघ्र ही अन्त हो जायेगा।

सोवियत सरकार के प्रारम्भिक कार्य—शासनात्मक होने के पश्चात् बाल्शेविकों ने समस्त भूमि के समाजीकरण की घोषणा कर दी। सभी गेहूँ के जमीनदारों की भूमि तथा उनका पशुश्रा और यंत्रों आदि पर राज ने अधिकार कर लिया। भूमिहीन कृषकों में भूमि वितरित करने के लिए भी घोषणा में व्यवस्था की गई थी। इन परिणामस्वरूप कृषकों की बहुत बड़ी संख्या सोवियत बाल्शेविकों के पक्ष में आ गई। जन कमिस्सार परिषद् ने एक सप्ताह के भीतर ही समस्त बेहरी और उद्योग व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। सोवियत सरकार ने युद्ध उद्द करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। सरकार ने

^१ Munro & Aycarst *Governments of Europe* p 649

रूसी सेना व प्रधान सनापति को युद्ध रन्द करने की आज्ञा दी, परन्तु उसने उसे मानने से इनकार कर दिया। तब लेनिन ने सैनिकों को अपने अधिकारिया व विरुद्ध विद्रोह कर उन्हें न्याय देने तथा युद्ध बन्द करने की अपील की। यह एक साहसिक कृत्य था, परन्तु लेनिन का विश्वास सत्य सिद्ध हुई। सैनिक युद्ध नहीं करना चाहते थे। रूसी जनता का तरह व भी शांति चाहते थे। नासरी व नेतृत्व में सोवियत सरकार व प्रतिनिधि जर्मन प्रतिनिधियों से सन्धि माना के लिए ब्रेस्त लिटोव्स्क (Brest Litovsk) नामक स्थान पर मिले। जर्मनी का सन्धि की शर्तें इतनी कड़ी थी कि बाल्शेविक नेता उन्हें स्वीकार करने का तैयार न थे। परन्तु लेनिन ने उन्हें स्वीकार करने पर राज किया। उसने अपने एक वक्तव्य में कहा— सन्धि जर्मनी को शानत हा। एक बाल्शेविक सरकार हटा दी जाय तथा हम युद्ध के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, अन्यथा नहीं। बाल्शेविक कन्द्रीय समिति ने उसकी सम्मति मान ली और सोवियत सरकार और जर्मनी व प्रतिनिधियों ने ब्रेस्त लिटोव्स्क में सन्धि पर पर हस्ताक्षर कर दिए।

नासरी व पतन व राज्य व्यवस्था सरकार न देश का भारी शासन व्यवस्था का निर्णय करने व लिए सन्धिमान सभा का आयोजन किया था। नवम्बर, १९१७ में इस सभा का निवाचन भी हुआ। ५, जनवरी, १९१८ को इस सविधान सभा का प्रथम बैठक हुई। इस सभा में बाल्शेविक अल्पमत में थे। सविधान सभा ने सोवियत शासन को वैधानिक मानना ही स्वीकार न किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस सभा की दूसरी बैठक हा न हो सकी। ६ जनवरी को सविधान सभा का नवम बाल्शेविक सैनिकों के अधिकार में था।

गृह युद्ध तथा वदेशिक हस्तक्षेप—मई १९१८ में रूस में बाल्शेविक व विरोधियों ने सोवियत शासन व विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सोवियत शासन के विरोधियों ने मित्र राष्ट्र (Allied Powers) की सहायता से श्वेत सेना (White Army) संगठित की। बाल्शेविकों ने भी राखवा व कुशल नेतृत्व में लाल सेना का संगठन किया। इन श्वेत और लाल सेनाओं में भीरण सन्धि हुआ। प्रिटोन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान ने जर्मनी व विरुद्ध युद्ध से निवृत्त होने पर सोवियत सेनाओं व लड़ने के लिए अपनी सहायता भरी।

मित्र राष्ट्रों ने चारों ओर से रूस की नाकेबन्दी की जिससे किसी अन्य देश से सोवियत शासन को सहायता या गृहायता न मिल सके। "सी समय पोलैंड की सेनाओं ने भी रूस पर आक्रमण कर मिया और कीव नगर पर अधिकार कर लिया। सोवियत शासन के लिए यह समय उड़ी कठिनाई का था। यह युद्ध प्रारम्भ होने तथा विदेशी सेनाओं ने रूस की भूमि पर पदार्पण करने का यह प्रमाण होने लगा था कि रूस के नगरों का जनता भूयः समर नायेगी। कृपका के पास जो सहायता थी वह उसने नही चाहत थी और किसी अन्य देश से किसी प्रकार का सहायता पाना समय नहीं था। ऐसी एकदम परिस्थिति में लेनिन ने एकात्मक सहायता उठाने वाला एक विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने का घोषणा की। सरकार ने यह आह्वान जारी कर दी कि व्यक्तिगत उपयोग से अधिक समस्त सहायता अनिवार्य रूप में निश्चित देश पर सरकार का देना होगा। सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप कृपका भी सोवियत शासन के विरोधी हो गए। बालशेविक नेताओं पर स्थान स्थान पर आक्रमण किए गये। अगस्त १९१८ में जन लेनिन एक जन सभा में भाषण दे रहे थे, उस पर एक स्त्री ने गोला चला दी। लेनिन घायन हुआ परन्तु वह सोवियत शासन की जल्द ही करने के लिए जीवित बच गया।

उन सब कठिनायियों और असुविधाओं के बावजूद भी सोवियत शासन अपने विरोधियों का दमन करने और विदेशों से सहायता को रूस की सीमा से बाहर जाने के लिए निवश करने में सफल हो सका। इसके अनेकों कारण थे। यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने रूस में अपनी सेनाएँ भर्नी, परन्तु वे एक युद्ध से निवृत्त होने ही दूसरे युद्ध में पूर्णतः कूटने की प्रस्तुत न थी। अतः मित्र राष्ट्रों में पारस्परिक द्वेष अतना अधिक था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते थे। उनमें से कोई दूसरे की शक्ति और प्रभाव बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। महायुद्ध ने उनकी अर्थ व्यवस्था को उस्त कर दिया था। एक अन्य कारण यह भी था कि सभी देशों के अधिक सोवियत शासन की ओर सहानुभूति रखत थे। इन कारणों से विदेशी सरकारें सोवियत शासन का अन्त करने के लिए युद्ध करने को प्रस्तुत न थीं। इधर सोवियत सरकार ने सभी क्रांति विरोधी वर्गों का पूरा तथा दमन किया और नाल सना विजय पर विजय प्राप्त करती रही। रूस

१९२२ के नवम्बर मास तक यह युद्ध का अंत हो चुका था और वैश्विक सेनाएँ रूस से वापस बुला ली गई थीं। परन्तु यह आवश्यक हो गया था कि नए प्रायः उद्योग धंधा, कृषि और यातायात के साधनों का पुनर्निर्माण के लिए एक नई नीति का अनुसरण किया जाय। लेनिन की नवीन आर्थिक-नीति इसी आवश्यकता का परिणाम थी।

नवीन आर्थिक नीति (N E P)—मार्च १९२१ में लेनिन ने पार्टी की ११^{वें} कांग्रेस के सम्मुख नवीन आर्थिक नीति उपस्था की। इस नीति में युद्धकालीन साम्यवाद (War Communism) का त्याग किया गया था और कृषकों को अपनी उपज का आधेका भाग खुले बाजार में बचने का अधिकार दिया गया। एक निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत संपत्ति रखने और उस उत्पादन कार्यों में प्रयोग करने की पुनः छूट दी गई। सोवियत शासन के प्रारम्भिक काल में धन का माध्यम को समाप्त करने के जो प्रयत्न किए गए थे उन्हें स्थगित कर दिया गया और करों का हटाने के प्रयास किए गये। सन् १९२१ में इस नवीन नीति का उद्देश्य कृषकों और बनवा के ग्रामों का सङ्गठन कर उत्पादन बढ़ाने में उनका सहयोग प्राप्त करना था। ग्राम देशों में इस नीति का सोवियत शासन तथा साम्यवाद का असफलता का द्योतक माना गया और इसे 'पँजावाद' की ओर वापसी का चिह्न माना गया। यद्यपि यह नीति सोवियत शासन और जनता की समस्त कठिनाइयों का अंत न कर सकी, जैसा यह कर भी नहीं सकती थी परन्तु इसने आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार किया। उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई।

पंचवर्षीय योजनाएँ तथा कृषि का सामूहिककरण—सन् १९२४ के जनवरी मास में लेनिन का मृत्यु हो गई। उसके दो प्रमुख सहकारी थे—त्रात्स्का और स्तालिन। सोवियत शासन की नीति का सम्बन्ध में इन दोनों में तीव्र मतभेद थे। त्रात्स्का विश्व के अन्य देशों में आतङ्कगी आन्दोलनों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी सहायता करने के पक्ष में था। स्तालिन 'एक देश में समाजवाद' की स्थापना करने के पक्ष में था। स्तालिन पार्टी का प्रधान मन्त्र था

और इस कारण अपने दल व संस्था में उसका पचास प्रभाव था। वह क्रान्ती गुप्त का न केवल सरकार और पाठ में, बल्कि देश में ही निष्कासित करने में सफल हुआ।^१ तब से सन् १८५३ में प्रस्तावित मृत्यु के समय तक निरन्तर सोवियत शासन का सूत्रधार स्तालिन ही रहा।

सन् १८२८ में प्रथम पंच-वर्षीय योजना पर काम आरम्भ हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश का त्वरित औद्योगिकरण था। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने पर द्वितीय और तृतीय पंच-वर्षीय योजनाएँ कायम की गईं। इन योजनाओं ने सोवियत संघ को संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों की श्रेणी में ला दिया तथा और उस देश को अग्रणी बना दिया कि वह अपना व मापदण्ड प्रारम्भण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सके।

देश के औद्योगीकरण के साथ ही कृषि के सामूहिकरण (Collectivisation) और यंत्रीकरण (Mechanisation) का प्रारम्भ स्तालिन का ध्यान गया। बिना सामूहिकरण व यंत्रीकरण समझ न था यह दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध थे। इस कारण नवीन प्राथमिक नीति के समझ में सुविधाएँ दी गई थीं उनका अन्त कर दिया गया और समस्त कुलका (Kulaks) का अन्त कर दिया गया। (कुलक ऐसे कृषकों का नाम था जो धन था और अन्य गरीब कृषकों का शोषण करते थे) सरकार की कृषि व सामूहिकरण की नीति के फलस्वरूप सन् १९२८ तक लगभग ६ प्रतिशत कृषक सामूहिक-कृषि व्यवस्था के प्रयोग कार्य करने लगे थे। अनुमान किया जाता है कि कुलका का कुल संख्या पचास लाख के लगभग थी और उनमें से कई हजार शासन का नाति का विरोध करने के कारण मारे गए। कृषि के सामूहिकरण तथा उद्योगों के यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप सोवियत संघ में समाजवादी राज्य स्थापित करने का लक्ष्य पट्ट किया जा सका। स्तालिन सविधान इस लक्ष्य के प्राप्त किए जाने की घोषणा ही था। स्तालिन ने सर्वोच्च सोवियत के समक्ष मापदण्ड देते हुए सोवियत संघ के नवीन सविधान के तार में कहा था— यह एक ऐसा लेखपत्र होगा जो स्व

^१ क्रान्ती विशेष में बाकर स्तालिन की नीति के विरोध में प्रचार करता रहा। सन् १९४१ में मस्को के एक नगर में उसकी हत्या कर दी गई।

राज का सिद्ध करेगा कि जो राज सोवियत समाजवादी शासन रूप में प्राप्त की जा चुकी है, दूसरे देशों में भी उसका प्राप्त करना बिल्कुल सम्भव है।^१

सन् १९१८ का संविधान

सोवियत संघ का वर्तमान संविधान सन् १९२९ में प्रवर्धित हुआ था। परन्तु इसके पूर्व दो अन्य संविधान प्रवर्धित हो चुके थे। यद्यपि सन् १८८८ तथा सन् १८९१ के संविधान। यद्यपि काल इन संविधानों के प्रचलन में इन सोवियत शासन-प्रणाली का पूर्ण अभाव नहीं था, परन्तु यह इस शासन प्रणाली का विकास सम्भवतः मर्यादित होगा। इस विधि से यहाँ उनसे प्रमुख लक्षण और विशेषता का उल्लेख किया जा रहा है।

बाल्शविक क्रान्ति के पश्चात् लाम्बा प्रारम्भिक काल में नए संविधान नहीं था। इस काल में शासन का संचालन उन कमिस्मर-परिषद् की आग्निवाहिका द्वारा होता था। परन्तु बाल्शविक नेताओं ने संविधान का प्रारम्भिक प्रारम्भ का समर्थन। बाल्शविक गणतन्त्र का केन्द्र-प्रकारिका समिति ने संविधान के शासन का निमाण करने के लिए एक प्रारम्भ निरूपित किया। इस आयोग ने लोनिन का देश-देश में कार्य किया और इसके प्रमुख गणतन्त्र में स्थापित और सुधारित भाषा। इस आयोग द्वारा प्रस्तुत संविधान के शासन का प्रवर्धित रूप साम्यवाद का क्षेत्र का अनुसन्धान प्राप्त होने पर सन् १९१८ में प्रवर्धित कर लिया गया। इस संविधान का 'रूसी सोवियत समाजवादी गणतन्त्र' (Russian Social st Federated Soviet Republic) का मूल विधि का संविधान गढ़ था।^२ उस समय सोवियत शासन का प्रारम्भिक रूप (Russia prop) तक ही सीमित था।

बाल्शविक क्रान्ति के पश्चात् रूस का साम्यवादी शासन महान् परिवर्तन हो गए थे। पहले-पहल शासन और शासितों में प्रचलित शासन प्रणाली

^१ Joseph Stalin's speech before the eighth Congress of Soviets of the U S S R.

^२ For the text of this Constitution, see E. L. McBain & L. Rogers, *New Constitutions of Europe* pp 395-400

ये और शोषक और शासक शासिन। लेनिन की इच्छानुसार रूस में सरकारी वग व अधिनायकत्व की स्थापना हो चुकी थी। सन् १९१८ के संविधान द्वारा इन परिवर्तनों को तथा सोवियत शासन द्वारा समय-समय पर प्रवर्तित आन्दोलनों को सांविधानिक रूप दे दिया गया। सर्वहारा वग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों, जैसे धर्माधिकारी, मध्यवर्गीय जनता, समृद्ध कृषक आदि तथा ऐसे सभी व्यक्ति जो दूसरों के काम पर स्वयं काम उठाते थे, का मताधिकार से वंचित रखा गया। नारशाही से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों तथा जार की पुलिस के कर्मचारियों को भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। उस समय गृह-युद्ध जारी था और पेंजीरानियों के द्वारा पुनः सर उठाने का प्रयत्न किये जा रहे थे, इस कारण ऐसे सभी वर्गों को निम्न सोवियत शासन का विरोध किए जाने की सम्मानना थी, सराफ़िस्ट दृष्टि से देखा जाता था। अर्थोडॉक्स चर्च का साथ से सम्बन्ध समाप्त कर दिया गया और शिक्षा व्यवस्था का भी धर्म निरपेक्ष बनाया गया। संविधान के साथ ही एक प्रस्तावना (Preamble) संलग्न थी जिसका नाम 'नैतिक तथा शोषित जनता के अधिकारों का घोषणा' था। उसमें उल्लिखित अधिकार नवल-जमींदारी वग को ही प्राप्त थे।

शासन के प्रधान अंग में वैधानिक ण्ट से अखिल रूसी सोवियतों की कांग्रेस (All Russian Congress of Soviets) सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। संविधान के अनुसार समस्त राजसत्ता इसी संस्था में निहित थी। यह संस्था विधानमण्डल के रूप में कार्य करती थी और इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष और वर्गीय निर्वाचन प्रणाली के अनुसार होता था। इस सदस्य प्रांतीय कांग्रेसों के द्वारा चुने जाते थे। प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य जिला कांग्रेसों के सदस्यों के द्वारा, जिला कांग्रेसों के सदस्य ग्राम या नगर सोवियतों के द्वारा और ग्राम या नगर सोवियतों के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए जाते थे। निर्वाचन की दृष्टि से नगरवासी मतदाताओं और ग्रामीण मतदाताओं में भेद किया जाता था। अखिल रूसी सोवियतों की कांग्रेस के सदस्यों की संख्या इस आधार पर निश्चित की जाती थी कि २५, नगरवासी मतदाताओं तथा

१ The Declaration of the Rights of the Working and Exploited People

१९५, ग्रामीण मतदाताओं पर एक सन्धि हो। इस व्यवस्था में परिणाम स्वरूप नगरवासी मतदाताओं को, जिनमें प्रविष्टा वास्तविकता में काम करने वाले अधिक होते थे, कांग्रेस में प्रभुत्व प्राप्त हो जाता था।

सोवियतों की कांग्रेस एक कृत्रिम कार्यकारी समिति का निर्वाचित करती थी। यह सोवियतों की कांग्रेस के सत्रावकाश काल में उसके कार्य भी करती थी। कृत्रिम कार्यकारी समिति एक जन कमिश्नर परिषद् (Council of People's Commissars) को निर्वाचित करता थी। यह परिषद् ही सोवियत शासन का वास्तविक कार्यागार था, क्योंकि यह शायद कार्यकारिणी समिति अपनी सभी सत्तारूपीयता के कारण अनवरत कार्य नहीं कर सकती थी। इन सत्तारूपीय विभिन्न शासन विभागों के प्रमुख हाथ में और अपने अपने विभागों के कार्यों का प्रभुत्व करने थे। ये वैधानिक दृष्टि में कृत्रिम कार्यकारी समिति के प्रति उत्तरदायी होते थे।

यद्यपि शासन में रुस की सभी गणराज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया था, परन्तु उनमें से एक एकल राज्य था। रुस के राज्य क्षेत्र में अनन्त स्वायत्तशासन (autonomous) एकाइयों का निर्माण किया गया था जिन्हें बहुत सी शाखाओं से गुजरना पड़ा था परन्तु राज्य महान के सभी प्रश्नों पर कृत्रिम सरकार का पूर्ण नियन्त्रण था। सन् १८९८ के संविधान में सोवियतों को अत्यधिक महत्व दिया गया था। उनके प्रथम अनुच्छेद में ही घोषणा की गई थी—'रुस को आमका सेनका प्रारंभ के प्रातनिधियों (deputies) की सौम्यता का गणराज्य प्रोत्साहित किया जाता है। सभी स्थानीय तथा केंद्रीय प्राधिकार इन सोवियतों में निहित हैं। रुस गणराज्य का इन्हीं सौम्यता का सध माना जाता था।

सन् १९२४ का संविधान

सोवियत संघ का निर्माण—यह युद्ध तथा वैदेशिक हस्तक्षेप के समाप्त

१ 'The Russian Socialist Federal Soviet Republic, although expressly termed a federation is and has always been essentially a unitary state —Sydney and Beatrice Webb, *Soviet Communism A New Civilisation* (1934 Ed.) p 55

हाने पर रूसी साम्राज्य के कई यर्रोराय क्षेत्रों में नए राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके अपने संविधान थे और अपनी सरकारें। इन नए राज्यों के संविधानों का आधार रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य का संविधान था और इनके शासक भी साम्यवादी विचारों में निश्वास रखते थे। सन् १९२२ में एक संधि के द्वारा रूसी गणराज्य, यूक्रेन स्वतंत्र रूस (White Russia) तथा दक्किकाशिया एक सूत्र में बंध गये। इस संधि ने सोवियत समाजवाद गणराज्य संघ (U S S R) का जन्म लिया। पूँजीवादी राज्यों के आक्रमण का भय, सामूहिक आर्थिक आयातन की आवश्यकता तथा कम्युनिस्ट पार्टी का राज्यों में प्रभाव हा के मुख्य कारण थे जिन्होंने इस तरह का निमाण समझना। सोवियत संघ के निमाण के बाद एक औपचारिक संविधान की आवश्यकता अनुभव का गई। सन् १९२३ के प्रारम्भिक काल में सोवियत संघ का कन्वन्स कार्रकारिणा समिति ने संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। संशोधित अवस्था में इस प्रारूप का चारों राज्यों ने स्वाकार कर लिया और ६ जुलाई सन् १९२४ को इस प्रवर्तित कर लिया गया। ११ जनवर, १९२४ को सोवियतों का द्वितार अखिल संघीय कांग्रेस ने इसका अनुसमर्थन कर लिया। सन् १९२४ में रूसी गणराज्य के क्षेत्र में से उजबेक (Uzbek) तथा तुर्कमान (Turkman) नामक दो नवान गणराज्यों का स्थापना का गई। इस प्रकार सन् १९२६ में ताजिक (Tadzhik) गणराज्य का स्थापना की गई। इन नवान गणराज्यों के निमाण के फलस्वरूप सोवियत संघ के एकका (Unit) का संरचना सात हो गई।

शासन के मुख्य अंग मात्रियता की कांग्रेस—सन् १९२४ का संविधान रूसी गणराज्य के संविधान के आधार पर बनाया गया था। संविधान के अनुसार राज का समस्त सत्ता प्रखिल संघीय सोवियत की कांग्रेस में निहित था। सन् १९१८ के संविधान के अनुसार के समान ही इस संविधान में मा कांग्रेस के निवाचन के लिये अप्रत्यक्ष राति की अवस्था थी। कांग्रेस का संस्य

संस्था निश्चित करने के लिये ग्रामीण और नगरवासियों में जो विभेद पड़ेने सविधान में किया गया था, उसे इस सविधान में भी कायम रखा गया था। सोवियतों की कांग्रेस की सदस्य-संख्या बहुत अधिक होती थी। सन् १९३१ में कांग्रेस की पूर्ण सदस्य संख्या २,४३ तथा सन् १९३५ में यह ३,००० के लगभग थी। सन् १९२४ के सविधान की एक धारा के अनुसार कांग्रेस का वष में कम से कम एक सत्र होना आवश्यक था। सन् १९२७ के एक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कम से कम दो वष में कांग्रेस का एक सत्र अनिवार्य होना चाहिये। 'यन्हार में उस उपबंध का अधिकतर पालन नहीं किया जाता था।' का सत्र सत्र से छोट सत्र की अधि कल एक दिन थी, और सत्र सत्र के का ११ दिन। 'यन्हार में कांग्रेस की समस्त विधायक और कार्यपालिका संस्थाओं शक्ति केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। कांग्रेस अपने सत्र में केवल अपने समस्त प्रस्तुत आस्थाओं का सत्र-सम्मति से अनुमोदन करना था और केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के संस्था का निर्वाचित करती थी।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति—केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का सोवियतों का कांग्रेस का ही एक अंग माना जाता था। यद्यपि इसका नाम कार्यकारिणी समिति (executive committee) था, परन्तु उसका कार्य विधायक (legislative) तथा कार्यपालिका सम्बन्धी दोनों ही थे। अन्य देशों के विधान मंडलों की भांति उसका सत्र दो सत्र होते थे, जिन्हें सत्र सोवियत (Soviet of the Union)^१ तथा जातिक सांघ (Soviet of Nationalities) का सत्र कहा गया था। सत्र सोवियत की संस्था संस्था विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती थी। लगभग १,००० निर्वाचकों पर एक संस्था का अनुमान रखा जाता था। सन् १९३३ में उसका संस्था संस्था ६२७

^१ तृतीय और चतुर्थ कांग्रेस क्रमशः मई १९२५ और अप्रैल १९२७ में हुई (अन्तर—१७५ दिनों)। षष्ठ्य और सप्तम कांग्रेस क्रमशः मार्च १९३१ और जनवरी १९३३ में हुई (अन्तर—३७५ दिनों और १ माह)।

कुछ लोगोंने ने उस सोवियतों का सत्र (Union of Soviets) भी लिखा है।

तथा १९३५ में ६ ७ थी। जानिक सोवियत की संसद संसद निश्चित करने के लिये यह आधार निश्चित किया गया था कि प्रत्येक उपराज (constituent republic) के ५, और प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र (autonomous region) का एक प्रतिनिधि हो। उस संसद की संसद संसद १५ थी। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि न तो सोवियत की कांग्रेस के संसद और न क्षेत्रीय कार्यकारिणी समिति के संसद प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किये जाते थे। सोवियतों का काम संसद के निर्वाचन का यही पद्धति था जिसका उल्लेख हमें सन् १९१८ के संविधान के अन्तर्गत कांग्रेस के संसद के निर्वाचन पर विचार करते समय कर चुके हैं। संसद कार्यकारिणी समिति के लिए प्रयोगिता की सूची पाठ के अन्तर्गत के द्वारा कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी और यह कि किसी परिणत के मद्देन ही कांग्रेस के द्वारा अनुमोदित कर ली जाती थी।^१

मानान्वित संसद कार्यकारिणी समिति की वय में तीन या चार संसद होता था। यह शासन का नाम पर विचार करती थी और अपने प्रेसीडियम तथा कमिस्सियर पारस के निरन्तरता का अनुसमर्थन करती थी।^२ उसका कार्यप्रणाली प्रेसीडियम द्वारा निश्चित किया जाता था। विधि निर्माण में उसका दोनों संसदों की शाक्तता समान थी। दोनों संसदों में विचार होने की स्थिति में संविधान में एक समाधान समिति (Conciliation Committee) के नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी, जिसके सदस्य दोनों संसदों से समान संसद में लिये जाते थे। यदि किसी विषय पर दोनों संसदों में मतभेद नहीं हो पाता था तो अन्तिम निर्णय करने का अधिकार अखिल संघीय सोवियतों की कांग्रेस का दिया गया था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति कई आयोग नियुक्त करती थी जो समय-समय पर अपनी प्रारोपणें उसका सम्मुख प्रस्तुत किया करते थे। इन आयोगों में मुख्य थे आय-व्यय आयोग (Budget Commission) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान आयोग, और शिल्प शिक्षा आयोग।

^१ Florinsky M. T. *The Govt & Politics of the U.S.S.R in Governments of Continental Europe* edited by Shotwell p. 737

^२ F. A. Ogg & H. Zink *Modern Foreign Governments* p. 839

माक्सवा, बाल्शेविक शक्ति तथा सोवियत शासन व्यवस्था का विकास ५३

यद्यपि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति लगभग सदैव हा प्रेसीयुम और कमिसार परिषद् के निर्णयों का अनुमोदन कर देती थी, परन्तु उसके सम्मेलन द्वारा उगकी तीव्र आलोचना भी की जाती थी। उस आलोचना के फलस्वरूप कभी कभी शासन का नीति में मन्त्रपूषण परिवर्तन किए जाते थे।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सत्र बहुत थोड़े समय के लिए होते थे। उसका एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच दो माह से लेकर तरह माह तक का अंतर रहा तथा उसका पूरा कार्यावधि (१८२ १६ ७) में उसका सत्र कुल १३६ दिन तक चले।

प्रमादियम—केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अपने सत्रावसान काल में कार्य करने के नियम एक अधिवेशन (प्रेसीडियम) निर्वाचित करता थी। उस प्रेसीयुम के ६ सम्मेलन सोवियत द्वारा ६ सदस्य जातिक सभियन गण तथा ६ सम्मेलन दोनो सम्मेलन के द्वारा एक समुक्त प्रावधान में चुने जाते थे। उस प्रकार प्रेसीयुम के सम्मेलनों की पूर्ण संख्या २७ होती थी। सन् १९२४ के संविधान में प्रेसीयुम को 'सोवियत संघ का सर्वोच्च विचारक, कार्यकारी तथा प्रशासनिक प्रावधान बनाया था। नए कर लगाने तथा पुराने करों में श्रद्धि करने जैसी सभी आज्ञाओं पर प्रेसीयुम का पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना आवश्यक था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सत्रावसान काल में प्रेसीयुम आवश्यकतानुसार नियम आदेश दे सकता था। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का सत्र बहुत थोड़े काल के लिये होता था। इस कारण, जैसा कि फ्लोरिन्स्की का मत है, सोवियतों की कांग्रेस का कार्य का भार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पर नहीं बरन् उसका प्रेसीयुम का वहन करना पड़ता था।^१

^१ Julian Towster *Political Power in the U S S R* (1917-1947) pp 223 230

^२ the highest legislative executive & administrative organ in the U S S R —*Constitution of the U S S R 1944*

^३ The brunt of the work of the Congresses of the Soviet devolved not upon the Central Executive committee but upon its residuum —Florinsky M T *op cit* p 737

जन कमिसार परिषद्—केंद्रीय कार्यकारिणी समिति एक जन कमिसार परिषद् (Council of People's Commissars) को नियुक्त करती थी, जो अन्य राज्यों के मन्त्रिमन्त्रालय समान संघीय शासन का मुख्य कार्याङ्ग थी। इसकी सदस्य-संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई थी, इस कारण उसमें समय समय पर परिवर्तन होन रहते थे। सन् १९३४ में उसके १५ सदस्य थे। परिषद् के सदस्यों को कमिसार (Commissar) तथा उनके प्रशासकीय विभागों का 'कमिसरियन' कहा जाता था। सोवियत संघ में राज का कार्य क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर राज का अधिकार है। इसके पक्षस्वरूप जन कमिसार परिषद् के सदस्यों या कमिसारों को न केवल अपने देश के मंत्रियों के कार्य करने पड़ते थे बल्कि अन्तर्राष्ट्रिय संबंधों का निर्देशन भी करना पड़ता था।

जन कमिसार परिषद् में दो प्रकार के विभाग थे—ग्रामिण संघीय कमिसरियत तथा सघ गणराज्य कमिसरियत। ग्रामिण संघीय कमिसरियत ऐसे विभागों का नाम था जिनका प्रधान व कार्य वे जो पूर्णतया संघीय सरकार के क्षेत्राधिकार में थे उदाहरणार्थ वैश्विक मामलों, वैश्विक व्यापार, सुरक्षा, आदि। ऐसे विभाग जिन के अन्तर्गत ऐसे विषय थे जिन पर संघीय शासन एवं एक (गणराज्य) का समान क्षेत्राधिकार था सघ गणराज्य कमिसरियत कहलाते थे उदाहरणार्थ, स्वायत्त्यात्मक जन पंच, इत्यादि।

सर्वोच्च न्यायालय—सन् १९२४ के संविधान में सोवियत संघ में निचे एक सर्वोच्च न्यायालय (Suprem Court) की भी व्यवस्था थी। परन्तु वहाँ यह माना गया कि आवश्यक है कि सोवियत संघ में शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धान्त का कभी मान्यता प्रदान नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मेलन का कांग्रेस का ही एक अंग माना जाता था। सोवियत संघ की कांग्रेस अपने अधिकृत कृत्य से प्रभावित करती थी। सर्वोच्च न्यायालय को किसी विधि के संविधान के प्रतिकूल होने पर अंग प्रोहित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

सन् १९३६ का संविधान (स्तालिन संविधान)

परिवर्तित परिस्थितियाँ—सन् १९२४ से १९३६ तक के काल में सोवियत संघ की आर्थिक दशा, सामाजिक व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सन् १९२४ के संविधान के निर्माण के काल में नवीन आर्थिक नीति के काल था, जो अथवा पेंजागानी व्यवस्था को पुनर्जाति कर सोवियत संघ की अर्थ-व्यवस्था को दृढ़ करने का प्रयत्न किया जा रहा था। उस समय सोवियत संघ की सारांशिक महत्वपूर्ण समस्या थी उत्पादन में वृद्धि करना। सन् १९२८ में प्रथम पंच वर्षा योजना का अन्तगमन कार्यालय में होने से सोवियत संघ के जीवन में भी वह काल प्रारम्भ हुआ वह था समाजवादी आन्दोलन पर देश का पुनर्निर्माण और पेंजागानी योजना के अग्रगण्य तत्त्व का पूर्ण अन्त करने का काल। सन् १९३६ तक उपराज्य लक्ष्य को बहुत ज़ीदा सामान्य प्राप्त कर लिया गया था। २५ नवम्बर १९३६ का अष्टम संविधान का प्रसंग के समस्त स्तालिन ने जो भाषण किया था उसमें उसने सोवियत संघ की प्रगति और परिवर्तित स्थिति का निरस्त चित्रण किया था। देश के औद्योगीकरण पर प्रकाश डालते हुए उसने कहा—“संयुक्त महत्वपूर्ण बात यह है कि पनीना हमारे आन्दोलन के क्षेत्र में निरस्त ही लुप्त हो चुका है जोर उत्पत्ति की समानता पद्धति और वह सिद्धान्त है जो कि हमारे आन्दोलन के हर क्षेत्र में अत्यन्त अधिकार करता है। हमारे आज के समानता आन्दोलन का उत्पादन युद्ध के पून के उद्योग से सात गुने से भी अधिक है। यह कोई मामूली बात नहीं है। कृषि की रक्षा करत हुए स्तालिन ने कहा—“सभी लोग जानते हैं कि कृषि में ‘कुलक’ (समृद्ध उपकरण) ऐसा लुप्त हो चुका है, और पिछले दशकानुसार कृषि प्रक्रियाओं से युक्त छात्र व्यक्ति उपकरण का अर्थ भी अत्यन्त गहन — उत्तम रह गया है। ज़ात हुए भूमि के लेने पर कृषि में इनका भाग २ या प्रतिशत से अधिक नहीं है। और इन संघ परिवर्तना का सारांश अतन्त्र हुए स्तालिन ने कहा—“संयुक्त मतलब है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का जीवन उत्तम हो गया है नष्ट हो गया है जब कि उत्पत्ति के उपकरण और साधना पर समान का अधिकार हमारे सोवियत समाज में अचल नींव के रूप में स्थापित हो गया। इस प्रकार सभी

शापक प्रशिया आ समाप्त हो चुका। अब शप है, श्रमिक श्रेणी। अब रोप है, कृषक श्रेणी। अब शप है, बुद्धिमान श्रेणी।

न केवल आन्तरिक क्षेत्र म हा, प्रत्युत अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र म भी सोवियत संघ की स्थिति सुदृढ़ हुई थी। सन १९४४ म सावित्र संघ राष्ट्र संघ (League of Nations) का संस्थापक सदस्य हो गया था। जर्मनी म नाजी दल का उदय के कारण अब पश्चिमी राष्ट्र अपना सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे थे। इससे सावित्र संघ को किसी तात्कालिक आक्रमण का भय न था। दूसरे सभी देशों - शान्तिनिष्ठ अब यह भला भाति जान गए थे कि कम म सावित्र शासन की जाह्नवाप्रवृत्ति कम गई है और अब उम हटाना अत्यंत कठिन है।

संविधान निर्माण—६ फरवरी १९३५ को सत्रम् सावित्र कांग्रेस ने १८२४ के संविधान म संशोधन करने का निश्चय किया। उक्त निश्चय के अनुसार ३१ सन्ध्या का एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग का अध्यक्ष स्तालिन था। आयोग को यह आदेश दिया गया था कि वह संविधान म ऐसे संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर जिससे असम-मतधिकार की जगह पर समान मतधिकार, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन और खुले मतदान की जगह गुप्त मतदान की व्यवस्था हो। साथ ही सोवियत संघ की वर शक्तियां व वर्तमान सम्बंध व अनुसार संविधान म परिवर्तन कर उसके सामाजिक और आर्थिक आधार का और अधिक स्पष्ट कर दिया जाए।

यद्यपि सावित्र कांग्रेस ने संविधान आयोग का १९२४ के संविधान म संशोधन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था परन्तु उसने एक नए ही संविधान का प्रारूप कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। स्तालिन ने अपने २५ नवम्बर १९३६ के सावित्र कांग्रेस के समक्ष दिए गए भाषण म यह घोषणा की कि “नए संविधान का प्रारूप, जितना मांग हमने तब किया है, जो वस्तुएँ हम पा चुके हैं, उनका सक्षप है। यह केवल प्राप्त उद्देश्य का वर्गनिक अकन मान है।

जून १९३६ म संविधान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया था, जिससे उम पर सामंजसिक बात चिदा किया जा सके। शान्कीय आकडा के अनुसार संविधान पर विचार करने के लिए ५२७ समाएँ हुई जिनमें २ करोड़ ६५ लाख लोगों ने भाग लिया। संविधान के प्रारूप में लगभग १५४,

माक्सवा, गाल्शेनिक क्राति तथा सोवियत शासन यवस्था का विकास ५७

सशोधन प्रस्तावित किए गए परन्तु इनमें से केवल ४३ सशोधन माने गए । फ्लारिन्सकी के मतानुसार वस्तुतः यह सभी सशोधन शान्दिक थे । स्वातंत्र्य सशोधना में केवल एक सशोधन कुछ औपचारिक महत्त्व का था जिसके द्वारा चातक सोवियत (Soviet of Nationalities) के लिए अप्रत्यक्ष निवाचन पद्धति के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई ।^१ इस सशोधन को मानने का परामर्श स्वयं स्तालिन ने सोवियत कांग्रेस के समक्ष अपने भाषण में किया । अस्वातंत्र्य सशोधना में से कुछ में द्विसत्तनामक व्यवस्था समाप्त करने, प्रेसीडियम के अध्यक्ष का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित करने, धार्मिक पूजा के अनुष्ठान का निषेध करने सश गणराया का सोवियत संघ से पृथक् होने का अधिकार न दिए जाने की मांग की गई थी । सोवियत की अप्रत्यक्ष (विशेष) कांग्रेस ने इस दिन तक सविधान के प्रारूप पर विचार किया और उनमें पश्चात् कुछ सशोधना के साथ उसे सबसम्मति से स्वीकृत कर लिया । सन् १९२७ के प्रारम्भिक काल में इसे प्रवर्तित कर दिया गया और १२ दिसम्बर १९३७ को नए सविधान के अन्तर्गत प्रथम सर्वोच्च सोवियत का निवाचन हुआ ।

अध्याय ४

स्तालिन सविधान की प्रकृति तथा विशेषताएँ

सोवियत प्रगति तथा विधिवत्ता पुन पुन यह घोषणा करत हैं कि सोवियत सविधान अन्य दशा न सविधाना से पूरुण भिन्न है। साथ ही वे यह भी दावा करत हैं कि सोवियत सच एक नए प्रकार का राज्य है। उस कारण सोवियत शासन प्रणाली का अध्ययन प्रारम्भ करने के पूर्व यह ग्रन्थक है कि हम सोवियत सच के उनमान सावधान का प्रकृति तथा उसकी विशेषताओं पर विचार करें।

सविधान का लिखित स्वरूप—सोवियत सच का सविधान एक लिखित सविधान है अर्थात् शासन के विभिन्न अंगों, उनके कृत्या एवं कार्यक्षेत्र तथा नागरिकों के मूल अधिकार आदि का एक लेखपत्र में उल्लेख है, और उसकी अन्य विधियाँ से अधिक महत्ता समझी जाती है। परन्तु उसमें कमल उल्लेख का ही उल्लेख नहीं है। उसमें सोवियत राज्य के स्वरूप, सोवियत राज्य की सामाजिक दशा सोवियत सच के राजनीतिक तथा आर्थिक आधार आदि का भी स्पष्ट उल्लेख है। उसमें भूमिस्वामियों (landlords) तथा पूँजीपतियों का सत्ता के उन्मूलन तथा संहारा के अनिवार्यत्व की विजय का अंकन है। उसमें साथ ही सोवियत सच के सविधान में नागरिकों के उन अधिकारों का उल्लेख है जो उन्हें प्राप्त हैं। उसमें निम्न आने वाले युग में नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकारों का उल्लेख नहीं है। इसी कारण सोवियत लेखक सोवियत सविधान का सामाजिकता का प्रतिबिम्ब बतलाने हैं। उनका मतानुसार सविधान राज्य में सामाजिक शक्तियों के वास्तविक पारस्परिक सम्बन्धों की वैधानिक अभिव्यक्ति मान है। यदि ऐसा नहीं है तो सविधान कबोच कल्पना मान होगा।

सविधान के प्रारूप पर अष्टम् सोवियत कांग्रेस के समक्ष लिये गये अपने भाषण में स्तालिन ने कार्यक्रम और सविधान का अंतर स्पष्ट किया था। उन्होंने

नहा था कि कार्यक्रम का समग्र सुपन्नता भविष्य से होता है और समिधान का मतमान मे । इसका कारण यह है कि कार्यक्रम मे उन वस्तुग्रा का उल्लेख होता है जो अभी विद्यमान नहा है, निह कि भविष्य मे प्राप्त करना है । इसर विपरात समिधान मे उन वस्तुग्रा का उल्लेख होता है ना कि विद्यमान हैं ना कि अब तक पाई और जाती जा चुका हैं । इस कारण लालिन ने सन् १९६६ क समिधान को 'विजित क्षेत्र (Conquered territory) अथात् राय म स्थानत राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का औपचारिक बणन बतलाना था ।'

यदि सार्वभौमिकता का सन्निधान निमित्त है और सार्वभौमिकता प्रत्यक्ष उभर
सार्वभौमिकता का निर्माण होता है परन्तु उसका सम्बन्ध म यह निश्चित रूप से
 कहा जा सकता है कि कबल सार्वभौमिकता उभरने का आधार बनने से ही नहीं
 बल्कि सार्वभौमिकता का शासन प्रणाली में पूर्णतः पारितोषिक नहीं हो सकता। इसका
 लिये उस निमित्त शासनांगों का सम्बन्ध तथा अनेक ऐसी सम्भावनाएँ काय
 से परिचित होना होंगी जिनका सन्निधान में कुछ उल्लेख भी नहीं है। यह जान
 किता है कि प्रत्यक्ष देश का शासन प्रणाली का सम्बन्ध म कहा जा सकता है
 परन्तु सार्वभौमिकता का सम्बन्ध में इसका सम्बन्ध सार्वभौमिक है।

राष्ट्र का समानवाद। आधार—नसा पहले तत्त्वांग गरा है, साहित्य सावधान व प्रथम अनुच्छेद में ही साहित्य संघ को समीचीन तथा हानि का समानवादी राय प्रकट किया गया है। प्राग न अनुच्छेदों में समानवादी विषयों को गहरा रूढ़ किया गया है। सविधान के चतुर्थ अनुच्छेद व अनुवाक साहित्य संघ का आर्थिक आधार माना गया प्रथम तथा तथा उपायन व साधना और उद्योग का समानवादी मानिय है ना कि पञ्जीयन अथवा सेवा व उद्योग उद्योग व साधना तथा उद्योग व सक्तिगत स्वामित्व का सन्नाति और मनुष्य द्वारा मनुष्य व शोषण व अनियमित ज्ञान व परिणाम तथा उत्पादन साधित हुआ है। अनुच्छेद छ — अनुवाक मूनी उसका प्रतिन संपत्ति जल, वन, कारागारे, पेट्रिया खान गल, नल तथा

वायु यातायात, बैंक, संचार राज्य द्वारा संगठित 'इ. व. वृषि उद्योग' (राजकीय फार्म यंत्र स्टेशन ट्रान्सि) तथा समस्त म्युनिस्सिपल उद्योग और नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के रहने योग्य भवन का अधिकांश भाग, राज्य की सम्पत्ति हैं प्रत्येक जन पर समान वनस्पति का स्वाभाव है।

राज्य की सम्पत्ति के अतिरिक्त समानता की सम्पत्ति का दूसरा रूप सहकारी समितियाँ और सामाजिक फार्मों का सम्पत्ति है। सामूहिक फार्मों तथा सहकारी संस्थाओं के सामाजिक उद्योग उन पशु और जन उनके द्वारा उत्पादित मनुष्य, तथा उनका सामाजिक भवन ट्रान्सि जनका सामाजिक समानता की सम्पत्ति हैं।^१ सामूहिक फार्मों द्वारा प्रदान भूमि यह अपने उपयोग के लिये नि शुल्क तथा प्रत्येक मनुष्य के लिये अर्थात् सत्ता के लिये, प्राप्त है।^२

राज्य के समानता के आधार का यह प्रयत्न लगाना कि सोवियत संघ में वस्तु-संपत्ति जनता का प्रगत अंत कर दिया गया है, असंगत होगा। समानता अथवा जनता के साथ जो कि सोवियत संघ की प्रमुख अर्थ प्रस्था है निरिक्त के द्वारा संगठित रूप से उत्पादन तथा कारीगरों का अपने भ्रम पर अवलंबित तथा शिक्षा दूर के भ्रम का उपयोग किये बिना छोटे परिमाण में व्यक्तिगत अर्थ प्रस्था की छूट दी गई है।^३ निरिक्त नागरिकों के अपने भ्रम से अर्जित आय तथा उच्च रहने के घर घर के समान तथा वैयक्तिक उपयोग तथा सुविधा का मनुष्यों पर अधिकार तथा उनके वस्तु-संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने के अधिकार का संरक्षण करती है।^४ असंदिग्ध होता है कि सोवियत संघ में भी व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का छूट दी गई है।

समाजवाद तथा साम्यवाद का सिद्धि में प्रन्तर—सोवियत संघ में समाज के विकास की उत्तमान स्थिति का समाजवाद का सिद्धि कहा जाता है। इसी कारण सोवियत संघ का वर्तमान समाज का आधार यह सिद्धान्त है—'प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार।' परन्तु साम्यवाद का अन्वेषण में एक दूसरा ही सिद्धान्त आधार

^१ अनु ७

^२ अनु ८

^३ अनु ६

^४ अनु १

From each according to his ability to each according to his work — Art 12 of the Constitution

होगा। वह सिद्धान्त है—“प्रत्येक से उसका सामर्थ्य” अनुसार, तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार।^१ सा समाज की समस्या में न तो वैयक्तिक सम्पत्ति होगी, और न काय न बत्ल में पारिवारिक पान का प्रस्था। उस अवस्था में प्रत्येक उक्ति अपना सामर्थ्य अनुसार समान का हित करेगा और समाज प्रत्येक उक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।^२ मजदूर और एगिल्ल द्वारा प्रतिपादित समाज की आशा अवस्था है। सोवियत प्रवक्ताओं का दावा है कि सोवियत संघ की उत्तमान अवस्था उमा अवस्था का दिशा में बना हुआ पग है।

अनन्य संविधानों में मराधिक नन्य संविधान—राय शास्त्र न प्रमुख विद्वानों ने संविधान का अनन्य (Rigid) और नन्य (Flexible) नामक दो वर्गों में विभक्त किया है। अनन्य और नन्य संविधानों में भेद का आधार संविधान में संशोधन करने का पद्धति का माना जाता है। प्रा स्वायत्त न भवानुसार जिस संविधान में संशोधन या पारित करने का अनन्य विचार पद्धति (साधारण विधि ज्ञान की पद्धति में भिन्न) न आवश्यकता पड़ती है वह अनन्य संविधान कहा जाता है। मजदूर प्रवक्ता जिस संविधान में संशोधन करने का पद्धति सामान्य विधि ज्ञान पद्धति से भिन्न नहीं होती उस नन्य संविधान कहा जाता है।

यदि हम सोवियत संघ के संविधान पर निर्धारित कड़ा न आधार पर विचार करें तो निश्चय ही हमें यह मानना होगा कि सोवियत संघ का संविधान अनन्य है। सोवियत संघ के संविधान के अनुच्छेद १४६ में संविधान में संशोधन करने की पद्धति का उल्लेख है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है ‘सोवियत संघ का संविधान केवल सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदन में कम से कम दो तिहाई बहुमत से अंगीकृत निश्चय न करा ही संशोधित किया जा सकता है। सर्वोच्च सोवियत साधारण विधि सामान्य बहुमत से ही पारित कर सकती

^१ From each according to his capacity to each according to his needs

^२ Strong C F Modern Political Constitution p 63

है, इस कारण सविधान में सशोधन करने की पद्धति विधि निमाण पद्धति स्थापित या भिन्न है।

सधामक शासन प्रणाली वाले सभी राज्यों में सविधान प्रायः अनुम्य होते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें सशासन करने में नित्य सघ में सम्मिलित होने वाले एकका (Units) का मत जानना आवश्यक होना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रालिया में सविधानों तथा भारतीय सविधान के अधिकांश भाग में सशोधन करने के लिये सघ में सम्मिलित होने वाले एकका की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। परंतु सोवियत संघ में सविधान में अनुम्य होने का यह कारण नहीं है। जैसा कि अनुच्छेद १४६ से जिसका हम अभी उल्लेख कर चुके हैं, स्पष्ट है, सोवियत संघ में सविधान में सशोधन करने के लिये एकका का स्वातंत्र्य प्राप्त करना तो दूर रहा, उनका मत जानना भी आवश्यक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सशोधन के लिए नौ निर्हास बहुमत का उपबन्ध सविधान का अन्य विधियाँ से अधिक महत्ता देने के लिये ही रखा गया है।

सोवियत संघ के सविधान की नम्यता (flexibility) का अनुमान हम ऐसा तथ्य से लगा सकते हैं कि सविधान के प्रवर्तित किये जाने से अथवा तब तक तब तक सोवियत के प्रायः प्रत्येक सघ (session) में ही उस में सशोधन किये गये हैं।^१ उनमें से कुछ सशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सोवियत सविधान की नम्यता का कारण केवल सावधानिक उपपत्ति ही नहीं हैं। इसका एक प्रमुख कारण सर्वोच्च सोवियत में कम्युनिस्ट पार्टी का प्राबल्य है। यदि सोवियत संघ में भी संसदीय (Parliamentary) शासन होता तथा सभी राजनीतिक दलों का निर्वाचन में खुल कर भाग लेने का स्वतंत्रता होती तो भी सोवियत सविधान इतना ही नम्य सिद्ध होता यह सदेह जनक है। ना कुछ भी हो यह निश्चिन्त रूप से कहा जा सकता है कि अनुम्य काटि के सविधानों में होते हुये भी सोवियत सविधान पराहार में अधिक नम्य सिद्ध हुआ है।

सुफ्ट के द्रव्युक्त सघीय परराज—सविधान के अनुच्छेद १३ के अनुसार सोवियत संघ समान सोवियत समाजवादी गणराज्यों का स्वेच्छा के

^१ Julian Towster op cit p 26

आधार पर निर्मित सघराज है। इस सघ में सोनह सघ-गणराज्य (Union Republics) हैं। इन गणराज्यों को सोनह विन्यास में पूर्ण स्वायत्तता (autonomy) प्राप्त है। वर्ष १८४४ के संविधान द्वारा उन्हें प्रभुता सौंप दी गई तथा विशेषा से प्रत्येक सघ स्वयं के भाग अधिकार दे दिया गया है। न केवल इतना ही, बल्कि सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रत्येक सघ-गणराज्य का प्रभुता सौंपा हुआ सविधान सघ से सघ विच्छेद करने का भाग अधिकार प्राप्त है।^१ यह अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा अन्य सघों के एकता का प्राप्त नहीं है। वास्तव में यह ऐसा अधिकार है जो एक सघ-राज्य (Federal State) में नहीं प्रचुर एक राज्य-मंडल (Confederation) में ही एकता का नियम पा सकता है।

सघ-गणराज्यों के अनिवार्य सविधान सघ के सविधान में स्वायत्तशासी राज्य का स्वायत्तशासी प्रदेशों तथा राज्य सत्ता का भाग सघ के एकता के रूप में मान्यता प्रदान का गइ है। नाटिक-सविधान (सर्वोच्च सविधान के द्वितीय सदन) में इन सभी का प्रतिनिधि भवन का आधिकार है। परन्तु उनका वास्तविक प्रतिष्ठा, अधिकार और कर्तव्य समान नहीं हैं। यहाँ यह मान रखना आवश्यक है कि उनका निम्न श्रेणी के सघ-गणराज्यों से प्रभुता नहीं है। उनका उन्हा के भाग हात हैं। उदाहरणार्थ, सघ सघ-गणराज्य में १ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा ६ स्वायत्तशासी प्रभाग हैं। निम्न श्रेणी के एकक सघ सघ-गणराज्य के सघ में होते हैं। वे उसी के सविधान में कार्य करते हैं। सघ-गणराज्यों में प्रजातन्त्र का स्वायत्तशासी गणराज्य का मात्र-परिणत निष्ठा तथा प्राप्ति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। निम्न श्रेणी के एकक सघ सविधान सघें पूरा करने पर सघ श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं तथा सघ गणराज्य तक का रूप ले सकते हैं। सविधान सघ में प्रभुता सघा जानेवाला तथा वास्तविक प्रभुता को प्रभुता भाग सघ सविधान में उन्नत करने का प्राप्त स्वयंसेवा प्राप्त है।

संविधानिक उन्नति। के अनुसार सघ में सम्मिलित होने वाले एकता के प्रभुता स्वायत्तता तथा इतने महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त जाने पर भाग सघ सविधान सघ उन सघों में है जहाँ सत्ता का प्रभुता केन्द्राकरण है।

इसका एक प्रमुख कारण यह है कि सावियत सघ के आर्थिक जीवन का निधारण तथा निर्देशन सघीय शासन की राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं द्वारा किया जाता है। प्रती आर्थिक प्रस्था - सघ में सघ पर आश्रित रहने के कारण सघ के एककों की स्वातन्त्रता संविधान के अनुच्छेद १ तक ही सीमित रह जाती है। सोवियत संविधान में सघ गणराज्यों को सघ से अलग होने का अधिकार प्रवश्य दिया गया है परन्तु उसका प्रयोग की सम्मानना इसा तथ्य से यह है कि सन् १९२७ के 'शुद्धाकरण' में अनेकों 'राज्यों' का 'सोवियत सघ' को विघाटन करने का प्रयत्न करने के अपराध में दण्ड भोगी होना पड़ा। फरवरी १९४४ के संशोधन के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग प्रयोग में प्रयोग नहीं हुआ है। वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत सघ में सर्वत्र शासन प्रभार के कारण एक-एक के अधिकारों पर रोक देने वाले राज्यों को राज्य विरोधी कार्यवाहियों के लिए दण्ड देने की ही सम्मानना प्रदत्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों के होते हुए भी यह कानून प्रत्युक्ति न होता कि सोवियत सघ एक मुक्त राष्ट्र युक्त सघ है।

— राज्य की प्रगति—संसार के प्राधिकांश सघीय शासन वाले देशों का प्रवृत्त सत्ता के अधिकारिक कन्द्राकरण की ओर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का उल्लंघन करने के द्वारा सघीय शासन के अधिकार क्षेत्र में प्राश्चयजनक वृद्धि हुई। स्विट्जरलैंड में यह वृद्धि सन् १८४८ के संविधान में समय पर समय किए गए संशोधनों के द्वारा हुई। सोवियत सघ मात्र इस प्रगति का अपवाद नहीं है। सन् १९२४ के

At first glance the most conspicuous difference (with the U.S.) might seem to be the right of secession of the union republics though for all its ideological appeal this right can scarcely be regarded as a matter of practical politics. There is to be noted in this connection the fact that many of those charged with treason and counter-revolution in the purges of 1937-38 were accused of working to dismember the Soviet Union.—Harper & Thompson op cit pp 52-53

संविधान में कृषि, आर्थिक मामले, न्याय, लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा व विभागों को एक-दूसरे के अनन्य (exclusive) क्षेत्राधिकार में रखा गया था। सन् १९३६ तक इनमें से केवल अंतिम दो ही उनके क्षेत्राधिकार में रह गए। स्तालिन संविधान के द्वारा तथा उसके बाद के कई संशोधनों के द्वारा भी सोवियत शासन के क्षेत्राधिकार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस कारण यह कहना उचित ही है कि सोवियत संघ में भी अन्य संघों की भांति सामान्य प्रकृति संघों के कन्द्रीकरण की ही रही है।

—नागरिकों के मूल अधिकारों की विशिष्टता—सोवियत संघ के संविधान के दशम अर्ध-भाग का हम सोवियत नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का घोषणा पत्र कह सकते हैं। इसमें उन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है जिनकी संरक्षण प्रत्याभूति करता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र सम्मिलित होना कोई नवीन बात नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस (संयुक्त गणराज्य) जर्मनी तथा भारत आदि अन्य अनेक देशों के संविधानों में भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है। परन्तु सोवियत संघ के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के अधिकारों की यह एक विशेषता है कि उनमें न केवल राजनीतिक अधिकार ही हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। संविधान ने केवल नागरिकों के अधिकारों का प्रत्याभूति (guarantee) मान ही करती है, बल्कि उनका उद्वेगन भी। यह आवश्यक व्यवस्था भी करती है। उदाहरणार्थ, यहाँ संविधान में नागरिकों के अधिकारों की समानता की घोषणा की गई है, वहाँ साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण और उनका अधिकारों का अग्रहण न कर सके। पूँजावादी देशों के संविधानों से सोवियत संविधान की तुलना करता हुए स्तालिन ने कहा था मेरे (पूँजावादी देशों के संविधानों) नागरिकों की समानता का बात करते हैं परन्तु वे इस भूल जाते हैं कि मानिक और धार्मिक भूखानों और वृक्षों के बीच कैसे सामाजिक समानता हो सकती है जब कि समाज में एक के पास धन और राजनीतिक शक्ति है और दूसरा उन लोगों से वंचित है जो कि एक श्रावक है और दूसरा शोषित।

मूलान्वित संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मूल अधिकारों पर विस्तृत विचार हम एक स्वतंत्र अध्याय में करेंगे। यहां कमल मुख्य विशेष महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। संविधान में संविधान सभा के प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार (Right to work) दिया गया है। संविधान में इस अधिकार का अर्थ काम (employment) पाने का अधिकार तथा अपने काम के पूर्ण और मान्य अनुसार पारिवारिक प्राप्त करने का अधिकार बताया गया है। प्रत्येक नागरिक को निराम और अवकाश पाने का अधिकार भी दिया गया है। उदाहरण, अस्वस्थता अथवा काम करने के अयोग्य व्यक्ति का जीवन निराह के लिए आवश्यक भत्ता दिया जाता है। समस्त नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है तथा साक्षात् ऐसा कि शिक्षा पर नागरिकों का कुछ व्यय नहीं करना पड़ता। नागरिकों को धार्मिक उपासना तथा धर्मविरोधी प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नैतिक जनता के हितों के अनुकूल तथा समाजवादी व्यवस्था का रूप देने के लिए नागरिकों को भाषण देने तथा सभा करने, जलूस निकालने और प्रदर्शन करने, सांजनिक संस्थाएँ बनाने का तथा समाचार पत्र प्रकाशित करने का स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं। किसान नागरिकों को न्यायवादी (Procurator) अथवा न्यायालय का स्वाकृत कर्मचारी बनाना नहीं बनाया जा सकता। संविधान में नागरिकों के निवास-स्थानों का निरापेक्षशीलता (Inviolability) तथा पत्र-व्यवहार की गोपनीयता को मान्यता प्रदान का गया है।

स्त्रियाँ तथा पुरुषों में एक निमित्त जातियों के नागरिकों में किसी प्रकार का भेद मान करना संविधान द्वारा अपसुख स्वरूप दिया गया है। संविधान सभा के सभी नागरिक उपनिमित्त अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां पर ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त अधिकारों पर कुछ ऐसे निबंध लगे हैं जिनके कारण इन अधिकारों के उपयोग पर पनात प्रभाव पड़ता है। इन निबंधों का आगे उल्लेख किया जाएगा।

नागरिकों के कर्तव्य—संविधान सभा की यह एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें न केवल नागरिकों के अधिकारों का ही उल्लेख है, बल्कि उनके प्रधान कर्तव्यों का भी उल्लेख है। क्योंकि संविधान सभा के नागरिकों के नौ

कृतय सविधान में गिनाए गए हैं उनमें कोई नवबानता नहीं है, परंतु सविधान में स्थानादय जाने के कारण उनकी महत्ता कम गई है। इनमें यदि ग्राम मुख्यालय उपयोग में भी हो तो भी यह नागरिका में अपने को समाज का एक अंग समझने का विचार तथा अपने और समाज के हितों के परस्पर पूरक होने का भाव आवश्यक उत्पन्न करते हैं।

सविधान में उल्लिखित नागरिकों के मुख्य कर्तव्यों में प्रथम सविधान का अनुसरण करना, विधियों का पालन करना, अथवा सभी अनुशासन उपाय करना अपने सामाजिक कर्तव्यों का इमानदारी से पालन करना, तथा समानता की नैतिकता (socialist intercourse) के नियमों का आदर करना है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह समाजवादी सामाजिक सम्पत्ति की रक्षा करे क्योंकि यही देश की शक्ति और धन तथा नागरिकों की समृद्धता एवं सभ्यता की स्रोत है। देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य माना गया है और इसके लिए प्रत्येक नागरिक का सब का सेवा में नैतिक सेवा करना सम्मानित कर्तव्य घोषित किया गया है। इन कर्तव्यों को पूरा न करने वालों को जनता का शत्रु तथा कठोर दंड का भागी बताया गया है।

प्रत्येक दूरस्थ सोवियत नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह काम करे। सविधान में अथवा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान का विषय घोषित किया गया है। सविधान में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है कि “जो काम नहीं करता, वह भोजन पाने का भी अधिकारी नहीं है।”

सोवियत प्रणाली—सविधान के द्वितीय अनुच्छेद के अनुसार सोवियत संघ का राजनीतिक आधार अथवा सभी जनता के प्रतिनिधियों (Working-People's Deputies) की सोवियतें हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि सोवियत किसे कहते हैं। रूसी भाषा में परिषद् (Council) को ही सोवियत कहते हैं। रूस में अथवा सभी जनता की प्रथम सोवियत अर्थात् परिषद् सन् १९१८ ई. की क्रांति के समय बनी थी। उससे पूर्व रूस में कोई आमिक संघ नहीं था। जब किसी कारणवश या अन्य कोई आन्दोलन होता था तो मिल मालिकों से बातचीत करने के लिए मजदूर अपने प्रतिनिधि चुन लेते थे। इस

प्रथा का एक दुष्परिणाम यह होता था कि विभिन्न मिलों के मजदूरों में एकता स्थापित न हो पाती थी। सन् १९५५ में आइवानोवो वोझनेसेन्स्क (Ivanovo-Voznesensk) में कपड़े के कारखाना में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल की। उस समय की स्थिति का चित्रण करते हुए पोन्कोवस्की ने लिखा है 'हर एक मिल मालिक कहता था—“मैं अपने मजदूरों से साथ बातचीत करने को प्रस्तुत हूँ, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं।’ परन्तु आइवानोवो वोझनेसेन्स्क के मजदूरों ने हड़तालियों की एकता को तोड़ने वाली पेंजीपतियों की इस प्रिय चाल को भाग लिया। उन्होंने समस्त हड़तालियों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने के लिए लगभग सौ प्रतिनिधि चुने और कहा कि समस्त मजदूरों के इन प्रतिनिधियों से ही समझौते की सारी बातचीत की जाय, जैसा एक बग दूसरे बग से करता है। उस प्रकार रूस के मेहनतकशा के प्रतिनिधियों की सबसे प्रथम सोवियत की स्थापना हुई।^१ इसी उदाहरण का अन्य औद्योगिक नगरों के मजदूरों ने अनुकरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९५५ की समाप्ति तक प्रायः प्रत्येक औद्योगिक नगर में श्रमिकों की सोवियत बन गईं। सन् १९५५ की क्रांति अचरित रही। नारशाही ने सोवियतता का अवैधानिक घोषित कर दिया, परन्तु नाल्शेविक नेता अधिकाधिक स्थानों में श्रमिकों और कृषकों की सोवियतें स्थापित कराने में प्रयत्नशील रहे।

सन् १९१७ में क्रांति आरम्भ होने के साथ ही समस्त रूस में फिर से सोवियतों की स्थापना हुई। इस बार न केवल श्रमिकों की सोवियतें बनीं, बल्कि कृषकों और सैनिकों की भी सोवियतें बनीं। फरवरी क्रांति के बाद रूस में दो राजशक्तियाँ थीं। केंद्र में करेन्सकी के नेतृत्व में सांविधानिक तथा प्रजातन्त्रात्मक शासन चलाते वाले लोगों की सरकार थी और नगरों तथा ग्रामों में श्रमिकों, कृषकों और सैनिकों की सोवियतें थीं। मार्च १९१७ में पेजोग्राद में हुए एक सम्मेलन में एक अखिल रूसी कांग्रेस का संगठन करने का निश्चय किया गया। जून में उस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और अक्टूबर में द्वितीय। द्वितीय अधिवेशन के समय ही रूस में नाल्शेविक क्रांति हो गई। देश का प्रशासन चलाने के लिए द्वितीय कांग्रेस ने एक जन कमिसार परिषद का निर्माण

^१Pok ovosky, *Brief History of Russia* p 153

किया। सन् १९२४ में सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ (U S S R) का निर्माण होने पर अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का स्थान अखिल सघ सोवियत कांग्रेस ने ले लिया।

सन् १९२४ के सविधान के द्वारा सोवियतों की एक उत्तरोत्तर व्यवस्था (Hierarchy) निर्मित की गई। निम्नतम सोवियतों अर्थात् नगर तथा ग्राम सोवियतों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष तथा खुले मतदान के द्वारा किया जाता था। निम्न सोवियतों उच्च सोवियतों के सदस्यों को निर्वाचित करती थीं और उच्च सोवियतों उच्चतर सोवियतों के सदस्यों को। इस उत्तरोत्तर व्यवस्था की चोटी पर अखिल सघ सोवियत कांग्रेस (All Union Congress of Soviets) थी। यह कांग्रेस एक केन्द्रीय कार्यकारी समिति को निर्वाचित करती था, जो वास्तव में सोवियत सघ के विधान मंडल के रूप में कार्य करती थी।

सन् १९३६ के सविधान ने द्वारा सारियतों की पद्धति तो जैसी की तैसी रखी, परन्तु उनके संगठन की प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये। अब निम्नतम स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक की सोवियतों के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं।^१ सन् १९२४ के सविधान में कृषकों की तुलना में नगरों के श्रमिकों को सारियत कांग्रेस में अधिक प्रभार शाली प्रतिनिधित्व दिया गया था परन्तु सन् १९३६ के सविधान ने इस विषयता का अन्त कर दिया। प्रथम सविधान में सोवियतों के चुनाव व्यवसाय के आधार पर कराने की जो व्यवस्था थी उसका भी सन् १९३६ के सविधान ने अन्त कर दिया। अब सोवियतों का चुनाव प्रादेशीय आधार (Territorial basis) पर होता है।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार न केवल सोवियत सघ और सघ-गणराज्यों के ही, प्रत्युत स्थानीय सोवियतों के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी अत्यन्त

^१ Members of all Soviets of Working People's Deputies are chosen by the electors on the basis of universal equal and direct suffrage by secret ballot —Art 134 of the Constitution of U S S R

महत्त्वपूर्ण है। इसी कारण स्थापित संविधान में उन्हें 'राज्य शक्ति' की स्थानापन्न सरथाएँ कहा गया है। "स्थानीय सोवियतें अपने क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का निर्देशन करती हैं आप-व्ययक्त बनानी हैं, सर्व-जनिक व्यवस्था का स्वरूप विभिन्न प्रकार के पापन तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है एवं देश की प्रतिरक्षा की सामर्थ्य (Defensive Capacity) को बढ़ाने में योग देती हैं।"

प्रत्येक स्थानीय सोवियत एक कार्यकारिणी समिति निर्वाचित करती है, जो अपने कार्यों के लिए ज़म्मेदार प्रति उत्तरदायी होती है। इस कार्यकारिणी समिति में एक समापन, एक उप-समापन, एक मंत्री तथा कुछ सदस्य होते हैं। निम्न स्तरों की कार्यकारिणी समिति उच्च स्तरों की कार्यकारिणी समितियों के प्रति भी उत्तरदायी होती हैं। इसी उत्तरोत्तर व्यवस्था के द्वारा शासन में एकमूर्तता (Co-ordination) लाई जाती है।

केन्द्रिय विधानमंडल में दो सभाएँ हैं—सोवियत संघ के केन्द्रीय विधानमंडल (सर्वोच्च सोवियत) में दो सदन हैं। एक सदन का नाम है सोवियत संघ (Soviet of the Union) और दूसरे का जातिक सोवियत (Soviet of the Nationalities)। दोनों सदन का निर्वाचन सोवियत संघ के समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से, एक ही समय पर तथा समान कार्यकाल के लिए किया जाता है। केवल दोनों सदन के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन क्षेत्र निश्चित करने की पद्धति में अंतर है। संघ सोवियत के निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। परंतु जातिक सोवियत के निर्वाचन क्षेत्र एक दूसरी ही पद्धति से निश्चित किए जाते हैं। संविधान में यह निश्चित कर दिया गया है कि प्रत्येक संघ राज्य, स्वायत्तशासी गणराज्य स्वायत्तशासी प्रदेश तथा राष्ट्रीय क्षेत्र जातिक सोवियत के किनारे सभ्य निर्वाचित करेगा। इसी आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिभाषित किया जाता है।

संविधान में सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन का समान अधिकार प्रदान

किए गए हैं। कोई विधि तभी अंगीकृत समझी जाती है जब उस सर्वोच्च सविधान के दोनों सभों में सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाए। रूसी संसद को विधियाँ के संपादन करने में समान अधिकार प्राप्त हैं।^१ रूसी संसद की मुख्य बैठक की अध्यक्षता सर्व सार्वभौम तथा जातिक सार्वभौम और सभापति गरी गरी में करते हैं।^२ दोनों सभों में किसी प्रश्न पर मतभेद होने का दशा में एक समायोजन आयोग (Conciliation Commission) नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। परन्तु, यदि किसी भी दशा में दोनों सभों में मत विवाद का अन्त न हो सके तो प्रेसीडियम दोनों सभों को विघटित कर नए निर्वाचन कराएगा। रूसी संसद में एक उच्च निर्वाचन प्रणाली तथा शासकों का दृष्टि से ही साम्य है, यहाँ उनकी सर्व सभों में भी अधिक प्रभुत्व नहीं है। वस्तुतः, सावधान और शास्त्र पर आधारित समय स्तानिन ने एक संपादन का समर्थन किया था जिसमें यह व्यवस्था जोर देकर की जा रही थी कि सर्वोच्च सार्वभौम के दोनों सभों की सम्यक् सहायता समान होनी चाहिए। स्तानिन ने अपना मत व्यक्त किया कि रूसी संसद की सदस्य संख्या समान होने में राजनीतिक लाभ स्पष्ट है, क्योंकि यह दोनों सभों की समानता पर जोर देता है।^३ प्रथम सर्वोच्च सार्वभौम में सर्व सार्वभौम तथा जातिक सार्वभौम की सदस्य संख्या लगभग समान (क्रमशः १६६ तथा ५७४) थी। परन्तु बाद में निर्वाचित सर्वोच्च सार्वभौम में दोनों सभों की सदस्य संख्या का अन्तर बढ़ा दिया गया। सन् १९४६ में निर्वाचित सर्वोच्च सार्वभौम में सर्व सार्वभौम तथा जातिक सार्वभौम की सदस्य संख्या क्रमशः ६८२ तथा ६५७ थी।

यद्यपि संसार में अधिकांश प्रजातान्त्रिक शासन वाले देशों में द्विसभात्मक विधान प्रचलित है परन्तु रूसी संसद की संरचना में समानता स्थापित करने में वैसी व्यवस्था नहीं पायी जा सकी है। ब्रिटिश संसद (House of Lords) कामस संसद द्वारा पारित विधियों को करने कुछ काल तक निर्वाचित कर

^१ अनुच्छेद ३६

^२ अनुच्छेद ३८

^३ अनुच्छेद ४५

सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यद्यपि विधि निर्माण में दोनों सत्रों के अधिकार समान हैं, परन्तु दोनों सत्रों को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी विशेष शक्तियाँ के अधिक महत्वपूर्ण होने का कारण हा अमेरिका की सিনेट (Senate) प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई है। भारत की संसद के दोनों सत्रों में प्रथम सत्र, लोक सभा, निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उस राज्य परिषद् से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत की संसद का द्वितीय सत्र तो और भी अधिक शक्तिहीन है क्योंकि संविधान में स्पष्ट लिखा है कि 'अकेली राष्ट्रीय सभा (निम्न सत्र) ही विधियों को पारित करेगी। वह अपने इस अधिकार का प्रत्याभुत नहीं कर सकती।' भारत की संसद का द्वितीय सदन, गणराज्य परिषद् (Council of the Republic) केवल विचार करने वाली परिषद् है जो राष्ट्रीय सभा का समक्ष अपने सुझाव रख सकती है। इस तुलनात्मक निष्कर्षना से हम इसी परिणाम पर पहुँचा हैं कि विधान मन्त्रालय दोनों सत्रों का बीच जितनी अधिक समानता सोवियत संघ में है उतनी अन्य किसी देश में नहीं।

प्रेसीडियम एक अनुपम शासन संस्था—सोवियत संघ की सर्वोच्च सत्रियत का प्रसीडियम सोवियत शासन की स्थायी रूप से कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनो द्वारा एक संयुक्त बैठक में किया जाता है। रचना की दृष्टि से प्रसीडियम में एक अध्यक्ष, सोलह उपाध्यक्ष, एक मंत्री तथा पन्द्रह अन्य सदस्य होते हैं।^१ अपने समस्त कार्यों के लिए प्रसीडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है।

स्तालिन ने संविधान के प्रारूप पर भाषण देते हुए प्रसीडियम को सत्रियत संघ का सामूहिक अध्यक्ष (Collective President) बताया था अर्थात् पार्ष्वात्य गणतंत्रों में जो कार्य राष्ट्रपति के द्वारा संपादित किए जाते हैं वही कार्य

^१ The National Assembly shall vote the laws. It may not delegate this right — Art 13 of the Constitution of the French (Fourth) Republic

^२ अनुच्छेद ४८

सोवियत सभ में प्रेसीडियम को सौंप गए हैं। इस दृष्टि से हम प्रेसीडियम को शासन का कार्यार्ह (Executive) कह सकते हैं। परन्तु सोवियत सविधान में शासन के एक अन्य अंग को कार्यार्ह घोषित किया गया है। यह अंग है मन्त्रिपरिषद् जो कि सोवियत सभ की वास्तविक कार्यपालिका है। यद्यपि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रेसीडियम के कार्य केवल कार्यपालिका संबंधी कार्य तक ही सीमित नहीं हैं। सर्वोच्च सोवियत के विराम काल (Recess) में प्रेसीडियम आह्वितिया (decrees) और अध्यादेश (Ordinances) जारी कर सकता है जो कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियाँ के समान ही प्रभावी होती हैं। यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के अगले सत्र में इनको विधि का रूप देने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, परन्तु यह अनुमति सदैव ही प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से प्रेसीडियम को विधानांग (Legislative organ) भी कह सकते हैं। अतः में, प्रेसीडियम को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जैसे सोवियत सभ की विधियाँ का निवचन (Interpretation) करना, समाधान करना, तथा सोवियत सभ तथा सभ-गणसभों की मन्त्रिपरिषदों के निर्णयों को विधि के अनुरूप न होने पर रद्द करना, आदि। इस कारण इसे एक न्यायिक समिति (Judicial Committee) भी कहा जा सकता है। व्यवहार में प्रेसीडियम अपनी अधिक शक्तियाँ का प्रयोग करता है कि अन्य देशों की किसी सामान्य सभा से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

विधान मानकिक प्रधानता (Legislative Supremacy)—सोवियत सविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत सभ में शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है। अनुच्छेद ३२ में कहा गया है कि सोवियत सभ की विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग अनन्य रूप से (Exclusively) सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद ६४ में सोवियत सभ की मन्त्रिपरिषद् को सर्वोच्च कार्यकारी तथा प्रशासनीय सत्ता घोषित किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद १४ में सोवियत सभ के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक सत्ता कहा गया है। परन्तु सविधान के समस्त उपबंधों की गंभीरता पृथक् निवचना करने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत सभ में

शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को कभी मान्यता नहीं दी गई। माक्सवादी नेक सदा से शक्ति पृथक्करण के प्रबल प्रालाचक रहे हैं और उस समय में राज भी उनसे मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सोवियत संघ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त अंगीकृत नहीं किया गया है यह तथ्य नती से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में मन्त्रि परिषद् प्रभाविम तथा सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था है। मन्त्रि परिषद् तथा प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति अपने सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं। यद्यपि संविधान में सिविल बनाने का अधिकार केवल सर्वोच्च सोवियत को दिया गया है परन्तु प्रेसीडियम एवं मन्त्रि परिषद् भी समय-समय पर आसिया विनिरचय तथा प्राप्ति जारी कर सकते हैं जो विधि का समान ही प्रभारी होती है। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि प्रेसीडियम के कृत्यों में कार्यकारी सचिव, विधायी तथा न्यायिक तीनों ही प्रकार के कृत्यों सम्मिलित हैं। यह तथ्य भी इसी परिणाम की ओर गति करता है कि सोवियत संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मान्यता नहीं दी गई है।

सांविधानिक उपस्था (Provision) के अनुसार सर्वोच्च सभियन, अर्थात् विधान मण्डल ही सोवियत शासन का सर्वप्रधान अंग है। इसी ऊपर उल्लेख किया जा चुका है प्रेसीडियम और मन्त्रि परिषद् उसके प्रति उत्तरदायी हैं तथा उसके द्वारा बनाए हुए विधि का अनुसार कार्य करते हैं। अनरिका के राष्ट्रपति के समान उन्हें सर्वोच्च सभियन के निर्णयों पर विरोध प्रहार का अभिप्रेषाधिकार (Veto) प्राप्त नहीं है। सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का निर्वाचन (Interpretation) करने की शक्ति भी नहीं दी गई है। सर्वोच्च सभियन के विरोध निषेध का संविधान के प्रतिष्ठित होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय के विरोध नहीं कर सकता। संविधान में सर्वोच्च सोवियत की सर्वप्रधानता का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद ५ के अनुसार सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत सोवियत संघ की राजसत्ता की सर्वोच्च संस्था है। इस कारण हम सोवियत संघ की गिनती उन देशों में कर सकते हैं जहाँ के संविधानों में विधानमण्डलिक प्रधानता के सिद्धान्त को अंगीकृत कर लिया गया है।

संवैधानिक दृष्टि से विचार करने पर हम सोवियत संघ की शासन प्रणाली

का मिश्रित संसदीय (parliamentary) प्रणाली के अनुरूप होते हैं। परन्तु यहार में दोषों में महान् अंतर है। संसदीय शासन प्रणाली के लिए संसद तथा देश में विरोधी पक्षों का होता समतुल्य माना जाता है परन्तु सोवियत संघ तथा उसकी सर्वोच्च सोवियत में कोई विपरीत राजनीतिक पक्ष नहीं है। इसी कारण सांविधानिक ऋति से कार्यपालिका पर सर्वाधिक सोवियत का पूर्ण नियंत्रण होता हुआ भी, यहार में वह पक्ष उसका नियंत्रण का अनुमथन (ratification) करने वाली संस्था सिद्ध हुई है।

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के उपकरणों में व्यवस्था—वर्तमान संघों के विभिन्न आचार और निश्चित जनसंख्या के कारण प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (Direct democracy) अथवा भूतकाल की समुदाय जनता का रहा है। ग्राम सभाएँ ४ किमी भी प्रमुख राज्य में शासन प्रणाली प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र व्यवस्था के आधार पर नहीं चलायी जाती। सिस्टीम के कुछ कैबिनेट में अग्री भी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र शासन प्रणाली का प्रचलन है, परन्तु वहाँ भी अथ इसकी सफलता के प्रति शकायत की गई है। संसार में समाज प्रजातन्त्रात्मक पक्षांश में अथ जनतन्त्र की प्रातिनिधिक प्रणाली अंगीकृत कर ली गई है। कुछ संघों के सर्वोच्चतम में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के उपकरण (Instruments) — लोक निर्णय (Referendum) उद्घम (Initiative) तथा प्रयास (Recall) — की व्यवस्था की गई है। इन उपकरणों के द्वारा जनता का अपने प्रतिनिधियों के कर्तव्यों पर नियंत्रण रखने का अंतरात्मा ज्ञात होता है।

सोवियत संघ के संविधान में लोक निर्णय तथा प्रयास का ही व्यवस्था है परन्तु की नहीं। संविधान के अनुच्छेद ६८ के अनुसार सर्वाधिक सोवियत का प्रस्तावित स्व विवेकानुसार या किन्हीं एक संघ संस्थाओं की मार पर राष्ट्रपति मतदान (लोक निर्णय) का संचालन करता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि सोवियत संघ में नागरिकों का मार्ग पर लोक निर्णय कदाचित् की व्यवस्था नहीं है। १ मई १९३७ में सम्मिलित संविधान के प्रवर्तन होने से अथ तक सोवियत संघ में लोक निर्णय का वास्तविक प्रयोग नहीं हुआ है।

१ सिस्टीम के संविधान में १, ० स्थित नागरिकों को संघ विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधि पर लोक निर्णय का मार्ग करने का

सोवियत सभ के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह अपने किसी प्रतिनिधि के कार्य से असुष्ट हों तो वे उस प्रत्यावर्तित (recall) कर सकते हैं। किसी प्रतिनिधि को प्रत्यावर्तित करने का नियम निवाचकों के बहुमत द्वारा किया जाना चाहिए।

✓ निर्वाचित न्यायालय—विभिन्न राज्यों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं। ब्रिटेन में न्यायाधीशों का नियुक्त लाइ चान्सलर (Lord Chancellor) द्वारा का जाता है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कङ्ग्रेस द्वारा की जाने का व्यवस्था है।^१ परन्तु वहाँ प्रतिबंध यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमूर्धन सेंनेट (Senate) द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ देशों के संविधानों में राज्याधीशों के विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ स्विट्स सभाय न्यायालय के सदस्यों का निवाचन संघीय विधानमण्डल के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में न्यायाधीशों का चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निवाचित किए जाने की व्यवस्था है। सोवियत सभ के संविधान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विधानमण्डल द्वारा निवाचित किए जाने तथा निम्नतम न्यायालयों (People's Courts) के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है। सोवियत सभ का सर्वोच्च न्यायालय या विशेष न्यायालय सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।^२ सभ-गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय सभ गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।^३ प्रदेश, क्षेत्रों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों के न्यायालय उनकी 'भूमि बीड़ी जनता के प्रतिनिधियों की सोवियतों' (Soviets of Working People's Deputies) के द्वारा निवाचित किए जाते हैं।^४ निम्नतम भेरी के न्यायालयों अधिकार दिया गया है। उनका द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर उस विधि का चुनाव के समान उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रखा जाता है।

^१ अनुच्छेद १०५

^२ अनुच्छेद १६ तथा १७

^३ अनुच्छेद १८

का लोक-न्यायमण्डल (People's Courts) कर्त हैं और वे जिसे क नागरिकों द्वारा सबव्यापक, प्रत्यक्ष तथा समान मताधिकार के आधार पर चुने मन्तान के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।

न्यायाधीशों के चयनता या विधानमण्डल द्वारा निर्वाचन किय जाने का प्रणाली का विरुद्ध मुख्यतः कहा दिया जाता है कि इसके द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन भी राजनैतिक दलबन्दी के आधार पर होता है प्रणालियों का योग्यता के आधार पर नहीं। परन्तु सोवियत संघ में केवल एक राजनैतिक दल है। वहाँ प्रत्येक न्यायाधीश के लिये यह एक गुण समझा जाता है कि वह मार्क्सवादी सिद्धांत का ज्ञान हो और पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) के निर्णय का हृत्पात्रक कार्यान्वित करने की क्षमता रखता हो।^१ ऐसी स्थिति में राजनैतिक दलबन्दी का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल उहाँ न्यायाधीश का न्यायाधीश-पद पर निर्वाचित होना समझ है ता नहीं द्वारा समर्थित हो।

योजनाबद्ध एवं सुनिश्चित अर्थ-व्यवस्था—जहाँ अन्य देशों का अधिकांश पद्धति पर आधारित होने के कारण अनिश्चित होता है वहाँ सोवियत संघ का अर्थ-व्यवस्था पूर्णरूपेण नियंत्रित तथा योजनाबद्ध है। यहाँ उत्पादन वस्तु के लिए कितनी नहीं रहने सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाता है। यहाँ कारण है कि सोवियत संघ में अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होने वाली मनी की स्थिति कभी नहीं आने पाती। वहाँ कौन सी वस्तु कितना मात्रा में उत्पादित की जानी चाहिए, इसका नियंत्रण करना राज्य का काम है। सविधान के अनुच्छेद ११ में स्पष्ट उल्लेख है कि सोवियत संघ के आर्थिक जीवन का निष्पत्ति तथा निर्देशन राज्य की राष्ट्रीय आर्थिक योजना द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक सम्पत्ति में वृद्धि करना, महानतम जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक सारों में उत्तरात्तर

^१ If the judge is a poor Marxist who does not know the party decision is unable to fight strongly enough for the party decisions and lets himself be led by local organizations he is no good —Kalinin's Speech at the tenth anniversary celebration of the Supreme Court

वृद्धि करना, सोवियत संघ की स्वतंत्रता को नष्ट करना और उसकी प्रतिरक्षा शक्ति (defensive cap city) को अधिक शक्तिशाली बनाना है। यह इसी नियंत्रित तथा योजनाबद्ध प्रथनीति का परिणाम था कि जिस समय संसार के अन्य सभी देश आर्थिक संकट के परिणामों का सामना कर रहे थे, उस समय सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के आर्थिक विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा था।

पार्टी का शासन पर कठोर नियंत्रण—सोवियत शासन और सोवियत संघ का कम्युनिस्ट पार्टी में कोई प्रत्यक्ष संबंध न होते हुए भी पार्टी का शासन के प्रत्येक अंग पर कठोर नियंत्रण रहता है। यह तथ्य सोवियत नेता स्वयं स्वीकार करते हैं। स्तालिन ने स्वयं कहा है—‘पार्टी यह खुले रूप में स्वीकार करती है कि वह शासन का परम प्रदर्शन करती है तथा उसका सामान्य निर्देशन करता है।’^१ ‘यन्त्रहार सही सिद्ध हुआ है कि हमें सोवियत संघ में ‘सर्वहारा के अधिनायकत्व’ (Dictatorship of the Proletariat) का अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकत्व ही समझना चाहिये। सोवियत संघ का वर्तमान संविधान पार्टी की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार करता है। संविधान में पार्टी का समाजवादी प्रणाली का सुदृढ़ तथा विकसित करने के लिये किये जाने वाले संघर्ष में भूमिनीय जनता का नेतृत्व करने वाला वर्ग (Vanguard), तथा भूमिनीय जनता की सभी राजकीय और सार्वजनिक संस्थाओं का नेतृत्व करने वाला संगठन कहा गया है।^२ कम्युनिस्ट पार्टी ही एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सोवियत नागरिकों का संगठित होने का अधिकार दिया गया है तथा जिसे निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी नामांकित करने का अधिकार दिया गया है। यद्यपि संविधान में अन्य भी ऐसी संस्थाओं के नाम उल्लिखित हैं जो प्रत्याशियों का नामांकित कर सकती हैं, परन्तु वे सभी अराजनीतिक संस्थाएँ, हैं उदाहरणार्थ श्रमिक संघ, सहकारी संस्थाएँ, युवक संगठन तथा सांस्कृतिक

^१ The party openly admit that it guides and gives general direction to the government Stalin as quoted by Ogg & Zink *op cit* p 812

संस्थाएँ।^१ सोवियत प्रवक्ताओं तथा लेखकों के अनुसार राजनीतिक दलों का नाम किंवा वर्ग विशेष के हितों का पोषण और संरक्षण करने के लिये होता है। इसलिये निम्न देशों में अनेकों विरोधी हितों वाले वर्ग होते हैं वही उन वर्गों के हितों का संरक्षण करने वाले अलग-अलग राजनीतिक दल भी होते हैं। “सोवियत संघ में अनेक वर्गों दो वर्ग हैं—श्रमिक और कृषक, जिनके हित एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं परन्तु एक दूसरे के सहायक हैं। अतः सोवियत संघ में अनेक राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं थी और इसलिये इन दलों का स्वतन्त्रता का भी प्रश्न नहीं उठता।”^२

सोवियत संघ में शासन पर पार्टी का प्रभाव का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विधानमण्डल के सभी सन्स या तो पार्टी के सदस्य होते हैं या पार्टी द्वारा समर्थित होते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका तथा मायपालिका के विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित होने के कारण उनका सन्स भी पार्टी के विश्वासमान व्यक्ति ही होते हैं। शासन के सभी उत्तरदायी पदों पर मार्क्सवादी में पूर्ण आस्था रखने वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। पार्टी की सभी शाखाएँ अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि रखती हैं और पार्टी की नीति के तत्त्वों का प्रतिकूल जाने की दशा में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

जनतांत्रिक केन्द्रवाद—सोवियत संघ में शासन पर पार्टी का प्रभाव का एक ऐसा तथ्य है जिसके विषय में दो मत नहीं हो सकते। सामंतीय शासन प्रणाली वाले देशों के नागरिक यह नहीं समझ पाते कि विरोधी दल का प्रभाव में प्रभाव का अस्तित्व किस प्रकार सम्भव हो सकता है। इसी कारण सोवियत संघ का प्रायः अप्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था या अधिनायकत्व वाले देशों में माना जाता है। परन्तु सोवियत नेता अपने देश की शासन प्रणाली को जनतन्त्रवादी केंद्रवाद (Democratic Centralism) के नाम से संज्ञाधन करते हैं। जनतन्त्रवादी केंद्रवाद का अर्थ यह बताया जाता है कि किसी विषय

^१ अनुच्छेद १४१

^२ Stalin *On the Draft Constitution of the U S S R* p 41

पर नीति निर्धारित किए जाने के पूर्व जनता तथा समस्त संस्थाओं का उस पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। जनता का मत जानने के पश्चात् शासन की सर्वोच्च संस्थाएँ नीति के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करती हैं। यह निर्णय जनता की इच्छा के अनुरूप ही होता है। इसका कारण यह है कि जनता को सोवियतों में अपने प्रतिनिधियों को जो कि प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय करते हैं, प्रत्यावर्तित (recall) करने का अधिकार दिया गया है। किसी प्रश्न पर निर्णय किए जाने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का बाद विवाद नहीं चलने दिया जाता। इसे हम अपने मत के अनुसार सोवियत शासन प्रणाली का शुभ प्रथवा दोष मान सकते हैं।

अध्याय ५

संविधान की एक प्रमुख विशेषता उसमें उल्लिखित नागरिकों के मूलाधिकार तथा कानून हैं। संविधान में नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख करने की परंपरा अबीन नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है। अन्य प्रमुख देशों के संविधानों में भी अधिकार पत्र (Bill of Rights) सम्मिलित किया गया है। प्रथम संविधान - पश्चात् निर्मित जर्मनी का वेइमर संविधान (Weimar Constitution), तथा प्रसिद्ध नतीज का संविधान में मूलाधिकारों का उल्लेख था। आयरलैंड का संविधान और भारत का संविधान में भी नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख है। अमेरिकन संविधान में अधिकार पत्र के अन्तर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं है परन्तु उसमें उनके अनुच्छेदों में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों का मूल अधिकारों से समान ही है। संविधान सभा के अन्तर्गत संविधान के अनेक भागों में हमें पश्चात्गत देशों के संविधानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। संविधान सभा के दृष्टि में, जिसमें नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं में से एक है। परन्तु ऐसा हाथ हुए भी संविधान के अधिकार पत्र (Bill of Rights) का अन्तर्गत विशेषता है। ऐसा अधिकार पत्र हमें जहाँ एक संविधान देश के संविधान में हाँ मिल सकता है। कर्तव्यों के अन्तर्गत संविधान के अधिकार पत्र की इसी विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है 'संविधान सभा संविधान संविधान नागरिकों का ऐसा अधिकार और ऐसा स्वतन्त्र प्रदान करता है जो कि अमेरिकन देश में न मिल सकती है और न पाई जा सकता'।

है।^१ फ्रेडरिक आग आर हेराल्ड जिक न भी सोवियत संविधान व अधिकार पत्र का 'इतिहास के सर्वाधिक असाधारण अधिकार पत्रों में से एक माना है।^२ स्तालिन संविधान में उल्लिखित नागरिकों व अधिकारों की इस विशिष्टता व कारण उनका कुछ विस्तार के साथ अध्ययन आवश्यक है।

सन् १९२६ की परिवर्तित परिस्थिति—सन् १९२८ में प्रवर्तित सोवियत संघ (R S F S R) व संविधान तथा सन् १९२४ में प्रवर्तित सोवियत संघ (U S S R) के प्रथम संविधान में नागरिकों व अधिकारों का उल्लेख नहीं था। सन् १९२८ के संविधान में प्रस्तावना के रूप में 'जनजीवी तथा शोषित जन' व अधिकारों का घोषणा प्रवर्णन सम्मिलित थी, परन्तु उसमें नागरिकों व उस अधिकारों का उल्लेख नहीं था जिन्हें सामान्यतः मूल अधिकारों के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस घोषणा में भूमि रहित पदाथों, वना, कारखाना, रेलों आदि व राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई थी तथा यह कहा गया था कि सन् १९२८ की भूमि का 'सामयिक' रैंडवार के आधार पर उपयोग कर सकेंगे। सोवियत शासन को उस समय भीषण आंतरिक उपद्रवों का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में संविधान द्वारा नागरिकों व अधिकारों का प्रत्याभूति किए जाने की आशा नहीं की जा सकती। सन् १९२३ में सोवियत संघ के प्रथम संविधान के निर्माण के समय यद्यपि यह युद्ध तथा बाह्य दशों व हस्तक्षेप का अन्त हो चुका था परन्तु क्रांति विरोधी (Counter Revolutionary) शक्तियाँ व पुनः पतन की संभावना थी। सन् १९३६ में स्तालिन संविधान के निर्माण के समय तक स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था। शासनार्हक हल अपने समस्त पिशाचों पर पूर्ण विजय पा चुका था और समस्त क्रांति विरोधी तत्त्वों का दमन किया जा चुका था। इसीलिए स्तालिन संविधान में नागरिकों व मूल अधिकारों का उल्लेख कर तथा उनमें ऐसे अनेक

^१ The Stalin Constitution grants Soviet citizens rights and liberties that do not and cannot exist in any of the capitalist countries—V K spinshy *op cit* p 148

^२ 'One of the most extraordinary bills of rights known to history—F A Ogg & H Zink *op cit* p 852

अधिकार सम्मिलित कर वा अन्य देशों में नागरिका का प्राप्ति नहीं है, यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सोवियत संविधान अन्य सभी देशों के संविधानों से अधिक जनताधिकारिक है।

स्तालिन संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूलाधिकार

स्तालिन संविधान में नागरिका के निम्न मूलाधिकार तथा स्वतंत्रताओं का उल्लेख है संक्षेप में वह निम्नलिखित हैं —

१. कार्य पाने का अधिकार
२. विश्राम तथा अवकाश का अधिकार
३. भौतिक सुरक्षा का अधिकार
४. शिक्षा पाने का अधिकार
५. समानता का अधिकार
६. धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार का स्वतंत्रता
७. नागरिक स्वतंत्रताएँ
८. सांस्कृतिक संगठन बनाने का अधिकार
९. वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार

सोवियत नागरिका के मूलाधिकारों को इन उनके प्रकृति के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वेग हैं (१) आर्थिक अधिकार, (२) सामाजिक अधिकार तथा (३) राजनैतिक अधिकार। स्तालिन संविधान द्वारा प्रदत्त राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकार अन्य देशों के नागरिकों के अधिकारों के समान ही हैं। उनका विशेषता यह है कि उनमें साथ कुछ ऐसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रताएँ शामिल हैं जो इन अधिकारों का उपयोग गति पूर्ण रूप से नहीं वा एक बहुत बड़ा सामाजिक अवस्था नष्ट कर देते हैं। परन्तु सोवियत संविधान के अधिकार-पत्र का विशेषता उसमें आर्थिक अधिकार हैं। ये अधिकार किसी असामान्य देश के संविधान में नहीं पाए जाते। कुछ लेवक इन अधिकारों का सकारात्मक (positive) अधिकार के नाम से भी संशोधित करने हैं। टाउमर ने मतानुसार नवम्बर संविधान के अधिकार-पत्र में सोवियत संघ ने निम्नलिखित स्वतंत्रताओं का दृष्टि से परस्पर अनुकरण किया है,

परंतु रचना मक स्वतंत्रताओं को स्थान देकर इसने अन्य देशों का माग-गन किया है।^१ अधिकार-पत्र में आर्थिक अधिकारों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से पहले स्थान दिया गया है यह तथ्य समाजवादी सिद्धान्तों के अनुरूप हो है। समाजवादीयों का निश्चित मन है कि आर्थिक अधिकारों की अनुस्थिति में राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार अर्थहीन होते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अब सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ के संविधान में आर्थिक अधिकारों का उल्लेख है, अन्य कम्युनिस्ट देशों के संविधानों में भी इनका उल्लेख किया गया है।^२

काम पाने का अधिकार

संविधान में इस अधिकार की व्याख्या करते हुए इसका अर्थ यह बताया गया है कि सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक को रोजगार पाने तथा अपने कान का माया और गुण के अनुसार पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। यह अधिकार राष्ट्रीय अर्थ-प्रस्था व समाजवादी संगठन, सोवियत समाज की उत्पादक शक्तियों की निरंतर वृद्धि आर्थिक सकल की संभावना की समाप्ति तथा बरोजगारी व उन्मूलन के द्वारा सुरक्षित किया गया है।^३ इस अधिकार को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर हमें कार्पिन्स्की व उस समय से मिलता है कि सोवियत युवक यह जानता ही नहीं कि बरोजगारी क्या है।^४

^१ In the Bill of Rights of the new constitution the Soviet Union has followed the Western democracies with regard to the negative freedoms while it has proceeded in the introduction of positive freedoms. Julian Tawney cit p 382.

^२ देखिए लोक गणराज चीन (People's Republic of China), के संविधान के अनुच्छेद ६१ तथा ६३।

^३ अनुच्छेद ११८

V. K. Puri cit p 140

नागरिकों के मूलाधिकार तथा कर्तव्य

अन्तर्वर क्रांति के समय बोलशेविक दल के कार्यक्रम का आधार प्रेमजीवी को समान पारिश्रमिक दिए जाने का सिद्धान्त था। लेनिन ने अन्तर्वर क्रांति के समय स्वयं अपने एक भाषण में कहा था कि क्रांति का पश्चात् एक प्रशासक (administrator) का एक कुशल श्रमिक से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। युद्ध कालीन साम्यवाद के काल (१९१८-२१) में इसी सिद्धान्त को कारगर देने का प्रयत्न भी किया गया था। परन्तु नवीन आर्थिक नीति के अंगीकार जाने पर इस सिद्धान्त के स्थान पर एक नया सिद्धान्त को अंगीकृत कर लिया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम की मात्रा और गुण के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। स्तालिन संविधान में भी इसी सिद्धान्त को मान्यता दी गई है और इसका इन शब्दों में उल्लेख किया गया है—“प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। इस सिद्धान्त का अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार कार्य करे तथा अपने काम के गुण और मात्रा के अनुसार प्रतिफल पाए। नवीन आर्थिक नीति के काल से पारिश्रमिक की असमानता में निरंतर वृद्धि होती रही है। तृतीय महायुद्ध के पश्चात् अल्पतम तथा अधिकतम पारिश्रमिक का अंतर पचास गुना तक हो गया था।^१ सोवियत प्रवक्ता वर्तमान व्यवस्था को समझाने के लिए साम्यवाद को आरंभ क्रांति के काल की व्यवस्था बताते हैं। साम्यवादी अवस्था में पारिश्रमिक का यह अंतर समाप्त हो जायगा।

सोवियत संघ के संविधान में उल्लिखित नागरिकों का काम पाने का अधिकार वास्तविक है यह देखी तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि सन् १९३३-३३ के आर्थिक संकट के काल में जब समस्त विश्व में बेकारों की संख्या बढ़ रही थी सोवियत संघ में किसी श्रमिक को काम पाने में कठिनाई नहीं होती थी।^२ यह वह समय था जब देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

^१ Lenin as quoted by Harper & Thompson in *Government of the Soviet Union* p. 174

^२ Harper & Thompson, *Ibid* p. 176

^३ “All during the 1930s when unemployment was a world phenomenon the Soviet worker had no difficulty in

औद्योगीकरण की महनी योजनाओं का कार्यान्वित किया जा रहा था। सन् १९२६ में सोवियत सच में बकारी का उन्मूलन कर दिया गया और तब से अमिका और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। सन् १९२८ में उनकी संख्या एक करोड़ पन्द्रह लाख थी। सन् १९३५ तक, अर्थात् सात वर्ष के समय में ही उनकी संख्या ढाई करोड़ हो गई। सन् १९४० तक यह संख्या तीन करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी थी।^२ यह देश के द्रुत गति से किए गए औद्योगीकरण, उत्पादन के साधनों पर समाज के नियंत्रण तथा अर्थ-व्यवस्था के समाजवादी आधार पर संगठित किए जाने के कारण ही संभव हो सका। द्वितीय महायुद्ध का समाप्ति के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूँजीवादी व्यवस्था वाले अन्य देशों में युद्ध सामग्रियों का उत्पादन करने वाले कारखानों का रुद्ध किए जाने या उनमें रुद्धनी किए जाने के कारण बेकारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। सन् १९४७ के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में बेकारों की संख्या ५७ लाख तक पहुँच गई थी। परन्तु सोवियत सच में ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि युद्ध काल में जो कारखाने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सामग्रियों का निमाण कर रहे थे उन्हें शांति काल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्रियों उत्पादित करने वाले कारखानों में परिणत कर दिया गया। अतः अतिरिक्त सोवियत सेना के सभी विमुक्त (discharged) सैनिकों का तुरन्त ही उपयोग या सामूहिक पानों आदि में काम दे दिया गया। अतः हमें विनिश्चित हाता है कि सोवियत सच में प्रत्येक नागरिक को जीवन निवाह के लिये काम मिलाना सरकार का उत्तरदायित्व है।

काम पान के अधिकार का एक दूसरा रूप भी है, जिससे परिचित होना हमारे लिए आवश्यक है। जहाँ राज्य नागरिकों को काम पाने का अधिकार प्रदान करता है वहाँ वह उनसे ऊपर पर्याप्त नियंत्रण भी रखता है। उनकी विचरण की स्वतंत्रता बहुत सीमित है। अधिकांश पूँजीवादी देशों के संविधानों

obtaining work on the contrary his difficulty consisted in his increasing inability to refuse it —Hopper & Thompson
The Government of the Soviet Union p 169

^२ See Tr. in The State Constitution p 14

में नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या उसने की स्वतन्त्रता का उल्लेख है। परन्तु सोवियत संघ के संविधान में ऐसा किसी स्वतन्त्रता का उल्लेख नहीं है। श्रमिकों को उनके निवास स्थान उनके काम करने के स्थान पर ही मिलते हैं। जब तक सोवियत संघ में रेशनिंग व्यवस्था जारी रही श्रमिकों को उनसे राशन का भी उनका काम करने के स्थानों पर ही मिलते थे। इस के अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक को एक कार्य पुस्तिका (Wage book) दी जाती है जिसमें उसके कार्य करने के स्थान, पारिश्रमिक, तथा कार्य के प्रकार आदि का विवरण दिया जाता है। जब तक पिछले कार्य स्थान के अधिकारी के द्वारा कार्य पुस्तिका में पदच्युति (dismissal) का आदेश का उल्लेख नहीं होता तब तक उन किताबें दूसरे स्थान पर कार्य नहीं मिल सकती। इस व्यवस्था के कुछ गुण भी हैं और दोष भी। यह श्रमिकों को साधारण स्थिति में एक ही स्थान पर कार्य करने के लिए विवश करती है जिसमें उनका कार्यक्षमता में वृद्धि होता है। इसका प्रमुख दोष यही है कि यह नागरिकों का एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर बसने की स्वतन्त्रता को प्रतिगन्धित कर देती है।

भौतिक सुरक्षा का अधिकार

सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक का वृद्धावस्था, अस्वस्थता या अगहनी होने का दशा में जीविका (maintenance) प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान में इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये तीन उपायों—कारखानों और कार्यालयों में काम करने वाले श्रमिकों तथा कर्मचारियों के लिए राजस्व पर सामाजिक बीमा व्यवस्था का प्रावधान, अगहनीयों के लिये नि:शुल्क चिकित्सा तथा उनके उपयोग के लिए स्थापित स्वास्थ्य केंद्र (Health resorts) के विस्तृत जाल की व्यवस्था का उल्लेख है।

प्रत्येक सोवियत श्रमजीवी को निवृत्ति वय (Age of retirement) पर पहुँचने पर राज्य की ओर से निवृत्ति वेतन (Pension) दिया जाता है। यह निवृत्ति वेतन निवृत्ति पाने वाले श्रमजीवी की औसत आय का ५ से ६ प्रतिशत तक होता है। यदि वह कार्य करना चाहे तो इसके पर भी वह कार्य

कर सकता है। ऐसे अमजबानों को अपना कार्य करते समय अगहिन हा जाते हैं, या ऐसे सैनिकों को अपने कर्तव्यों का पूर्ति करने में अपनी कार्यक्षमता से वंचित हा जाते हैं, अपनी औसत आय का ५ से १ प्रतिशत तक निवृत्ति वतन पाते हैं। यह व्यवस्था अस्थायी या स्थायी दोनों प्रकार से कार्यक्षमता से वंचित होने वाला व लिए है। ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से अपना कर्तव्य सच वंचित हो जाते हैं अपनी औसत आय का दो तिहाई भाग निवृत्ति वतन के रूप में पाते हैं। जिन व्यक्तियों को अपने पारिवारिक किसी अस्वस्थ सदस्य का देखभाल करने के लिए कार्य में अवकाश दे दिया जाता है वह भी इसी प्रकार निवृत्ति वतन पाते हैं। जिन परिवारों में सदस्यों के लिए चिकित्सापचार करने वाले एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के व्यवस्थापक या अन्य न कर सकने योग्य सदस्य को निवृत्ति वतन दिया जाता है। अधिकतर और सैनिकों के लिए जिस प्रकार का सामाजिक बीमा व्यवस्था का उल्लेख ऊपर किया गया है, सामूहिक फर्मों में काम करने वाले कृषकों के लिए भी ऐसी ही सुविधाओं का प्रबंध करना उनका सामूहिक फर्मों का कर्तव्य है। यद्यपि निवृत्ति वतन की प्रत्येक विधि द्वारा निर्धारित कर दी गई है परंतु अच्छा काम करने वाला को उनका कार्य के प्रतिकर के रूप में विशेष दरों पर निवृत्ति वतन दिया जा सकता है। प्रो. हार्पर और थॉमसन का कथन है कि इन पारितोषिका के वितरण में विशेष सुविधा या पक्षपात का तब सदैव अनुपस्थित नहीं रहा है। अर्थात् पक्षपात किए जाने के उदाहरण भी नहीं पाए जा सकते हैं।

सामाजिक बीमा व्यवस्था के साथ ही समस्त अमजबानों का चिकित्सा चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। समस्त अमजबानों को अपने घर पर, चिकित्सालय में या चिकित्सक की स्वीकृति से स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करने का सुविधा प्राप्त है। पट थॉम ने इस सुविधा का उल्लेख ही नहीं करना किया है "यदि आप एक सोवियत भूमिक हैं और आपका स्वास्थ्य अनुमति करते हैं तो आप सदैव अपने क्षेत्र के चिकित्सालय का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी तो यह चिकित्सालय आप के कार्यस्थान के ही

संबंध होते हैं। यदि आप का ताप (temperature) है या यदि आप चल नहीं सकते तो आप को चिकित्सक को अपने घर बुलाने का अधिकार है। यदि अस्पताल व उपचार की आवश्यकता होता है तो चिकित्सालय (clinic) आवश्यक प्रबंध कर देता है और जब आप वहां से मुक्त कर लिये जाते हैं तो आप पुनः स्वामत्तव्य के लिये चिकित्सालय की देख रेख में आ जाते हैं।^{१२} सन् १९५५ में लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए दो ग्राम बीन करो रूपय के निनियोग (appropriation) की व्यवस्था थी।

जय देशों से सोवियत संघ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की तुलना करके विभिन्न लोक भिन्न भिन्न परिणामों पर पहुँचे हैं। वहाँ एक ओर हमें सोवियत लोकों के अपने देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आतशयान्ति पूर्ण दावे मिलते हैं वहाँ दूसरी ओर हम ऐसे लोकों के कथन भी मिलते हैं जो उस अपूर्ण तथा प्रभावहीन बताते हैं। उदाहरणार्थ, हापर और थॉमसन का कथन है कि बड़े नगरों में भी लोक स्वास्थ्य में संशोधन और योगदान का कथन है कि बड़े नगरों में भी लोक स्वास्थ्य में संशोधन नैवाह्य अप्रयाप्त है तथा सदन तुरन्त उपलब्ध नहीं होता।^{१३} एक अन्य लेख, फ्लोरिन्सकी, का मत है कि नागरिकों की प्राण लागा की दृष्टि से निवारण करने पर सोवियत संघ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावहीन प्रतीत होता है।^{१४} पण्डित हम यह मान रखना चाहिये कि बोलशेविक क्रांति के पूरे रूस में जारशाही शासन था। जारवालीन रूस संसार के सर्वाधिक पिछड़े हुए देशों में था, तथा जनता का एक बड़ा भाग अत्यन्त कृषाजनक स्थिति में अपना जीवन यापन करता था। ऐसा हीन अवस्था से मुक्ति प्रदान कर उन्हें आधुनिक युग की सामान्य प्रदान करने का प्रयत्न

^{१२} Pat Sloan *Russia without Illusion* p 133

^{१३} Public health services are still inadequate even in the large cities however, and are not immediately available — Harper & Thompson *op cit* p 253

^{१४} Viewed from the standpoint of the benefits received by the citizens the social security program is singularly unimpressive — Florinsky M T *op cit* p 843

सोवियत शासन को ही है। आज भी पूँजीवादी व्यवस्था वाले अनेक देशों में श्रमजीवियों का वृद्धावस्था तथा रूग्णावस्था में अथवा अग्रहान हो जाने पर अत्यन्त कठिन परिस्थितियाँ का सामना करना पड़ता है। उनमें से उन्हा से ता जीविकोपानन का कोई साधन न होने के कारण भिक्षा वृत्ति अपना के लिए बाध्य हा जात हैं। नागरिका, विशेषतः श्रमजीविया क लिय, स्वास्थ्य सेवास्रा का पला प्रबन्ध सोवियत संघ में हे वंसा बहुत कम देशों में है। इस कारण सोवियत संघ में स्तालिन सविधान द्वारा नागरिका का प्रदत्त भौतिक सुखों का अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

विश्राम तथा अवकाश का अधिकार

स्तालिन सविधान में न रवल नागरिका का काम पाने का ही अधिकार दिया गया हे वरन् उन्हें विश्राम तथा अवकाश (leisure) का अधिकार भी दिया गया है। सविधान क अनुच्छेद ११६ की प्रथम धारा में कहा गरा है कि सोवियत संघ क नागरिकों का विश्राम तथा अवकाश का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का सुनिश्चित करने क लिए सविधान में जिन साधनों की व्यवस्था की गई है व निम्नलिखित हैं —

- १ कारखाना तथा कार्यालयों में कार्य करने वाले श्रमजीवियों के लिय आठ घंटे के दिन का नियत किया जाना
- २ श्रम साध्य यापारों क लिये कार्य दिवस (Working day) का घटा कर सात या छ घंटे किया जाना तथा ऐसी दूकानों में जहा श्रम परिस्थितिया विशेष रूप से श्रम साध्य हैं कार्य दिवस का चार घंटे नियत किया जाना
- ३ कारखाना तथा कार्यालयों क श्रमजीविया के लिये पूर्ण पारिश्रमिक सन्ति शारीरिक छुटिया का प्रचलन किया जाना, तथा
- ४ श्रमजीवी चनों क लिय स्वास्थ्य सन्नों (Sanatoria), विश्रामि गृहों, समा गृह (clubs) आदि की विस्तृत व्यवस्था।

यहा उह उताने की आवश्यकता नहीं है कि मानवीय चक्षित्व के विकास क लिए विश्राम और अवकाश का किनना महत्व है। सत्तेप में इतना ही कह

देना आवश्यक है कि किसी कार्य के करने में जो शक्ति बच की जाती है उसकी पूर्ति के लिए विराम अवलोकन आवश्यक है। परन्तु बहुत से देशों में आज भी श्रमिकों से इतना अधिक कार्य लिया जाता है कि उन्हें प्रवकाश हा नहीं मिलता। इससे परिणामस्वरूप अधिक शीघ्र ही श्रमबल और कम हो जाते हैं जिससे उनकी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। अधिक कार्य करने से कारण उनका जीवन शक्ति भी कम हो जाती है और वे अल्पकाल में ही कालकवलित हो जाते हैं।

सोवियत संघ में निर्माण के समय श्रमजीवियों के लिए सात घंटे का कार्य दिवस नियत किया गया था। सन् १९४४ में सर्वोच्च सोवियत ने श्रमजीवियों की एक शक्ति के द्वारा यह समय कम कर आठ घंटे कर दिया गया। शिवाय महायुद्ध के पर्यन्त पुनः सात घंटे का कार्य निश्चित किए जाने पर स्थान पर लविधान के अनुच्छेद २१६ में सर्वोच्च न्यायालय से कार्य निश्चित करने का कर दिया गया। अतः हम एक लक्ष्य श्रमजीवियों का अग्रसार दिया जाता है। इससे अतिरिक्त उन्हें अनेक पूर्ण वतन सहित वार्षिक छुट्टियाँ भी दी जाती हैं। महायुद्ध के काल में सामान्यतः श्रमिकों से प्रतिदिन नियत समय में तीन घंटे अधिक कार्य कराया जाता था, परन्तु महायुद्ध के पश्चात् यह प्रथा समाप्त कर दी गई है। वार्षिक छुट्टियाँ के अतिरिक्त श्रमिकों तथा कामचारियों को प्रत्येक वर्ष २५ दिन तथा उसके पश्चात् २८ दिन का विशेष छुट्टी मिलती है। शिशुओं का पालन करने वाली माताओं को प्रत्येक साढ़ तीन घंटे का आराम घंटे का अवकाश दिया जाता है।

सोवियत संघ में श्रम की आरंभ से विराम-काल स्थापित किए गए हैं, जहाँ सोवियत सरकारों एक निश्चित शुल्क लेकर टहर सकते हैं। यद्यपि यह कहना गलत होगा कि प्रत्येक श्रमिकों अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग कर सकते हैं परन्तु यह सत्य है कि श्रमिकों को अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। श्रमिकों के भूतकालीन कर्मचारियों के मकानों शाही महल, धनी श्रमिकों के ऊँचे-ऊँचे भवन तथा उपासना-गृह आदि को अब विराम-गृह और स्वास्थ्य केंद्रों का रूप दे दिया गया है। श्रमजीवियों के मनोरंजन के लिए अधिकतर नगरों में 'कल्चरल और विराम' के उद्यान (Parks for culture and rest) का प्रबंध किया

गया है। कारखानों में 'अमिका क क्लर्कों का स्थापना की गई है।' उस अतिरिक्त पुस्तकालयां, वाचनालयां, नाट्यशालायां, संग्रहालयां आदि का भी राज्य की ओर से प्रबंध किया गया है। जारशाही काल में अमजीनिया की टुरानस्था में तुलना करने पर, जब उन्हें चौदह चौदह घंटे तक अस्वास्थ्यप्रद स्थानों में कार्य करना पड़ता था और जब उन्हें अपने प्रकाश का समय उचित रीति से व्यतीत करने की कोई सुविधा न थी, यह परिणतन निश्चय ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है।

शिक्षा पाने का अधिकार

सावियत सघ के प्रत्येक नागरिक का सविधान द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।^१ उस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सविधान में निम्न व्यवस्थाओं का उल्लेख है —

- १ सार्वपाक तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा
- २ सातवां त्रेणी तक नि शुल्क शिक्षा
- ३ उच्च शिक्षण संस्थाओं के अपने अध्ययन में विशेष योग्यता प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों को राज्य का ओर से छात्र वृत्तियों का प्रबंध
- ४ विद्यालयों में मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना, तथा
- ५ कारखानों, राजकीय फार्मों, मशान और ट्रेक्टर स्टेशनों, तथा सामूहिक फार्मों में अमजीनिया के लिए नि शुल्क औद्योगिक (Voc tional) बहुशिल्पिक (Technical) तथा कृषि-सम्बन्धी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था।

सावियत सघ का शिक्षा व्यवस्था की प्रशंसा न केवल सावियत लेखकों ने ही की है, बल्कि विदेशी लेखक भी उससे प्रभावित हुए हैं। हापर और थापसन ने लिखा है^२—'सोवियत शासन की सर्वाधिक प्रभावी राजसेवा शिक्षा के

^१ अनुच्छेद १२१

^२ The most eff ctive state service of the Soviet regime has been in the field of education —Harper & Thompson op cit, p 254

क्षेत्र में रहा है। सोवियत सरकार का शिक्षा-व्यवस्था पर 'व्यय निरन्तर बढ़ता ही रहा है। सन् १९५६ में शिक्षा-व्यवस्था पर इक्कीस अरब रूबल व्यय किए गए थे। सन् १९५५ में इस मद पर लगभग साठ अरब रूबल व्यय किया गया। शिक्षा-व्यवस्था पर व्यय हुई इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि द्वितीय महायुद्ध में बहुत से विद्यालयों के भवन पण्डित या अशुभ नष्ट हो गए थे और उनका पुनर्निर्माण पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय करना आवश्यक हो गया था।

नागरिक शिक्षा प्रसार के कारण सोवियत संघ में अशिक्षिता का संख्या निरन्तर कम होता गया और आज सोवियत प्रवक्तारों का यह दावा है कि सोवियत संघ में अशिक्षिता का उन्मूलन किया जा चुका है।^१ सन् १९१७ में शारदाजिक क्रान्ति के समय जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग (६७%) अशिक्षित था। क्रिया के लिए ता शिक्षा प्राप्त करना आरंभ कर दिया था। शिक्षित क्रान्ति का सन् १५ प्रतिशत से अधिक नहीं थी। सन् १९६६ में जनगणना के अनुसार सोवियत संघ में अशिक्षिता का संख्या कम हो गई १६ प्रतिशत रह गई थी। इनमें से अधिकांश पचास वर्ष से अधिक आयु के थे। सन् १९४४ तक सोवियत संघ में उच्च शिक्षा भी निःशुल्क थी परन्तु महायुद्ध के दौरान परिस्थितियों के कारण सन् १९४४ में निःशुल्क शिक्षा का सारा प्रणाली तक ही सीमित कर दिया गया। परन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य विद्यार्थियों का राजस्व छात्रवृत्तियों की जाती है जिससे वे अपना शिक्षा जारी रख सकते हैं।

सोवियत संघ का शिक्षा के स्तर तथा पाठ्यक्रम के पक्ष और विषय में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। वहाँ सोवियत लालक अपना शिक्षा प्रणाली का सर्वाधिक जनवादी और समाज के लिए हितकारक बताते हैं वहाँ अनेक विदेशी लेखक उन्हीं पार्टियों के सिद्धान्तों के प्रचार का साधन मानते हैं।^२

^१ Karpinsky op cit, p. 169

^२ Courts in the History (History of the Communist Party of the Soviet Union) as an immutable feature of school curriculum and Stalin's dogmatic political and untruthful and leniently humanised in the schools and universities.

जिस सम्बन्ध में इतना निश्चित है कि यदि का अपने अध्ययन के लिए सामग्री चुनने की जितनी स्वतंत्रता अन्य देशों में है उतनी सोवियत संघ या अन्य साम्यवादी देशों में नहीं है। सोवियत संघ की शिक्षा प्रणाली के समर्थकों को इसे स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, पेट स्लोन ने, जो सोवियत प्रणाली के प्रसिद्ध प्रशंसक हैं, सोवियत प्रणाली को बखान करत हुए लिखा है—“लेनिन और स्टालिन की पुस्तकों का लाखों प्रतिया छापी जावेंगी हिटलर और ब्राउन्सकी द्वारा लिखित पुस्तकों की एक भी नहीं। इसे आप अपने राजनीतिक विचारों के अनुसार अच्छा या बुरा समझेंगे।” इसका कारण यही बताया जाता है कि सामाजिक हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य विचार धारा ही जनता के सामने आना चाहिए। परन्तु यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या राज्य तथा उसके अधिकारियों को ही वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक, सत्य और असत्य का निर्णय करने का एकाधिकार होना चाहिए।

समानता का अधिकार

सोवियत संविधान में समानता के अधिकार को दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। प्रथम अर्थ के अनुसार स्त्रियाँ का, जो आरसाही शासन में समान का सर्वाधिक नस्ल और सतत वर्ग थीं, पुरुषों से आर्थिक, शासनीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा अन्य सभी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में समता प्रदान की गई है। द्वितीय अर्थ में सोवियत संघ के समस्त नागरिकों को बिना किसी जाति या राष्ट्रीयता के भेद-भाज के उपरोक्त सभी क्षेत्रों में समानता प्रदान की गई है।^१

study groups organised by the Party trade unions and so on. The History indeed is compulsory reading and compulsory source of inspiration for every Soviet citizen. Education under such auspices not an unmixed blessing —Florinsky M T op cit P 844

^१ Books by Lenin and Stalin will be produced in millions of copies, books by Hitler and Trotsky will not be printed at all. This you will consider good or bad according to your politics —Pat Sloan *Resistance without Illusions* p 118

इस अधिकार ने सोवियत संघ के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले पत्नियाँ के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर दिया है। इस अधिकार के कारण आज सोवियत संघ के स्त्री और पुरुष, पशुधन और वन्यजीव, स्नान और मगान, ताना और धमनी सभी नागरिक मिल कर राज्य निर्माण का महान योजनाओं को पारस्परिक सहयोग के साथ कार्यान्वित करते हैं।

घर में उपरोक्त अधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सावधानों में आवश्यक व्यवस्था की गई है। स्त्रियों को पूर्णतः समान ही कार्य पाने का अधिकार, अपने काम के बन्ने में समान पारिश्रमिक का अधिकार, तथा विराम, अवकाश, सामाजिक श्रमा और शिक्षा का अधिकार प्रदान किये गये हैं। राज्य का और से माताओं और शिशुओं के हिता के संरक्षण, अनिवारित तथा अधिक शिशुओं को जनने वाली माताओं को राजस्व सहायता, पूर्ण घटन के साथ 'प्रसूति अवकाश' (maternity leave), तथा बड़ा संख्या में प्रसूति पक्षा, शिशु-मर्त्य तथा शिशु निद्यालया की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। विभिन्न जानियाँ के बीच भेदभाव का अन्त करने के लिए किसी प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नागरिकों के अधिकारों पर हस्तक्षेप या राष्ट्रीयता के कारण निर्बंध लगाना या इस कारण से कोई विशेष भुविधाएँ देना वर्जित कर दिया गया है। ऐसा करना तथा जाति या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव, घृणा, तथा अपमान का प्रचार करना वैधानिक रूप में दंडनीय घोषित किया गया है।

जाराही काल में रूस में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनकी बंसी स्थिति का कारण न केवल समाज की विच्छिन्न हुई दशा थी, बल्कि स्वयं जाराहा विधियाँ भी थी जिनमें उनसे पति का प्रत्यक्ष आज्ञा का अड्डापूर्वक पालन करने की अपेक्षा की जाती थी।^१ रूसी साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में तो

^१ अनुच्छेद १२३

^२ According to the Tsarist law valid until Feb 1917 demanded that the wife must obey her husband as head of the family, love and respect him with boundless docility showing the utmost compliance and devotion in the home

स्त्री को पुरुष का पूरा दास माना जाता था और वे पुरुषों के साथ बैठ भी नहीं सकती थीं। चाहे हम वर्तमान सोवियत नारी की बारम्बाही रूस की नारी से तुलना करें तो निश्चय ही हमें आश्चर्य होगा। युद्ध-काल में जिस उत्साह व साथ स्त्रियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य किया वह अनुलनीय है। उदाहरणार्थ सन् १९४३ में सामूहिक फाँलों पर किये गये समस्त भाग का तीन चौथा भाग स्त्रियों के द्वारा किया गया था। परन्तु “शांति काल में भी सोवियत नारियाँ समस्त पारिश्रमिक वाली नौकरियों (Wage paying jobs) के ४ प्रतिशत, तथा समस्त कृषि संबंधी पदों के ५ प्रतिशत, स्थानों पर कार्य करती हैं। चिकित्सक जस-यसमान में, निसम अति उच्च कोटि की कुशलता आवश्यक होती है उनकी सराफा पुरुषों के समान ही है।^१ अन्य देशों में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र श्रद्धापूर्वक सीमित रखने के कारण राष्ट्र जनसंख्या के लगभग आध भाग का मवात्रा से वंचित रह जाता है। सोवियत संघ में ऐसा नहीं है। वहाँ राष्ट्र निर्माण के कार्य में स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान भाग वाहन करती हैं।

सोवियत संघ में स्त्रियाँ सभी क्षेत्रों में अपनी स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर पाती हैं। इसका एक कारण है। राज्य ने उन्हें प्रजनन मातृत्व-सम्बन्धी उत्तरदायित्व का पूर्ण करने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की हैं। गभवती स्त्रियों को प्रजनन के पूर्व पर्याप्त छुट्टी दी जाती है। छोटे शिशुओं को दुग्धपान कराने के लिए प्रति साढ़े तीन घंटे पश्चात् माताओं को आधा घंटे की छुट्टी दी जाती है। बालक के पालन पोषण में राज्य स्त्रियों की सहायता करता है। माताएँ अपने बालकों को शिशु-शालाओं में रख सकती हैं जहाँ उनका समुचित पालन पोषण होता है। दो से अधिक बालकों को जन्म देने वाली माताओं को राज्य की ओर से अधिक सहायता दी जाती है। अधिक बालकों का जन्म देने वाली माताओं को अनेक उपाधियों से विभूषित किया जाता है। सोवियत संघ में अधिवाहित माताओं को भी राजकीय सहायता दी जाती है और उन्हें अपने बालकों को शिशु-शाला में पालन पोषण के लिये रखने की सुविधा दी गई है। दूसरे देशों में ऐसा माताओं को समान रूप से हेतु दृष्टि से देना जाता है। इस अन्तर का सैद्धान्तिक कारण

यह है कि सोवियत मंत्र में विवाह न स्त्री पुरुषों के संयोग का सामाजिक स्वीकृति माना जाता है उसका कोई धार्मिक महत्त्व नहीं माना जाता। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि सोवियत संघ के शासन की नीति जन सरिता में वृद्धि का प्रोत्साहित करने की रही है।

बारशाही काल में साम्राज्य की समाप्ति और राष्ट्रीयताओं के लोगों पर रुसिया की भाषा, संस्कृति और प्रथाएँ लागू करने का प्रयत्न किया जाता था। उसका उल्लंघन करते हुए एक बार स्टालिन ने कहा था 'पिछले समय में जब हमारे देश में बार, पञ्जाबिया और भूखानिया के हाथ में सत्ता थी, सरकार का यह नीति था कि एक जाति रुसिया का प्रभु जाति बनाया जाय और अन्य सब का अधीन और उत्पादित। यह पार्श्विक नीति थी। आज भी अनेक देशों में बार और काल नागरिका में भर्त्ता किया जाता है। अपने को संप्रदेश प्रभावित करने वाला देश अमेरिका भी इस कलह से मुक्त नहीं है। परन्तु सामान्य सभ में सभी जातियाँ के नागरिका का समान माना जाता है। उन्हें अपना भाषा संस्कृति तथा परंपराओं का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। किसी एक जाति का प्रभु जाति नहीं माना जाता। स्त्री का परिणाम यह है कि आज सोवियत संघ का विभिन्न जातियाँ के लोगों में पारस्परिक कलह और घृणा के स्थान पर भ्रातृत्व और सहयोग की भावना का विकास हो रहा है। सामान्य सभ की शासन एकता और सुखता का आधार नागरिका की समानता का सिद्धान्त है।

धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार की स्वतंत्रता

बारशाही रुस में, जहाँ कि इसका पूरा उत्थान किया जा चुका है, अर्थोडॉक्स चर्च (Orthodox Church) का शासन प्रभाव था। राज्य और चर्च के अधिकारिता में एक प्रकार का सम्मिश्रण था जिसके कारण अन्य धर्मों के अनुयायियों का अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनको उपासित किए जाने के सम्बन्ध में भी निषेध था। अल्पसंख्यक जातियों पर शास्त्रात्मक नियमों का प्रथम लोगों में से एक अर्थोडॉक्स चर्च का शासन से संबंधित किया जाना था। परन्तु १८१८ के प्रथम सामान्य शासन के

एक आज्ञाति में यह घोषणा की गई कि कोई नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी धर्म का पालन कर सकता है, या यदि न चाहे तो वह किसी का न करे। संक्षेप में, प्रत्येक नागरिक का विश्वास का स्वतन्त्रता (Freedom of Conscience) प्रदान की गई। तब से आधिकारिक रूप से धर्म न सम्बंध में सोवियत शासन की निरंतर यही नीति रही है। म्लाचिन सविधान के अनुच्छेद १२४ में नागरिकों के किसी धर्म को मानने या धर्मापरोधी प्रचार करने की स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान की गई है। धर्माधिकार (Religion) जारशाहों के अनन्य समर्थक माने जाते थे और क्रांति के पश्चात् बहुत से धर्माधिकारियों ने क्रांति विरोधी तत्वा का साथ भी लिया। इस कारण उन्हें बहुत समय तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। परंतु स्तालिन सविधान में उन्हें भी सामान्य नागरिकों की भांति राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गये।

व्यवहार में सोवियत शासन की धर्म के प्रति नीति में महत्वपूर्ण अन्तर होते रहे हैं। प्रारम्भिक काल में सोवियत शासन ने अर्थोक्स चर्च की सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर लिया और कम्युनिस्ट पार्टी तथा सरकारी संस्थाओं ने पर्याप्त धर्म विरोधी प्रचार किया। सन् १९२५ में धर्म विरोधी प्रचार को और अधिक तीव्र करने के लिये उग्र अनाश्वरवादियों की एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम लीग ऑफ मिलिटेंट एथीस्ट्स (League of Militant Atheists) था। इस संस्था का कार्यक्रम का पश्चात्त्य देशों में बहुत प्रचार किया गया और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि सोवियत शासन सोवियत संघ में धर्म का अस्तित्व मिटा देने के लिये कटिबद्ध है। सन् १९२६ में अर्थोक्स चर्च के कम्युनिस्ट विरोधी पत्रिका टिचोन (Tichon) की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी कार्यकारी—पत्रिका सर्जेंट (Sergue) ने चर्च की कार्यकारी संस्था सिनोड (Synod) के साथ एक संयुक्त दस्तावेज में सोवियत शासन के प्रति प्रतिक्रिया की घोषणा की। उस दस्तावेज में भी कम्युनिस्टों का धर्म विरोधी प्रचार जारी रहा। सन् १९२८ में रूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य (R. S. F. S. R.) के सविधान में संशोधन कर नागरिकों का 'धार्मिक और धर्म विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता के अधिकार के स्थान पर' धार्मिक उपासना तथा धर्म विरोधी प्रचार की स्वतन्त्रता का

अधिकार निया गया। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि धार्मिक प्रचार का वजित कर निया गया। सन् १६३६ के समिधान में भा नागरिका को धार्मिक उपासना का ही अधिकार दिया गया, धार्मिक प्रचार का नहीं, जबकि धर्म विरोधा प्रचार का स्पष्ट रूप से स्वतन्त्रता दी गई हे। सोवियत शासन की धर्म सम्बन्धी नीति में स्पष्ट परिवर्तन अगस्त, १९४१ के नानी आक्रमण के पश्चात् हुआ जब नागरिका का देश की प्रतिरक्षा के लिये उत्साहित करने के लिये धर्माधिकारिया की सहायता आनश्यक समझी गई। युद्ध प्रारम्भ होने के समय से हा पणियाक सर्जियस और अन्य धर्माधिकारिया ने अपने अनुयायियों से प्रतिरक्षा में भाग लेने का अनुरोध किया। इसी समय 'लीग आफ मिलिटेड एथास्ट्स' को शान्तिपूर्ण नियन्त्रित कर निया गया और उसका मुख्यालय आदि को उसका प्रमुख प्रतिद्वंद्वी अर्थोङ्गस् चर्च को दे दिया गया।^१ सन् १९४३ में 'पट्रीयार्केट' (Patriarchate) की पुनर्स्थापना की गई और धर्माधिकारियों की एक सभा में सर्जियस को पणियाक चुन लिया गया। अगले वर्ष जन कमिस्तर परिषद् (सोवियत मन्त्रिमल) ने दो परिषदों की स्थापना की—प्रथम, अर्थोङ्गस् चर्च के मामला के प्रबंध के लिये, और दूसरी अन्य धर्मों से संबंधित मामला की देख-भाल के लिये। महायुद्ध में शासन की सहानुता करने वाले अनेक धर्माधिकारिया को सम्मानसूचक उपाधिया तथा पदक प्रदान किये गये। सन् १९४४ में धर्माधिकारिया की शिक्षा के लिये एक संस्था (Seminary) भी स्थापित की गई। युद्ध प्रारम्भ होने के काल से ही धर्म विरोधा प्रचार में बहुत कमी कर दी गई थी। यद्यपि विचारधारा की दृष्टि से साम्यवादियों की धर्म के प्रति नीति में कोई अन्तर नहीं हुआ हे, परन्तु उन्हाने अथ चर्च को साम्यशासन का जनता पर प्रभाव सुद्ध करने वाला एक आवश्यक अंग के रूप में अस्तित्व स्वीकार कर लिया है। यथार्थ में, परिवर्तन धर्माधिकारिया की सोवियत शासन के प्रति नीति में हुआ हे, शासन की धर्म के प्रति नीति में नहीं।

अर्थोङ्गस् धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के अनुयायियों की भी अपनी संस्थाएँ हैं जिनका उल्लेख हम प्रथम अध्याय में कर चुके हैं। यह सत्य है कि

सोवियत नागरिका को धार्मिक उपासना की रीतिरिवाज प्राप्त हैं, परन्तु सोवियत शिक्षा प्रणाली में साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादित करने वाली पाठ्य पुस्तकों का बाहुल्य होने के कारण धर्म का प्रभाव अब युवक नागरिकों पर अधिक नहीं है। धर्म का सर्वाधिक प्रभाव कृषक समुदायों में है, परन्तु राज्य की उपलब्ध सभी साधना तथा विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले भौतिकवादी प्रचार व सम्मुख उसका अस्तित्व अधिक समय तक टिका रहेगा, यह संशयामक है।

राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ

किसी देश की शासन प्रणाली व संवर्धन में यह नियंत्रण करने के लिए कि वह कितना तक जनतात्मिक है एक ही निश्चित मापदण्ड है और वह है जनता की उपलब्ध राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ। जिस देश के नागरिक राजनीतिक स्वतन्त्रताओं से वंचित हों उस देश का किसी भी दशा में प्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का तात्पर्य विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं पर नागरिकों को अपना मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता से होता है। अन्य देशों की भांति सोवियत संघ के संविधान में भी नागरिकों को कुछ राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं। संविधान में कहा गया है कि “श्रमजाती जनता के हितों व अनुकूल तथा समाजवादी व्यवस्था का सुदृढ़ करने के लिए विधि (law) नागरिकों की निम्न स्वतन्त्रताओं की प्रत्याभूति करती है

(क) वाक् स्वतन्त्र्य (freedom of speech)

(ख) प्रेस स्वतन्त्र्य (freedom of the press)

(ग) सभा स्वतन्त्र्य (freedom of assembly) उनमें जन सभाएँ करने की स्वतन्त्रता सम्मिलित है

(घ) अर्थों पर उल्लेख निकालने और प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता।

यह नागरिक अधिकार (civil rights) श्रमजाती जनता तथा उनके संगठनों को मुद्रणान्तरण कागज व मन्थार, साप्ताहिक भरण, सन्धे, परिहृत की सुविधाएँ तथा जन अधिकारों का प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक जन सामग्री का उपलब्ध कर सुनिश्चित किए गए हैं।^१

भी हैं। सोवियत संविधान ने शाखा व हाथ में अपने विरोधियों का सत्तावादी व्यवस्था का विरोधी प्रोफ़ा कर उन्हें उन्दी बनाने या उन्हें कठारतन दह देने का एक असीमित अधिकार दे दिया है। क्रांति विरोधी (Counter Revolution y) कायदाविरुद्ध व अपराध में सोवियत संघ में अनगिनत व्यक्तियों को लैबोर शिविर (Labour Camps) की यादनाएँ सहनी पड़ी हैं अथवा प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। इनमें सोवियत शासन के अनेक उच्चाधिकारी तथा मंत्री भी थे। यदि पश्चात् देशों व लेनका के कथन पर विश्वास न भा किना जाय तो भी इनका तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन अनेक प्रश्नों पर पश्चात् प्रणाली व जननत्रों में नागरिक सहज सति से विचार प्रकट कर सकता है, उन पर सोवियत संघ में प्रानोचना करना सोवियत विरोधी या क्रांति विरोधी कृत्य समझा जायगा। इन प्रश्नों में से कुछ प्रमुख हैं उद्योग का राष्ट्रीयकरण, कृषि का सामूहिकरण, राज्य की विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति, सोवियत संघीय व्यवस्था, सराफा व अधिनायकत्व सम्बन्धी धारणा तथा कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधानता। कौन सा कथन या लेख समाजवादी व्यवस्था पर प्रहार करता है, उस तथ्य का निखर करना शासनाधिकारियों का कृत्य है। ऐसी दशा में राज्य बाक्-स्वातन या प्रेस स्वातन्त्र्य के अधिकारों का प्रयोग करने का जन साधारण को साहस ही न हा तो आश्चर्य नहीं।

सोवियत नेता आर लेख उस तथ्य पर बहुत जोर देते हैं कि साम्बाप प्रणाली व तथाकथित प्रजातन्त्र देशों में जनजातियों को कोई स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती। स्टाकिन ने राय हाउस (Roy How sd) व साथ एक बैठक में अपना मत प्रकट किया था कि मरे लिए यह कहना करना कठिन है कि एक बंसार व्यक्ति को भूत रहता है तथा रोजगार नहीं पा सकता, किंतु “व्यक्तिगत मननता का उपयोग कर सकता है। वास्तविक स्वतन्त्रता ऐसे स्थान पर ही विद्यमान रह सकता है जहाँ शासन का उपयोग कर दिया गया हो, जहाँ कुछ व्यक्ति दूसरों का उत्पीड़ित न करते हों, जहाँ बकारी और गरीबी का नाम भी न हो बल्कि किसी व्यक्ति को अपने अपने अपना काम, अपना घर तथा अपने भोजन को तो देने का भय न हो। ऐसे समाज में ही वास्तविक, न कि कागजी, स्वतन्त्रता संभव है। स्टाकिन व इन शब्दों से कोई

फार्मों के प्रबंधका, सरकार कर्मचारियों तथा की अकाउपटुता या दफ्तरराह प्रवृत्ति (Bureaucratic tendency) तथा स्थानीय संस्थाओं तथा की कार्य की आलोचना करने तक ही सीमित है। समाचार पत्र तथा अन्य पत्रिकाएँ जनता में राजकीय योजनाओं पर प्रति विश्वास तथा उत्साह उत्पन्न करने के साधन-माध्यम हैं। उनमें अधिकारियों तथा प्रबंधका का अक्षमता, उनके द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग तथा उनकी नाकूरशाही प्रवृत्ति के वृत्तान्त तथा इनकी कड़े शब्दों में मूर्खता प्रदर्शित मिलेगी परन्तु उनमें शासन की किसी महत्वपूर्ण नाति या पार्श्व के किसी उच्च नेता का आलोचना करने वाले व्यक्ति को निराश ही होना पड़ेगा।

सार्वजनिक संस्थाओं में संगठित होने का अधिकार

भाषण तथा प्रसंग का स्वतंत्रता तथा समान ही सोवियत संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार भी प्रतिनिधित्व है। 'श्रमजीवी जनता के हितों के अनुकूल तथा जनसाधारण की राजनीतिक कर्मशाला तथा संगठन सम्बंधा प्रतिभा को विकसित करने के लिये सोवियत संघ के नागरिकों को सार्वजनिक संस्थाओं में संगठित होने के अधिकार की संविधान द्वारा प्रत्याभूति की गई है। संविधान में 'सार्वजनिक संस्थाओं' का व्यापक स्फुट कर दिया गया है। ये संस्थाएँ हैं श्रमिक संघ (Trade Unions), सहकारी समितियाँ, तरुण संघ, श्रमिक और सैनिक संगठन, सांस्कृतिक प्रशिक्षण तथा वैज्ञानिक संस्थाएँ तथा सोवियत संघ का कम्युनिस्ट (बाल्शेविक) पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी में संगठित होने का अधिकार श्रमिकों तथा अन्य श्रमजीवी वर्गों के स्वाधिक क्रियाशील तथा राजनीतिक चेतनायुक्त नागरिकों का ही प्राप्त है। संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी को समाजवादी व्यवस्था का सुदृढ़ बनाने और विकसित करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष में श्रमजीवियों का नेतृत्व करने वाली संस्था, तथा श्रमजीवियों की समस्त सार्वजनिक और राजकीय संस्थाओं का मूल केंद्र कहा गया है।

उपरोक्त उपक्रमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहते थे कि सोवियत संघ में केवल एक ही राजनीतिक दल रह सकता है और वह है कम्युनिस्ट पार्टी। स्टालिन ने

संविधान के प्राप्ति पर अग्रिम कानून के समक्ष लिए गए मापन में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि अब—“सोवियत सङ्घ में केवल नौ प्रेरितियाँ हैं, समजीवा और क्रमिक जिनके हित एक दूसरे के विरोधी नहीं। इसलिए सोवियत सङ्घ में अनेक राजनीतिक दलों का आवश्यकता ही नहीं। और इसलिए इन दलों की स्वतन्त्रता का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। सोवियत सङ्घ में केवल एक दल साम्यवादी दल की आवश्यकता है। सोवियत सङ्घ में केवल एक दल, साम्यवादी दल, रह सकता है जो कि सहज न साथ अमनाबिया और क्रमिकों के हितों का पूरित रखा करता है। हिंसात्मक कार्यवाहियों को उत्पन्न करने के कारण यदि किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, या उसके सन्स्था का धनी बनाया जाता है तो कम्युनिस्ट नेता नागरिकता तथा नागरिक-स्वतन्त्रताओं की दुहाई देने हैं। परन्तु उनके स्फूर्ति के माध्यम सङ्घ में विरोधी राजनीतिक दल का अस्तित्व कहा तक सम्भव है यह उक्त वचन से मलीभाति स्पष्ट हो जाता है।

सोवियत संविधान में नागरिकों का निम्न अनेक अराजनीतिक सन्स्थाओं में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनमें सम्मिलित होने पर किसी राज्य में प्रतिबंध नहीं होता। वालन में सोवियत नागरिकों को साम्प्रतिक सन्स्थाओं, सहकार समितियों, ग्रामीण सङ्घों आदि को सम्मिलित करने का पूर्ण स्वतन्त्रता है। परन्तु श्रमिक सङ्घों का स्थिति पर दो शब्द लिख देना आवश्यक है। गल्शविक प्रतिबंध पश्चात् शासन द्वारा श्रमिकों के लिए श्रमिक सङ्घों का सन्स्था बनना अनिवार्य कर दिया गया था। परन्तु गल्शविक प्रतिबंधों के कारण सन् १९२२ में श्रमिक-सङ्घों की सदस्यता को पुनः वैकल्पिक कर दिया गया। श्रमिक सङ्घों की सदस्यता से श्रमिकों को अनेक लाभ प्राप्त हैं इस कारण वे उनके सन्स्था बनना स्वयं ही पसन्द करते हैं। देश भर में बिखरे हुए श्रमिक सङ्घों की केन्द्रीय सन्स्था अखिल सङ्घीय केन्द्रीय श्रमिक सङ्घ परिषद् है। प्रारम्भ में श्रमिक सङ्घों का उद्देश्य केवल प्रवचन में पराजित भाग रहता था। क्रमशः उनका यह काम समाप्त होता गया और उनका प्रमुख कार्य श्रमिकों के हित के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों का सञ्चालन करना हो गया। सोवियत बीमा व्यवस्था का सञ्चालन अब श्रमिक सङ्घ ही करते हैं।

यद्यपि उद्योगों के प्रबंधकों से सामूहिक सम्मेलन करने का अधिकार उन्हें अभी भी प्राप्त है, परन्तु व्यवहार में राज्य हाथमिर्का के पारिभाषिक आदेश निश्चित करता है और श्रमिक संघ उस स्वाकार कर लेते हैं। सोवियत संघ में श्रमिक संघों का कार्य हड़तालें करना नहीं, राष्ट्रीय-उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों में उत्साह उत्पन्न करना है। हड़तालों पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है परन्तु सोवियत संघ के किसी कारखाने में हड़ताल होने का समाचार कभी नहीं सुना जाता।^१ सोवियत संघ में हड़ताल प्रायोजित करने वाले व्यक्ति निश्चित ही 'जनता के शत्रु' घोषित कर लिए जायेंगे।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार

सोवियत संविधान के अनुच्छेद १२७ तथा १२८ में नागरिकों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रयाभूति की गई है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्यायवादी (Procurator) या न्यायालय की स्वीकृति के बिना नहीं गिरा जा सकता, तथा किसी नागरिक के निवास स्थान का अतिक्रमण (violation) नहीं किया जा सकता। नागरिकों के पत्र-परिचार की गोपनीयता को भी विधि का संरक्षण प्राप्त है।

देश की सुरक्षा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से सभी देशों में नागरिकों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर कुछ निर्वेध लगाये जाते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय संविधान में सरकार को कुछ विशेष परिस्थिति में नागरिकों का गिरावट (detention) करने का अधिकार दिया गया है। सोवियत संघ में वर्ष १९२४ के संविधान में एक पूरा अध्याय राजनीतिक पुलिस (OGPU) की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में था। संविधान में इस राजनीतिक पुलिस का कार्य प्राति की उलटने के राजनीतिक और आर्थिक प्रयत्न अन्य देशों के भविष्य की कार्यवाहियों तथा दंडाधिकारों के विरुद्ध संघर्ष में नागरिकों के तत्वा का नेतृत्व करना बताया गया था। इसी प्रकार स्तालिन ने अपने एक

^१ 'Strike are not expressly prohibited, but they are very conspicuous by their absence in this workers State'—Hill & Thompson *op cit* p 88

लेख में 'जनानिक पुलिस' का अर्थ का अटल सरलक तथा 'सर्वद्वारा की नगी तलवार' बताया था। इस का प्रमुख कार्य सावित्र राय - तथाकथित शत्रुओं का पता लगाना और उन्हें दंड देना था। यद्यपि सन् १९२६ के संविधान में राजनानिक पुलिस का कहीं उल्लेख नहीं है, परन्तु वह आज भी विद्यमान और कार्यरत है। सामान्य मामला पर न्यायालय विचार करते हैं और उनमें नागरिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है परन्तु सोवियत राय के विरुद्ध भी जाने बाना कार्यवाहियाँ पर राजनानिक पुलिस के द्वारा विचार किया जाता है। निम्न व्यक्तियों पर संदेह होता है उन्हें पता बनाने की स्वीकृति न्यायनाली (Procurator) से सरलता से मिल जाती है। राजनीतिक पुलिस का औपचारिक दृष्टि से सन् १९२६ का कानून - मुक्तता का सुनिश्चय करने का अधिकार नहीं है परन्तु वह उन्हें निम्न निम्न मुक्तता के अन्तर्गत में भन सकती है। उन अन्तर्गत का मन्त्रालय भी राजनीतिक पुलिस के एक विभाग के द्वारा ही होता है। इन अन्तर्गत में भेजे गये नागरिकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। मनुष्य के मतानुसार इनमें कई मिलियन (million) व्यक्ति हैं निम्न राजनीतिक पुलिस (MVD) के अधीनस्थ में निम्न प्रकार के काम कराये जाते हैं।

सावित्र लेखक तथा सावित्र प्रणाली के समर्थक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि राजनीतिक पुलिस केवल सावित्र राय के विरुद्ध पकड़ करने वाला के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए है। निम्न का पालन करने वाले और समाजवादी अवस्था में विश्वास रखने वाले नागरिकों का उसमें भयानक हानि का कोई कारण नहीं है। परन्तु ऐसे अनेक कार्य का अन्तर्देश में निम्न-संगत माने जाते हैं सावित्र राय में सावित्र राय का नाट्य करने के प्रयत्न माने जायेंगे। और ऐसे सभा कार्यों पर न्यायनाली में नहीं, उन पुलिस के द्वारा विचार किया जाता है। सन् १९२४ में कम्युनिस्ट पार्टी का राजनानिक समिति (Politbureau) के सन् १९२४ तथा लेनिनग्राद पार्टी कमटी

गोपनीयता के अन्तर्गत राजनानिक पुलिस के नाम में कई बार परिवर्तन हो चुका है। इसमें सन् १९२४ तथा १९२६ प्रचलित नाम ये हैं
CHEKA OGPU NKVD और ग्रेनोच MVD

क मंत्री किराव (Kirov) की हत्या के पश्चात् गुप्त पुलिस का कार्यवाहिका में विशेष वृद्धि हो गई थी। सन् १९३५ में एक विशेष आशक्ति (decrec) प्रवर्तित की गई थी जिसके द्वारा अभियुक्ता के वकील रखने के अधिकार तथा न्यायालय द्वारा लिये गए दण्ड के विरुद्ध अपील करने के अधिकार को निलग्नित कर दिया गया था। उस आशक्ति के प्रवर्तित किये जाने के पश्चात् ११७ व्यक्तियों पर सोवियत संघ के प्रति द्रोह करने के अपराध में गुप्त रूप से मुकदमा चलाया गया और उन्हें प्राणदण्ड दिया गया। मालिन की मृत्यु के पश्चात् सोवियत संघ के आन्तरिक मामला क मंत्री बेरिया (Beria) को सोवियत शासन के विरुद्ध पदच्यत्र करने के अपराध में प्राणदण्ड दिया गया। इन घटनाओं के कारण विदेशी लोगों का यह विश्वास हो गया है कि सोवियत संघ में सबिधान द्वारा नागरिका के निःश्वेतक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रत्याभूति की गई है वह किसी नागरिक को तभी तक प्राप्त रहता है जब तक उस पर सोवियत शासन के विरुद्ध किसी पन्थन में सम्मिलित होने का सदेह नहीं किया जाता। मनरो का मत है कि निःश्वेतक पर शासन का विरोधी होने का सदेह हो उसके लिये कोई सुरक्षा का साधन विद्यमान नहीं है और उसके साविधानिक अधिकारों की भी अवहेलना की जाती है।

सोवियत संघ में वैयक्तिक स्वतंत्रता के प्रश्न पर विचार करते हुए हम एक तथ्य स्मरण रखना चाहिए और वह यह कि सोवियत शासन को न केवल ऐसे आंतरिक तत्त्वों से ही सावधान रहना पड़ता है जो वर्तमान व्यवस्था का अत करना चाहते हैं बल्कि उसे विदेशिया तथा विदेशों की सरकारों के द्वारा सोवियत संघ में निद्रोह की ज्वाला प्रवर्तित करने के प्रयत्नों से भी सशंक रहना पड़ता है। बाल्शेविक क्रांति के तुरन्त बाद रूसी शासन को एक साथ ही आन्तरिक और बाह्य विरोधियों का सामना करना पड़ा था। सोवियत सनाओं का सग्रह मोर्चों पर विदेशी सरकारों की सेना से लड़ना पड़ा था। सोवियत

^१ "The simple fact is that no protection exists for the citizen suspected of hostility to the regime and that his constitutional rights are disregarded — Munro & Aycarst, *op cit*, p 674

शासन का स्थापना न लगभग चार दशाने बाद भी आन सोवियत सरकार का उलटने की आशा करने वाला का सबया अभाव नहा हे। ऐसी स्थिति में सोवियत नेताआ का सतक रहना स्वाभाविक हे। यह आशा की जा सकती हे कि बाध्य आक्रमण तथा आतरिक निद्राह की सम्भापना समाप्त हो जाने पर सोवियत सरकार नागरिकों को अधिक वयक्तिक स्वतन्त्रता उरलध हांगी। टाउस्टेर क शब्दा में हम कह सकत हैं कि "पूर्ण चित्र क उज्ज्वलतर पक्षा म एक तथ्य यह भा हे कि मानसाय स्वतन्त्रताआ का सांविधानिक व्यवस्था विद्यमान हे आर सोवियत सिद्धान्ता म उम कभा भविष्य में कावरूप म परिणत हाने से राकने गाना दुख भा नहा हे।"

वैयक्तिक सम्पत्ति का सीमित अधिकार—वाल्शरिक आति के पूर वयक्तिक सम्पत्ति (Private Property) क अधिकार नागरिका का एक प्रमुख अधिकार माना जाता था आर अनक देश न सविधाना म इसका नागरिका न मूलाधिकार क रूप म उल्लेख किया गाना था। रूस म सोवियत शासन का स्थापना क पश्चात् साभ्यगानी सिद्धान्ता क अनुरूप वयक्तिक सम्पत्ति की सथा का उन्मूलन करने का प्रयत्न किया गया, परंतु इसम सोवियत नेताआ को सफलता न मिल सका। देश न आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन करने क लिए नवान आर्थिक नीति में वैयक्तिक सम्पत्ति न सामित अधिकार को स्वीकार किया गया। स्तालिन सविधान म भी नागरिका क वैयक्तिक सम्पत्ति क सीमित अधिकार को मान्यता प्रदान का गइ हे, यद्यपि इसका नागरिका क मूलाधिकारों म उल्लेख नहा किया गया हे। सविधान क अनुच्छेद १ म कहा गया हे कि नागरिका का अपने काम से आय तथा बचत, अपने रत्ने के मरान तथा घर का पूरक सम्पत्ति, उरलू सानान एवं वैयक्तिक प्रयोग तथा सुविधा का अन्य वस्तुआ पर वयक्तिक स्वामित्व न अधिकार तथा नागरिका क उत्तराधिकार स सम्पत्ति प्राप्त करने क अधिकार का विधि का सरक्षण प्राप्त हे। सविधान म वयक्तिक कृपा तथा कारागारा को अगना उद्योग करने का स्वतन्त्रता दा गाना हे परन्तु इसा शून पर कि क निष्ठा दूसरे न जन का उपयोग न कर।

स्वायत्ति सविधान का सिद्धान्तों पर विचार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सावित्र स' में समस्त दूनि प्रविष्ट पदार्थों, वनों, दफ्तारों, कारखानों रेल, तेल तथा वायु यातायात को परिवहन व साधना प्रणाली पर राज्य का अधिकार है। इस कारण यह वैयक्तिक स्वयत्ति का प्रणाली प्रत्यक्ष सामित है। परन्तु आगों में प्रन्तर व कारण प्रमी भा वहा समुद्र औ निषेध का प्रन्तर रूप है। निषेध आय अधिक है यह निश्चय हा कम आय वालों से अधिक धन संचित कर सकत हैं।

विदेशी क्रांतिकारियों को आश्रय का अधिकार

नागरिकों व मूलाधिकारों वाल प्रमाण में हा ऐसे विदेशी नागरिकों का जो भूमिजातियों व इतों का रक्षा करने व नियंत्रण, या वन्यनिक कार्यवाही के लिए अथवा शासन स्वतंत्रता के लिए सहाय करने के लिए उद्देशित किए जात हैं सावित्र स' में आश्रय (asylum) देने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक देशों के प्रसिद्ध कन्वन्शन् ने पता सनर तक सावित्र स' में रहे हैं और सहाय वगैरे का प्रतिभा प्रार प्रन्तर करने के उपायों का विज्ञापन पाते रहें हैं। इस प्रमाण में हम यह साबित नागरिकों व मूलाधिकारों तथा कर्तव्यों पर ही विचार कर रहे हैं, इस कारण विदेशी नागरिकों का प्रत्यक्ष इस अधिकार का उल्लेख मात्र कर देना हा पयात है।

नागरिकों के मूल कर्तव्य

सावित्र स' के सविधान का यह एक प्रमुख विशेषता मानी जाता है कि उसमें न केवल नागरिकों के मूलाधिकारों का ही उल्लेख है, प्रत्युत उनका मूल कर्तव्यों का भी वर्णन है। जब दशमि ने ता इस सन् १९२६ के संविधान सविधान का विशिष्ट लक्षण (Peculiar characteristic) माना है।^१ अन्य साम्यवादी देशों के सविधानों में भी अधिकार व साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है।^२ सावित्र लेखकों के अनुसार आरशाद्ध रूप में अधिकारों और कर्तव्यों का भी जनता के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन या। उदाहरणार्थ,

^१ Sydney & Beatrice Webb *op cit* p 437

^२ देखिए लोक-गदगद चान के सविधान के अनुच्छेद १: १३।

कान काना नवन सम्पत्तिहान ननता, अथान् अनिका तौर कका का कन या उनक नन का फल भागना सनत्तिगानिा त्रयान् पूजागानिा नूनानिा ता कका का अनन्य त्रिधिनं या। अविउ सविधान न इउ काना पूर यिति का अत नर प्रनर त्ति क त्रिधिकार प्रगन कि ह तथा उउउ उउ कतन निश्चित किए हैं।

सविन सविगन दाय निधाति सान नारिका क ना क निम्नलिगित हैं —

- १ सविगन तथा विधिा का पालन करना
- २ नन-सन्ध्या अनुगसन का पालन करना
- ३ ग्रान सावजनिक स्वत्ता तथा सन्ध्याग नतिक्ता - निम्न का पालन करना
- ४ सनातना सामनिक सगति का पालन करना
- ५ सावजनिक सनिक सग
- ६ देश का रक्षा करने क निध प्रस्टुत रहना।

सविगन तथा विधिा का पालन करना—प्रनर सन ग्रन नारिका न यह त्राशा करता हे क व उउक सविन तथा विधिा का पालन क। ननु, बनता अना स्वद्या न किता सविगन न विधि का तना पालन करता हे, वर वर उहे ग्रने रिता क अउकन सनन्ता हे। नि ऐसा नह होता त नारिक किता नन या ताव क काय विधिा का पालन चाहे करें र व ऐसा करना ग्रना कतन नहा सनन्त। सविउ स का सनवाता (निधा तथा कका) का पालन ताता गाता हे। नविन प्रता हे गाता हे कि अय सविन सन मे कवन सनवाता का हा ग रह गा हे औ शासन ता का इच्छाता का प्रतिनिधित्व कता हे। इस कारण सविगन और अना विधिा सविन बनता क रिता का सनय कता हे। एा विधि मे ना कइ नारिक सविधान या विधि क निधूल का करता हे। सनन्त सविउ बनता तथा सविउ सना क विरुद्ध नन कता हे। सनन का तथा सविउ वा क हिता मे क विरुध न होने क कारण

समस्त समाज की समृद्धि व परिणामस्वरूप निश्चित ही समाज व प्रत्येक सत्त्व का हित होगा। इसीलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताया जाता है कि वह सविधान तथा विधियों का पालन कर समाज का समृद्धि का मांग प्रशस्त कर।

श्रम सम्बन्धी अनुशासन को पालन करना—जिस प्रकार सविधान और विधियों व अपने हित व अनुकूल न होने पर नागरिक उनका पालन स्वच्छा से अपना कर्तव्य समझ कर नहीं करते, उसी प्रकार श्रमजीवी श्रम सम्बन्धी अनुशासन को पालन करना तब तक अपना कर्तव्य नहीं समझते जब तक व उसे अपने हित व अनुकूल नहीं समझते। पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हान से श्रमिकों का कोई लाभ नहीं होता लाभ होता है मुट्ठी भर पूँजीपतियों का। इस कारण श्रमिक श्रम सम्बन्धी अनुशासन का स्वच्छा से पालन नहीं करते। व अनुशासन सम्बन्धी नियमों को पूँजीपतियों द्वारा निर्मित शोषण व्यवस्था का एक अंग समझते हैं। परन्तु यह दावा किया जाता है कि सोवियत संघ में स्थिति दूसरी ही है। श्रमजीवियों द्वारा अधिक लगन के साथ किये गये कार्य का लाभ अन्ततोगत्वा उन्हीं का होगा। कार्दिन्स्की के मतानुसार 'श्रमजीवाङ्गन अब स्वयं अपने प्रभु बन गए हैं, व अपनी समान भलाई के लिए ही काम करते हैं, और इसी कारण अपनी पूरा योग्यता के साथ काम करने में उनका हित है।'^१

सोवियत संघ के सविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के गुण और मात्रा के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार अपने काम में गिरावट रूप से सलग्न रहने वालों तथा बिना योग्यता प्रदर्शित करने वालों का पारितोषिक न्यून आते हैं तथा उन्हें सम्मानित किया जाता है। राज्य का ओर से ऐसे श्रमिकों का अनक उपोषण दी जाती है जिनमें सर्वाच्च हारो आफ सायलिस्ट लेकर है।

अपने सावधानिक कर्तव्य तथा समाजवादी नैतिकता के नियमों का पालन करना—एन की ओर से नागरिकों का जो अधिकार प्रदान किए

जात हैं उनका उदना किन जाना तमा सम्भव है जब नागरिक अपने कृत्य का भला भाति जानन करें। एक नति का असावधाना का पारखान अनेका गतिर्या या संपूर्ण समान का सुगतना पड सकता है। इसा कारण अपन सामनिक कृत्यो का भला भाति पालन करना प्रत्येक सोचिसत नागरिक का कृत्य ज्ञाता गया है।

समिधान म समाजवादी नैतिकता (Socialist behaviour) का अर्थ स्पष्ट नही किया गया है इस कारण से इस वाक्य का यथाय अर्थ बताना कठिन है। सोचिसत लेवका न मतानुसार 'समानवादी नैतिकता कि नियमा म कान का अना कृत्य मानना, मतुन द्वारा मतुन न शास्य का अपन समानवादी सावजनिक सम्पत्ति का अनातिक्रमणता (intiolability) तथा समान क हितों का नति न हितो म गेठ समझला सम्मिपित हैं। समानवादी नैतिकता का एक प्र नियम प्रत्येक नति में भावुच तथा सत्काति का भावना मिशान हाना है।

सावजनिक समानवादी सम्पत्ति का संरक्षण—सोचिसत सत्र में उपादन न सभी प्रनु सााना पर राय का स्वातन्त्र्य है। इसा कारण बहा की प्रविकाश सत्ति समानवादी सावजनिक सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति पर कित्ता एक नति का नही, रन् सारे समान का समान अधिकार हाने क कारण प्रत्येक नागरिक का यह कृत्य है कि वह इस नष्ट हाने से बचान। सोचिसत सोचिधान में ऐसे नति का ना समानवादी सावजनिक सम्पत्ति का हानि पहुचान 'बनता का शत्रु ठाग गया है। सोचिसत सत्र का विधिना में ऐसे नतिनो क निर प्रवृत्त क दृष्ट का व्यवस्था का गत है। एक अमरिका पत्रकार क बर्णन के अनुसार सोचिसत सत्र क एक जन-न्यायालय में एक नति का एक समानवादी सत्र (p p p ss), जिनका मूल्य लगभग दो गजर था और जिहें राय का सत्ति माना गया था चुपने क प्रत्येक म एक वष का कतिन-अन सति क का दृष्टि गता था।^१

मैनिंक संवा—न्यायिन समिधान में मैनिंक संवा का प्रत्येक सोचिसत नागरिक का सम्मानित कृत्य ज्ञात गया है। सितम्बर १८३८ म न्यायिन

सर्वव्यापक सैनिक सेवा विधि (Universal Military Service Law) के द्वारा प्रत्येक पुरुष नागरिक के लिये यह प्रावधान कर दिया गया है कि वह सोवियत संघ की सशस्त्र सेना (Armed Forces) में सेवा करे। सशस्त्र सेना का मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर देश का चिकित्सा पशु चिकित्सा तथा बहुशिल्प सम्बंधी शिक्षण प्राप्त स्त्रियों का संग्रहण भी प्राप्त कर सकता है। अंगरक्षक या उल्लास वगैरे की वजह से प्राप्त करने पर प्रत्येक स्वस्थ पुरुष नागरिक को सैनिक सेवा के लिये बुलाया जाता है तब उस कम से कम दो तथा अधिक से अधिक चार वर्ष तक सक्रिय सैनिक सेवा करना पड़ता है।

देश का प्रतिरक्षा प्रत्येक नागरिक का पुनात कर्तव्य—संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह पुनात कर्तव्य है कि वह देश का प्रतिरक्षा करे। मातृभूमि के प्रति द्रोह करने वाले अर्थात् अग्राभक्ति (Allegiance) की शपथ का अतिरिक्त करने वाले शत्रुओं से मिलने वाले राष्ट्र की सैनिक शक्ति को हानि पहुँचाने वाले तथा शत्रुओं का भेद देने वाले का हानितम अन्वेष करने वाला व्यक्ति माना जाता है तथा उस विधिक अनुसार कानूनमंद दंड दिया जाता है। 'मातृभूमि के प्रति द्रोह करने के प्रसंग में दंड पाने वाले में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक उच्चतम नेताओं तथा प्रमुख शासनाधिकारियों के नाम सम्मिलित हैं। समय-समय पर संविधान सभ में "शुद्धीकरण (Purges) की प्रणिया के द्वारा ऐसे समस्त तंत्र का नष्ट कर दिया जाता है जो सोवियत राज्य के शत्रु माने जाते हैं। इस 'शुद्धीकरण प्रणाली के अनेक लोकों ने सोवियत शासन के द्वारा अपने विरोधियों का अंत किए जाने का एक रास्ता माना है।

काम करने का कर्तव्य—सर्व नागरिकों के मूल कर्तव्य माने अंगण में काम करने के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु एक अन्य स्थान पर काम करना प्रत्येक स्वस्थ नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। वस्तुतः यह कर्तव्य काम करने के अधिकार का पूरक है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता वह मोबल करने का अधिकारी नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शांति का समा अंत हो सकता है अब प्रत्येक व्यक्ति अपना सामर्थ्य के अनुसार काम करे।

अध्याय ६

सोवियत सघनाद

(Soviet Federalism)

सोवियत सविधान का विश्वनाशा पर विचार करते समय हम देख चुके हैं कि सविधान में सोवियत संघ का एक समान-राज्य (Federal State) कहा गया है। अब हम समझें (Federalism) क्या है। मारक्स एंगेल्स और लेनिन के विचारों पर दृष्टि डालते हैं तो हम उसी विषय पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। एंगेल्स ने १८४८ में कहा है कि सबहारा वर्ग (Proletariat) केवल राज्य के एकात्मक तथा अविभाज्य गणराज्य रूप का ही उपयोग कर सकता है।^१ मारक्स ने सन् १८४८ में लिखा था—‘हम विद्वान्तर समझ का विरोध करते हैं। यह आर्थिक बन्धन (Ties) का शिथिल करता है यह एक राज्य के लिए अनुपयुक्त प्रणाली है।’^२ सन् १८४७ का कतिपय पूरा आत्मविक्रि नेता समझ का ‘अविभाज्य गणराज्य (Babb : ideal) का सारा स संबंधित किया करते थे। उनका विचार था कि समान आर्थिक विकास के मांग का अवलोकन करता है और इसलिये समानता के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। ऐसा स्थिति में पहले रूस गणराज्य (R. S. F. S. R.) तथा बाद में सोवियत संघ (U. S. S. R.) के सविधानों में समान राज्य का अन्तर्गत जाना आवश्यक हो रहा है।

“The proletariat can use only the form of the one and indivisible republic.”—Engels as quoted by Lenin in his *State & Revolution* p 60

“We regard the federalism on principle as weakens the economic ties and is an unfit type for one state.”—Lenin as quoted by Julius Tawster in *etc* p 62

संघराज एक अध्यायी व्यक्ति—यद्यपि मार्क्स और एंगेल्स ने संघराज सिद्धान्त का प्रबल विरोध किया है और उस समाजशास्त्रीय व्यवस्था के लिए आनिष्कार लगाया है परन्तु उन्होंने कुछ निश्चित परिस्थितियों में संघराज व्यवस्था का एक अन्तर्गत या अन्तर्कालीन युक्ति (D vice) के रूप में अपनाए जाने का समर्थन भी किया है। उनके मतानुसार संघराज व्यवस्था उसी समय अपना जाना चाहिये जब यह एक राजाज्य, प्रकार राज का श्राव्य प्रगति में होता है। इस सिद्धान्त के आधार पर मार्क्स ने तर्क देखा कि संघराज का निमाण का समर्थन किया जा सकता है। लेनिन ने वास्तविक प्रगति के पश्चात् मार्क्स और एंगेल्स के इस सिद्धान्त का प्रागल्भ्य और रूसी संघीय गणराज्य को एक एकात्मक, प्रजातान्त्रिक, केंद्राज्य शासित राज के निमाण के लिए उत्तरदायी निश्चित पाया। स्टाकिन जा १९२८ का अन्तर्कालीन सरकार में जातियाँ के मंत्री (Commisat of Nationalities) के, ने भी स्विट्स और अमेरिका संघ के उत्तरदायी के कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस प्रकार के स्वरूप राजा संघराज्य और संघराज्य के कर अन्त संघराज्य व्यवस्था हन हुए भी व्यवस्था में एकात्मक राजा राजा हो जाया है कि स्विट्स ने राजा संघराज्य में एकात्मक राजा नहीं, एक एकात्मक राजा स्थापित करना चाहता है, परन्तु परिस्थिति ने उन्हें संघराज्य को एक अध्यायी युक्ति के रूप में अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया।

संघराज व्यवस्था अपनाए जाने के कारण—हम हमार समुदाय के प्रश्न आता है कि वास्तविक नेत्राज्य के संघराज्य व्यवस्था निचाय में रह परिवर्तन के कारण यह ऐसा कौन सी परिस्थितिवादी जिन्होंने उन्हें संघराज्य के समर्थन सहायता दी। राजा के लिए संघराज्य व्यवस्था प्रगति के लिए विरोध किया। इस प्रश्न का उत्तर हमें वास्तविक प्रगति के पश्चात् रूसी साम्राज्य की दशा का अध्ययन करने में मिलता है। इस पुस्तक के आरम्भिक अध्यायों में हम उस पर विचार कर चुके हैं। संघराज्य में, निम्नलिखित तीन कारणों ने शासित नगरों का संघराज्य व्यवस्था अपनाए जाने में प्रेरित किया।

- १—जारशाही साम्राज्य की विभिन्न जातियों का महान् रूसियों (Great Russians) के प्रति अनिश्वास ।
- २—पूँजावादी देशों के प्रहार का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के लिए मुदत शक्ति की आवश्यकता ।
- ३—सोवियत राज्य के आर्थिक विकास के लिए पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता ।

जातियों की समस्या—जारशाही के काल में रूसी साम्राज्य की रूसतर (Non Russian) जातियाँ का निम्न प्रकार उत्पीड़न किया जाता था, इस पर विद्वानों अध्यायों में प्रकाश डाला जा चुका है। उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराओं, प्रथाओं आदि को निन्दित कर किम प्रकार उनका रूसीकरण (Russification) करने का प्रयास किया जाता था, यह यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। जारशाही शासन की इस नीति के परिणाम स्वरूप साम्राज्य की समस्त रूसतर जातियाँ शान्तिहीन रूसिया की दासता से अपने को मुक्त करना चाहती थीं। सन् १९१७ का क्रान्ति ने उन्हें ऐसा करने का अवसर प्रदान किया। विचार धारा की दृष्टि से रूसियों से कोई विभिन्नता न होत हुए भी भूतपूर्व जारशाही साम्राज्य की रूसतर जातियाँ ने रूसिया से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने में ही अपना कल्याण समझा। उन्हें यह विश्वास न हो सका कि रूस के नवीन शासन उक्त धृष्टि नीति का पूर्णरूपेण परित्याग कर सकेंगे, निसक कारण उनका भाषा, संस्कृति और सम्पत्ता का अन्त होता जा रहा था। इसी कारण जारशाही साम्राज्य की साम्राज्य पर स्थित ऐसे प्रदेशों में जहाँ रूसतर जातियों के लामा निवास करते थे, स्वतंत्र सोवियत समाजवादी गणराज्यों (S S R s) की स्थापना हुई।

लेनिन ने रूसतर जातियों के इन मनोभावों को समझने में कभी त्रुटि नहीं की। उन्हें सतुष्ट रखने के लिए क्रान्ति के अनेक वर्ष पूर्व से वह 'राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन कर रहा था। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माक्सवादी राज्यान्तरे कट्टर विरोधी हैं और स्वयं लेनिन ने अनेक स्थानों पर समाजवादीयों को प्रत्येक प्रकार के राज्यान्तरे का शत्रु कहा है। सन् १९११ में लेनिन ने घोषणा की थी कि 'मार्क्सवाद का किसी भी

प्रकार क, यहा तक कि सनाधिक "याय", "विशुद्ध", "परिशाधित तथा सम्य प्रकार क राष्ट्रवाद स समन्वय नही किया जा सकता। "न स्पष्ट उन्धियों को यान में रखत हुए लेनिन द्वारा 'राष्ट्रा क ग्राम नियम' के अधिकार का समान किये जाने में निरोधभास प्रतीत होता ह। परन्तु इसका कारण तत्कालीन परिस्थितियों को यान में रखन से स्पष्ट हा जाना हे। रूसी साम्राज्य क निषेधन को रोकने का एकमात्र उपाय था, उसकी विभिन्न जातियां में रुसिया क प्रति विश्वास उत्पन्न करना। यह विश्वास तभी उत्पन्न हा सकता था जन समस्त रूसतर जातिया को रुसिया से पूर्णरूपण समानता, तथा सांस्कृतिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाय। सोवियत नेताओं ने इसी उपाय का अवलम्बन किया। उन्होंने रूसी साम्राज्य की सभी राष्ट्रीयताओं को ग्राम नियम का अधिकार प्रदान किया जिसमें रुसियों से अपना पूर्ण सम्पन्न रिश्ते करने का अधिकार सम्मिलित था। सन् १९१८ क संविधान में रूसी गणराज्य का 'स्वतंत्र राष्ट्रा का संघ' (A free Union of Free Nations) घोषित किया गया। सन् १९२४ तथा १९२६ क संविधानों में भी संघ क 'स्वायत्त' (voluntary character) तथा विभिन्न गणराज्यों तथा जातियों की समानता पर बहुत बल दिया गया हे।

सोवियत नेताओं द्वारा विभिन्न जातिया क प्रति अपनाई गई इस नीति को अपूर्व सफलता मिली। इसी नीति का यह परिणाम हे कि आज सोवियत संघ में अनेकों जातिया क लोग सम्मानपूर्वक जीवन व्यता करते हैं तथा अपनी भाषा क संस्कृति का अनाधित विकास करने में समर्थ हो सके हैं। सोवियत संघ क नागरिकों में एकता तथा भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करने तथा उसे 'नाये' रखने एवं पारस्परिक सहयोग क आधार पर आर्थिक विकास क द्वारा देश का शक्ति का मुक्त प्रयोग में इस नीति का अत्यंत महत्पूर्ण योग हे।

The Constitution of 1924 declared the U S S R to be a voluntary association of peoples enjoying equal rights (See Part I). According to the Stalin Constitution the U S S R is a federal state formed on the basis of a voluntary union of equal Soviet Socialist Republics. See Art 13.)

मन्वपूर्ण कारण देश का शीघ्रातिशय आर्थिक पुनर्निर्माण किए जाने तथा आम निभरता (S If sufficiency) की स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। महायुद्ध, गृह युद्ध, तथा राज्य हस्तक्षेप ने परिणामस्वरूप सोवियत गणराज्य की अर्थ व्यवस्था अस्त-वस्त हो गई थी। आर्थिक पुनर्निर्माण की कोई महती योजना जनता के हार्दिक सहयोग के बिना पूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि विभिन्न क्षेत्रों और जातियों के लोगों को संघ प्रकार से आश्वासन कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाय। इसका एकमात्र उपाय उच्च स्थानांश तथा सांस्कृतिक मामलों में अधिकधिक स्वतंत्रता देना ही था। साथ ही पड़ोसी देशों का आर्थिक नाकामगी के कारण यह भी आवश्यक था कि ऐसे अधिक से अधिक क्षेत्रों को सोवियत संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाय जो प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से संपन्न हों। यूरेन की लोहे और कोयले के खाना, तथा कार्बनस के तेल-भंडार के बिना सोवियत संघ की औद्योगिक स्थिति आज का दिग्गज से भिन्न होती, यह निश्चय है। इन क्षेत्रों का सोवियत संघ में सम्मिलन उसके सघीय स्वरूप के कारण ही सम्भव हो सना।

सोवियत संघके एकक

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (U S S R) में निम्नलिखित १६ पूर्ण एकक हैं —

- १ रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य (The Russian Soviet Federative Socialist Republic)
- २ यूक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (The Ukrainian S S R)
- ३ बेलारूसी " (The Byelorussian S S R)
- ४ उजबेक " " (The Uzbek S S R)
- ५ कजाक " " (The Kazak S S R)
- ६ जर्जिया " (The Georgian S S R)
- ७ अज़रबैजान " " (The Azerbaijan S S R)
- ८ लिथुआनिया " " (The Lithuanian S S R)

६ मोल्दोविया सोवियत समाजवादी गणराज्य	(The Moldavian S S R)
१ लेटविया	(The Latvian S S R)
११ किर्गिज	(The Kirghiz S S R)
१२ ताजिक	(The Tadjik S S R)
१३ तुर्की	(The Turkmen S S R)
१४ अरमीनी	(The Armenian S S R)
१५ एस्तोनिया	(The Estonian S S R)
१ 'करोतो फिनिश'	(The Karelo Finnish S S R)

उपयुक्त एकका को संविधान में संघ गणराज्य कहा गया है। प्रथम संविधान - निर्माण (१९२४) के समय सोवियत संघ में केवल चार एकक अथवा संघ गणराज्य थे। इनके नाम थे रूसी संघीय गणराज्य, गदालो रूसी गणराज्य, यूक्रेन गणराज्य, तथा त्सकारेसस संघीय गणराज्य। सोवियत संघ के निर्माण के पश्चात् कुछ ही वर्षों में उसकी मध्य एशिया सीमा पर हिन्द तान प्रवेश का संघ गणराज्य का पद दे दिया गया और त्स प्रकार उजबेक, तुर्क, एर ताजिक संघ-गणराज्य का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १९२६ के संविधान के निर्माण के समय सोवियत संघ में दो अन्य एशिया प्रदेश, कज़ाक तथा किर्गिज को संघ गणराज्य का पद दे दिया गया तथा गन्सकारशियन संघ का तान एकका में विभक्त कर दिया गया। इस प्रकार संघ-गणराज्यों की संख्या ग्यारह हो गई। द्वितीय महायुद्ध के काल में सोवियत संघ के राज्य क्षेत्र में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप तीन नवान गणराज्यों का निर्माण हुआ, तथा दो स्वायत्तशासी-गणराज्यों को संघ-गणराज्य का पद दे दिया गया। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप संघ गणराज्यों की संख्या सन् १९४४ में १६ हो गई।

मध्य-गणराज्यों की सीमाओं में परिवर्तन—सोवियत संविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया गया है कि किसी संघ-गणराज्य के क्षेत्र में उसकी स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत भारतीय संविधान में संघीय संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा किसी राज्य का नाम या क्षेत्र बदलने का अधिकार दिया गया है।

परन्तु हम यहां यह बात साफ चाहिए कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का सत्तावादी प्रभाव के कारण यदि कभी पार्टी के उच्चतम नेताओं में सत्ता गणराज्य के स्तर में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की जा ऐसा करने में कठिनाई न होगी। उदाहरणार्थ, सन् १९२६ में ट्रान्सकाउकेशियन संघ के तीन गणराज्यों को बिना किसी कठिनाई के संघ गणराज्यों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया था।

संघ गणराज्यों का सोवियत संघ से अलग होने का अधिकार— सन् १९२४ के संविधान का भाग सन् १९३६ के संविधान में भी प्रत्येक संघ गणराज्य को अपनी इच्छानुसार सोवियत संघ से अलग होने का अधिकार दिया गया है।^१ किसी अन्य सघीय शासन वाले देश के संविधान में हम इस समरूप उपबंध नहीं मिलता। सोवियत नेता संघ गणराज्यों के इस अधिकार को बहुत महत्व देते हैं और इसे सोवियत संघ के अंतर्गत स्वरूप (voluntary character) का प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। इस अधिकार का सांसारिक प्रयोग कहा तक समय है उस समय में लेण्का के विभिन्न मत हैं। अमेरिका पश्चात् लेखकों का यही मत है कि इस अधिकार का प्रयोग किया जाना असंभव है। लेनिन ने लिखा है कि समाजवाद के हित राग के ग्राम नियंत्रण के अधिकार से अधिक उच्च हैं।^२ इस वाक्य से सोवियत नेताओं द्वारा प्रतिपादित 'ग्राम नियंत्रण का अधिकार का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। विद्यमान तर्कों का सांसारिक अनुभव भी यही सिद्ध करता है कि इस अधिकार का प्रयोग किया जाना असंभव ही है। सन् १९३७ ई. के "शुद्धीकरण (purge)" में जिन राज्यों को क्रांतिविरोधी कार्यवाहियों के लिए दान्त किया गया था उनमें से अनेकों ने विरुद्ध सोवियत संघ को विपत्ति करने के लिए कार्य करने का आरोप लगाया गया था। उन व्यक्तिों में अनेक यूरेन ग्लाज़ोव, कामेगन तथा मध्य एशिया गणराज्यों के कम्युनिस्ट पार्टी संगठना के सदस्य

The right freely to secede from the U S S R is reserved to every union Republic — Art 17 of the Soviet Constitution

^२ Lenin's quoted by Torgler op cit p 61

ये। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट कर देता है कि सोवियत संघ स अलग होने का अधिकार प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं।

संघ गणराज्यों से निम्न श्रेणी के एकक—कृषि संघ-गणराज्य का ही सोवियत संघ का मुख्य एकक (constituent units) माना जाता है, परन्तु सोवियत संघ के केन्द्रीय विधान मण्डल के द्वितीय सत्र, जातिक सोवियत, में अन्य निम्न श्रेणी के एकक को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य जातिक सोवियत के ११ सत्रों में प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र में सदस्य, तथा प्रत्येक राज्य क्षेत्र १ सत्रों में निर्वाचित करता है। इन एककों की शक्तियाँ और पद समान नहीं हैं। स्वायत्तशासी गणराज्यों को अपना मन्त्रिपरिषद् रखने का अधिकार दिया गया है परन्तु उन्हें संघ गणराज्यों के समान सोवियत संघ से सम्बंधित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अतः वे उस संघ गणराज्य की जिसके क्षेत्र में वे अवस्थित हैं, के समान हैं। क्योंकि उनकी मन्त्रिपरिषद् के नियमों का संघ गणराज्य की मन्त्रिपरिषद् नियमित कर सकती है। तथा संघ-गणराज्य का सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम उन्हें रख कर सकता है संघ गणराज्य पर अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी स्वायत्तशासी गणराज्यों के अधिक तथा सांस्कृतिक विकास का भी उत्तरदायित्व होता है। स्वायत्तशासी गणराज्यों का यह गणराज्य की मानि किन्हीं नियमों पर स्वतन्त्र शक्ति भी प्राप्त नहीं है।

स्वायत्तशासी गणराज्यों की श्रेणी से निम्नतर श्रेणियों में स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा स्थानीय क्षेत्र आते हैं। इनकी शक्तियाँ स्वायत्तशासी गणराज्यों से भी अधिक सीमित हैं और उन्हें अपना मन्त्रिपरिषद् रखने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। संघ-गणराज्य का मन्त्रिपरिषद् इनका मन्त्रिपरिषद् के विनिश्चय का रख कर सकती है।

स्वायत्तशासी गणराज्यों, स्वायत्तशासी क्षेत्रों और स्थानीय क्षेत्रों का विभाजन कम संख्या वाला जातियों का स्वायत्तता प्रदान करने के लिए किया गया है। अनेक स्वायत्तशासी क्षेत्रों तथा स्थानीय क्षेत्रों का जनसंख्या तो कमल कुछ हजार है। अधिकांश स्वायत्तशासी गणराज्य तथा स्वायत्तशासी क्षेत्र रूसी गणराज्य

में ही हैं। रूसी गणराज्य में १२ स्वायत्तशासी गणराज्य, ६ स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा १ राष्ट्रीय क्षेत्र हैं। अथ सत्र गणराज्यों के स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों की संख्या इस प्रकार है। अजरबैजान गणराज्य—१ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा १ स्वायत्तशासी क्षेत्र बार्जिखा गणराज्य—२ स्वायत्तशासी गणराज्य तथा १ स्वा क्षेत्र उजबेक गणराज्य १ स्वा गणराज्य तथा ताजिक गणराज्य—१ स्वा क्षेत्र। स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा क्षेत्रों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। पिछले महायुद्ध के काल में पांच स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा क्षेत्रों को देशद्रोहिता के आरोपों के लिये निषेधित कर दिया गया था। रूसी गणराज्य के अतिरिक्त तब किसी संघ गणराज्यों में राष्ट्रीय क्षेत्र नहीं हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों की पदावृत्ति—स्तालिन सचिवानु के प्रारूप पर जिस समय सोवियत कांग्रेस में विचार किया जा रहा था उस समय एक संशोधन के द्वारा सचिवानु में यह उपबंध जोड़ देने का अनुरोध किया गया था कि उपयुक्त आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के तल पर पहुँचने के पश्चात् स्वायत्तशासी गणराज्यों को संघ गणराज्यों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। स्तालिन ने संशोधन के इस प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य का उपयुक्त आर्थिक और विकास के तल पर पहुँचने के पश्चात् स्वायत्तशासी गणराज्य बनाया जाना संभव नहीं है। स्तालिन ने किसी स्वायत्तशासी गणराज्य को संघ गणराज्य के रूप में परिवर्तित किये जाने के लिये तीन शर्तों का आवश्यक बताया था।

१ स्वायत्तशासी गणराज्य का सोवियत संघ की सामा पर स्थित होना चाहिये अर्थात्, उसे सब ओर से सोवियत संघ के प्रदेशों से घिरा नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा न होगा तो संघ गणराज्य बनने के बावजूद यह गणराज्य सोवियत संघ से अलग होने के अधिकार को प्रयोग न कर सकेगा।

२ जिस जाति के नाम पर किसी सोवियत गणराज्य का उसका नाम दिया गया है उसे उस गणराज्य में सुगठित बहुमत में होना चाहिए।

३ गणराज्य की जनसंख्या बहुत कम न होना चाहिये। कम से कम उसका जनसंख्या दस लाख अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह

सोचना गलत होगा कि कोई अन्य जनमर्या और अल्प सेना वाला गणराज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में अधिक समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा।^१

युनहायर में कई बार स्वायत्तशासी गणराज्यों का गणराज्य के रूप में परिणत किया गया है परन्तु यह पदानात किस विचार के आधार पर की गई यह बनाना कठिन है।^२

संघ तथा एककों के बीच शक्ति वितरण

संघीय शासन तथा एककों (units) के बीच शक्ति वितरण संघीय संविधानों का एक निश्चित लक्षण है। यह वितरण सामान्यतः तीन प्रकार से किया जाता है। कुछ संविधानों में केवल संघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख है, तथा 'अवशिष्ट' शक्तियाँ एकका को प्रदान की गई हैं। इसके विपरीत सावधान में एककों की शक्तियाँ स्पष्ट की जा सकती हैं और शेष शक्तियाँ संघ का प्रदान की जा सकती हैं। तीसरी पद्धति के अनुसार संघ और एककों के बीच शक्तियों का संविधान में स्पष्ट रूप में निरूपण कर लिया जाता है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ दोनों में से किसी एक का प्रदान की जाती हैं। सोवियत संघ के संविधान में इनमें से प्रथम पद्धति का अनुसरण किया गया है। उभय तरफ संघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख है और शेष शक्तियाँ को संघ गणराज्य के लिए सुरक्षित रखा गया है।

महायुग शासन का शक्तियाँ—सोवियत संविधान के बादहमें अनुच्छेद में संघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघीय शासन के क्षेत्राधिकार में निम्न विषय आते हैं—

(१) वैदेशिक सम्बन्धों में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करना, अन्य राज्यों से संधियाँ करना तथा उन्हें रद्द करना तथा संघ गणराज्यों के वैदेशिक राज्यों से सम्बन्धों को निश्चित करने वाली सामान्य प्रक्रिया निर्मित करना।

^१ St lin On the Draft Constitution pp 25

^२ According to Florensky 'the tiny Caucasian and Asiatic Republics were brought into existence by the whims of Moscow See Florensky op cit p 74

(२) युद्ध तथा शांति सम्बन्धी प्रश्न ।

(२) सोवियत सभ में नवान गणराज्यों को सम्मिलित करना, सगणराज्यों का सीमाओं में परिवर्तनों की पुष्टि करना, तथा सभ गणराज्यों - अन्तर्गत नवान प्रेशो क्षेत्रों वास्तविकता गणराज्यों एवं स्वायत्तशासी क्षेत्रों के निर्माण का पुष्टि करना ।

(४) सभ सविधान के कार्यपालन पर नियंत्रण रखना तथा सभ गणराज्यों के सविधानों की सहाय सविधान से अनुकूलता का सुनिश्चित करना ।

(५) राज्य एकधिकार (State monopoly) के आधार पर वैदेशिक व्यापार का संचालन करना ।

(६) राज्य का सुरक्षा का सुनिश्चित करना सोवियत सभ की प्रतिष्ठा का सगठन करना, सभ सयुक्त सभाओं का निर्देशन करना तथा सभ गणराज्यों के सैनिक सघनों के सम्बन्ध में निर्देशक सिद्धान्तों को निश्चित करना ।

(७) सोवियत सभ की राज्यीय आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना । सभ के सचित आवश्यक तथा उच्च कार्यक्रमों का आख्या का अनुमान करना तथा सभ-गणराज्यों और स्थानीय कार्य में करो और राजस्व की आय का वितरित करना ।

(८) मुद्रा तथा श्रम-व्यवस्था का निर्देशन करना । श्रम लेना तथा देना ।

(९) राज्यान्तर आर्थिक आकर्षण का समन्वय-व्यवस्था का सगठन करना ।

(१०) वैज्ञानिक तथा कृषि संस्थाओं एवं प्रगति सहाय महत्व के आंतर व्यवसायी के प्रशासन का अधीक्षण करना ।

(११) यातायात तथा परिवहन के प्रशासन का अधीक्षण करना ।

(१२) न्याय व्यवस्था तथा न्यायिक प्रक्रिया एवं व्यवहार और दंड संहिताओं के सभ में विधि निर्माण ।

(१३) सभ नागरिकता तथा विदेशियों के अधिकारों के सभ में विधि निर्माण ।

(१४) अखिल-संघीय चुनाव (massy) का आयोजन करना ।

(११) निम्नलिखित नियमों का मन्त्र म मौलिक सिद्धान्त निधारित करना

भूमि व्यवस्था (land tenure) अनिवार्य संपत्ति बना तथा जल का उपयोग शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य म संधी विधिया बिनाह तथा परिवार म विधिया ।

इन शक्तियों पर एक दृष्टि डालने से ही हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोनियत सधन संधीय शासन का क्षेत्राधिकार अत्यंत विस्तृत बना गया है । अतः संधीय शासन म जो नियम सामान्यतः एकका क क्षेत्राधिकार में होते हैं उनमें संधीय म सोनियत सधन म मौलिक सिद्धान्त निधारित करने का अधिकार संधीय शासन को दिया गया है । यह अधिकार इतना विस्तृत तथा व्यापक है कि संधीय शासन मौलिक सिद्धान्त निधारित करने की ग्राह्य म इन संधीय म मनचाही व्यवस्था कर सकता है । इस प्रकार देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन का प्रायः प्रत्येक पक्ष संधीय शासन की विधि निर्माण क्षमता के अन्तर्गत आ जाता है । इसी कारण भ्रूजार्किन्स्की ने संधीय शासन की शक्तियों को असामान्य रूप से 'वापक, विस्तृत तथा व्यापक बनाया है'।

केंद्राकरण की प्रवृत्ति—यहां यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्तालिन संविधान सोवियत नेताओं के चरम उद्देश्य, सत्ता के अधिकारों के केंद्राकरण, की ओर उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण पग था । ऐसी अनेक शक्तियां जो सन् १९२४ के संविधान म संधीय शासन के क्षेत्राधिकार म थीं इसके द्वारा संधीय शासन के क्षेत्र म स्थानांतरित कर दी गईं । सन् १९२४ के संविधान म संधीय शासन को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के संधीय म केवल एक सामान्य योजना तथा आगर निश्चित करने का ही अधिकार था । इसी प्रकार न्याय व्यवस्था तथा संधीय नागरिकता के संबंध म उसे मूल सिद्धान्त निश्चित करने का ही अधिकार था । परंतु नव संविधान म इन सब विषयों पर विधि निर्माण की पूर्ण शक्तियां संधीय शासन को दे दी गई हैं । सन् १९२४ के संविधान म संधीय शासन को केवल 'संधीय शासन का सीमाओं म परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों पर समायोजन (adjustment) करने का ही अधिकार दिया गया था, परंतु स्तालिन संविधान म उस संधीय शासन की सीमाओं

में परिवर्तन व प्रश्नों पर निष्काधिकार (veto) दे दिया गया है। वही प्रकार वंदोशक व्यापार और आम्यन्तरिक और बाह्य शृणों व सम्बन्ध में संघ गणराज्यों का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। जहाँ पिछले संविधान में संघीय शासन को केवल वंशिक व्यापार का निर्देशन करने का अधिकार था तथा संघ गणराज्यों को संघीय शासन की आज्ञा से आंतरिक तथा वैदेशिक शृण लेने की शक्ति प्राप्त थी, जहाँ अब यह शक्ति संघीय शासन व अन्य क्षेत्राधिकार (exclusive jurisdiction) में हैं। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि स्लानिन संविधान के निर्माताओं की सामान्य प्रवृत्ति सत्ता व केन्द्रीकरण की ओर ही थी।

सन् १९४४ के संशोधन का संघीय शासन का शक्तियाँ पर प्रभाव— प्रथम फरवरी, १९४४ को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम ने दो आनसिया जारी की जिनके द्वारा संघ गणराज्यों को दो अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। ये अधिकार निम्नलिखित हैं —

१. विदेशी राज्यों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने, तथा अंतरराष्ट्रीय करारों (Agreement) में भाग लेने का अधिकार एवं

२. अपनी वृद्ध सशस्त्र सेना का अधिकार।

यह अधिकार जतन महत्वपूर्ण हैं कि इन्होंने सोवियत संघ को संघ राज्य के स्थान पर एक संयुक्तमंडल—(Confederation) का रूप दे दिया। परन्तु इन अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगें हैं उनसे कारण उनका सारा महत्व समाप्त हो जाता है। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है संघीय शासन का जतन विषयों के सम्बन्ध में क्रमशः 'सामान्य प्रक्रिया तथा निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित करने की शक्ति' दी गई है। जबकि परिणामस्वरूप संघ और एकका के वैचारिक सम्बन्धों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। अधिकांश लेखकों का यही मत है कि सन् १९४४ के संशोधन संघ राज्यों को अधिक स्वायत्तता दिये जाने के लिए नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण किये गये थे। उनका एकमात्र प्रावहारिक परिणाम यही हुआ कि सोवियत संघ के दो संघ गणराज्यों (एलास तथा यूक्रेन) को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हो गई और इस प्रकार उस संघ में सोवियत संघ का अपने दो समर्थक प्राप्त हो गए। सोवियत

संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के सर्व-यापी प्रभाव के कारण, तथा अब तक के अनुभव के आधार पर, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन दोनों संघ-गणराज्यों ने प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोवियत संघ के प्रतिनिधि का ही अनुकरण करके। न तो अब तक किसी संघ गणराज्य ने अपने पृथक् मैम्य सङ्गठन का ही निर्माण किया है और न किसी वैदेशिक राज्य से प्रत्यक्ष सम्बंध ही स्थापित किया है। इस कारण इन संशोधनों को हम कन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का विरोधी नहीं मान सकते।

जुलाई, १९४४ में प्रेसीडियम द्वारा जारी का गई एक अव्यवस्थापति से निश्चित रूप से सघीय शासन की शक्ति में वृद्धि हुई। इस अव्यवस्थापति के द्वारा सघीय शासन का विवाह तथा परिवार सम्बंधी विधियाँ के संघ में मौलिक सिद्धान्त निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। सोवियत शासन के प्रारम्भिक काल से सन् १९४४ तक पारिवारिक संबंधों पर विधियाँ बनाने का अधिकार संघ गणराज्यों को प्राप्त था। उपरोक्त अव्यवस्थापति ने इसे एक समन्वय (Concurrent) विषय बना कर सघीय शासन के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की। यह वृद्धि सोवियत संघ में सत्ता के कन्द्रीकरण की प्रवृत्ति की परिचायक है।

केंद्र की शक्तिशाली बनाने वाले कुछ अव्यवस्थापक—सोवियत संघ में केन्द्र शासन केवल इसी कारण शक्तिशाली नहीं है, कि संविधान में उसे अन्यतम मिली शक्तियाँ दी गई हैं। इसके अन्य अनेक कारण भी हैं। सोवियत संघ के समस्त एकक समान नहीं हैं। उनमें जनसंख्या तथा भूक्षेत्र की दृष्टि से महान् अंतर है। अतः रूसी गणराज्य का क्षेत्रफल सोवियत संघ के क्षेत्रफल का लगभग तीन चौथाई भाग है, तथा उसकी जनसंख्या सोवियत संघ की सम्पूर्ण जनसंख्या के आधे से अधिक है। ऐसी स्थिति में केन्द्र में उसका प्राधान्य होना स्वाभाविक ही है। यहाँ हमें यह याद रखना चाहिये कि यद्यपि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के द्वितीय सदन में समस्त संघ गणराज्यों का समान प्रतिनिधि बनने का अधिकार दिया गया है परन्तु उसमें भी रूसी गणराज्य के प्रतिनिधि का महत्त्व रहता है। इसका कारण यह है कि रूसी गणराज्य में अनेक स्वतन्त्रशासी गणराज्य स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, निम्न

जातिक सोवियत में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस कारण रूसी गणराज्य के क द्वारा अन्य सभी गणराज्यों पर प्रबल प्रभाव रखता है।

सोवियत संघ में वसूली का एक प्रमुख कारण उसने संविधान के संशोधन तथा निर्वाचन की पद्धति है। संघीय राज्यों का संविधान संघ तथा एककोई अन्य एक प्रकार का संविधान (Contract) होता है जिसे दोनों पक्षों की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है, तथा दोनों पक्षों में से कोई पक्ष उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। सोवियत संघ का संविधान का विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। वहां संविधान में संशोधन करने के लिए एकका की सहमति का आवश्यकता नहीं है बल्कि केंद्रीय सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। सांविधानिक संशोधन के द्वारा संघीय शासन के क्षेत्राधिकार में चाहे कितनी बढ़ी जा सकती है। इसलिए एककोई को भी शक्ति प्राप्त है वह सर्वोच्च सोवियत के द्वारा संघ को दी जा सकती है। यद्यपि यह सिद्ध हुआ है कि सांविधानिक संशोधन के लिए सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन की भागीदारी आवश्यक नहीं है। प्रेसीडियम की शक्ति से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऐसी शक्तियों पर सर्वोच्च सोवियत की स्वायत्ति का बल औपचारिक होता है। इसी प्रकार संविधान का निरूपण (Interpretation) करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय रखता है जो स्वयं स्वतंत्र प्राधिकारी का न देकर प्रेसीडियम का सौंपा गया है, जो स्वयं सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में यदि केंद्र द्वारा सर्वोच्च सोवियत अपना शक्तियों का सीना लाने कर कोई ऐसा अधिनियम पारित करता है जो संघ गणराज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सोवियत संघ में उस प्रबंध को करने का सामर्थ्य रखने वाली कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार संविधान में संशोधन करने का प्रक्रिया तथा उसका निर्वाचन करने की पद्धति यह दोनों ही बातें व केंद्रात्मकता में संश्लेषण हैं।

सोवियत संघ में संघीय शासन का शक्तिशाली बनाने में उन सांविधानिक व्यवस्था का माध्यम था है जिनके अनुसार केंद्रीय सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम संघ गणराज्यों की मंत्रिपरिषदों के विनिश्चयों को विधिसंगत न

ज्ञान पर रण कर सकता है, तथा सोवियत संघ की मजि पण्डित उनके निनिश्चयों का निलम्बित कर सकता है।^१ संघाय शासन यमस्था म यह आवश्यक होता है कि किसी प्राधिकारी (Authority) का यह शक्ति प्राप्त हो कि वह विभिन्न एककों तथा संघ न ग्रीव सन्तुजन का भग न होने दे परन्तु संघीय कार्य-पालिका को हा यह अस्मिन् दे देने से एकका की स्वायत्तता सुरक्षित नहीं रह सकती। यहा यह उल्लेखनीय है कि एककों की मात्र परिणाम में कन्द्रीय मजि-पण्डित न अनेक प्रतिनिधि रहत हैं जो साविधानिक दृष्टि स तो सम्भवत परमशताता मात्र हा होते हैं, परन्तु यवहार में संघ-गणराया क शासनो पर पयान नियन्त्रण रखते हैं। कन्द्रीकरण इस यमस्था का स्वाभाविक परिणाम है।

संघीय शासन का शक्तिशाली बनाने में एक अन्य पन्नाधिकारी तथा उसके विभाग का भी पर्याप्त योग है। यन् पन्नाधिकारी सोवियत संघ का महान्यायवाणी (Proc rator General) है। सोवियत संघ क सभी भागों में उसके विभाग क पन्नाधिकारी तथा कमचारी रहते हैं जो स्थानीय तथा संघ-गणरायिक अधिकारियों के प्रभाव स सवथा मुक्त हात हैं। व सब कवल सोवियत संघ क महान्यायवाणी क प्रति उत्तरनाया होत हैं जा सर्वोच्च सोवियत क द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यह तथ्य ध्यान में रखत हुए कि न्यायवाणियों (Procur tors) की स्थापति से किछा सोवियत नागरिक को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चन काल क लिए बन्नी बनाया जा सकता है, इस विभाग क कमचारियों का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है।

सोवियत संघ में संघीय शासन का शक्तिशाली बनाने वाला अतिम महत्वपूर्ण तत्व कम्युनिस्ट पार्टी का सवकारी प्रभाव है। सोवियत शासन क। सभी महत्वपूर्ण नीतियां कम्युनिस्ट पार्टी क उच्च नेताओं अथवा उक्त प्रेसी किम क द्वारा ही निधारित की जाती हैं। विभिन्न शासनागों का काय तो इन नातियों को कायान्वित करना तथा औपचारिक रूप देना ही होता है। कम्युनिस्ट पार्टी क उच्च नेता सामान्यतः सभी शासन में महत्वपूर्ण पदों पर काय करते हैं इस कारण कन्द्रीय शासन का अधिक शक्तिशाली होना स्वाभाविक ही है।

सघीय शासन तथा एककों के बीच वास्तविक सम्बन्ध—सांविधानिक विधि कुछ भी क्यों न हो, सोवियत सङ्घवात् की यथार्थ प्रकृति समझने के लिए हमें सङ्घ तथा एककों के बीच वास्तविक सम्बन्धों पर विचार करना होगा। ऊपर हम सङ्घ तथा एककों के राजनीतिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाल चुके हैं। इस विवेचना से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि सोवियत संविधान में समस्त सङ्घ गणराज्यों की समानता तथा “संप्रभुता की प्रत्याभूति की ग” है, परन्तु सोवियत सङ्घ में ऐसे अनेक तत्व विद्यमान हैं जिनके कारण सभी महत्वपूर्ण विषयों पर वह केन्द्र का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य है। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का आधार योजनामय आर्थिक नीति होती है। सोवियत सभ में एककों के आय व्यय तथा उनकी योजनाओं में एकसूत्रता स्थापित करने का कार्य सघीय शासन द्वारा सम्पन्नित किया जाता है। अपने इसी अधिकार के अन्तर्गत सघीय शासन एककों की ग्राम नीति का निर्देशन करता है।^१ राष्ट्रीय योजना में एककों के विकास की ओर ध्यान न दिया जाता हो, ऐसी बात नहीं है। सोवियत सभ के मध्य एशियाई भागा द्वारा की गई प्रगति उसका प्रमाण है। परन्तु आर्थिक आयोजन में सम्पूर्ण सोवियत सभ के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष के विकास पर नहीं। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप एक क्षेत्र के साधनों का दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। बरन्तर में सोवियत सभ की अर्थ-व्यवस्था अपनी ही एकीकृत है जितनी किसी एकीकृत राज्य की।

सोवियत नेता प्रायः सोवियत सभ के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक स्वायत्तता पर बहुत अधिक जल देते हैं। व्यवहार में भी सोवियत सभ की विभिन्न जातियों तथा उसके विभिन्न क्षेत्रों को अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने तथा उसका विकास करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त है। परन्तु यह स्वतन्त्रता भी असीमित नहीं है। सोवियत नेताओं का अंतिम उद्देश्य समस्त जातीय संस्कृतियों का एक समान संस्कृति में सम्मिलन है।^२ सोवियत शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य

^१ देखिए अनुच्छेद ११।

^२ “The n t o l c ltu must e permit d to d v l p

ऐसी समान सृष्टि का निर्माण करना भी है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा के सम्बन्ध में "सामान्य सिद्धान्त" निर्धारित करना मरीय शासन का एक कृत्य है। यह तब कि जहाँ सोवियत शासन के प्रारम्भिक काल में सोवियत सघ की राष्ट्रीय अनेकता (national diversity) पर विशेष बल दिया जाता था वहाँ अब उसकी राष्ट्रीय एकता पर अधिक बल दिया जाता है, सघथा महबहीन नहीं है।^१

सोवियत सघ की कुछ अन्य सघ रायाँ म तुलना—सोवियत सघ क अतिरिक्त सघाय यवस्था वाले अन्य प्रमुख देश समुक्त राय अमेरिका, आंग्लिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और भारत हैं। सन्धेप में हम यहाँ सोवियत सघाय यवस्था की इन रायों की सघीय यवस्था म तुलना करेंगे।

सघीय यवस्था का एक प्रमुख लक्षण होता है सन्धिधान की सबप्रधानता त म उसकी अनम्यता। उपरोक्त सभी देशों के सन्धिधान लिखित तथा अनम्य हैं, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा और प्रनम्यता समान नहीं है। जहाँ समुक्त राय अमेरिका और आंग्लिया क सन्धिधान म सशोधन करन की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल भिन्न हुई है, वहाँ स्विट्जरलैंड, भारत और सोवियत सघ म सन्धिधान में बहुत जल्दी-जल्दी पम्धितन किए गए हैं। सोवियत सघ क सन्धिधान में सशोधन करने का प्रक्रिया इन सभी दशा ने सन्धिधाना म सरल ह। जेसा हम पहले उल्लख कर चुक हैं, केवल सघीय शासन का ही एक अग, सगोच्च सोवियत, एककों का मत जाने निना ही उसे सशोधित कर सकता है। ऐसी व्यवस्था उपयुक्त दशों में से अन्य किसी क सन्धिधान म नहीं है। यह तथ्य इस निष्प

and e p and to reveal all their pote ti l qualities in order to c e te the conditions necess ry for their fusion into a single common cultur with a singl , common language '—St lin s speech at the Sixteenth Party Cong ess

^१ A few years ago the current expression met in Soviet writings was the interests of the peoples (plural) of the Soviet Union In the 1st years the term the Soviet People (singular) has come to be used —Harper & Thomp on op cit p 56

की ओर सन्नत करता है कि सोवियत संघ की व्यवस्था इन अन्य सभी देशों की व्यवस्था की तुलना में अधिक उन्नत है।

प्रायः सभी सघीय सामधाना में केन्द्रीय विधान मण्डल द्विसदनात्मक रखा जाता है। इसका कारण यह है कि विधान मण्डल के द्वितीय सदन के द्वारा सघीय शासन में संघ में सम्मिलित होने वाले एककों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। परन्तु रचना और शक्तियों की दृष्टि से उपयुक्त संघ सघीय राज्यों के विधानमण्डलों के द्वितीय सदन समान नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और आस्ट्रेलिया के सघीय विधान मंडलों में समस्त एककों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और कनाडा और भारत में असमान। सोवियत संघ के संविधान में जातिक सोवियत में समस्त संघ-राज्यों को समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है परन्तु संघ-राज्यों से निम्नतम श्रेणी के एककों को भी जातिक सार्वभौम में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह एक विशिष्ट लक्षण है। शक्तियों की दृष्टि से सोवियत संघ की जातिक सोवियत सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन में है।

संघीय व्यवस्था का एक अन्य प्रमुख लक्षण शक्ति वितरण है। विभिन्न सघीय राज्यों में संघ और एककों के बीच शक्ति वितरण भिन्न सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है। जहाँ कनाडा तथा भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को दी गई हैं, वहाँ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड आस्ट्रेलिया और सोवियत संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ एककों को प्राप्त हैं। सोवियत संघ में एककों को कुछ ऐसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य संघ राज्यों के एककों का प्राप्त नहीं हैं उदाहरणार्थ संघ से तलग होने का अधिकार, पृथक सैन्य संगठन रखने का अधिकार तथा विदेशों से प्रत्यक्ष सम्बंध स्थापित करने का अधिकार आदि। परन्तु यह आश्चर्य, कहा तक व्यवहार किए जा सकते हैं, यह कहना कठिन है। इस जितनी शक्तियाँ सोवियत संघ के केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं उतनी अन्य किसी संघ-राज्य में केन्द्र को प्राप्त नहीं हैं। भारत का केन्द्रीय सरकार को संघ राज्यों में सर्वाधिक शक्तिमान केन्द्रीय शासन माना जाता है परन्तु सोवियत संघ की केन्द्रीय सरकार को उससे भी अधिक शक्ति प्राप्त है।

संघीय व्यवस्था का अन्तिम प्रमुख लक्षण न्यायिक प्रधानता (Judicial Supremacy) को माना जाता है। भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि संघीय देशों में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ तो इतनी अधिक हैं कि उसे 'कांग्रेस का तृतीय सदन' तथा 'संविधान का संतुलन चक्र' कहा जाता है। सोवियत संविधान में न्यायिक प्रधानता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ विधान मण्डल ही शासन का सर्वप्रधान अंग है। 'स्विट्ज़रलैंड' के संविधान में भी न्यायिक प्रधानता के सिद्धान्त को अंगीकृत नहीं किया गया है, परन्तु वहाँ विधान मण्डल को संविधान का निराकर न करने देने के लिए एक अन्य व्यवस्था की गई है। वहाँ मतदाता विधान मण्डल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर लोक निर्णय (Referendum) की मांग कर सकते हैं तथा लोक निर्णय में उस रू कर सकते हैं। सोवियत संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

आधुनिक काल में सभी संघ संस्थाओं की प्रवृत्ति सत्ता के केन्द्रीकरण की ओर रही है परन्तु सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में यह प्रवृत्ति अन्य संघ संस्थाओं से अधिक है। इसका कारण जानना कठिन नहीं है। सोवियत संविधान के निर्माताओं ने संघवाद का एक अस्थायी एवं अन्तःकालीन युक्ति के रूप में अंगीकृत किया था, मूल सिद्धान्त के रूप में नहीं। इस सम्बन्ध में सोवियत संघ के कण्ठधारों के विचारों में अभी भी काँट परिलतन नहीं हुआ है। केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति उनका इन्हीं विचारों की शोथक है। सोवियत संविधान में संघीय व्यवस्था के अपनाए जाने पर भी अनेक ऐसे उपबन्ध मिलते हैं जो इस निष्कर्ष की आर सक्त करते हैं कि सोवियत संघ एक संघ संस्था न होकर एक संघमण्डल (Confederation) है परन्तु व्यवहार में वह सभाधिक केन्द्रीकृत संस्थाओं में है।

अध्याय ७

सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत

स्तालिन संविधान के अनुसार सोवियत सभ का राज्य शक्ति का उच्चतम अंग सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत (Supreme Soviet) है।^१ सोवियत संघ का शासन — अन्य अंग इसके प्रति उत्तरदायी हैं। अनुच्छेद ३२ के अनुसार सोवियत सभ की विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग अनन्य रूप से सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही किया जाता है। सभ शासन के क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर विधियाँ बनाने का अधिकार इस प्राप्त है।

संविधान की विशेषताओं पर विचार करने समय यह उल्लेख किया जा चुका है कि सोवियत सभ के सहाय निधानमाल, अर्थात् सर्वोच्च सोवियत, के दो सदन हैं। उनमें से एक सदन का नाम सभ सोवियत (Soviet of the Union), और दूसरे का नातिक सोवियत (Soviet of the Nationalities) है। सभ सोवियत के सदस्यों का निर्वाचन सोवियत सभ के समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। इसके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नातिक सोवियत के सदस्यों का निर्वाचन भी सोवियत सभ के समस्त वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है परन्तु इसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता। संविधान में यह निश्चित कर लिया गया है कि प्रत्येक सभ गणराज्य (Union Republic) स्वायत्तशासी गणराज्य (Autonomous Republic) स्वायत्तशासी प्रांत (Autonomous Province) तथा राष्ट्रीय क्षेत्र (National Region) कितने सदस्य निर्वाचित करेंगे। इसी व्यवस्था के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं।

^१ The highest organ of state power in the U.S.S.R. is the Supreme Soviet of the U.S.S.R. — *Constitution of the U.S.S.R.* Art 30

द्विमन्त्रात्मक विधानमंडल ही क्या ?—यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि जब सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का निर्वाचन समस्त नागरिकों द्वारा एक ही साथ तथा एक ही अवधि के लिए किया जाता है तो विधानमंडल को द्विसद नामक बनाने की ही क्या आवश्यकता थी। जब दोनों सदन के संस्य सोवियत नागरिकों का ही प्रतिनिधित्व करने हैं, तो क्या एक सदन ही पर्याप्त न होता ? हम प्रश्न का उत्तर में सोवियत नेतागण सोवियत संघ के अनुज्ञात स्वरूप की ओर इंगित कर विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व देने के लिए द्वितीय सदन की आवश्यकता पर जल दते हैं। संविधान निर्माण के समय स्वयं स्तालिन ने जातिक सोवियत का प्रस्ताव देने के प्रस्ताव का विरोध किया था।^१ रूसी लेनक कार्पिन्सकी ने द्वितीय सदन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है "सोवियत संघ के नागरिकों के मुख्य हित बिना किसी राष्ट्रीयता या जाति के समान हैं। उन सभी हितों का हमारे राज्य की सर्वोच्च सभा में प्रतिनिधित्व सब सोवियत के संस्यों के द्वारा किया जाता है। परन्तु इस अतिरिक्त सोवियत संघ में निवासर करने वाली विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों के अपने विशेष हित भी हैं जो कि प्रत्येक जाति के लोगों की विशिष्ट राष्ट्रीय विशेषताओं तथा भाषा जीवन तथा सभ्यता की विशिष्टताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न राज्यों के इन विशेष हितों का हमारे राज्य का सर्वोच्च संस्था में प्रतिनिधित्व जातिक सोवियत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।"^२

अधिकतर सहाय शासन वाले देशों में द्वितीय सदन का निर्माण संघ में सम्मिलित होने वाले एककों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है। उस विधि में समस्त एककों को द्वितीय सदन में समान संख्या में प्रतिनिधित्व भंडने का अधिकार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया

^१ देखिए स्तालिन का आठवां सोवियत कांग्रेस के समक्ष २५ नवम्बर १९३६ को दिया गया भाषण।

^२ V. Karpinsky *The Social and State Structure of the USSR* p 114

आदि में द्वितीय सभना का संगठन इसी आधार पर किया जाता है। परन्तु सोवियत सभ में ऐसा नहीं है। यहाँ न केवल सभ में सम्मिलित एककों को ही बल्कि उनका अन्तर्गत स्थित विभिन्न स्वायत्तशासी गणराज्यों, स्वायत्तशासी प्रान्तों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों का भी जातिव सोवियत के सभस्य चुनने का अधिकार दिया गया है।

उपराक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सोवियत सभ में विधान मण्डल को द्विसन्नामक बनाने का उद्देश्य न तो इंग्लैंड के लार्ड्स सरीखे किसी बग विशेष को प्रतिनिधित्व देना था और न सभ में सम्मिलित होने वाले एककों को। सैद्धान्तिक दृष्टि से इसका उद्देश्य निश्चित रूप से सोवियत सभ की विभिन्न जातियों को केन्द्रीय विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व देना था। कार्पेन्मका के मतानुसार जातिव सोवियत राष्ट्रीय गणराज्या, प्रदेशों तथा क्षेत्रों की आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देती है। यह सोवियत सभ की सर्वोच्च सभ्या में स्वतन्त्र सोवियत जातियाँ ४ लोगों के विशेष हितों का पालन निधित्व करती है। स्तालिन विशेष रूप से ऐसी सभ्या के निर्माण के लिए प्रयत्नशील था और सन् १९२१ के अपने एक भाषण में भी उसने ऐसी सभ्या के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया था।

सर्वोच्च सोवियत की रचना

सभ सोवियत तथा जातिव संगठन सेना सोवियत सभ के नागरिका तथा निर्वाचित की जाती हैं। १८ वर्ष या उस से अधिक आयु के समस्त नागरिकों को सभ सोवियत तथा जातिव सोवियत दोनों के निर्वाचनों में भाग लेने का अधिकार है। इस नियम के दो ही अपवाद हैं प्रथम, विभिन्न उक्ति तथा द्वितीय ऐसे अपवादों के लिये दत्त उक्ति जिनके दम में मताधिकार में वंचित किये जाने का विधान है निर्वाचनों में भाग नहीं ले सकते। सभ सोवियत (Soviet of the Union) के निर्वाचना के लिए २, जनसंख्या के लिये एक सभस्य (deputy) के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाते हैं। जातिव सोवियत का निर्वाचन सभ-गणराज्या स्वायत्तशासी गणराज्या, स्वायत्तशासी

प्रान्तों और राष्ट्रीय क्षेत्रों के अनुसार होता है। प्रत्येक संघ गणराज्य को २५, प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य को ११, प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रान्त को ५ और प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र को १ सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार होता है। उस संघसभा के परिणाम स्वरूप "जातियों की सोवियत में १, , जनसंख्या के हिसाब से गणना भी उतनी ही (२५) प्रतिनिधि भेजता है जितने ३, , निम्न संघसभा वाली आरमीनिया या लिथुनिया जिसकी जनसंख्या २, , अनिवार्य है।" १ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संघ सोवियत के सदस्यों का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर होने के कारण रूसी गणराज्य को उसने लगभग आधे स्थान प्राप्त हैं।

सोवियत संघ का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु २३ वर्ष या उससे अधिक है सर्वोच्च सभियत का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। नागरिकों में जाति, राजाजता, लिंग, धर्म, शिक्षा, अधिवास, सामाजिक श्रेणी, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा या पूर्व कार्यवाहियों के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता।

सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का निर्वाचन सार्वजनिक, समान और प्रत्यक्ष मतधिकार के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। सन् १९२३ के संविधान की व्यवस्था में स्तालिन संविधान द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सन् १९३७ के पूर्व सोवियत संघ में केवल ग्राम और नगर सभियतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था शेष सभी सोवियतों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता था। निम्न सभियतें उच्च सोवियतों के सदस्य निर्वाचित करती थीं। मतधिकार पर अनेक प्रतिबंध थे। दूसरों के मत से लाभ उठाने वाला, निजी व्यापारियों, धर्माधिकारियों, जारशाही के अधीन पुलिस अधिकारियों तथा जार परिवार के व्यक्ति आदि को मतधिकार में बहिष्कृत रखा गया था। मतदान गुप्त रीति से न हो कर प्रकट रीति से हाथ उठा कर किया जाता था। साथ ही निर्वाचन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (territorial representation) के स्थान पर मानस्यिक प्रतिनिधित्व (Occupational representation) के आधार पर होता था। सन् १९४६ के संविधान के प्रवर्तित होने के पश्चात् सन् १९३७ में सभियतों के निर्वाचन सार्वजनिक, समान और प्रत्यक्ष मतधि

कारक आधार पर शुद्ध रीति से हुए। अब, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अबल विधिमां और विशिष्ट अपराधियों को छोड़ कर सब नागरिकों को मतदाताधिकार प्राप्त है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही निर्वाचित करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है। सोवियत संघ की सेना में सेवा करने वाले नागरिकों का भी अन्य नागरिकों के समान ही निर्वाचित करने का अधिकार है। ग्राम और नगर सोवियतों से लेकर संघीय सोवियत तक के समस्त नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किये जाते हैं।

सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन—१२ सितम्बर, १९२७ को नए संविधान के अनुसार प्रथम बार सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुआ। संविधान के द्वारा सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल ४ वर्ष निश्चित किया गया है। इस कारण अगला निर्वाचन १९४१ में होना चाहिए था। परन्तु सन् १९४१ के अग्रस्त माह में नाज़ी आक्रमण ने उत्पन्न परिस्थिति के कारण निर्वाचन न हो सका। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् सन् १९४६ में सर्वोच्च सोवियत के दोनो सभा के निर्वाचन कराए गए। तब से निरन्तर चार वर्ष का अवधि के पश्चात् सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुना है। वर्तमान सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन फरवरी १९५४ में हुआ था।

सब सोवियत तथा जातिक सोवियत के निर्वाचन के लिए सोवियत संघ के राज्यक्षेत्र को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सब सोवियत के निर्वाचन के लिए प्रति तान लाख निवासियों का एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। इस प्रकार सोवियत संघ में उतने निर्वाचन क्षेत्र हैं जितने वहां की पूर्ण जनसंख्या की तीन लाख से भाग देने से प्राप्त होते हैं। जातिक सोवियत के निर्वाचन के लिए प्रत्येक संघ गणराज्य को पचीस निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य को ग्यारह क्षेत्रों में तथा स्वायत्तशासी प्रान्त को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र का जातिक सोवियत के निर्वाचन के हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। सन् १९२४ के सर्वोच्च सोवियत के निर्वाचन के लिए कुल १३३१ निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें से ७ संघ सोवियत के निर्वाचन के लिए थे और ६३१ जातिक सोवियत

के निवाचन के लिए। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सभी निवाचन क्षेत्र एक-सदस्यीय होते हैं, अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य निर्वाचित करता है। सोवियत सभ के राज्य क्षेत्र के बाहर स्थल या जलसेना में सेवा करने वाले सोवियत नागरिकों के लिए विशेष निवाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के निवाचनों का संचालन करने के लिए एक केंद्रीय निवाचन आयोग (Central Election Commission) तथा उसके अधीन अनेक अन्य आयोग नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय आयोग की नियुक्ति सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम (Presidium) के द्वारा निवाचन की तिथि से कम से कम पचास दिन पूर्व की जाती है। यह निवाचन करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करता है, इस बात की देखभाल करता है कि निवाचन सम्बन्धी विधियाँ का पशुरूप पालन किया जाता है, और निवाचन आयोगों के द्वारा अनियमितताओं का शिकायती पर विचार करता है तथा उन पर अन्तिम निर्णय देता है।

सर्वोच्च सोवियत के निवाचन का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग प्रत्याशियों का नामांकन (nomination) है। संविधान के अनुच्छेद १४१ के अनुसार प्रत्याशियों को नामांकित करने का अधिकार सावन्तिक संगठना तथा जनप्रतिष्ठानों की संस्थाओं—कम्यूनिस्ट पार्टी संगठन, श्रमिक संगठन, सरकारी संस्थाएँ, युवक संगठन तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ—का प्राप्त है।^१ निवाचन सम्बन्धी विधियों में कुछ और ऐसा संस्थाओं के नाम जोड़ दिए गए हैं जिन्हें प्रत्याशियों का नामांकित करने का अधिकार प्राप्त है। ये हैं श्रमिका, नियोजिता, सैनिक तथा श्रमिक कृषकों तथा अन्य कृषकों की सामान्य सभाएँ। प्रत्याशियों से किसी प्रकार की 'सिक्योरिटी' आदि जमा नहीं कराई जाती। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च सोवियत के निर्वाचन में किया गया सम्मेलन सोवियत सभ में

^१ Candidates are nominated by election districts. The right to nominate candidates is secured to public organisations and societies of the working people Communist Party Organisations Trade Unions Co-operatives Youth organisations and cultural societies —Art. 141 of the Soviet Constitution

राज्य द्वारा वहन किया जाता है।^१ नामांकन निर्वाचन से कम से कम तीस दिन पूर्व होना चाहिए। निम्न निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि यदि निर्वाचन के नियमों से संबंधित कोई गान पूरी नहीं है तो वह प्रयाशी का नामांकन अस्वीकार कर सकता है। निम्न निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित दो तिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। केन्द्रीय आयोग का निम्नलिखित इस सम्बन्ध में अंतिम होता है।

सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन सोवियत संघ के सभी भागों में एक ही दिन होता है। निर्वाचन रविवार को ही होता है जिससे जनता मतदान में सुविधापूर्वक भाग ले सके। मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को मत पत्र दिया जाता है जिस पर सभी प्रत्याशियों के नाम अंकित रहते हैं। मतदाता को उसके पश्चात् एक एकान्त कमरे में जाकर बरतल उस प्रयाशी के नाम के त्रितिरिक जिसे वह मत देना चाहता है अन्य प्रत्याशियों के नाम काट देना होते हैं, और मतपत्र को पटी में ढाल देना होता है। मतदान समाप्त हो जाने के पश्चात् मतगणना की जाती है। जिस प्रयाशी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में गले गए समस्त मतों का पूरा बहुमत प्राप्त हो जाता है, वही विजयी माना जाता है। यदि किसी प्रयाशी का मतों का पूरा बहुमत प्राप्त नहीं होता या यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या का आध से भी कम भाग अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो पुनः मतदान कराया जाता है। किसी प्रत्याशी के मतों का पूरा बहुमत प्राप्त न करने की दशा में बरतल दो सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशियों के लिए पुनः मतदान कराया जाता है, सब के लिए नहीं। यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि व्यवहार में पुनः निर्वाचन कराने की कमी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रायः सभी स्थानों के लिए एक एक प्रयाशी ही होता है। यदि मतदाताओं का पूरा बहुमत उम्मेदवार समर्थन नहीं करता तभी पुनर्निर्वाचन की आवश्यकता पड़ सकती है।

सोवियत संघ में निर्वाचन का एक लोकोत्सव का रूप दे दिया जाता है। यद्यपि प्रायः सभी स्थानों के लिए क्वचन एक ही प्रयाशी खड़ा होता है, परन्तु

^१ Art 11 of the Regulations Govern g Elections to the Supreme Soviet of the U S S R

निर्वाचन व पूर्व पर्याप्त प्रचार किया जाता है। प्रचार में प्रयाशियाँ के तीन और उनकी सेवाओं पर प्रकाश डाला जाता है और ज़रूरतों से सोवियत संघ की वर्तमान परिस्थितियों की तुलना कर साम्यवादी ढंग की सेवाओं का प्रचार वणन किया जाता है। सन् १९३७ में निर्वाचन व पूर्व किए गए प्रचार का वणन करते हुए प्रसिद्ध पत्रिका राहुल जी में लिखा है “निर्वाचन व वक्तव्य धूम धाम से देश के कोने कोने में प्रचार किया गया था। रशियों का स्तेमान हुआ था। लोगों की सराय में छपने वाले अखबारों में लेख लिख गए। उम्मेदवारों के फोटो व साथ न न उलूख निकाले गए। दामन और मोर बर्सा में रंग प्रिणी रोशनिया और साइनबोर्डों से प्रचार किया गया। लेनिनग्राद में तो मैंने देखा कुछ नई दमास्ता पर उम्मेदवारों के १ १ हाथ ऊँच-ऊँचे चित्र लगे हुए हैं। उम्मेदवार तथा दूसरे जन-नायक सभाओं में व्याख्यान देते थे। उनका धारणन व बातें फिल्म तैयार करके चौकों और खुला जगहों पर निललाये जाने थे। चुनाव के तीन चार दिन पहले से तो लेनिनग्राद में हर पचास गन पर शर प्रसारक वज्र लगा दिए गये थे, और मान्का तथा दूसरी जगहों में होत उसन वक्त धारणन का ब्रान्कास्ट किया जाता था। सारा नगर इस ब्रान्कास्ट से शब्दात्मान हो रहा था।”

सर्वोच्च सोवियत के सदस्य—सोवियत प्रवक्ता सर्वोच्च सोवियत को जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों की संस्था मानते हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए वे पुनः पुनः संसद की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सर्वोच्च सोवियत के सदस्य जनसभाय जनानि नहीं होंत प्रयुक्त जनता के सभी भागों के प्रतिनिधि होते हैं। फरवरी १९४९ में निर्वाचन में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत के १२२६ सदस्यों में से ५११ अधिक ३४८ कृषक तथा ४७६ कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, यथाप्रा तथा बुद्धिजीवी (intellectuals) थे।^१ अन्य देशों में प्रशासनीय कर्मचारियों का प्रधान मन्त्र का सदस्य बनने का अधिकार नहीं होता, परन्तु इस विषय में सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत के सदस्य का एक सम्पूर्ण भाग ऐसे कर्मचारियों का ही होता है। सन्

^१ राहुल साङ्गखान, सोवियत भूमि, भाग २, पृष्ठ २१।

^२ Ogg & Zink, *Modern Foreign Governments* ■ 856

१९३७ में निर्वाचित सदस्यों में २७ ऐसे अधिकारी थे तथा ६५ संसद सभा में कार्य कर रहे थे। सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में स्त्रियों की संख्या भी अन्य देशों की तुलना में अधिक होती है। सन् १९४६ में २७७ स्त्रियां सर्वोच्च सोवियत के सदस्य निर्वाचित हुए। यह संसद सर्वोच्च सोवियत की पूर्ण संसद का लगभग २ प्रतिशत है। सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में हमें कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिक, कृषक, लेखक, अधिकारी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यवसाय और सभी वर्गों के व्यक्ति मिलते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के अधिकांश सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं, परन्तु सभी सदस्य पार्टी के सदस्य नहीं होते। जैसा इसके पूर्व उल्लेख किया गया है सोवियत संघ के संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी के अनिरीक्त भी कुछ संस्थाओं को प्रशासिकों का नामांकन करने का अधिकार दिया गया है परन्तु वे सभी राजनीतिक संस्थाएँ हैं जैसे, युवक संस्थाएँ, श्रमिक संगठन आदि। इनके द्वारा नामांकित किये जाने वाले प्रत्याशी भी मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों को मानने वाले होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित होते हैं। सन् १९३७ में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत में पार्टी के सदस्यों की संसद पूर्ण सदस्य संसद का ७६२ प्रतिशत तथा १९४६ में निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत में ८१ प्रतिशत थी। मनरो के मतानुसार 'सर्वोच्च सोवियत सम्पूर्ण सोवियत संघ के राजनीतिक दृष्टि से विनाशपात्र ऐसे लोगों की तात्कालिक सम्मान के योग्य समझ जाते हैं, सूक्ष्म दशन हैं।' निर्वाचन के पूर्व प्रत्येक क्षेत्र का कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से विचार विनिमय कर ऐसे प्रत्याशी का हवा नामांकित कराने का प्रयत्न करते हैं जो पार्टी के सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत हों। टाउस्टर का विचार है कि यदि शासन या वर्तमान नेतृत्व के प्रति विरोध भाव रखने वाले किसी व्यक्ति का नामांकन हो भी पाये तो अधिक सम्माननीय यह है कि क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग उस प्रत्याशी का पञ्जीकरण (Registration) करने से नकार कर देगा। इसका कारण यह

The Soviet system of the politically reliable people of the entire Soviet Union who refer it to the election hono —M nro & Ayca t o c t p 643

है कि क्षेत्रीय निवाचन आयोगों के अधिकार सत्स्य कम्यूनिस्ट होते हैं।^१ मनरो ने प्रयाशिया के जानाकन तथा पजीररख के बाद निवाचन काल में ऐसे प्रयाशियों के, जिनका कम्यूनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं था, नाम हटाये जाने तथा उनके स्थान पर दूसरे के नाम रखे जाने के उदाहरण का उल्लेख किया है।^२ उपरोक्त कारणों से ऐसे प्रक्रिया का सर्वोच्च सावित्र का सत्स्य निवाचन होना निह कम्यूनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं है, अतः भय ही है।

सत्स्यों के कृत्य विशेषाधिकार, तथा भत्ते—सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों का सोवियत प्रजा जनता के समस्त अथवा सर्वोच्च सावित्र में जनता के दूत कह कर उल्लेख करने हैं। प्रत्येक सत्स्य का यह कृत्य माना जाता है कि वह अपने निवाचकों के अपने तथा सर्वोच्च सावित्र के कार्यों के बारे में विचार दे। सत्स्य में अपने निवाचकों से निरंतर सम्पर्क बनाए रखना तथा उनकी शिकायतों का जल्द निवारण को दूर कराने का प्रयत्न करना उसका प्रधान कृत्य है। सत्स्य का अपने कृत्य का भली-भांति गुण करने के लिये कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सर्वोच्च सोवियत के किसी सत्स्य का बिना सर्वोच्च सोवियत की महमति के बंदी नहीं बनाया जा सकता, या उस पर मुकद्मा नहीं चलाया जा सकता। जिस समय सर्वोच्च सावित्र का सत्र न हो रहा हो तब किसी सत्स्य को गृही बनाने या उस पर मुकद्मा चलाने के लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रेसामियम की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।^३ प्रत्येक सत्स्य सरकार से या उसका किसी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे प्रश्नों का लिखित या अलिखित उत्तर तीन दिन का अवधि के भीतर दिया जाना आवश्यक है। सर्वोच्च सावित्र के प्रत्येक सत्स्य का सावित्र सच के

^१ J. L. Towster *Political Process in the U. S. S. R* 1917 194, p. 194

^२ Muir & Aycarst *Ibid*, p. 662 also Towster *Ibid* 194

^३ अनुच्छेद ५२

^४ अनुच्छेद ७३

सभा रेल तथा जल मार्गों पर निशुल्क यात्रा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

प्रत्येक सदस्य को सर्वोच्च सावित्त का वत्स में भाग लेने पर एक निश्चित दर ^४ अनुसार दैनिक भत्ता मिलता है। इसका अतिरिक्त उन्हें प्रति मास अपने कर्तव्यों का पूर्ति के लिए किए गए व्यय का प्रक्षिप्त रूप में भी भत्ता मिलता है।

निर्वाचका का प्रत्यावतन का अधिकार (Right to Recall)—सोवियत संघ के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह सर्वोच्च सावित्त में अपने प्रतिनिधि के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वे उसे पुनरावर्तित कर सकते हैं, और उसका स्थान पर दूसरा सदस्य को निर्वाचित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो पार्लामेन्ट प्रजातन्त्र देशों के नागरिकों का प्राप्त नहीं है।^१ संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में भी राज्याधिकारियों का जनता द्वारा पुनरावर्तित किए जाने का व्यवस्था है। ओरेगन राज्य में तो न्यायाधीशों का भी पुनरावर्तित किया जा सकता है। परन्तु अमेरिका में भी विधानमण्डल के सदस्यों का पुनरावर्तित करने का अधिकार निर्वाचकों का नहीं दिया गया है। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का यह माना जाता है परन्तु वहाँ भी निर्वाचकों का प्रत्यावतन का अधिकार प्राप्त नहीं है।

सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल तथा विघटन—सर्वोच्च सावित्त के दोनों सत्रों का कार्यकाल संविधान द्वारा चार वर्ष निश्चित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद ४७ के अनुसार यदि किसी प्रश्न पर सर्वोच्च सावित्त के दोनों सदन में विचार उपलब्ध हो जाता है और वे दोनों उस पर एकमत नहीं हो पाते तो सर्वोच्च सावित्त का प्रेसिडियम दोनों सत्रों का निर्णय कर

^१ The constitutions of bourgeois countries = not in no such provision. There once the elections a over and the successful candidates have taken the seat. All relations between them and their constituents are at an end. —V Karpinsky, *op cit* p 102

उन नवान निवाचन कराने की आ । देता है । सर्वोच्च सोवियत का कायकाल समाप्त होने पर अगला उस न पृथ अनुच्छेद ४७ क अनुसार उसका विघटन किए जाने पर प्रसीन्धिम को अगधि समाप्त होने या विघटन होने की तिथि स दो माह न अन्दर ही नवीन निवाचन काने का प्राप्ति देना प्राप्तिश्यक है ।

सर्वोच्च सोवियत क दोना सत्रों के सत्रमा पर कम्युनिस्ट पार्टी क प्रभाव के कारण सविधान म विघटन क लिए आवश्यक तिस परिस्थिति का उल्लेख किया गया है उसक उत्पन्न होने की कोई स भावना नहा है । सन् १९२७ म लालिन स विधान क प्रवर्तिन होने से अग तक कभी सर्वोच्च सोवियत का विघटित करने की आवश्यकता नहा पकी ।

सर्वोच्च सविद्यत के पनाधिकारी—सर्वोच्च सोवियत के दोना सत्र अपने लिए एक सभापति तथा चार उप सभापति निवाचित करत हैं । सत्र सविद्यत तथा जातिक सोवियत क सभापति अपने अपने सत्रमा की बैठका की अध्यक्षता करत हैं तथा उनकी कायवाही तथा प्रक्रिया का सचालन करत हैं ।^१ संयुक्त सत्रा (Joint sessions) की अध्यक्षता सत्र सोवियत तथा जातिक सोवियत क सभापति बारी बारी स करत हैं ।^२ सर्वोच्च सोवियत का सत्र बहुत धा काल के लिए हाता है । शेष काल म दोना सत्रों के सभापतियों को अपने अपने सत्र क सत्रमा से सपक स्थापित रखने क लिए तीन लाख रुबल वार्षिक मिये जाने हैं ।

ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य अनेक देश म सत्र के जन्म सदन का अध्यक्ष (Speaker) अत्यन्त सम्मानित तथा प्रभावशाली व्यक्ति हाता है । इसका कारण यह है कि जहा एक सत्र म यनस्था बनाए रखने की दृष्टि से उसका काय अत्यन्त महत्वपूर्ण हाता है, वहा दूसरी सत्र उम कई महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त हाते हैं उदाहरणार्थ यह निणय करने का अधिकार कि कोई विषयक धन विषयक है अथवा नहीं । सोवियत सत्र की सर्वोच्च सोवियत न सत्रों क सभी सत्रमा या ता कम्युनिस्ट पार्टी क सत्रमा हाते हैं या साम्यवादी

^१ अनुच्छेद ४४

^२ अनुच्छेद ४५

सिद्धान्तों के समर्थक। इन कारण उनका आपको मेरे अवस्था नाए रहने की सम्मति उपरत हा नहीं हाता। आपको सन्नों के अधिकार पृथक् ग्यार हान कारण किहा सन्नों के प्रत्यक्ष की प्रिन्स का कानस सना के प्रत्यक्ष का माति को प्रिशाधिकार मा प्राप्त नहीं है।

सर्वोच्च सावियत के सत्र तथा कार्य प्रणाली

सर्वोच्च सावियत के सत्र—सर्वोच्च सावियत के प्रस्तावित की सर्वोच्च सोवियत के सत्र जुलाने का अधिकार है। संविधान के अनुसार वर्ष में कम से कम दो बार सर्वोच्च सोवियत के सत्र बुलाने का प्रावश्यक है। सर्वोच्च सावियत का प्रस्तावित स्वनिर्देशक सत्र किहा एक संघ-राज्य (Union Republic) के प्राव माग किए जान पर सर्वोच्च सोवियत के प्रस्तावित सत्र भी हो सकता है।^१ नव निर्वाचन के पश्चात् तीन माह का प्राधिकार प्रत्यक्ष सर्वोच्च सावियत का सत्र जुलाना जाना प्रावश्यक है। सर्वोच्च सावियत के नव-निर्वाचन के माग मा पूर्व सर्वोच्च सावियत का प्रस्तावित हा ता तक कार्य करता हा है जब तक नवान प्रस्तावित का निर्वाचन नहीं हा जाता। इस कारण नव निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत का सत्र मा पूर्व सर्वोच्च सावियत के प्रस्तावित द्वारा हा जुलाना जाता है। सर्वोच्च सावियत के सत्र सन्नों के सत्र सोवियत सत्र की राजधानी मास्का में अवस्थित क्रैमलिन (Kremlin) भवन में हाता है। सर्वोच्च सावियत के सत्र सन्नों में दशको और पत्रकारों के बैठने के लिए भी म्यान नियत है। प्रत्यक्ष सदन में सबप्रथम सत्र किहा वर्षावृद्ध सत्र का उद्घाटन-नाम्य हाता है।^२ उसक पश्चात् सन्नों सत्र प्रत्यक्ष सत्र समानास तथा उपसमापति का निर्वाचित करते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के सत्रों सत्रों में कोई विरोधा ल नहीं हाता इस कारण सदस्य प्रदर्शनाकार या गालाकार स्थिति में नहीं है। वे सत्रों में

प्रत्यक्ष ४६

सर्वोच्च सत्र में ग्रेट प्रिन्स का माति लीच प्राप्त कि दोन मा मात सत्र सत्र सत्र के माग मा किहा व्यक्त नहीं है।

का प्रारंभ मुँह कर इस प्रकार स्थान ग्रहण करते हैं जैसे व किमी संगीतशाला में बैठ हाँ।^१

सर्वोच्च सोवियत के दोना सदना व सत्र एक साथ ही प्रारंभ होते हैं, तथा एक साथ ही समाप्त होते हैं। प्रेसीडियम मन्त्रि परिषद् (Council of Ministers), उच्चतम न्यायालय, तथा सोवियत संघ के महान्यायाधीश (Procurator General) को निराचिन करने व लिए दोना सत्रना की संयुक्त बैठक होती है। जिस समय कोई नया विधेयक या प्रान्तीयक प्रस्तुत किया जाता है उस समय भी दोना सत्रनों का प्रस्ताव (move) का भाषण सुनने के लिये संयुक्त अधिवेशन होता है। इसमें समय का बचन होता है। महत्वपूर्ण प्रतिवेदन (reports) भी दोना सत्रना व संयुक्त अधिवेशन में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। परंतु सामान्यतः दोना सत्रना व सत्र प्रणाली अलग हाते हैं। संयुक्त अधिवेशन में भा विधेयका पर दोना सत्रना व सत्र अलग अलग मतदान करते हैं। संयुक्त अधिवेशन का अर्थवत्ता, तथा कि ऊपर उलान किया जा चुका है, दोना सत्रना के समापति प्रायः जारी स करत हैं।

सर्वोच्च सोवियत के आयोग तथा समितियाँ—संविधान के अनुच्छेद ५ व अनुसार संघ सोवियत तथा तात्विक सोवियत प्रमाण समितियाँ (Credentials Committees) निर्वाचिन करता है, ता अपने अपने सत्रना के सत्रना के प्रमाण पत्र (credentials) का परीक्षण करता है। प्रमाण समितियाँ की आस्था पर ही सत्रन यह निश्चित करत हैं कि किमी सदस्य के निराचन का प्रमाण कर लिया जाय या उस मान समझा जाय। संविधान में सर्वोच्च सोवियत को यह अधिकार दिया गया है कि उन भी वह आवश्यक समझ वह किसी विषय के अनुसंधान तथा परीक्षण के लिये आयोगों की नियुक्ति कर सकती है। सभी संस्थाओं तथा अधिकारियों का यह कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह ऐसे आयोगों की मांगों का पालन करें, तथा समस्त आवश्यक सामग्री तथा लेखपत्र आदि उनसे सम्मुख रखें।

^१ They occupy seats in a solid mass facing the stage as in a concert hall —Miro & Aycarst op cit p 66

दोनों सदन अपने प्रथम सत्र में कुछ स्थायी आयोग निर्वाचित करते हैं। दोनों सभना के स्थायी आयोग समान हैं। सक्षप में इनका विवरण निम्न लिखित है —

१ **यवस्थापक आयोग (Legislative Commission)**—यस आयोग का कार्य नए विधयका के प्रारूप पर विचार करना तथा स्वयं उनका प्रारूप बनाना है। यह ऐसे विधयका के प्रारूप तैयार करता है जो सर्वोच्च सोवियत के किसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सन् १९८८ में निर्वाचित सभ सोवियत तथा जातिक सोवियत के यवस्थापक आयोगों की संस्य संख्या १ थी परन्तु सन् १८४६ में निर्वाचित यवस्थापक आयोगों में १६ संस्य थे।

२ **आय-व्ययक आयोग (Budget Commission)**—यस आयोग का कार्य आय-व्ययक के प्रारूप पर विचार करना तथा उस पर सभन के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत करना है। सन् १९३८ में निर्वाचित आय-व्ययक आयोगों की संस्य संख्या १३ था परन्तु १९४६ में यह २७ हो गई।

३ **वर्शिक कार्य आयोग (Commission on Foreign Affairs)**—जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसका कार्य वैश्विक नाति से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करना तथा सभन के सम्मुख उन पर अपनी राय प्रस्तुत करना है। सन् १९३८ में निर्वाचित वर्शिक कार्य आयोगों का संस्य संख्या सभ सोवियत में १ तथा जातिक सोवियत में ११ था। सन् १८४६ में निर्वाचित दोनों सभना के आयोगों की संस्य संख्या ११ था।

उपरोक्त आयोग कार्य की सुविधा के लिए समय-समय पर उप-आयोग (Sub Commissions) की नियुक्ति करते हैं। इनके अतिरिक्त सभना में समय-समय पर विशेष आयोगों की भी नियुक्ति की जाती है जो महत्वपूर्ण विधयकों पर विचार करते हैं। दोनों सभना की समितियाँ या आयोग मन्त्रिपरिषद् द्वारा प्रस्तुत विधयका में सहायन प्रस्तावित करते रहते हैं। सर्वोच्च सोवियत की आय-व्ययक सम्बन्धी समितियाँ अपने कार्य को विशेषतया मन्त्र देती हैं। प्रत्येक वर्ष आय-व्ययक में वह महत्वपूर्ण परिवर्तना का सुझाव

देती हैं। यद्यथा यह परिवर्तन यथ व्रताने, न कि घटाने, की दिशा में होते हैं।^१

उल्लिखित समितियों व अतिरिक्त एक अन्य समिति का संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक है। यह समिति है सर्वोच्च सावियत की 'येठ सभ्य परिषद्' (Council of Elders)। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के येठ सभ्य सम्मिलित होते हैं। यह सर्वोच्च सोवियत के सत्रों व लिए कार्यक्रम आदि निश्चित करने में योग देती है, तथा बहुत से महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसी परिषद् के नाम से सर्वोच्च सोवियत में प्रस्तावित किये जाते हैं।

सर्वोच्च सोवियत के कृत्य तथा शक्तियाँ

संविधान के अनुच्छेद २१ के अनुसार सर्वोच्च सोवियत उन सभी अंगों द्वारा का प्रयोग करती है जो संविधान के चाहते हैं अनुच्छेद ५ अन्तर्गत राष्ट्रीय शासन का दिए गये हैं, जहाँ तक कि वे अधिकार उन संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आते जो कि सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी हैं। वे संस्थाएँ हैं सर्वोच्च सावियत का प्रेसीडियम, सावियत सभ्य का मान परिषद् (Council of Ministers), तथा सोवियत सभ्य व मन्त्रालय। अनुच्छेद १४ के आधार पर सर्वोच्च सोवियत के निम्नलिखित दून् तथा शक्तियाँ हैं —

१ युद्ध तथा शान्ति संधि की स्वीकृति करना।

२ सोवियत सत्र में नवान गणराज्या का सम्मिलित करना।

३ सत्र गणराज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का पुष्टि करना तथा सभ्य गणराज्या का सीमा में नवीन स्वायत्तशासी गणराज्या, स्वायत्तशासी प्रान्त, तथा क्षेत्र आदि के निर्माण का पुष्टि करना।

^१ The budget committees of the Supreme Council (Soviet) ordinarily take themselves especially seriously. Indeed they have a reputation for earnestly scrutinising every annual budget submitted by the finance minister and in the case of every budget at least some changes are recommended frequently in the direction of increasing rather than decreasing expenditures. — Ogg and Zink *Modern Foreign Governments* p. 858

- ४ यह निर्णय करना कि सङ्घ गणराज्य २ सविधान सावियत सङ्घ के सविधान के अनुरूप है या नहीं ।
५. वंशेशिक तथा सुरक्षा नाति के मूल सिद्धान्तों का निश्चय करना तथा सङ्घ गणराज्य और विदेशों के सम्बन्धों तथा सङ्घ-गणराज्यों के सैनिक सङ्गठनों में एकरूपता लाना ।
- ६ राज्य के एकाधिकार के आधार पर विदेशों का निश्चय करना ।
- ७ सोवियत सङ्घ का राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं का निश्चित करना ।
८. सावियत सङ्घ के आर्थिक नियम तथा नवम्ब कय आदि के प्रस्तावों का अनुमोदन करना ।
- ९ समस्त सङ्घ के लिए महत्व रखने वाले वैज्ञानिक और कृषि सम्बन्धी समस्याएँ, तथा व्यापारिक समस्याएँ और कारखानों एवं परिवहन तथा सञ्चार सुविधाओं आदि का प्रशासन ।
- १० धन तथा ऋण सम्बन्धी प्रणालियों का नियंत्रण करना तथा ऋण लेने तथा देने के प्रस्तावों का स्वीकृत देना ।
- ११ राज्य जमा समस्याओं का सङ्गठन करना ।
- १२ भूमि प्राकृतिक माधन, जलवायु आदि के उपयोग तथा शिक्षा लोक-स्वास्थ्य, श्रम, विवाह एवं परिवार आदि में सम्बन्धित विधियाँ के मूल सिद्धान्तों निधारित करना ।
- १३ न्याय-व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया, तथा दावानी एवं परीक्षा सहित आदि से सम्बन्धित विधियाँ बनाना ।
- १४ समस्त सङ्घ में सामान्य सम्बन्धी अधिनियम जारी करना ।
- १५ सावियत सङ्घ की नागरिकता तथा विदेशियों के अधिकारों से सम्बन्धित विधियाँ बनाना ।

इनके अतिरिक्त सर्वोच्च सावियत का अपने प्रेसन्सियम, मन्त्रिमण्डल तथा सर्वोच्च न्यायालय का निवाचित करने का अधिकार है । सर्वोच्च सोवियत सोवियत सभ के महान्यायवादी (Procurator General) को सभ वर्ष का अधि के

लिए नियुक्त करती है। यह पांच वर्ष की अवधि के लिए विशेष न्यायालया का भी निर्माण कर सकता है। सर्वोच्च सोवियत का सोवियत संघ के संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। इस अधिकार का सर्वोच्च सोवियत अब तक अनेक बार प्रयोग कर चुकी है। अतः म. नेद्वान्तिक दृष्टि से सर्वोच्च सोवियत को संप्रत्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार है क्योंकि म. परिषद् का संविधान द्वारा उक्त म. परिषद् उत्तरदायी रहना म. है।

संविधान के अनुच्छेद २० के अनुसार सोवियत संघ की विधि निर्माण की शक्ति का प्रयोग करके सर्वोच्च सोवियत के द्वारा ही किया जाता है। संविधान प्रस्ताव इस अनुच्छेद पर बहुत बल देता है और सर्वोच्च सोवियत का सोवियत संघ का एक मात्र विधि निर्माण संस्था घोषित करता है। व्यवहार में यह बात कहा तब सत्य है इस पर हम अभी आगे आगे विचार करेंगे।

विधि निर्माण प्रक्रिया (Law making procedure)—सर्वोच्च सोवियत में विधियाँ किस प्रकार पारित (पास) होंगी इस सम्बन्ध में संविधान में विस्तृत उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल इतना ही उल्लेख है कि संविधान संविधान के दोनों सदनों अर्थात् संघ संविधान तथा जातिक सोवियत का विधि निर्माण का सहायक करने का समान अधिकार है, तथा का विधि उसी समय अंगीकृत (adopted) समझी जायेगी जब यह सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन द्वारा संमत अनुमत से पारित कर दा जायेगा।^१ संविधान ने प्रवर्तित किए जाने से जब तक की कार्य प्रणाली के आधार पर हम विधि निर्माण सम्बन्धी निम्न प्रक्रिया का उल्लेख कर सकते हैं।

यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के सदन का भी विधायक प्रस्तुत करने का अधिकार है, परन्तु व्यवहार में सदन ही विधायक म. परिषद् या सर्वोच्च सोवियत के विधान सदन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी एक सदन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधायक का प्रारूप उस सदन का परामर्शक आयोग

^१ अनुच्छेद ३८

^२ अनुच्छेद ३६

(Legislative Commission) तैयार करता है, तथा उस का एक प्रतिनिधि वक्ता विधायक का नवाब सोनियत व सवत्र में प्रस्तुत करता है। सामान्यतः नवीन विधायक सत्रों के सावनत के दोनों सत्रों के संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाते हैं। सत्रप्रथम प्रस्तावक का भाषण होता है। प्रस्तावक व भाषण के पश्चात् दोनों सदन विधायक पर अलग अलग विचार करते हैं। ऐसे सभी विधायकों पर जो मति परिषद् की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं पहले व्यवस्थापक आयोग विचार करता है और सर्वोच्च सोनियत व सदनों में किसी विधायक पर वास्तु विधान आरम्भ होने के पूर्व पहला भाषण व्यवस्थापक आयोग के प्रस्ताव का ही होता है। वह विधायक की आयोग के दृष्टिकोण से आलोचना तथा आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात् सभा सत्रों की विधायक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। मति परिषद् के द्वारा प्रस्तावित विधायक पर वाद विवाद के पश्चात् एक मंत्री का भाषण होता है जो आलोचना का उत्तर देता है, तथा मति परिषद् का स्वाकृत संशोधनों का उल्लेख करता है। अंतिम भाषण व्यवस्थापक आयोग के अध्यक्ष का होता है। व्यवस्थापक आयोग के अध्यक्ष के भाषण के पश्चात् प्रस्तुत विधायक का प्रत्येक धारा पर अलग अलग मतदान होता है। संशोधन किए जाने के पश्चात् जिस रूप में विधायक स्वाकृत किया जाता है उस उसी रूप में सदन का पारित मान लिया जाता है। दोनों सत्रों में अलग अलग वृत्त प्रक्रिया के अनुसार विचार तथा मतदान होता है। एक सदन द्वारा विधायक को स्वाकृत कर लिए जाने पर मंत्री दूसरे सत्र में उसके द्वारा स्वाकृत संशोधनों का उल्लेख कर देते हैं, जिससे दूसरा सत्र भी उनसे परिचित हो जाता है। इन संशोधनों के प्रतिरिक्त भी यदि दूसरा सदन चाहे तो वह विधायक में कुछ और संशोधन कर सकता है। दोनों सत्र एक दूसरे के द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करते हैं और यदि वे एक ही रूप में विधान का पारित कर देते हैं तो विधायक का पारित मान लिया जाता है।

दोनों सत्रों में विवाद—यदि किसी विधायक के अंतिम रूप पर दोनों सत्र एकमत नहीं होते तो संविधान के अनुच्छेद ४७ में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रश्न का निपटारा कराया जाता है। किसी प्रश्न पर दोनों सत्रों के

असहमत होने की स्थिति में सत्रप्रथम एक समाधान आयोग (Conciliation Commission) का निमाण किया जाने की व्यवस्था है, जिसमें दाना सभना के बराबर प्रतिनिधि हों। यदि यह आयोग किसी समझौते पर पहुँचने में असफल रहता है, या इसका निष्पत्ति किसी एक सभना को माय नहो होना, तो उस प्रश्न पर दूसरी बार दोनों सभना में विचार होगा। यदि अब भी दाना सभना किसी ऐसे निश्चय पर नहो पहुँचते जो उन दोनों को माय हो तो सभोच सावियत का प्रेसाइडियम दोनों सभनों को भग कर नए निवाचन करएगा। यहा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यवहार में अभी तक दाना सभना के बीच कभी ऐसा गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके कारण सभोच सावियत को विघटित कर नवान निवाचन कराने की आवश्यकता पनी हो। सदन ही दाना सदन विधिका का एक ही रूप में पारित कर दन हैं।

आय-व्ययक—जिस प्रक्रिया का उल्लेख अभी हमने सामान्य विषयों के सम्बन्ध में किया है लगभग उन्ही प्रक्रिया का प्रयोग आय-व्ययक को पारित करने के लिए होता है। सामान्य विधरना की भांति आय-व्ययक भी सभोच सावियत में दाना सभना में संयुक्त अभिनयन में प्रस्तुत किया जाता है। आय-व्ययक प्रस्तुत करने का कार्य निम्न मंत्री का है। निम्न-मंत्री के भाषण के पश्चात् दोनों सभना अलग-अलग आय-व्ययक पर विचार करते हैं। सत्रप्रथम आय-व्ययक आयोग (Budget Commission) में प्रस्ताव का भाषण होता है जो आयोग की ओर से आय-व्ययक का आलोचना प्रस्तुत करता है तथा सभासदों के प्रस्ताव रखता है। "सक पश्चात् सभना में सभना को आय-व्ययक पर विचार करने और सभासद प्रस्तुत करने का प्रसर दिया जाता है। अतः निम्न मंत्री वाचन" का उत्तर देता है तथा यह नतलाता है कि कौन कौन सभासद स्थापित कर लिए गए हैं। "सक पश्चात् आय-व्ययक आयोग के प्रस्ताव का भाषण होता है और सदन के सभस्य आय-व्ययक में विभिन्न भाग पर अलग-अलग मत देने हैं। सामान्य विधरना की भांति आय-व्ययक का मा दाना सभना के द्वारा एक रूप में पारित किया जाना आवश्यक है।

सांविधानिक सभासद—सभोच सावियत का सोनियत सभ के सभासद

म सशोधन करने का भी अधिकार है। परन्तु सांविधानिक सशोधन का कोई प्रस्ताव तभी अंगीकृत माना जाएगा जब उसे दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से पारित करें।^१ सोवियत संविधान में सशोधन करने का अधिकार केवल सर्वोच्च सोवियत को ही प्राप्त है और इसका प्रयोग करने के लिए उसे किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी का मत जानना आवश्यक नहीं है।

सर्वोच्च सोवियत के वाच विचार—बाद विचार (D bat) विधि निम्नलिखित प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। वाच विचार में ही किसी विचारक के गुण-गौरव पर प्रकाश डाला जाता है, तथा उसमें बाह्यीय सशोधन स्पष्ट हो जाता है। सोवियत संघ में भी प्रत्येक प्रश्न पर सर्वोच्च सोवियत के सदन को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। परन्तु सर्वोच्च सोवियत के वाच विचार अन्य देशों के विधानमण्डल के वाच विचारों से भिन्न होते हैं। इसका कारण जानना कठिन नहीं है। सर्वोच्च सोवियत के सभी सदन, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है या तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं या पार्टी के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले तथा पार्टी द्वारा समर्थित रहते हैं। इसका विपरीत पश्चात्त मजार्तन देशों तथा भारत आदि की संसद में पूर्णरूपसे विपक्षी विचारों के सदस्य होते हैं जहाँ एक ओर ऐसे स्थितियों तथा कल्पनाओं का प्रतिरोध होता है जो प्रत्येक परिवर्तन का विरोध करती हैं वहाँ दूसरी ओर ऐसे आवरणों (E stems) सदन भी होते हैं जो वर्तमान अवस्था में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि पश्चात्त रात्रि के जनतांत्रिक देशों के निवासियों को सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के वाच विचार विचार प्रतीत हो।

सर्वोच्च सोवियत के सदन में लिए जाने वाले मासों में संसद शासन की भाँति के आधारभूत सिद्धान्तों की योजना बना करती है। समानता की शासन प्रणाली का विरोध करने वाले के लिए सदन में स्थान नहीं है। वाच विचार में मुख्यतः उस मंत्रालय के कार्य का आलोचना की जाती है जिसका

कार उस विधेयक का कार्यान्वित करना होगा।^१ सर्वोच्च सोवियत के सदस्य अपने अनुभव के आधार पर मन्त्रालय की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए अपने सुझाव भी देते हैं। सर्वोच्च सोवियत के कार्य विभाग की तुलना सामान्यतः सासनीय वाद विभाग से न कर एक प्रतिनिधि सम्मेलन (Delegates conference) के साथ विभाग से की जाती है। पेट स्लोन ने ऐसी ही तुलना करते हुए लिखा है, “प्रतिनिधि सम्मेलन में सभ्य अपने मत या स्थान विशेष की जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं प्रगत और उन्नति का विवरण देते हैं, कार्यकारिणी सत्ता के शासन प्रणाली की प्रक्रिया की आलोचना करते हैं, उन नई व्यवस्थाओं और नीति को प्रस्तुत करते हैं जिससे उनका संगठन जनहित में अधिक योग्यतापूर्वक कार्य कर सके। सावियन सभ की सर्वोच्च सोवियत के आख्याना में विशेषण से पता चलता है कि आमतौर से अधिकार प्रतिनिधियों के सम्मान इसी तरह होते हैं। कुछ लेखकों का भी यह भी कथन है कि सभ्य के भाषण भी पहले से तैयार किये गए होते हैं। उदाहरणार्थ मनरो का मत है कि “सभ्य भाषण ग्रन्थ देते हैं परन्तु उनमें उसी प्रकार की सामधान तैयारी के लक्षण स्पष्टगोचर होते हैं जैसे कि किसी निष्ठा के लिए किए गए प्रश्न में। उच्च अधिकारियों की आलोचना की जा सकती है और की जाती है परन्तु यह भी पहले से तैयार का हुआ तथा पार्ष्व के उच्चाधिकारियों के द्वारा अनुमानित प्रतीत होगी।”^३

^१ “It is not the text of the proposed legislation that has usually been the centre of attention but the actual work of the commissariat or ministry responsible for carrying it out — Samuel N Harper and R. Thompson *The Government of the Soviet Union* p 136

^२ Pat Sloan *How the Soviet State is Run* (हिन्दी अनु.), p 22

^३ ‘D debate, as we know it is unknown Speeches from the floor are made but all but the indications of careful preparation as in an arranged pageant Criticisms of particular high officials can and does occur This too would appear to be prepared and approved beforehand by the high command of the party’ — Munro & Aycarst, *op cit* p 663

बैदेशिक नीति मन्त्री प्रतिवटना (reports) पर सामान्यतः सर्वोच्च सोवियत मन्त्रालय विचार नहीं होता। सन् १९३७ में नए संविधान के प्रवर्तित होने से सन् १९४७ तक की प्रक्रिया का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस बीच कबल दो बैदेशिक नीति सम्बन्धी प्रतिवटना पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। प्रथम मई १९४२ की ऐंग्लो सोवियत सत्र पर जिसका दस सदस्यों ने अनुमान किया, तथा द्वितीय फरवरी १९४४ के संशोधन पर जिनके समर्थन में अनेक सदस्यों ने भाषण दिए। “परंपरा के अनुसार, प्रतिवदन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् एक प्रसिद्ध सदस्य उठ कर यह प्रस्ताव रखता है कि ‘शासन की बैदेशिक नीति की अत्यंत सुस्पष्टता तथा दृढ़ता को ध्यान में रखते हुए वास्तविकता न किता जाय तथा एक सक्षिप्त प्रस्ताव में शासन की विदेश नीति का पूरा अनुमान किया जाय। इसके पश्चात् दानों से दान सम्बन्धित से विदेश नीति का अनुमान कर देते हैं जैसा कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा अंगीकृत सभी निधियों तथा निष्कर्षों पर होता है।”^१

यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के अधिक सक्षिप्त (औसतन एक सप्ताह) होने के कारण मुख्यतः समितियां तथा आयोगों में ही वास्तविक विवाद होता है। इसी कारण अधिकांश संशोधन आयोगों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं।

सोवियत शासन प्रणाली में सर्वोच्च सोवियत का स्थान

यद्यपि सोवियत संघ के संविधान में सर्वोच्च सोवियत को राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग कहा गया है परंतु व्यवहार में ध्यान में रखने पर यह कथन उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। सोवियत संघ के लोगों के अतिरिक्त आधिकारिक लेखकों का यही मत है कि सर्वोच्च सोवियत में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय नहीं किया जाता, बल्कि वह अन्यत्र किए गए निर्णयों का अनुमान कर उन्हें औपचारिक तथा वैधानिक रूप दे देती है। इस परिणाम पर पहुँचने के अनेक कारण हैं, जिन पर हम यहां सक्षिप्त में विचार करेंगे।

उपरोक्त परिणाम पर पहुँचने का सबसे प्रथम कारण सर्वोच्च सोवियत के

^१ *Julia A. Towster op cit*, p 262

सत्रों का अल्पावधि है। सर्वोच्च सोवियत के सत्र की औसतन अवधि एक सप्ताह होना है, और एक वर्ष में दो सत्र होते हैं। सर्वोच्च सोवियत का सत्र करलान दिन में ही समाप्त हो जाने का उन्माहण दिया जा सकता है। एक वर्ष में कुल नितने समय समाच्च सोवियत की बैठक होती है, अन्य देशों में उनका समान कभी कभी एक ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार में लग जाता है। ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि परिषद् के अनुसार सामान्यतः वेशिष्ट नानि जसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भां सर्वोच्च सोवियत में वाद विवाद नहीं होता। असे यह सिद्ध होता है कि सर्वोच्च सोवियत अधिकतर दूसरे शासनागाली निणया की पुष्टि ही करता है।

संविधान में सर्वोच्च सोवियत का ही एकमात्र विधि निमात्री सस्था धारित किया गया है, तथा नए प्रयत्न किया गया है कि किसी दूसरी सस्था के निणया को विधि नाम से न पुकारा जा सके। यद्यपि संविधान में प्रेसाडियम तथा मंत्रि परिषद् का क्रमशः 'आज्ञातया' (Decrees) तथा 'निणय व आज्ञा' देश (decisions and ordinances) जारी करने का ही अधिकार दिया गया है परन्तु व्यवहार में उनमें और सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियां में कोई अंतर नहीं होता। प्रेसाडियम द्वारा सर्वोच्च सोवियत के विद्राति काल में समन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु सर्वोच्च सोवियत का समन अनुमोदन के पूर्व व पश्चात् समय तक लागू रह सकती हैं। उस अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व व पश्चात् समय तक लागू रह सकती हैं। उस समन उनमें और विधियां में कोई अंतर नहीं किया जाता। उन आज्ञातया का विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् न तो सर्वोच्च सोवियत में उन पर वाद विवाद होता है और न विचार, प्रत्युत् उनमें प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उन ही उन्हें अनुमोदित कर दिया जाता है। इस परपरा को ध्यान में रखते पर सोवियत प्रवक्तारों का यह कथन है कि सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत ही एकमात्र विधि निमात्री सस्था है, असंगत ही प्रतीत होता है।

'The practice is not to debate or discuss the decrees but to vote their approval as soon as they have been reported upon'—Julian Towster *op cit* p 261

सर्वोच्च सोवियत प्रत्यक्ष विचार का तबना किसी संसाधन के जैसा का तैसा स्वीकार कर लेती हो, ऐसी बात नहीं है। फ्रेडरिक आग और हैराल्ड जिन्क का मत है^१ कि इस विषय में कोई संशय नहीं है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर नियम पालिटब्यूरो (कम्यूनिस्ट पार्टी की राजनीतिक समिति)^२ के द्वारा किए जाते हैं, तथा सर्वोच्च सोवियत के द्वारा उनका विरोध या उनमें संशोधन किए जाने की संभावना नहीं है। परंतु सोवियत संघ जैसे बड़े तथा जटिल देश में बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन पर उनके अराजनीतिक अथवा क्रमागत (routine) स्वरूप के कारण पालिटब्यूरो का ध्यान नहीं जाता। यहाँ सर्वोच्च सोवियत को कार्य करने का अधिक अवसर होता है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले सदस्य ऐसे दृष्टिकोण उपस्थित कर सकते हैं जिनकी ओर मंत्रालयों का पहले ध्यान ही न गया हो। ऐसे विषयों में मंत्रिपरिषद् के द्वारा समय-समय पर अनेक संसाधन स्वीकृत कर लिए जाते हैं।

प्रचुरता में सर्वोच्च सोवियत में सभी प्रश्नों पर नियम संसन्मत् मत (unanimous vote) में किया जाता है। अन्य देशों के संसदों का यह एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रतीत होता है। सोवियत प्रणाली का कारण यह प्रचुरता है कि सोवियत संघ में वर्गभेदों (class differences) का अंत हो जाने के कारण सर्वोच्च सोवियत में सर्वस्य विरोधी हत्यों के संरक्षक तथा प्रतिनिधि नहीं होते। इसी तरह से उनमें किसी प्रश्न पर शीघ्र ही एक मत हो जाता है। परंतु इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत के मतदान की जनता के प्रतिनिधियों की शासन के प्रति आस्था तथा निष्ठा प्रदर्शित करने का एक अवसर माना जाता है। इसी कारण सर्वोच्च सोवियत को विदेशी लेखक सोवियत प्रचार-यंत्रण का एक अंग बतलाते हैं।

^१ Ogg, F. A. & Zink H. *Modern Foreign Governments* pp. 859-60

^२ पालिटब्यूरो का स्थान उन पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम ने ले लिया है।

सन् १९२७ से १९४७ तक व सर्वोच्च सोवियत व कमररग की विवेचना कर चूलियन टाउस्टर ने अपना मत पत्त किया है कि सर्वोच्च सोवियत ने अब तक मुख्यत एक अनुसमर्थन तथा प्रचार करने वाली संस्था व रूप में कार्य किया है। उसका प्रमुख कार्य समान समान पर, अथवा आवश्यकता पाने पर, शासन की नीति को एक प्रतिनिधि सभा के अनुमोदन से विभाषित कर देना प्रतीत होता है।^१ उसका बाट व उपाय अब तक सर्वोच्च सोवियत की कार्य प्रणाली में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ जिससे इस कथन की सत्यता प्रभावित हुई हो। उस्तुन, सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत की हम प्रान्त या प्रास का पालमट से तुलना नहा कर सकते। सत्तीय शासन प्रणाली वाले देशों में संसद या पालमट देश की स्वशक्तिमान् संस्था होता है जा मानमल का पद युक्त कर सकती है। यत्रापि यह सत्य है कि सामान्यत पालमेट भी मन्त्रिमल व निष्ठा का ही अंगीकृत कर लेती है परन्तु पालमेट तथा मन्त्रिमल ने निनिश्चया का अस्वाकृत कर देने तथा उस प्रकार उस पर्याय करने व लिए विवश करने व उठाहरणा का संस्था अभार नहा है। सोवियत संघ का सर्वोच्च सोवियत ने सब में यह न नहा कही जा सकता। इसी कारण उसे ब्रिटेन या प्रास की पालमट अथवा अमरिका की कांग्रेस व समरूप नहीं माना जा सकता।

^१ Though theoretically the sole legislative organ in the Soviet system the Supreme Soviet, like its predecessors — the Constituent Assembly and the Congress of Soviets — has so far operated primarily as a ratifying and propagating body. Its chief purpose appears to be periodically on occasion demand, to lend the voice of approval of a representative assembly to governmental policy — Julian Towster, *op cit* P 263

अध्याय ८

सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम

संश्लिष्ट सच का सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम (अध्यक्ष मन्त्र) सोवियत सच की सारसत्ता का सर्वोच्च स्थायी कृत्यकारी अंग है। इसे ऐसी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो अन्य देशों के सावधाना में राज्य के सांख्यिक प्रधान, मन्त्रिपरिषद्, विधान मंडल के उच्च सदन, विधान-मन्त्र, तथा उच्चतम न्यायालय को दी जाती हैं। इसके कृत्यों में कार्यपालिका-सचवा (executive) प्रशासन (administrative), विधायक (legislative), तथा न्यायिक कृत्य सम्मिलित हैं। अन्य किसी देश के संविधान में प्रेसीडियम के समान का सस्था नहीं है। इसी कारण हम एक अनुपम सस्था कहा जाता है।

सोवियत शासन व्यवस्था में प्रेसाडियम का प्रादुर्भाव—आल्ताविक क्रांति के पश्चात् ७ नवम्बर, १९१७ का संश्लिष्ट सोवियत शासन सस्था में प्रेसाडियम की कोई सस्था नहीं था। प्रेसीडियम का प्रादुर्भाव अनाधिकारिक (unofficial) सस्था के रूप में हुआ जिस कन्दान कार्यकारिणा समिति (विधान मन्त्र) ने सस्थापित किया था। यद्यपि पुनः १९१८ में अंगीकृत रूसी सोवियत सघान सनानवाग गणराज्य के संविधान में प्रेसाडियम के संश्लिष्ट कार्यो अधरा शक्तियों का उल्लेख नहीं था परन्तु उस समय तक वह कार्य करने लगा था। उस समय वह वहा काम करता था जो उसे कन्दान कार्यकारिणा समिति (C. E. C.) के गरा सौंप जात थे। इसी गणराज्य के संविधान के निमात् लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् प्रेसीडियम को अधिकारक मान्यता प्राप्त हुई। दिसम्बर १९१९ में सप्तम् अग्निल रूस सोवियत कांग्रेस ने कन्द्रीय कार्यकारिणा समिति के प्रेसाडियम के निम्नलिखित कृत्य बताए अर्थात् रूसी कन्द्रीय कार्यकारिणा समिति के सत्रों का संचालन करना, समिति के सत्रों में विचारार्थ सानआ तैयार करना, आह्वानियों के प्राह्वों का समिति के सनद निचार के लिए सूत्रगत करना समिति के निर्णयों का पालन करना,

जमादान की याचिकाओं पर विचार करना उपाधिया तथा पदक देना, तथा समिति के तत्परमान का मचन कानसार परिषद् (Council of People's Commissars) के निखुना की पुष्टि करना अथवा उह निलविन करना, आदि। उह आरकार पत्रात महत्पण है। उह गान् मां सानियत काप्रसों के निखुना के अनुसार प्रेसीडियम के प्राचराय तथा कृता म वृद्धि हुइ।

साविन सत्र के प्रथम सविधान (१६४ म प्रबन्धन) के तारा प्रेसीडियम का प्रनिष्ठा आर शक्तियां म और वृद्धि हुइ। इस सविधान म कन्द्रीय कार्य कारिणी समिति के प्रेसीडियम को समिति के सत्रा के बीच के काल म सोनियत सत्र की सत्ता का सर्वाच्च विवायक (legislative), कार्यपालिका (executive) तथा प्रशासनीय अग जनाया गया था।^१ प्रेसीडियम म कन्द्रीय काव कारिणी समिति के दोना सन्ना के सभापति सम्मिलित होत थे जा गरी गरी से इसकी बैठका की अयच्छता करते थे। प्रेसीडियम का आगप्तिया जारी करने सर्वोच्च न्यायालय के सभापति तथा उसभापति को नियुक्त करने तथा केन्द्रीय तथा स्थानीय सोवियत सस्थाओं में विना उत्पन्न होने पर समायोजना करने की शक्तिया प्राप्त हो गई, जिसम वह सावियत शासन अवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अग बन गया। यद्यपि सविधान म सविधान का निर्नचन (interpretation) करने की शक्ति कन्द्रीय कार्यकारिणी सामिति तथा उसके प्रसाडियम दोना को ही दी गई था, परन्तु व्यवहार म प्रेसीडियम ही इस शक्ति का प्रयोग करता था।

सन् १९३६ में नवान सविधान के निमाण के समय प्रेसीडियम की न्ययोगिता के कारण उरो शासन के स्थायी कृत्यकारी अग के रूप में घना रहने लिया गया। यद्यपि प्रेसीडियम की सदस्य-सख्या, संगठन तथा शक्तियों म कुछ परिवर्तन किए गए, परन्तु इन परिवर्तनों से उसका स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं आया। (नवीन सविधान में विधान-मंडल के सदनों के पीठासन पदाधिकारियों (Presiding officers) को सम्मिलित करने की व्यवस्था का अंत-कर दिया गया। इसका कारण यह बताया जाता है कि

^१ See Articles 26 & 29 of the Constitution of 1924

क्याकि वे सर्वोच्च सोवियत संघ सभा का संचालन करते हैं जिसके प्रति प्रेसीडियम उत्तरदायी है, उन्हें प्रेसीडियम का सन्स नहीं होना चाहिए।

प्रेसीडियम की रचना तथा संगठन—सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन एक संयुक्त सत्र में प्रेसीडियम का निर्वाचन करते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रेसीडियम में एक अध्यक्ष सोव्ह उपाध्यक्ष, एक मंत्री, तथा पंद्रह सामान्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार प्रेसीडियम में कुल इमलाकर तैंतीस सदस्य होते हैं। यद्यपि संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है, परन्तु परम्परा के अनुसार प्रेसीडियम के सन्स सर्वोच्च सोवियत के सन्सों में से ही चुने जाते हैं।^१ उपायक्षा की संख्या इतनी अधिक होने का कारण यह है कि सोवियत संघ के प्रत्येक संघ-गणराज्य (Union Republic) से प्रेसीडियम का एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। संविधान के प्राप में मूल चार उपायक्षा के निर्वाचन की व्यवस्था थी। परन्तु एक संशोधन में यह मांग की गई कि इस संख्या को बढ़ा कर ग्यारह^२ कर दिया जाए, जिसमें प्रत्येक संघ-गणराज्य से एक उपायक्षा चुना जा सके। इस संशोधन का स्वन स्तालिन ने समर्थन दिया और इसे मंजूर कर लिया गया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान में सोवियत संघ में धार्मिक देशों के सम्मिलित हो जाने के कारण संघ-गणराज्यों का संख्या सोव्ह हो गई, और इसी कारण एक संविधानिक संशोधन के द्वारा प्रेसीडियम के उपायक्षों की संख्या बढ़ा कर सोव्ह कर दी गई। एक परिपाटी के अनुसार संघात सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के उपाध्यक्ष संघ-गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियमों के अध्यक्ष हो जाते हैं।^३ सन् १९४६ तक प्रेसीडियम के सामान्य सन्सों का संख्या चौदास थी परन्तु उस वर्ष इसे घटा कर पंद्रह कर दिया गया।

^१ Julian Towster cit p 266

^२ S. K. pin ky of cit p 118

^३ उस समय संघ-गणराज्यों की संख्या ग्यारह ही था।

^४ Julian To s c cit p

सन्निधान के प्रारूप पर प्रस्तुत किए गए सशोऽना में से एक में यह प्रस्ताव रखा गया था कि प्रेसोनियम के अग्रदूत का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत द्वारा नहीं बल्कि देश की सम्पूर्ण जनता द्वारा होना चाहिए। स्तालिन ने इस सशोधन का विरोध करत हुए इसे सन्निधान का मूल मानना न प्रतिकूल बताया था। स्तालिन ने अपना मत व्यक्त किया था कि “हमारे सन्निधान की परम्परा व अनुसार सन्निधायक सभ का अग्रदूत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस सम्पूर्ण जनता सर्वोच्च सोवियत न समान आधार पर चुने और जो सभासद सोवियत न निराश में अपने का स्थिर रख सके। सोवियत सभ का अग्रदूत सामूहिक है (अर्थात् सर्वोच्च सोवियत का प्रेसोनियम निम्न प्रेसोनियम का अग्रदूत भा सम्मिलित है), जिसका निर्वाचन सम्पूर्ण जनता द्वारा न किया जा कर सर्वोच्च सोवियत द्वारा किया जाता है, और जो सभासद सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। इतिहास से प्राप्त अनुभव यह बताता है कि सभासद सभा का ऐसा लक्ष्य सभासदक प्रभावशाली है और यह देश का अनभिलाषित घटनाओं से सुरक्षित रखना है। सोवियत लेनक ‘अनभिलाषित घटनाओं का’ अर्थ स्पष्ट करत हुए नेपोलियन वृत्तार्थ अर्थ का हटात देत हैं, जो जनता व नगर निर्वाचित अग्रदूत न जनता व नगर निर्वाचित विधानमण्डल का प्रवहना की। उनका मतानुसार प्रेसोनियम का निर्वाचन का वर्तमान परम्परा संशोधन है क्योंकि वही इसका द्वारा प्रेसोनियम एक और जनता न प्रतिनिधि। नगर निर्वाचन तथा उनका प्रति उत्तरदायी होने न कारण सम्पूर्ण जनता के प्रति का प्रतिनिधि करता है वही दूसरी ओर इसमें सभी सभ गणराज्य के प्रति का सम्मिलित होने न कारण यह विभिन्न राष्ट्रीयताओं व हितों का भी प्रतिनिधित्व करता है।

प्रेसीडियम का कार्यकाल—सामान्यतः प्रेसोनियम का कार्यकाल चार वर्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक नगर निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत नए प्रेसोनियम का निर्वाचित करता है। नगर प्रेसोनियम न निर्वाचित निये जाने तक पुरानी सभासद सोवियत का प्रेसोनियम ही कार्य करता रहता है इस कारण उसका कार्यकाल चार वर्ष से अनन्त माह अधिक भा हो सकता है। यदि सर्वोच्च सभासद व दाना सभा में किसी प्रश्न पर विवाद होने के कारण उसे विघटित कर दिया जाता है तो नगर निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत नए प्रेसोनियम का निर्वाचित करता है। ३४

लिए प्रेसीडियम का कार्यकाल चार वर्ष से कम भी हो सकता है। उस प्रतिरिक्त प्रेसीडियम सत्राच्च सावियत व प्रति उत्तरदायी होता है, उसलिय सर्वोच्च सावियत किसी भी समय प्रेसाडियम व सत्स्था में परिवर्तन कर सकता है।

महायुद्ध जनित्र निशेध परिस्थितिया व कारण सन् १९१७ में निर्वाचित प्रेसीडियम सन् १८४ तक कार्य करता रहा परन्तु यह एक अपवाद है।

प्रेसीडियम के अध्यक्ष क कृत्य—सोवियत संविधान म न ता प्रेसाडियम क अध्यक्ष को कि हा शक्तिया का उल्लेख है और न उस क कृत्या का। वास्तव में उसे अपने पद के कारण को शक्तिया प्राप्त नहीं हैं। वह सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित निर्णय तथा प्रेसीडियम की आज्ञाप्तियों पर हस्ताक्षर ग्रहण करता है, परन्तु उस उन पर को अभिप्रायधिकार (veto) प्राप्त नहीं है वह विदेशा क राजदूत व प्रमाण पत्र हए करता है और कुछ आपत्ताकि अनसरा पर सम्मानपूण पद भी ग्रहण करता है परन्तु वह सत्ता प्रेसीडियम व प्रतिनिध क रूप में ही यह सत्र कार्य करता है। यद्यपि उस कभी कभी सोवियत संघ का अध्यक्ष (President) कह कर भी संबोधित किया जाता है परन्तु उसका समस्त प्रभाव पाटा का एक प्रमुख नेता होने व कारण ही होता है अपने उच्च पद व कारण नहीं।

सालिन संविधान व अनुसार निर्वाचित प्रथम प्रेसीडियम व अध्यक्ष कालिनिन (M I Kalinin) थे जो कम्युनिस्ट पार्टी क उच्च नेताओं म थे। उनकी मृत्यु क पश्चात् तून १९४६ में सर्वोच्च सावियत ने एन एन श्वरनिक (N M Shv nik) को प्रेसाडियम व अध्यक्ष पद व लिए चुना। श्वरनिक अगिल सहाय श्रमिक संघ की केन्द्रीय समिति के मंत्री थे। सन् १९५१ में उस पद व लिये क इ. वारोशिलोव (K E Vo oshilov) चुने गए जो अनेक उच्च पदों पर कार्य कर चुक ई और पार्टी क प्रभावशाली नेताओं में से हैं।

प्रेसीडियम का मंत्री—सर्वोच्च सावियत व द्वारा हा प्रेसीडियम का एक मंत्री भी निर्वाचित किया जाता है जो प्रेसीडियम क समस्त साचिविक कार्य का अधीक्षण करता है। वह सर्वोच्च सावियत द्वारा पारित विधिया तथा प्रणितिम की आज्ञाप्तिया पर भा अपने प्रति-हस्ताक्षर करता है। सम्भवत उसका हम्मानर

विधि या आशक्ति की प्रामाणिकता का पुष्टि करने के लिए ही होते हैं। उसके पक्ष का कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं है।

प्रेसीडियम के कृत्य तथा शक्तियाँ

सोवियत संविधान के अनुच्छेद ४६ में सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के कृत्य तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार प्रेसीडियम के निम्नलिखित कृत्य तथा शक्तियाँ हैं —

प्रेसीडियम की कार्यपालिका तथा प्रशामनीय शक्तियाँ

(१) प्रेसीडियम सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सत्रों को बुलाना है। अनुच्छेद ४६ के अनुसार वष में सर्वोच्च सोवियत के दो सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं, परन्तु प्रेसीडियम स्वविवेक से अथवा किसी एक सत्र गणराय द्वारा मांग किये जाने पर सर्वोच्च सोवियत के असाधारण सत्र बुलाना सकता है।

(२) प्रेसीडियम दोनों सदनों में किसी प्रश्न पर गतिरोध (deadlock) होने की दशा में सर्वोच्च सोवियत को विघटित कर सकता है और नये निर्वाचन कराने की आज्ञा जारी कर सकता है।

(३) प्रेसीडियम स्वविवेक से अथवा किसी सत्र गणराय द्वारा मांग किए जाने पर किसी प्रश्न पर राष्ट्रप्राप्ति मतसंग्रह (लोक निर्णय) कर सकता है।

(४) सर्वोच्च सोवियत के सत्रों के बीच के काल में प्रेसीडियम सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् के सभापति (अर्थात् प्रधान मंत्री) का मनत्रणा पर मंत्रियों का पत्राचार कर सकता है तथा नए मंत्रियों का नियुक्त कर सकता है। प्रेसीडियम की इन आजायों का गठन में सर्वोच्च सोवियत का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। व्यवहार में यह अनुसमर्थन सदन ही प्राप्त हो जाता है।

(५) प्रेसीडियम विभिन्न प्रकार के पत्र तथा पत्रियों को सन्तुष्ट कर सकता है। सोवियत संघ में नागरिकों को अनेक प्रकार के पत्र तथा उपाधियाँ देने की व्यवस्था की गई है, उदाहरणार्थ योद्धावीर (Hero of Labour), योद्धा (Heroic Mother & Order), आदि। परन्तु यहाँ

यह जान रखना आवश्यक है कि ये सब उपाधियाँ वैयक्तिक हैं, वशगत नहीं।

(६) प्रेसीडियम बन्क आदि तथा सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान करता है।

(७) प्रेसीडियम निम्न में सोनियत सच के प्रतिनिधियों (एम्बूता) का नियुक्त करता है तथा उन्हें पुनर्बतित (recall) भी कर सकता है। सोनियत सच में विदेशों के राजपूतों के प्रमाणपत्र भी प्रेसीडियम के सम्मेलन प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण में प्रेसीडियम का प्रो. स. उसका प्रान्त में प्रमाणपत्रों का स्वाकार करता है।

(८) प्रेसीडियम सोनियत सच का सशस्त्र सनात्रा (Armed Forces) के उच्च अधिकारियों का नियुक्ति करता है तथा उन्हें पदच्युत भी कर सकता है।

(९) प्रान्त्यन्तता पडने पर प्रेसीडियम पूर्ण या आंशिक सैन्योन्नत (mobilisation) का आदेश प्रवर्तित कर सकता है। प्रेसीडियम सोनियत सच के किसी क्षण में प्रथमा समस्त देश में सोनियत सच का प्रतिरक्षा के लिए अथवा सामान्यक व्यवस्था तथा शांति का सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिक विधि (martial law) लागू कर सकता है।

प्रसाडियम की विधायना (Legislature) शक्तियाँ

(१) प्रसाडियम आनक्ति (advice) जाय कर सकता है। संविधान में प्रेसीडियम का इस शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं लगाए गए हैं। प्रेसीडियम सभापति शासन के क्षण में होने वाले सभा निर्णयों पर आदेश जारी कर सकता है जो सर्वोच्च सोनियत द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभावी होते हैं। ऐसी शक्तियाँ सर्वोच्च सोनियत के सम्मुख उसका सच आरम्भ होने पर प्रस्तुत की जाती हैं और उसका अनुसन्धान होने पर ही अधिक समय तक लागू रह सकती हैं।

(२) सोनियत सच के द्वारा काय सचिवायों का अनुसन्धान करने तथा उनका नियंत्रण करने का अधिकार भी प्रेसीडियम का प्राप्ति है। व्यवहार में प्रेसीडियम सर्वोच्च सचिवायों को सर्वोच्च सोनियत के सम्मुख ही अनुसन्धान

के लिए रखा जाता है। उदाहरणार्थ अगस्त सन् १९३६ की सोवियत जनतन्त्र सभा सर्वोच्च सोवियत द्वारा अनुसमर्थित का गयी।

(३) समिधान में युद्ध और शांति की घोषणा करने का प्राधिकार सर्वोच्च सोवियत का दिया गया है परन्तु ऐसे समय में जब सर्वोच्च सोवियत का सत्र न चल रहा हो, सोवियत सत्र पर सैनिक आक्रमण होने का तथा म प्रस्तावित युद्ध कालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। यदि पारम्परिक मान्यता में सम्बन्धित किसी अन्तराष्ट्रीय संधि का आभार को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़े तो भी प्रेसीडियम युद्धमालीन स्थिति का घोषणा कर सकता है।

प्रेसीडियम का न्यायिक (Judicial) शक्तियाँ

(१) प्रेसीडियम सोवियत सत्र में प्रवर्तित समस्त कानून का निवाचन (interpretation) करता है।

(२) प्रेसीडियम सोवियत सत्र का मन्त्रिपरिषद् तथा सर्व-गणराज्य की मन्त्रिपरिषद् के निनिश्चय तथा उनकी आज्ञाओं को विधिवत् न मान पार कर सकता है।

(३) प्रेसीडियम को दिये गये हुए नागरिकों का जमाना प्रदान करने का शक्ति प्रदान की गई है।

प्रेसीडियम द्वारा अमला शक्तियाँ का व्यावहारिक प्रयोग—मन्त्रिपरिषद् के प्रवर्तित होने से तब तक के अनुभव के आधार पर यहाँ कहा जा सकता है कि प्रेसीडियम अपना शक्ति का पूरा प्रयोग करता रहा है। राजधानी सत्र के अनिश्चित सर्वोच्च सोवियत के प्रस्तावों पर सर्वोच्च सोवियत के द्वारा कानून उलूख गये हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय में प्रेसीडियम ने अमला शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सोवियत का निवाचन स्थापित कर दिया था। यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सत्रों में किसी प्रश्न पर मतभेद (deadlock) होने के कारण सर्वोच्च सोवियत का निवाचन करने का अभी तक कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी प्रकार न तो कभी किसी प्रश्न पर प्रेसीडियम ने स्वयं ही जनमत जानने के लिए लोकनिर्णय (referendum) कराने के अधिकार का प्रयोग किया और न कभी

किसी सभ गणराज्य ने लोक निगम करने की माग की । इनक अतिरिक्त प्रेसीडियम ने अपने प्राय सभा अधिकारों का प्रयोग किया है । प्रेसीडियम ने मन्त्रि परिषद् के अध्यक्ष की प्राथना पर मन्त्रिया की नियुक्तिया का हैं तथा उन्हें पदच्युत किया है । अनेकों अध्यादेशों तथा आरम्भियों को रद्द किया है । सैनिक विधि (martial law) की घोषणा की है, तथा उसका अन्त किया है । सभा के सामूहिकरण तथा सैन्यप्रियावन (demobilisation) के आदेश प्रसारित किए हैं तथा अनेकों सम्मानसूचक पदों पदों, एवं उपाधिया का स्थापित तथा वितरित किया है । उसने सेना के उच्चाधिकारियों को नियुक्त तथा पदच्युत किया है । विदेशों में सोवियत सभ के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है तथा प्रयासित किया है विदेशों से का गद्द सधिया की पुष्टि की है, तथा अपने क्षमादान करने के अधिकार का प्रयोग किया है । व्यवहार में राजनीतिक उप राधा के लिए दंड पाने वालों को क्षमादान नही दिया जाता ।

प्रेसीडियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार आज्ञासिपा जारी करने का अधिकार है । प्रेसीडियम के द्वारा पिछले वर्षों में जारी की गद्द आज्ञासिपा को हम निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं —

१ ऐसे विषयों से सम्बंधित आज्ञासिपा जिन पर आज्ञासिपा जारी करने का अधिकार प्रेसीडियम का स्पष्ट रूप से संविधान में दिया गया है । उन विषयों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । अब तक जारी की गद्द ऐसी आज्ञासिपा की संख्या बहुत अधिक है ।

२ पूर्ण प्रवर्तित विधियों को कायान्वित करने अथवा उनका निर्वचन करने वाली आज्ञासिपा । उसी उग म के आज्ञासिपा आती है जिनके द्वारा सभा मन्त्रि परिषद् अध्यक्ष सभ गणराज्यों का मन्त्रि परिषदों के विषयों तथा आदेशों का विधित न होने पर प्रेसीडियम रद्द करता है ।

तीसरें वर्ग में वे आज्ञासिपा आती हैं जो उन विषयों से सम्बंधित होता हैं जिन पर आज्ञासिपा जारी करने का अधिकार संविधान में प्रेसीडियम को स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है परन्तु जो संघीय शासन अथवा संघीय सर्वोच्च सोवियत — क्षाधिकार में हैं । उस वर्ग में आने वाली आज्ञासिपा की संख्या भी बहुत अधिक है ।

मालिन सविधान क लागू होने से अब तक प्रेसीडियम ने इतना अधिक तथा इतनी अधिक विषयां से सम्बन्धित आज्ञापितिया जारी की हैं, कि कुछ लेखकों ने तो उसके आज्ञापितिया जारी करने के अधिकार का असिमित ही कह डाला है। मनरो क मतानुसार प्रेसीडियम का आज्ञापितिया जारी करने की असामत शक्ति का प्रश्न सन् १९४६ के निर्वाचन के पूर्व हुआ, जब इसने एक आज्ञापित क द्वारा सर्वोच्च सोवियत क सदस्यों की अल्पतम आयु १८ वर्ष न बढ़ा कर २३ बढ़ कर दी तथा विदेशों में सेवा करने वाली सोवियत सेना का प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की। यह दोनों आज्ञापित व्यवहार में सविधानिक सहायन ही थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन सशर्तों का अनुसमर्थन (ratification) उस सर्वोच्च सोवियत के द्वारा किया गया जो इन सशर्तों का गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही चुनी गई थी।^१ डाउम्टर के मतानुसार प्रेसीडियम अपना आज्ञापितिया जारी करने का शक्ति का उपयोग न केवल ऐसी परिस्थितियों में ही करता है जब सर्वोच्च सोवियत को बुलाना असम्भव या कठिन होता है, परन्तु ऐसी परिस्थितियों में भी जब किसी उच्च सोवियत शासनाग का आज्ञापित की आवश्यकता प्रतीत होता है, परन्तु वह इतनी आवश्यक नहीं मनभी जाना कि सर्वोच्च सोवियत का बुलाना आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च

1 The unlimited decree issuing power of the Presidium were demonstrated before the elections of 1946. It issued decree raising the minimum age of deputies to the Supreme Soviet from eighteen to twenty three (Constitutional amendment) and another providing for replacement of Red Army units serving abroad (a constitutional amendment). Both were formally ratified by the Supreme Soviet which had been elected in accordance with the amendments. — Munro & Ayres *op cit* p 657

2 This power is being used not only in situations when it is impossible or difficult to convene the Supreme Soviet but also where the occasion seems to call for action by the high Soviet even yet do not seem to warrant the convocation of the Supreme Soviet. — Julian Towster *op cit* p 269

सोवियत का प्रसाधारण सत्र तब ही बुलाया जाता है जब ऐसा करना अत्यंत आवश्यक होता है अन्य अवसरों पर प्रेसीडियम ही अपनी आवश्यकताओं के द्वारा आवश्यक व्यवस्था कर देता है।

सोवियत शासन प्रणाली में प्रेसीडियम का स्थान—अपनी शक्ति की व्यापकता और विविधता के कारण सभाच्च सोवियत के प्रेसीडियम का सोवियत शासन व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसकी प्रमुख विशेषता इसका स्थायी इत्युक्त स्वरूप है। सोवियत लेखक प्रेसीडियम को एक प्रतिदिन कार्य करने वाला मंत्रालय (daily working organ) के नाम से संबोधित करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी इसकी एक माह में कई बैठकें होती हैं। सोवियत संघ का सभाच्च सोवियत के सत्र अत्यंत संक्षिप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में शासन के समस्त उपस्थित होने वाली समस्त आकांक्षा का निम्न प्रेसीडियम के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वह अपनी जनक-संस्था, सर्वोच्च सोवियत से बहुत अधिक क्रियाशील सिद्ध हुआ है।

शासन की नीति निर्धारित करने में प्रेसीडियम की स्थिति उतना कठिन है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इसका बैठका भी कार्यक्रमों का सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं की जाती। सामान्यतः यह धारणा किया जाता है कि शासन की आन्तरिक वैदेशिक प्रधान प्रवृत्ति नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण निष्पत्ति कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम के द्वारा किए जाते हैं जिन्हें सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम औपचारिक रूप से प्रस्तावित कर देता है। परन्तु यह धारणा अत्यंत आवश्यक है कि पार्टी के प्रेसीडियम के अनेक सदस्य सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के भाग्यवान् होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के वर्तमान प्रधान मंत्री (First Secretary) निकिता ख्रुश्चेव (Nikita Khrushchev) का प्रेसीडियम के एक सदस्य हैं। इस कारण प्रेसीडियम का बैठका में भी महत्वपूर्ण निष्पत्ति निकाला जा सकते हैं। ये बैठकें न केवल प्रेसीडियम का सर्वोच्च सोवियत का मन्त्रालय तथा सोवियत संघ का सर्वोच्च

ऊपर हम प्रेसीडियम का आज्ञातिथि जारी करने की शक्ति तथा उसका प्रशासनिक प्रयोग पर विचार कर चुके हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि संविधान में विधियाँ बनाने की शक्ति केवल सर्वोच्च सोवियत का ही दी गई है परन्तु व्यवहार में प्रेसीडियम ही अधिनाश विधियाँ बनाना है। सर्वोच्च संविधान का केवल उसका द्वारा प्रख्यापित आज्ञातिथि का औपचारिक स्वीकृति मात्र प्रदान करती है। प्रेसीडियम द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव से सर्वोच्च सोवियत ने कभी अपनी असहमति पत्र नहीं की है।^१ इसी से हम प्रेसीडियम का विधायनांश शक्तियों का, ताकि प्रत्येक देश में विधानमण्डल की सराविक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, अनुमान लगा सकते हैं। उसका अनिरीक्षित सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् के द्वारा प्रस्तुत विधेयका के स्वरूप पर भा प्रेसीडियम के द्वारा विचार किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका द्वारा की गई संधियों का अनुसमर्थन करने की शक्ति विधानमण्डल के द्वितीय सदन, सिनेट (Senate), को दी गई है। परन्तु सोवियत संघ में यह शक्ति प्रेसीडियम को प्राप्त है।

अतः, प्रेसीडियम का कुछ ऐसा शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं जो अन्य देशों में देखा में देश के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती हैं। इनमें प्रमुख हैं संविधान तथा विधियों का नियन्त्रण करने तथा संघीय मन्त्रिपरिषद् एवं संघ-नागराज्यों की मन्त्रिपरिषदों के नियुक्ति तथा आदेशों के विधिवत् न होने पर उन्हें रद्द करने की शक्तियाँ। एक संघीय-राज्य (Federation) में संविधान तथा विधियों का निर्वचन करने की शक्ति का क्या महत्व है, यह यहाँ बताना आवश्यक नहीं है। डी बेसिली ने प्रेसीडियम की इस शक्ति को अभिवेधाधिकार (Right of veto) से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है।^२

^१ 'The Supreme Soviet has never been known to dissent on any measure which has been submitted to it by the Presidium —Harpe and Thompson *op cit* pp 134-135

^२ the Stalin constitution accords to the Presidium a right which in practice may have a much greater import than that of the right of veto —de Basilly *op cit* p 19

सांसद सभ की सर्वोच्च सांसद व प्रेसीडियम का यन्त्रण समाप्त करने व पूरा हम अति सक्षेप में सांसद प्रेसीडियम का स्विम सभा परिषद् से भी तुलना करग, क्योंकि बहुधा ऐसा सस्थाओं की बन्धन या मन्त्रालय कार्यपालिका (Plural or Collegiate Executive) कहा जाता है। सोवियत सभ का प्रेसीडियम और स्विम सभा परिषद् समस्त मन्त्रालय नही हैं बल्कि नीचा का रचना, संगठन, शक्तिया तथा कृत्य म मन्त्रालय अन्तर है। सोवियत सभ का प्रेसीडियम राज्य का सामूहिक अर्थ है न कि शासन का। मन्त्रालय सभ सभ सभा परिषद् शासन की सामूहिक प्रमुख है। सोवियत सभ की सरकार (Govt) मन्त्र परिषद् है न कि प्रेसीडियम। इसके अतिरिक्त सोवियत प्रेसीडियम तथा स्विम सभा परिषद् की शक्तिया में भी बहुत अंतर है। इस सभा परिषद् न तो इतनी आपत्तियां जारा कर सकती है और न सविधान का निषेधन करती है। इसका अतिरिक्त स्विम सभा परिषद् और सोवियत प्रेसीडियम में एक मुख्य अंतर यह भी है कि यद्यपि ऐसा का निर्वाचन विधान मन्त्रालय द्वारा किया जाता है, परन्तु नही स्विट्जरलैंड में सभा (विधान मन्त्रालय) सभा परिषद् का पद-त्याग करने व निलय नहीं कर सकती। नही सोवियत प्रेसीडियम स्पष्टतया सर्वोच्च सोवियत का प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार दोनों सस्थाओं में समानता कम और अंतर हा अधिक हैं।

उपमूल निवेचना से हम अभी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत सभ का सर्वोच्च सोवियत व प्रेसीडियम के समस्त को सस्था किता अन्य देश के सविधान में नहीं है। यद्यपि इस सोवियत सभ का सामूहिक अर्थ कहा जाता है, परन्तु इसकी रचना, शक्तिया तथा कृत्य अन्य सभी राज्यों के प्रधानों से भिन्न हैं।

अध्याय ६

सोवियत सभ की मन्त्रि परिषद्

सोवियत सभ की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रि परिषद् (Council of Ministers) है जिसे सावधान से सोवियत सभ की सरकार तथा सोवियत सभ की राज्य सत्ता का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासनिक अंग^१ कहा गया है। यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम को भी, जिस पर हम निम्नलिखित प्रमाणों से विचार कर चुके हैं अनन्त महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं परन्तु मुख्यतः उन्हीं के ही हस्त में दी गई हैं जो अन्य देशों में राज्य के मानविक प्रमाणों के लिए जाते हैं। वैधानिक दृष्टि से सोवियत सभ की मन्त्रि परिषद् जन्म कुछ ससदीय शासन वाले देशों के मन्त्रिमण्डल के समरूप है, क्योंकि यह सर्वोच्च सोवियत के द्वारा नियुक्त की जाती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। परन्तु यथार्थ में ससदीय शासन वाले देशों के मन्त्रिमण्डल तथा सोवियत मन्त्रि परिषद् में बहुत अन्तर है। इस अध्याय में हम मन्त्रि परिषद् की रचना सम्बन्धी शक्तियाँ, तथा सोवियत शासन व्यवस्था में उसके स्थान पर विचार करेंगे।

मन्त्रि परिषद् का पूरा रूप सोवियत सोवियत—मात्र १९४६ तक सोवियत सभ की वास्तविक कार्यपालिका को सोवियत सोवियत (Sovnarkom) तथा जन कमिसार परिषद् (Council of People's Commissars) कहते थे। जन कमिसार परिषद् के नामाङ्कन की घोषणा सभ प्रथम जनवरी १९१७ की एक अधिवेशन के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में जन कमिसार परिषद् का कार्य

The highest executive and administrative organ of the state power of the U S S R is the Council of Ministers of the U S S R —Article 64

^१ Sovnarkom is the abbreviated form of the Russian title *Sovet Narodnykh Komissarov*

संविधान सभा के बुलाए जाने तक देश का शासन चलाना बनाया गया था। इस प्रथम जन कमिसार परिषद् का अध्वक्ष रुस का बाल्शविक क्रांति का प्रणेता लेनिन था। जनवरी, १९१८ में जन कमिसार परिषद् का नाम से अन्तर्कालीन (Provisional) शब्द हटा दिया गया और इस प्रकार यह सोवियत शासन-प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गई। सोवियत संघ का स्थापना के पश्चात् जुलाई १९२३ में संघ जन कमिसार परिषद् का निर्माण किया गया। सन् १९२४ में लेनिन की अस्वस्थता के कारण उनके स्थान पर रिक्कोव (Rykov) को जन कमिसार परिषद् का प्रधान निर्वाचित किया गया। सन् १९२६ में स्तालिन संविधान में जन कमिसार परिषद् को सोवियत संघ की संघीय कार्यपालिका तथा प्रशासनीय सत्ता प्रेषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद ६८ व ६९ में मन्त्रि-परिषद् की शक्तियों तथा कृत्यों का उल्लेख किया गया है। मार्च १९४९ में इस जन कमिसार परिषद् अथवा सोन्तारकोन का नाम 'मन्त्रि-परिषद्' तथा इसकी सदस्यों का नाम मन्त्री कर दिया गया।

मन्त्रि-परिषद् का रचना तथा संगठन—वर्तमान संविधान के अनुसार सोवियत संघ की मन्त्रि-परिषद् सर्वोच्च सोवियत के द्वारा नियुक्त की जाती है।^१ मन्त्रि-परिषद् का निर्माण सर्वोच्च सोवियत के दोनों सभा के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च सोवियत मन्त्रि-परिषद् के समारोधि (Chairman) को नियुक्त करती है और उसे अपनी मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों के नाम प्रस्तुत करने का कहती है। जब मन्त्रियों की सूची सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है तो सर्वोच्च सोवियत के सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तथा विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। यदि सदस्य किसी व्यक्ति के मन्त्रि-परिषद् में सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति करें तो प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर अलग अलग मतदान कराया जा सकता है अन्यथा पूरा सूची पर एक साथ मतदान कराया जाता है। जनवरी १९३८ में जन सर्वोच्च सोवियत द्वारा प्रथम सोन्तारकोन की नियुक्ति की जा रही थी, कुछ मन्त्रालयों (Commissariats) का क्षेत्र आलोचना की गई। इस परिणामस्वरूप अन्तिम रूप से सर्वोच्च सोवियत की स्वीकृति के लिए

^१ अनुच्छेद ७७

प्रस्तुत सूची में तीन कमिषनों के नाम को हटा दिया गया था।^१ सन् १९४६ में स्तालिन द्वारा प्रस्तुत सूची को सर्वोच्च सोवियत ने बिना किसी परिवर्तन के सब सम्मति से स्वीकृत कर लिया। हफ्थानि और जयजयकार के बीच सर्वोच्च सोवियत ने स्तालिन को मन्त्रि परिषद् का सभापति तथा सेना मन्त्री चुना।

स्तालिन सविधान के अनुसार सोवियत संघ का मन्त्रि परिषद् में निम्न पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं —

- १ मन्त्रि परिषद् का सभापति
- २ मन्त्रि-परिषद् का प्रथम उप-सभापति
- ३ मन्त्रि परिषद् का उप सभापति
- ४ मन्त्रि-परिषद् का राज्य आयाचना समिति (State Plan & Committee) का सभापति
- ५ मन्त्रि परिषद् की निर्माण सम्बन्धी राज्य समिति (State Committee on Construction) का सभापति
- ६ मन्त्रि परिषद् का राज्य सुरक्षा समिति (State Security Committee) का सभापति
- ७ सोवियत संघ के राज्य बैंक के प्रशासकीय मन्त्रालय (Administrative Board of the State Bank) का सभापति
- ८ सोवियत संघ के मन्त्री

सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् की रचना तथा संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रह रहे हैं। सन् १९१७ में गालेशेनिक क्रांति के तुरन्त पश्चात् संगठित जन कमिषन परिषद् में १ सदस्य थे। सन् १९२१ में उस संस्था की संख्या १५ तथा मन्त्रियों की संख्या १७ थी। उसका कारण था कि उस ६ सदस्यों ने मन्त्रियों के प्रमुख थे। इसके पश्चात् जन कमिषन परिषद् की संख्या संख्या कम होकर सन् १९२५ में १ तथा १९३१ में १२ रह गई। स्तालिन सविधान के निर्माण के पूर्व, सन् १९२५ में, इसकी संख्या १५ थी। तीन सारधान के अनुसार निर्मित प्रथम मन्त्रि परिषद् में २६ सदस्य थे। मुद्रा-काज में मन्त्रि परिषद् की संख्या में बहुत शक्ति हुई जिसके

कारण इसकी सदस्य संख्या सन् १९४६ में ६८ हो गई थी। इस वृद्धि का कारण सोवियत संघ की सरकार द्वारा की जाने वाली बहुसंख्यक आर्थिक कार्यवाहियां तथा देश की सैनिक आवश्यकताओं में हुई वृद्धि बताई जाती है। सन् १९५५ में एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रि-परिषद् की सदस्य-संख्या ५८ निश्चित की गई। परंतु इसके पश्चात् भी उसमें अनेक बार परिवर्तन किए गए हैं।

मात्र परिषद् का सभापति (सोवियत प्रधान मंत्री)—सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् के सभापति का बहुधा 'सोवियत प्रधान मंत्री' के नाम से संबोधित किया जाता है। ससदीय शासन प्रणाली वाले देशों में प्रधान मंत्री का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना है और इसी कारण ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को समस्त प्रशासन की धुरी माना जाता है। लार्ड रॉल्ले ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री को "मनिमडल रूपी वृत्तखण्ड का मुख्य प्रसार" कहा है।^१ प्रश्न उठता है कि क्या सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् ने सभापति का भी वही स्थिति है जो ब्रिटेन या भारत में प्रधान मंत्री की होती है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें निम्नलिखित बातों का अनुभव का आश्रय लेना होगा।

नवम्बर १९१७ में बाल्सेविक क्रांति के समय से जनवरी १९२४ तक लेनिन सोवियत संघ का जन कमिसार परिषद् के सभापति रहे। लेनिन ने नवम्बर क्रांति के समय क्रांतिकारी शक्तियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और यही कारण था अपनी मृत्यु तक जनता तथा पार्टी के सर्वमान्य नेता रहे। लेनिन की मृत्यु के पश्चात् जन कमिसार परिषद् के सभापति का स्थान रिकोव (Rykov) को प्राप्त हुआ। उसके पूर्व सन् १९२२ में स्टालिन को कम्यूनिसट पार्टी का प्रधान-मंत्री पद प्राप्त हो गया था। रिकोव नवम्बर १९२९ तक तथा उनके पश्चात् मोलोटोव मई १९४१ तक सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् के सभापति रहे। परंतु इस काल में स्टालिन ही सोवियत संघ का सर्वाधिक सम्मानित तथा प्रति

^१ "He is the axis around which the entire administration revolves"

^२ Keystone of the cabinet arch

भ्रित व्यक्ति था। लेनिन की मृत्यु के पश्चात् स्तालिन को त्रात्स्की (Trotsky) के “सामंती विरोध और बुद्धारिन के “दक्षिणपंथी विरोध का सामना करना पड़ा। त्रात्स्की का सोवियत संघ से निष्कासित होकर विदेशों में अपना जीवन यापन करना पड़ा और अन्त में उसकी हत्या कर दी गई। रिक्व और बुद्धारिन को भी “देशद्रोह के अपराध में अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ा। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि तब स्तालिन प्रधान मंत्री के पद पर आसीन नहीं था तब भी उसे ही जनता, पार्टी तथा राज्य का सर्वोच्च नेता माना जाता था।^१ इस स्थिति का अन्त मई १९४१ में हुआ जब स्तालिन ने सोवियत संघ की मन्त्रि परिषद् के सभापति का पद ग्रहण कर लिया। अपनी मूल्यपयत् स्तालिन मन्त्रि परिषद् के सभापति और कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महा-मंत्री इन दोनों ही पदों पर आसीन रहा। वरिष्ठ दम्पति का विचार है कि स्तालिन का प्रबल प्रधान उसका कम्युनिस्ट पार्टी का महामंत्री होने का कारण था।^२ यह तथ्य इस निष्कर्ष को और दृढ़ करता है कि सोवियत संघ में कम्यु

^१ मन्त्रि परिषद् का सभापति बनने के पूर्व स्तालिन की स्थिति का अनुमान हम इस घटना से लगा सकते हैं कि सन् १८३६ में प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार एंड्री गाइड (Andre Gide) ने स्तालिन के जन्म स्थान से स्तालिन को तार द्वारा संपर्क देनी चाही। उस समय गान्ध सोवियत संघ में सरकार के अतिथि के रूप में दौरा कर रहे थे। तत्पश्चात् कमचारी ने उनका तार इस कारण स्वीकृत नहीं किया कि उसमें स्तालिन का कथन “आप (you) कह कर सम्बोधित किया गया था। गाइड को बताया गया कि स्तालिन को “आप, भ्रमदीविया के नेता (‘you, leader of the workers’) या ‘आप जनता के स्वामी (you master of the peoples) कह कर सम्बोधित किया जाना चाहिए। देखिए, (Andre Gide *Return from the U S S R* pp 45-46

^२ The office by which Stalin earns his livelihood and now his predominant influence is that of General Secretary of the Communist Party — Sydney & Beatrice Webb, *Soviet Communism* Introduction to 1942 edition ■ x

निरा पार्टी व महा मन्त्री का पद मन्त्रि परिषद् क सभापति (प्रधान मन्त्री) के पद से अधिक महत्वपूर्ण है।

स्तालिन ने अपनी मृत्यु से कुछ काल पूर्व ही पार्टी के प्रधान मन्त्री पद का त्याग दिया था, और उसके स्थान पर मालेन्कोव (Malenkov) को नियुक्त किया गया था। स्तालिन की मृत्यु व पश्चात् मालेन्काव को ही सोवियत सभ की मन्त्रि परिषद् क सभापति पद पर नियुक्त किया गया। परन्तु यह व्यवस्था अस्थायी सिद्ध हुई। प्रधान मन्त्री बनने व पश्चात् मालेन्कोव ने पार्टी व महा मात्र पद से त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर खुर्चव को नियुक्त किया गया। मन्त्रि परिषद् क सभापति पद पर नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर ही मालेन्कोव का पद त्याग करना पड़ा। उनका स्थान अब प्रतिरक्षा मन्त्री माशल बुल्गानिन ने लिया। वर्तमान स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्यिक रूप से मन्त्रि परिषद् और पार्टी व महा-मन्त्री को समान सम्मान दिया जाता है। जब भी माशल बुल्गानिन विदेश यात्रा को गए, नाकता खुर्चव उनके साथ गए। इन सब परिवर्तनों से भी हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोवियत सभ में कमल मन्त्रि परिषद् का समापति होने से ही कोई व्यक्ति त्रिटन के प्रधान मन्त्री व समान शक्तिशाली नहीं हो जाता। इसके लिए उसे कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेता भी होना चाहिए।

मन्त्रि परिषद् क कृत्य तथा शक्तियाँ—सोवियत सभ की मन्त्रि परिषद् को सविधान द्वारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिकार तथा कृत्य प्रदान किए गए हैं। सविधान में उल्लिखित उसकी कुछ मुख्य शक्तियाँ तथा कृत्य निम्नलिखित हैं—

१ मन्त्रि परिषद् को पूर्व प्रवर्तित विधियाँ (Laws in operation) के आधार पर तथा उनकी व्यवस्था क अनुसार निनिश्चय और आदेश (decisions and orders) निकालने का अधिकार है। साथ ही मन्त्रि परिषद् विधियों के कार्यालयन का भी निरीक्षण करती है।

मन्त्रि परिषद् क विनिश्चय तथा आदेश सोवियत सभ के पूर्ण राज्य क्षेत्र में मान्यता पाते हैं।

२ मन्त्रि-परिषद् सोवियत सभ क अखिल संघीय (All Union) तथा सभ गणराज्य (Union Republican) मन्त्रालयों एवं अपने अधिकार क्षेत्र की

अन्य संस्थाओं के कार्यों को एकसूत्रता प्रदान करती है तथा उनका निर्देशन करती है।

३ मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रीय आर्थिक योजना तथा राज्य आय-व्यय को कार्यान्वित करने तथा मुद्रा और बाजार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक पग उठा सकती है।

४ मन्त्रिपरिषद् सावजनिक व्यवस्था बनाए रखने, राज्य के हितों का संरक्षण करने, तथा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है।

५ मन्त्रिपरिषद् विदेशी राज्यों से संबंधों के विषय में एककों का सामान्य पथ प्रदर्शन करती है।

६ मन्त्रिपरिषद् प्रति वर्ष सैनिक संवा के लिए बुलाए जाने वाले नागरिकों की संख्या निश्चित करता है तथा देश की सामुद्रिक सेना (Armied for sea) के सामान्य संगठन का निर्देशन करता है।

७ मन्त्रिपरिषद् आवश्यकता पड़ने पर अपने अधीन आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्रतिरक्षा संबंधी विषयों पर विशेष समितियों तथा केन्द्रीय प्रशासन-संस्थाओं को स्थापित करती है।

८ मन्त्रिपरिषद् को संघीय क्षेत्र में आने वाले प्रशासनीय और अर्थ व्यवस्था संबंधी विभागों के समक्ष में संघ-गणराज्यों की मन्त्रिपरिषद् के विनिश्चयों और आदेशों का निमित्तित (suspend) करने तथा संघीय मंत्रियों के आदेशों और अनुदेशों (instructions) को रद्द करने का अधिकार है।

मंत्रियों के कृत्य तथा शक्तियाँ—ऊपर मन्त्रिपरिषद् के सामूहिक कृत्यों का उल्लेख किया गया है। परन्तु स्वरूप अतिरिक्त विधान में मंत्रियों के कुछ कृत्य तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संक्षेप में वे निम्नलिखित हैं —

१ मन्त्री संघीय क्षेत्र में आने वाले राज्य प्रशासन के विभागों का निर्देशन करते हैं।

२ मन्त्री अपने अपने मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत पृथक् प्रवर्तित विधियों तथा मन्त्रिपरिषद् के विनिश्चयों एवं आदेशों के आधार

पर तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए, आदेश तथा अनुदेश जारी कर सकते हैं।

३ मंत्री सर्वोच्च सोवियत के सत्रों द्वारा पृष्ठे गए प्रश्नों का लिखित अथवा मौखिक उत्तर तीन दिन की अवधि के अन्दर लेने के लिए बाध्य हैं। बा प्रश्न सोवियत संघ की सरकार से पृष्ठे जाते हैं उनका उत्तर मंत्रि परिषद् का द्वार से तीन दिन की अवधि में दिया जाना आवश्यक है।

सचिधान में उल्लिखित इन कृत्या के अतिरिक्त मंत्रिया द्वारा किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कृत्य सर्वोच्च सोवियत के सदन में विधेयक प्रस्तुत करना है। सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयकों में से अधिकांश मंत्रि परिषद् या उसने किसी सत्रों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। गारिक आवश्यक भी मंत्रि परिषद् के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है।

मंत्रि परिषद् द्वारा अपनी शक्तियाँ का व्यावहारिक प्रयोग—सोवियत संघ की मंत्रि परिषद् को सचिधान में जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उनका उसने पूरी तरह प्रयोग किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि स्तालिन सचिधान में निधि निमाण का कार्य केवल सर्वोच्च सोवियत को ही सौंपा गया है, परन्तु मंत्रि परिषद् के द्वारा जारी किए जाने वाले “विनिश्चयों और आदेशों की बहुत संख्या यही सिद्ध करती है कि वास्तव में मंत्रि-परिषद् ही राज्य-नीति का निर्देशन करती है, न कि सर्वोच्च सोवियत। मंत्रि परिषद् द्वारा जारी किए जाने वाले “विनिश्चय तथा आदेशों के द्वारा सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभाव होते हैं। यद्यपि वैधानिक दृष्टि से वे सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों पर ही आधारित होते हैं, परन्तु प्रथा में उनका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है। उनमें कृषि उद्योग, यातायात, शिक्षा तथा वसाय में महत्वपूर्ण समस्याएँ की जाती हैं। उद्योगों तथा कृषि पानों का उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के संबंध में नियंत्रण करना मंत्रि परिषद् का ही काम है। वह सामाजिक उत्सर्ग की घोषणा करती है। विभिन्न प्रकार के पारितोषिक तथा सम्मान प्रदान करती है। सामाजिक नीति की दूरों की पुष्टि करती है, और करो, सामाजिक संग्राम के प्रातकर की दूर, तथा पारिश्रमिकों

की दरा को निर्धारित करती है। मन्त्रि-परिषद् अपने अधीन काम करने वाले समस्त प्रशासकीय विभागों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है, तथा आवश्यकता पाने पर समितियों तथा आयोग नियुक्त करता है। प्रत्येक मन्त्रालय अपने द्वारा प्रवर्तित समस्त महत्वपूर्ण आगमों और अनुदेशों को मन्त्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करता है जिन्हें वह स्वीकार कर सकती है। मन्त्रि-परिषद् ने अपने इस अधिकार का अनेक अवसरों पर प्रयोग किया है।

सन् १९४४ के पूर्व सना तथा वैदेशिक-संबंध धोरणरूपण कन्दान विनियोगे। फरवरी १९४४ में किए गए एक संशोधन के द्वारा संघ-गणराज्यों को नए अपनी सनाएँ रखने तथा विदेशों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है। परन्तु इन विषयों के संबंध में मन्त्रि-परिषद् का निर्देशन विद्वान्त निश्चित करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के प्रयोग के द्वारा मन्त्रि-परिषद् न केवल सघान सना और प्रज्ञ-उद्घाटन से सम्बंधित विभिन्न उपायों के मन्त्रालयों के कार्यों में एकनूना लाती है वरन् सघ-गणराज्यों का सना सनाधी नाति पर भी नियंत्रण रखता है। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विदेशी राज्यों को मान्यता प्रदान करना अथवा उस वापस लेना दूसरे देशों में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करना, दूसरे देशों से का जाने वाली सधियों का परीक्षण करना तथा उन्हें स्थापति देना विदेशी-व्यापार संबंधी नाति निश्चित करना तथा वैदेशिक विभाग और वैदेशिक व्यापार से सम्बद्ध अधिकारियों के कार्यों का अधीक्षण करना, मन्त्रि-परिषद् के कुछ अन्य मुख्य कार्य हैं।

मन्त्रि-परिषद् का न केवल सघान मन्त्रालयों के विनिश्चयों और आदेशों का स्वीकार करने का ही अधिकार प्राप्त है वरन् सघ-गणराज्यों की मन्त्रि-परिषदों के विनिश्चयों और आदेशों का भी निलवित (*approval*) करने का अधिकार है। प्रायः सभा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शासन-नाति के सामान्य विद्वान्त निर्धारित करने का अधिकार सघीय शासन को प्राप्त है, इस कारण मन्त्रि-परिषद् सघ-गणराज्यों के शासन पर भी नियंत्रण रखती है।

मन्त्रालयों का वर्गीकरण

संविधान में कन्दान मन्त्रालयों का दो वर्गों में विभक्त किया गया है। य

वर्ग हैं (१) अखिल संघीय मन्त्रालय (All Union Ministries) तथा (२) संघ गणराज्यिक मन्त्रालय (Union Republican Ministries)। अखिल संघीय मन्त्रालय उन विषयों के प्रशासन का संचालन करते हैं, जो अनन्य रूप से (exclusively) संघीय शासन के क्षेत्र में हैं। प्रत्येक अखिल संघीय मन्त्रालय अपने विभाग से सम्बन्धित प्रशासन का निर्देशन सोवियत संघ के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में या तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करता है, या अपने द्वारा नियुक्त निकायों (bodies) के द्वारा करता है। इस प्रकार मन्त्रालय संघ गणराज्यिक मन्त्रालय अपने विभाग से सम्बन्धित प्रशासन का निर्देशन संघ-गणराज्यों के समस्त मन्त्रालयों के द्वारा करते हैं। वे केवल बहुत सीमित तथा निश्चित कार्यों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ऐसे कार्यों की सूची सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के द्वारा अनुसमर्थित की जाती है। प्लातिन्स्की ने आपल संघाय तथा संघ गणराज्यिक मन्त्रालयों के अन्तर को अशक्त बताया है। सोवियत शासन व्यवस्था के विकास के काल में अनेकों मन्त्रालयों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानान्तरित किया गया है। उदाहरणार्थ, सन् १९४४ में वैदेशिक कार्यों तथा राज्य सुरक्षा मन्त्रालयों को अखिल संघीय वर्ग से संघ-गणराज्यिक वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया गया था। परन्तु इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं आया।

सन् १९३६ में संविधान में केवल आठ अखिल संघीय मन्त्रालयों की, तथा दस संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों की व्यवस्था थी। इन संख्याओं में तब से अनेक बार परिवर्तन हुए हैं। सन् १९५४ में संविधान में चौबीस अखिल संघीय मन्त्रालयों तथा तेइस संघ गणराज्यिक मन्त्रालयों की व्यवस्था थी।

अखिल संघाय मन्त्रालय—संविधान के अनुच्छेद ७७ के अनुसार निम्नलिखित मन्त्रालय अखिल संघाय मन्त्रालय हैं—

- १ वायुयान उद्योग मन्त्रालय
- २ संचालित वाहनों (मोटर्स), जैक्टर तथा कृषि इंजीनियरिंग मन्त्रालय
- ३ कागज तथा काष्ठ-कला उद्योग मन्त्रालय
- ४ विदेशी व्यापार मन्त्रालय
- ५ उच्चतर शिक्षा मन्त्रालय

६ भूतत्वाय-परिमाण (Geological Survey) तथा एनिज सम्पत्ति के संरक्षण का मन्त्रालय

७ कृषि-पशु मन्त्रालय

८ यन्त्र तथा उपकरण निर्माण उद्योग मन्त्रालय

९ वन्यिक पोत तथा अन्तर्राष्ट्रीय जलपथ यातायात मन्त्रालय

१० तैल उद्योग मन्त्रालय

११ प्रतिरक्षा उद्योग मन्त्रालय

१२ रेलवे मन्त्रालय

१३ रैन्यो इजानियरिंग उद्योग मन्त्रालय

१४ संचार मन्त्रालय

१५ मध्य क्रोटिक यन्त्र निर्माण उद्योग मन्त्रालय

१६ यन्त्र-उपकरण (Machine Tool) तथा उपकरण उद्योग मन्त्रालय

१७ भवन तथा माग निर्माण यन्त्र मन्त्रालय

१८ धातुशाोधन तथा रासायनिक उद्योग मन्त्रालय

१९ पोत निर्माण मन्त्रालय

२० पातापात यन्त्र उद्योग मन्त्रालय

२१ भारी यन्त्र निर्माण उद्योग मन्त्रालय

२२ रासायनिक उद्योग मन्त्रालय

२३ शक्ति केन्द्र (Power Stations) का मन्त्रालय

२४ विद्युत इजानियरिंग उद्योग मन्त्रालय

संघ गणराष्ट्रियक मन्त्रालय—निम्नलिखित मन्त्रालय संघ गणराष्ट्रियक मन्त्रालय हैं —

१ मोटर यातायात तथा राजपथ (Highways) मन्त्रालय

२ राज्यन्तरिक-कार्य (Internal Affairs) मन्त्रालय

३ राज्य नियन्त्रण मन्त्रालय

४ सार्वजनिक स्वास्थ्य मन्त्रालय

५ वैदेशिक कार्य मन्त्रालय

६ संस्कृति मन्त्रालय

- ७ इमारती लकड़ी (Timber) के उद्योग का मन्त्रालय
- ८ प्रतिरक्षा मन्त्रालय
- ९ मांस तथा दुग्ध पदार्थ उद्योग मन्त्रालय
- १० लान्ध-पदार्थ उद्योग मन्त्रालय
- ११ मकान सामग्री उद्योग मन्त्रालय
- १२ उत्पादित उपभोग्य वस्तुओं का मन्त्रालय
- १३ मीन उद्योग (Fish Industry) मन्त्रालय
- १४ कृषि मन्त्रालय
- १५ राशकाय फार्मों का मन्त्रालय
- १६ निमाण मन्त्रालय
- १७ याताय मन्त्रालय
- १८ कारला उद्योग मन्त्रालय
- १९ वित्त मन्त्रालय
- २० अलौह धातु (Non fer ous Metal) उद्योग मन्त्रालय
- २१ लौह तथा स्पात उद्योग मन्त्रालय
- २२ न्याय मन्त्रालय

मन्त्रालयों का इस प्रकार का वर्गीकरण सोवियत संविधान में ही पाया जाता है। प्रत्येक संघ-भाषण में कन्द्रीय संयन्त्रालयिक मन्त्रालयों के प्रमुख मन्त्रालय होते हैं। उन मन्त्रालयों से निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं, और उनका सहयोग संकाय करते हैं। कुछ स्वीय राज्यों में इस से मिलती जुलती एक व्यवस्था पाई जाती है। इन देशों के संविधानों में स्वीय तथा स्थानिक विधायिका की सूचना अनिवार्य एक संवर्गों सूची होती है जिस पर संघ और राज्य दोनों ही विधायिका बना सकते हैं। परन्तु दाना में निर्वाह होने पर संघ विधायिका का प्राथमिकता दी जाता है। भारतीय संविधान में ऐसा ही व्यवस्था है। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय संघ की मंत्रि-परिषद् में समस्त सूचना में लिए गए विधायिका के लिए अलग मन्त्रालय नहीं हैं। एक ही प्रमुख अन्तर यह है कि भारत की सूचना में लिए गए विधायिका उन विधायिका

के समान नहीं हैं जो सोवियत संघ म संघ-गणराज्यिक मन्त्रालयों द्वारा शासित होते हैं।

मन्त्रि परिषद् के सहायक अंग

प्रशासन तथा अधीक्षण कार्य में सहायता देने के लिए केन्द्रीय मन्त्रि परिषद् ने अनेकों समितियाँ, परिषदें, प्रशासन संस्थाएँ आदि नियुक्त की हैं। उन पर विस्तार से विचार करने के स्थान पर हम यहाँ अति संक्षेप में केवल उन निकायों (Bodies) का उल्लेख करेंगे जिन्हें सोवियत मन्त्रि परिषद् का सहायक अंग (Auxiliary org n) माना जाता है। ये निकाय हैं—(१) आर्थिक परिषद् (२) राज्य योजना आयोग (Gosplan) तथा (३) सचिवालय।

आर्थिक परिषद्—आर्थिक परिषद् मन्त्रि-परिषद् का एक स्थायी आयोग है। मन्त्रि परिषद् का समापति आर्थिक परिषद् का अध्वन्य होता है। यद्यपि संविधान में इस संस्था का कहीं उल्लेख नहीं है परन्तु यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य कार्य समस्त आर्थिक योजनाओं का परीक्षण करना तथा उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रस्तावित करना है। यह वस्तुओं के मूल्यों तथा भूमिका के पारिभ्रमिक के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योग देती है। राज्य की अर्थ व्यवस्था का एकसूत्रता प्रदान करने में इसका पर्याप्त योग होता है। जब तक मन्त्रि परिषद् इसके आदेशों को रद्द न करे तब तक संघीय, तथा संघ गणराज्यों के मन्त्रालय एवं स्थानीय अधिकारी उसके आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। उन्हें एक निर्धारित अवधि के अन्तर उसके आदेशों के विरुद्ध संघीय मन्त्रि-परिषद् के समक्ष अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

कार्य में सुविधा के लिए सन् १९४४ में आर्थिक परिषद् को ११ विभागों में विभाजित कर दिया गया था जिनमें से प्रत्येक का अध्वन्य आर्थिक-परिषद् का एक उप-समापति होता है।

राज्य योजना आयोग—राज्य योजना आयोग—(State Planning Commission), जिसे गोस्प्लान (Gosplan) भी कहते हैं, मन्त्रि परिषद् का दूसरा प्रमुख सहायक अंग है। इसका समापति मन्त्रि-परिषद् का भी सन्तुष्ट होता है। इसका अधिकार सदस्य प्रमुख अर्थशास्त्री तथा अनुभवी राजकर्मचारी होते हैं। इस

आयोग का मुख्य कार्य रात्र का अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन कर योजनाएँ बनाना है। इसका सहायता के लिए सभ-सदस्यों में भी योजना आयोग बनाया गया है। यह समस्त मन्त्रालयों से आवश्यक विवरण तथा आकड़े माग सकता है, और उनका उपयोग कर सकता है। यह देश भर के लिए आयाजन के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करता है जिनके आधार पर सभ-सदस्यों के यात्रना आयोग योजनाएँ बनाते हैं।

सावित्र सभ में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था होने के कारण रात्र योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य का महत्त्व बहुत अधिक है। विभिन्न यात्र नाओं का एकसूत्रता प्रदान कर एक सुसंयोजित योजना बनाने तथा योजनाओं का कार्यान्वयन देने वाले अधिकारियों के कार्यों का अन्वेषण करने का समुचित व्यवस्था के अन्तर्गत में समन्वय। अर्थ-व्यवस्था से भी नागरिकों का कल्याण नहीं हो सकता है। सर्वोच्च सावित्र के प्रेसीडियम द्वारा जनवरी १९४८ में जारी की गई एक आशुति के द्वारा रात्र योजना आयोग का रात्र योजना समिति के रूप में पुनर्गठन किया गया है।

सचिवालय—मन्त्रि परिषद् का साचिबिक कार्य में सहायता देने के लिए राजधानी में एक सचिवालय है। यह मन्त्रि-परिषद् का बैन्का के लिए आवश्यक प्रबंध करता है तथा उसके विनिर्देशों को प्रकाशित करता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी सचिवालय का प्रबन्धक होता है। प्रबन्धक का सहायता के लिए कुछ सहायक-व्यवस्थाक तथा कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं।

मन्त्रि परिषद् का उत्तरदायित्व

सावित्र सभ का मन्त्रि-परिषद् सर्वोच्च सावित्र के प्रति उत्तरदायी है। सर्वोच्च सावित्र के सत्रावकाश का यह मन्त्रि-परिषद् का उत्तरदायित्व सर्वोच्च सावित्र के प्रेसीडियम के प्रति होता है। समिधान का यह उद्देश्य सावित्र सभ का मन्त्रि-परिषद् का बहुत कुछ संस्थापन रखने वाले देशों के मन्त्रि-मन्त्र

(Cabinet) का समर्थन बना देता है। परन्तु जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद् एक संसदीय शासन के मन्त्रिमण्डल से बहुत भिन्न है। इस कारण उसका सर्वोच्च सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों पर विचार करना आवश्यक है।

सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद् तथा सर्वोच्च सोवियत के वास्तविक सम्बन्धों को हम केवल साविधानिक उपबन्धों का अध्ययन कर नहीं समझ सकते। इन सम्बन्धों को प्रभावित करने वाला एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सोवियत संघ में न तो कोई विरोधी राजनीतिक दल है, और न बड़ा किसी साविधानिक विरोधी राजनीतिक दल का अस्तित्व संभव ही है। नागरिकों के सम्मेलन बनाने के अधिकार को इस प्रकार प्रतिरक्षित कर लिया गया है कि कोई भी विरोधी दल बनाने का प्रयत्न अमर्त्यियों के हितों के प्रतिकूल घायल कर देगा लिया जायेगा। साथ ही निम्नलिखितों में जिन संस्थाओं को प्रत्याशियों का नामांकित करने का अधिकार दिया गया है, उनमें एकमात्र राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी है। इस कारण सर्वोच्च सोवियत के सभी संसद या तो कम्युनिस्ट पार्टी के संसद होते हैं या उसका द्वारा समर्थित व्यक्ति होते हैं। निश्चय ही ऐसे संसद पार्टी के आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। यही कारण है कि प्रायः सदैव ही मन्त्रिपरिषद् की सदस्यता के लिए जिन व्यक्तियों के नाम की सूची सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत की जाती है वह सर्वसम्मति से निर्वाचित हो जाते हैं। जब तक उन्हें पार्टी के नेताओं का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक उन्हें पदच्युत नहीं किया जा सकता। परन्तु जैसे ही वे पार्टी के उच्च नेताओं का विश्वास खो देते हैं उन्हें अपने पद से अलग होना पड़ता है। प्रेसीडियम को जिसमें पार्टी के अनेक उच्च नेता भी होते हैं, यह अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च सोवियत के सत्रावकाश काल में मन्त्रियों को मन्त्रिपरिषद् के समारोह की सिफारिश पर मुक्त (release) या नियुक्त कर सकता है। इसी अधिकार के उपयोग के द्वारा अनाजनायक मन्त्रियों का पदभार से मुक्त किया जा सकता है और उनका स्थान अन्य ऐसे व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिन्हें पार्टी के नेताओं का विश्वास प्राप्त है। इसी स्थिति का यह परिणाम है कि सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद् के संसद स्वतन्त्र रूप

से अपनी नीति का पालन न कर सदेव पाटों की नाति की ओर आस लगाए रहत हैं।^१

मविधान में सर्वोच्च सोवियत के सन्स्यों को मंत्रि परिषद् या उसके किसी सन्स्य से प्रश्न करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित मंत्री द्वारा तीन दिन के अन्दर दिया जाना आवश्यक है। सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मंत्रियों के कार्यों की आलोचना भी कर सकते हैं। कभी कभी यह आलोचना इतनी तीव्र होती है कि मंत्री अपनी नीति में परिवर्तन करने का बाध्य हो जाते हैं। परन्तु यह समझना कि जिस प्रकार ब्रिटेन कास या भारत की सत्ता मन्त्रि-मन्त्रियों का निर्माण और अन्त कर सकती है वैसा सर्वोच्च सोवियत भी कर सकती है, असंगत ही होगा। आगे और निक का मत है कि सर्वोच्च सोवियत में किसी विषय पर मतान्तर भ अल्प मत पाने पर भी मंत्रि परिषद् को पदत्याग करना आवश्यक नहीं है।^२ व्यवहार में, मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव या विधेयक प्रायः सत्ता ही सर्वोच्च सोवियत द्वारा संसम्मति से पारित कर दिए जाते हैं। इस कारण सर्वोच्च सोवियत का विश्वास तो देने के कारण मंत्रि परिषद् या उसके किसी सन्स्य के पदत्याग करने का प्रश्न ही सामने नहीं आता। अब तक जितने भी मंत्री पदयुक्त किये

They (Soviet ministers) have little opportunity to carry out their own policies with obstructionist and dilatory methods for by unwritten law and open injunction they are required to be extremely alert to the contour and oscillations of the Party line. Formally elected in a body by the Supreme Soviet and individually appointed and displaced by the Presidium of the Supreme Soviet and individually appointed and replaced by the Party centre the members of the Council of Ministers are in fact supersensitive to all changes in high policy —Julian Towster *op cit* p 237

^२ 'To be sure ministers may be called upon to reply to questions put by the Supreme Council but the Council (Council of Ministers) does not have to resign because of an adverse vote in that body —Ogg & Zink *op cit* p 866

गए हैं व इस कारण पद-युक्त नहीं किए गए कि उन्होंने सर्वोच्च सोवियत का विश्वास खो दिया था प्रत्युत इस कारण कि पार्टी के उच्च नेताओं का विश्वास उन पर से उठ गया था। इस कारण यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सांविधानिक दृष्टि से मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है, परन्तु व्यवहार में यह उत्तरदायित्व पार्टी की कन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के प्रति है। सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद् तथा कम्युनिस्ट पार्टी का सम्बन्ध मालेनोव के उस भाषण से स्पष्ट हो जाता है जो उन्होंने अपने प्रधान-मन्त्रित्व के काल में १६ जनवरी १९२८ को सर्वोच्च सोवियत के सम्मुख किया था। उन्होंने कहा था—‘सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम, अर्थात् जन कमिसार परिषद्, बाल्शेविक पार्टी की कन्द्रीय समिति तथा कामरेड लाविन की मन्त्रणा तथा अनुमति लेते रहेंगे। यह हमारे महान् सविधान की शान्मयली और मूल भावना (spirit) दोनों के अनुकूल है।’ मालेनोव के पदत्याग की घटना जिसका हम मन्त्रिपरिषद् की स्थिति पर विचार करते समय उल्लेख कर चुके हैं, इसी निष्कर्ष का पुष्टि करता है कि सोवियत संघ में मन्त्रियों तथा मन्त्रिपरिषद् का सामान्त्रिक उत्तरदायित्व कम्युनिस्ट पार्टी की कन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के प्रति (सन् १९५२ के पून पालिटब्यूरो के प्रति) होता है।

सोवियत शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् की स्थिति

सोवियत संघ के सविधान में स्पष्ट रूप से मन्त्रिपरिषद् को संघ का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अंग घोषित किया गया है। परन्तु इस उद्देश्य के गवचन भी सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद् की यथार्थ स्थिति का निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। इसका कारण सोवियत संघ का एककालीय स्वरूप है। संसदीय शासन में शासन की नीति निर्धारित करना

‘In all important questions we the Council of the People Commissars shall seek advice and instructions from the Central Committee of the Bolshevik party and in the first instance from comrade Stalin. This, in spirit and in letter is in conformity with our great constitution.—Molotov speaking as quoted by de Basily in *Russian Under Soviet Rule* from Pravda Jan 20 1938

है कि वे अपनी दक्ष मन्त्रणा देते हैं, प्रारम्भिक योजनाएँ बनाते हैं, ऐसी नीतियों के सुझाव देते हैं जो अंगीकृत की जा सकती हैं, तथा निर्धारित नीतियों का कार्यपालन (Execution) का संचालन करते हैं। इस सीमा तक वे नीति निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। परन्तु प्रत्येक मौलिक कार्यविधि का सन्ध में वास्तविक निष्पत्ति, अन्तिम शब्द, पालिटब्यूरो के द्वारा लिया जाता है। वह किसी निर्णय का सन्ध में पूरा विवरण दे सकती है अथवा उसका सारांश स्वीकृत कर सकती है और उसका सन्ध में विस्तृत विचार करने का कार्य मन्त्रि परिषद् की सामान्य बैठक में लिये छोड़ सकती है।^१

वस्तुस्थिति यही है कि सोवियत संघ में सभी महत्वपूर्ण नातियाँ या तो कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के द्वारा निश्चित की जाती हैं अथवा मन्त्रि परिषद् के उन सदस्यों के द्वारा जो पार्टी प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के काल में युद्धजनि परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एक रॉन सुरक्षा समिति (State Defence Committee) का स्थापना की गई थी। उस समिति में स्थापना के समय पाँच सदस्य थे परन्तु बाद में तीन अन्य सदस्य भी सम्मिलित कर लिए गए थे। यह समिति ही सभी महत्वपूर्ण विषयों पर नीति निर्धारित करती थी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इस समिति को विघटित कर लिया गया। परन्तु आज भी महत्वपूर्ण विषयों पर निष्पत्ति इस समिति की एक समरूप सस्था के द्वारा किये जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने सोवियत संघ के 'इनरिंग मन्त्रिमन्त्रालय' (Inner Cabinet) का नाम

^१ They render expert advice draw up initial plans and suggest policies that may be adopted and they administer the execution of policies decided upon. But the actual determination the definitive word on all fundamental courses of action lies with the Politbureau which may busy itself with the details of decision or as is apparently often the case adopt the substance of it leaving its detailed consideration to the plenary session of the Sovnarkom —Julian Towster
op cit p 288

से संबोधित किया है। इस 'अंतरंग मन्त्रिमंडल' में मन्त्रि परिषद् का सभापति तथा उसके उप सभापति, जिनकी संख्या लगभग दस के होती है, सम्मिलित होते हैं। इनमें से अधिकांश पार्टी प्रेसीडियम के भी सदस्य होते हैं। इस कारण यह 'अंतरंग मन्त्रिमंडल' मन्त्रि परिषद् और पार्टी प्रेसीडियम के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है।

अध्याय १०

गणराज्यों का शासन तथा स्थानीय स्वशासन

संविधान सभ, वैसा कि पिछले अध्यायों में उल्लेख किया जा चुका है, एक संघीय राज है जिसमें सोलह सभ गणराज्य सम्मिलित हैं। सभ गणराज्यों में अनेकों स्वायत्तशासी गणराज्य, स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। यद्यपि समस्त सभ से संबंधित महत्वपूर्ण विषया पर केन्द्रीय शासनागों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, परन्तु आन्तरिक क्षेत्र में सभ के उपरोक्त एककों को पर्याप्त शक्ति का मान है। सोवियत संविधान में सभ-गणराज्यों को संप्रभु राज्य (sovereign states) कहा गया है, और सभ को इन संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने का निर्देशन दिया गया है।^१ गणराज्यों तथा क्षेत्रों की शासन व्यवस्था पर विलुप्त विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। परन्तु इस अध्याय में हम उनकी शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षणों पर विचार करेंगे। सोवियत संविधान में सभ-गणराज्यों स्वायत्तशासी गणराज्यों, क्षेत्रों प्रदेशों आदि के मुख्य शासनागों का व्यवस्था का उल्लेख है। सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के शासनागों के अनुरूप ही हैं।

सभ गणराज्यों का शासन-व्यवस्था

सभ गणराज्यों के संविधान—प्रत्येक सभ गणराज्य का अपना अपना संविधान होता है, जिसका निर्माण में गणराज्य के विशिष्ट लक्षणों का ध्यान रखा जाता है। इस संबंध में सोवियत संविधान में केवल एक विधान का उल्लेख है और यह यह कि प्रत्येक सभ-गणराज्य का संविधान संघीय संविधान के पूर्णरूप में अनुकूल होना चाहिए।^२ सभ गणराज्य के संविधान का अंगीकृत करने तथा उसमें आवश्यकानुसार संशोधन करने का अधिकार

^१ अनुच्छेद १५

^२ अनुच्छेद १६

न्यायाग (judicial organ) के द्वारा किसी नागरिक को दिए गए दंड को क्षमा कर सकती है। फरवरी १९४४ के संशोधन के बाद से संघ गणराज्यों का सर्वोच्च सोवियत अंतराष्ट्रीय सम्बंधों में संघ गणराज्य के प्रतिनिधित्व के प्रश्न का निणय करती है तथा गणराज्य के सैन्य संगठन की पद्धति निर्धारित करती है। इन शक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक संघ-गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत को अपना प्रेसीडियम, गणराज्य की मन्त्रि-परिषद्, तथा गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय निवाचित करने का अधिकार भी प्राप्त है।

सामान्यतः संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों के वर्ष में चार सत्र होते हैं परन्तु उनमें केवल नाति सम्बंधी प्रश्नों पर ही विचार किया जाता है। सर्वोच्च सोवियत अपनी अधिकांश शक्तियां अपने प्रेसीडियमों तथा समितियों को प्रत्यावाजित कर देती हैं जो इन्हें उनके सन्तानकाश काल में प्रयोग करती हैं।

सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम—संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत द्वारा निर्वाचित प्रेसीडियम में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (vice president), एक मंत्री तथा कुछ सभ्य होते हैं। सविधान में संघ गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियतों के प्रेसीडियमों की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु उन्हें निश्चिन करने का कार्य संघ गणराज्यों के सविधानों पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः सर्वोच्च सोवियत के सन्तानकाश काल में प्रेसीडियम ही उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है और आनश्यकता पड़ने पर आशुतिया जारी करता है। प्रेसीडियम अपने कार्यों के लिए गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होता है।

मन्त्रि परिषद्—संघ-गणराज्य की राजसत्ता का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासकीय अंग इसका मन्त्रि परिषद् होता है जो संघ-गणराज्य का सर्वोच्च सोवियत द्वारा नियुक्त की जाती है तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। सर्वोच्च सोवियत के सन्तानकाश काल में मन्त्रि परिषद् का उत्तरदायित्व सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के प्रति होता है। मन्त्रि परिषद् में एक सभापति, उपसभापति (vice chairman), राज्य आयोजन आयोग का सभापति तथा कुछ मंत्री होते हैं। उपसभापतियों तथा मंत्रियों का संस्था प्रत्येक संघ गणराज्य में भिन्न होती है। संघ

गणराज्यों का कार्य (executive) विधानमण्डल (legislature) के पूर्णतः प्रधीन है। मन्त्रिपरिषद् न केवल विधानमण्डल (सर्वोच्च संविधान) द्वारा निर्वाचित ही होती है बल्कि उसका प्रति उत्तरदायी भाव रहता है। परन्तु वास्तव में, ऐसा कि केन्द्रिय मन्त्रिपरिषद् तथा सर्वोच्च संविधान के सम्बन्धों के बारे में भी सत्य है, संघ-गणराज्यों का सर्वोच्च साधारणतः उच्चतम-सदन पर अपने प्रेक्षाधिकारों तथा मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों की पुष्टि मात्र ही करता है। प्रेक्षाधिकार तथा मन्त्रिपरिषद् का वास्तविक उत्तरदायित्व सम्पूर्णतः राज्य के सगठनों के प्रति है। मन्त्रिपरिषद् प्रश्नों पर विनिश्चय पार्लियामेंटों के द्वारा किए जाते हैं। उपर्युक्त सत्यता का फल उन्हें प्राधिकारिक रूप देता है तथा प्रचारित करता है। नाति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों के प्रतिनिधित्व सामान्य विधानों पर प्रेक्षाधिकार तथा मन्त्रिपरिषद् द्वारा विनिश्चय किए जाते हैं तथा 'प्राप्ति' और 'प्राप्ति' के रूप में जारी किए जाते हैं। ये सर्वोच्च संविधान द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रमाण होते हैं तथा सर्वोच्च ही सर्वोच्च संविधान द्वारा अनुसन्धित कर दिए जाते हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों की शासन व्यवस्था

संविधान सभा के उप-विभाग (Sub-divisions) में संघ-गणराज्यों के बाह्य स्वायत्तशासी-गणराज्य आते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें किसी संघ-गणराज्य का कोई पयात्र सम्बन्ध वाला अत्यन्त ज्ञात निर्वास करता है तथा अपना स्वायत्तशासी प्रशासन स्थापित करना चाहती है। संविधान सभा ने प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य का अपना संविधान रचने का अधिकार एवं निषेध के साथ दिया गया है कि उनका संविधान उस संघ-गणराज्य के संविधान से अलग होना चाहिये जिसके वह भाग है। स्वायत्तशासी गणराज्य उन विधियों पर विधियाँ बना सकते हैं जो उनके प्राधिकार में हैं।

स्वायत्तशासी गणराज्यों के शासन-संघ-गणराज्यों के शासन-संघ के रूप में होते हैं। प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य में एक नागरिक शासन प्रणाली एवं चार वर्ष का अवधि के लिए निर्वाचित सर्वोच्च संविधान होता है जिस संविधान में स्वायत्तशासी गणराज्य का 'राजसत्ता' का सर्वोच्च अंग तथा एकमात्र विधायक अंग बना होता है। सर्वोच्च संविधान स्वायत्तशासी गणराज्य

तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों की कार्यकारिण समिति व विनिश्चयो तथा प्रायों का रख कर सकती है।

जिलों, ग्रामों और नगरों का शासन

सावियत संघ के गणराज्यों व पूरे राज्य क्षेत्र को प्रशासनाय सुविधा के लिए जिलों (Rajon) में विभाजित किया गया है। समस्त सावियत संघ में जिलों की पूरे संख्या तीन हजार से भी अधिक है। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का दृष्टि से सब जिले समान नहीं हैं परन्तु उनका औसत जनसंख्या लगभग पैंता सौ हजार है। पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगर जिलों में सम्मिलित नहीं माने जाते तथा गणराज्यों में व प्रांत (oblast) के अधीन होते हैं और अन्य गणराज्यों में सब गणराज्य हैं।

जिले के शासनाय—वधानिक दृष्टि से जिले का सर्वोच्च शासनाय जिला सविम (Rajon Sovet) होता है जो दो वर्ष का अवधि के लिए निर्वाचित की जाती है। स्थानिक सविधान के प्रवर्तित किए जाने के पूरे जिला सविम के संघ नगर और ग्राम सविम के साथ निर्वाचित किए जाते हैं परन्तु अब वे समस्त नागरिकों के प्रत्यक्ष रूढ़ि से चुने जाते हैं। सामान्यतः एक हजार जनसंख्या पर जिला सविम का एक प्रतिनिधि चुने जाने का व्यवस्था है, परन्तु कितने सविम में पचास से कम या साठ से अधिक संघ नहीं हो सकते। प्रत्येक सविम एक कार्यकारिण समिति तथा कुछ स्थानिक समितियाँ निर्वाचित करती है। उस में जिला सविम का कम से कम छह अंशें होना आवश्यक है। नगर में अधिकांश प्रशासनीय कार्य सविम के प्रवर्तित और कार्यकारिण समिति के द्वारा ही किया जाता है और सविम के अन्य अंशों में उसके अनुमाने मात्र हो करती है।

नगर के शासनाय—जिले का भाग प्रत्येक नगर में भी एक भनजावा जनता के प्रतिनिधियों का सविम होता है जो नगर के समस्त नागरिकों द्वारा चार वर्ष का अवधि के लिए निर्वाचित की जाता है। एक सौ या अधिक जनसंख्या वाले नगरों का अनेक बार्ड (wards) में विभाजित कर दिया जाता है। इन बार्डों की भी एक एक सविम होता है जो बार्ड के नागरिकों द्वारा चुना जाता है। नगर नगर में ऐसे सौ बार्ड हैं। इस प्रकार नगरों के नागरिक

वार्ड सोवियत और पौर सोवियत (Municipal Soviet) दोनों के लिए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। नगर सोवियतों में कार्यकारिणी समिति तथा अनेक स्थायी समितियाँ निर्वाचित करती हैं। सोवियतों की बैठकों में न केवल उनके सदस्य ही भाग लेते हैं, बल्कि “विकल्प सभ्य” (alternates) भी उपस्थित रहते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामी प्रशासकों को प्रशिक्षित करना है।

ग्रामों के शासनांग—भारत की भाँति सोवियत सभ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामों में निवास करता है। सोवियत सभ में कई लाख ग्राम हैं। इनमें से बहुत से ग्रामों की जनसंख्या बहुत कम है। उन्हीं ग्रामों के नागरिक, दो वर्ष की अवधि के लिए, समजीवियों के प्रतिनिधियों का सोवियत निर्वाचित करते हैं। कम जनसंख्या वाले ग्रामों को ऐसी समितियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए परस्पर सम्मिलित कर लिया गया है। नगर तथा जिला सोवियत की भाँति ग्राम सोवियतें अपने पदाधिकारी तथा समितियाँ निर्वाचित करती हैं जो व्यवहार में अधिकांश कार्य करते हैं।

स्थानीय सोवियतों के कृत्य तथा शक्तियाँ—जिला, ग्रामों तथा नगरों की सोवियतों को वैधानिक दृष्टि से अत्यन्त विस्तृत शक्तियाँ तथा महत्वपूर्ण कृत्य सौंप गये हैं। प्रत्येक सोवियत अपने क्षेत्र के लिये अपनी इच्छानुसार प्रबंध करने के लिये स्वतन्त्र है। वंदेशिक विभाग के अतिरिक्त अन्य शासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण विभाग स्थानीय शासनों में भी पाये जाते हैं। मास्को सोवियत में निम्न विषयों पर कार्य करने के लिए समितियाँ हैं—निर्माण, गृह निर्माण, विद्यालय, भाग और नगरों के बाध, सार्वजनिक जल निकास, रेल यातायात, ग्राम कृषि और सभ्यता, स्थानीय व्यापार, स्थानाध्यक्ष, स्थानीय उद्योग और सहयोग, नाली, निर्यात, हरियाता और कृषि, सार्वजनिक-प्रापण (public feeding) व्यायाम, पुलिस और आग बुझाने का विभाग, अनाथ बालक, प्रौढ़ शिक्षा, भूमिगत रेल (Underground railway) सड़क, मोटर और अश्ववाहन, कृषि, इधन, वायुयान प्रतिस्पर्धक रक्षा, रक्षा और अर्थ। सोवियत सभ के अतिरिक्त अन्य कृषि देश का स्थानीय-संस्थाओं का इतने अधिक विषयों का प्रबंध नहीं करना होता। इसका कारण सोवियत सभ की समाजवादी व्यवस्था है। यदि हम

अपने देश की स्थानीय शासन संस्थाओं की शक्तियाँ स सोवियत स्थानाय संस्थाओं की शक्तियों तथा उनका द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तुलना कर तो हमें आश्चर्यचकित हो जाना होगा।

स्थानीय सोवियता पर नियंत्रण—सोवियत लेनक तथा न्यायविद् प्रत्येक स्थानीय सोवियत को अपने क्षेत्र में 'सुप्रभु' (sovereign) बनाता है। इसका कारण स्थानीय सोवियतों की विस्तृत शक्तियाँ हैं। परन्तु यहाँ हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्थानीय सोवियतों पर उच्च शासनार्गों का कन्ट्रोल नियंत्रण रहता है। यह सत्य है कि स्थानीय सोवियत अपने क्षेत्र के सन्तुष्ट में किसी भी विषय पर मनचाहा निर्णय कर सकता है परन्तु उसके ऊपर के शासनार्गों को उससे निर्णयों पर प्रतिरोध अधिकार (Veto) प्राप्त है। उच्च शासनार्गों के नियंत्रण के अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी स्थानीय सोवियतों पर अत्यधिक रूप से नियंत्रण रखती है। निर्वाचन प्रणाली का विशिष्टता के कारण कवल कम्युनिस्ट पार्टी के सन्तुष्ट तथा पार्टी द्वारा चुनिष्ठ शक्ति का सोवियतों के सन्तुष्ट निर्वाचित हो सकते हैं। इस कारण कन्ट्रोल द्वारा निश्चित की हुई नीति का स्थानीय सोवियतों द्वारा अनुसरण किया जाना निश्चित ही है। दूसरा बात यह है कि स्थानीय सोवियता की कार्यकारिणी समितियों के अधिकांश सन्तुष्ट पार्टी के विश्वासपात्र व्यक्ति होते हैं या पार्टी के प्रत्येक आदेश का पूर्णतः पालन करते हैं। इससे स्थानीय संस्थाओं और उच्च शासनार्गों में विरोध की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। पार्टी सोवियतों की कार्यवाहियों पर अपनी स्थानीय शाखा के द्वारा दृष्टि रखती है और आवश्यकता समझने पर उनकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में परिवर्तन करा देती है।

सोवियत संघ की स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों का देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत शासन प्रणाली विघटनकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। परन्तु, वास्तविकता यह है कि स्थानीय शासनार्गों पर उच्च शासनार्गों तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण के कारण सोवियत संघ का शासन व्यवस्था में कन्द्रीकरण की मात्रा बहुत अधिक है।

अध्याय ११

सोवियत न्यायपालिका

लार्ड ब्राइट ने न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता को किसी देश के शासन की उत्तमता का सबूत कसौटी माना है।^१ राज्य शास्त्र व अन्य अनेक प्राधिकारी लेखकों ने भी न्यायपालिका व कानून को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा गम्भीर मतलाया है। इसीलिए यह आवश्यक है कि सोवियत शासन प्रणाली का अध्ययन समाप्त करने के पूर्व हम सोवियत संघ का न्याय व्यवस्था पर भी विचार करें। माहौलिक प्रतिष्ठे के पश्चात् से अब तक सोवियत न्याय व्यवस्था में अनेक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण हम पहले प्रतिष्ठे में इन परिवर्तनों पर विचार करेंगे और इसके पश्चात् वर्तमान न्याय व्यवस्था तथा उसका विशेषताओं का उल्लेख करेंगे।

न्याय व्यवस्था के दो रूप—सोवियत संघ में न्याय तथा सुरक्षा का अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्भावित माना जाता है। राज्य सुरक्षा के लिये सोवियत संघ के पास एक विशाल सेना है। परन्तु राज्य सुरक्षा के अतिरिक्त आन्तरिक सुरक्षा की समस्या सामने आती है। सोवियत राज्य तथा समाज व्यवस्था को न्याय प्रसार के शत्रुओं से अपनी रक्षा करनी होती है। प्रथम प्रकार के शत्रु वह व्यक्ति हैं जो शासन द्वारा बनाई गयी विधियों का पालन नहीं करते तथा समाज विरोधी कार्य करते हैं। इनके कार्यों का कोई राजनैतिक महत्त्व नहीं होता। दूसरे प्रकार के शत्रु वह व्यक्ति तथा संगठन हैं जो सोवियत संघ के राज्य शत्रुओं से मिलकर अथवा स्वतंत्र रूप से सोवियत संघ की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को उलटना चाहते हैं। इनके कार्यों से शासन का विशेष रूप से

^१ The case is no better statement of the efficiency of its judicial system — Lord Bryce *Modern Democracies* Vol II p 384

सावधान रहना होता है। इसी कारण उन दोनों वर्गों के अपराधियों के मामलों पर विचार करने तथा दंड देने के लिए भिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है। वैयक्तिक अराजनीतिक अभियुक्तों के मामलों पर सामान्य न्यायालयों में विचार किया जाता है परंतु राजनीतिक अपराधियों को दंड देने का कार्य राजनीतिक पुलिस को सौंपा गया है। यद्यपि राजनीतिक पुलिस को अपराधियों के मुकदमों सुनने का अधिकार नहीं है परन्तु वह उन्हें भ्रम शिविरों (labour camps) में भेज सकती है जो उसी के द्वारा संचालित होते हैं। स्टालिन सविधान में राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु आज भी वह एम. वी. पी. (M. V. P.) के नाम से काम करती है।

स्टालिन सविधान के पूर्व सोवियत न्याय व्यवस्था की रूपरेखा— बाहराविक क्रांति के पश्चात् आरशाही शासन की समस्त विधियों को रद्द कर दिया गया था। न्यायालयों का यह आदेश दिया गया था कि वह केवल सोवियत शासन द्वारा प्रवर्तित आशक्तियों को ही विधि मानें तथा प्रत्येक मामले पर 'क्रांतिजनित औचित्यता' (Revolutionary expediency) की दृष्टि से ही निष्पत्ति करें। पूरा दृष्टांतों के आधार पर नहीं। उस समय सुरक्षा का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण था इसी कारण क्रांति विराधियों के मामलों पर राजनीतिक पुलिस (CHEKA) के विशेष न्यायालयों में अत्यन्त संक्षेप में विचार किया जाता था।

एक युद्ध की समाप्ति तथा नवीन आर्थिक नीति के अपनाए जाने के पश्चात् सोवियत न्याय व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता अनुभव की गई। मार्क्सवादी सिद्धांतों को, जिनके अनुसार साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के पश्चात् विधियों की कोई आवश्यकता ही शेष नहीं रहेगी, कार्यरूप देने का प्रारंभिक उत्साह अब शिथिल हो गया था। यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक अन्य देशों में पूँजीवादी व्यवस्था है, सोवियत सभ में भी मार्क्सवादी दर्शन को पूर्णरूपेण कार्यरूप नहीं दिया जा सकता। इसी कारण विधियों के संहिताकरण का कार्य आरंभ किया गया। सन् १९२२ में दंड संहिता (Criminal Code) तैयार की गई। इसके पश्चात् व्यवहार संहिता, भ्रम संहिता, तथा पारिवारिक विधि संहिताओं को भी तैयार कर प्रकाशित किया गया।

नवम्बर १९१७ में ही एक आगस्त द्वारा जन न्यायाधीशों के संगठन की व्यवस्था की गई थी। माक्सिम गिल्लासोव के अनुसूच्य चार प्रशासन में जन सभाओं प्राप्त करने के लिये न्यायाधीशों के साथ जन निगरान (People's Assessors) के बैठने की प्रणाली का आरम्भ उसी काल में हुआ। आज भी यह सोवियत शासन प्रणाली का एक प्रमुख विशेषता है। सन् १९२४ में सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उस निम्न सत्र गणराज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर विचार करने तथा निष्पत्ति देने का अधिकार दिया गया था। ऐसे सत्र-गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायाधीशों के निर्णयों का पुनर्विचार करने का भी अधिकार था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केन्द्रीय कार्यकारी समिति के प्रेसीडियम द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उस न्यायालय ने स्थापित सत्रधान के प्रारम्भित किए जाने के समय तक कार्य किया। इस पश्चात् उसका स्थान नव-सत्रधान के उपरान्त के अनुसार संगठित सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया।

सोवियत संघ की वर्तमान न्याय व्यवस्था

सोवियत संघ के नवम्बर अध्याय में सारित संघ के न्यायालयों के संगठन, अधिकार तथा कृत्य आदि का उल्लेख है। सांविधानिक उपबंधों के आधार पर अगस्त १९३८ में सर्वोच्च सोवियत ने एक विधि पारित की थी जिसका नाम सोवियत संघ, संघ गणराज्यों तथा स्वायत्त शासी गणराज्यों की न्यायपालिका सम्बन्धी विधि है। इन्हीं के आधार पर सोवियत संघ की वर्तमान न्याय व्यवस्था कार्य करती है। न्याय व्यवस्था का संगठन एक प्रारम्भिक रूप में किया गया है। नवम्बर नाच नागरिकों द्वारा प्रयत्न रीति से निर्वाचित जन न्यायालय हैं। उनसे ऊपर क्षेत्रीय न्यायालय हैं। क्षेत्रीय न्यायालयों के ऊपर स्वायत्तशासी गणराज्यों तथा संघ गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय हैं। न्याय व्यवस्था के स्तर पर सोवियत संघ में सर्वोच्च न्यायालय है। इन सामान्य न्यायालयों के आन्तरिक कुछ विशेष न्यायालय भी हैं जो अपने निश्चित क्षेत्र में कार्य करते हैं।

उत्तमान 'याय' व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्त तथा विशेषताएँ—
 सावियत संविधान तथा सन् १९३८ की विधि के अनुसार सावियत 'याय' व्यवस्था
 का प्रथम मौलिक सिद्धान्त विधि के समस्त नागरिकों की समानता है। सोवियत
 सभ के नागरिकों में किसी भी आधार पर 'न्यायालयों' में भेद भाव नहीं किया
 जाता। योरोप के कुछ महाद्वीपीय देशों में राजकर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा पर
 विचार करने के लिए प्रशासनीय न्यायालय हैं परन्तु सोवियत सभ में ऐसी को
 'व्यवस्था' नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त 'न्यायाधीश' की स्वतंत्रता है। इसका
 अर्थ यह है कि सभ अथवा एक्का का कोई अधिकारी या शासनांग 'न्यायालयों'
 की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायाधीश विधि के अनुसार मुकदमों
 पर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभियुक्तों को अपनी वैधानिक प्रतिरक्षा
 करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वह अपनी वैधानिक प्रतिरक्षा के लिए
 यकीन नियुक्त कर सकते हैं। सोवियत सभ के पूर्ण राज्य क्षेत्र में 'गणराज्य'
 (11) और द (12) प्रक्रिया की एकरूपता सोवियत न्याय व्यवस्था
 का एक अन्य विशेषता है। इससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
 सोवियत न्यायालयों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से होती है। जो 'यदि'
 न्यायालय में प्रयुक्त भाषा न जानने हो वह कार्यवाही को समझने के लिए एक
 'वाक्यान्ता' (interpreter) की सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा 'न्यायालय' में
 अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। केवल कुछ विशिष्ट मुकदमों में ही
 'न्यायालय' की कार्यवाही गोपनीय रखी जाती है। सोवियत सभ में समस्त 'न्याया'
 धीश निर्वाचित होते हैं। जनन्यायालय के न्यायाधीश नागरिकों द्वारा निर्वाचित
 होते हैं तथा अन्य न्यायालयों के 'न्यायाधीश' सोवियतों द्वारा। सोवियत सभ के
 सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों के साथ 'जन निर्धारक' अथवा सह-न्यायाधीश
 भी मुकदमों पर विचार करते तथा निर्णय देते हैं। यह प्रथा अनेक देशों की जूरी
 प्रथा के समान है परन्तु इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर भी हैं जिन पर
 हम आगे विचार करेंगे। सोवियत 'न्यायालयों' के वातावरण में 'अनाधिकारिता'
 का प्राधान्य रहता है और दूसरे देशों जैसी कानूनी 'कड़बटनी' नहीं पाई जाती।
 अपनी इस विशेषताओं के कारण सोवियत न्याय व्यवस्था ने अनेक विदेशों
 व्यवस्थाओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है।

जन निर्धारक (Peoples Asse sors)—सोवियत संघ के प्रत्येक न्यायानय में न्यायाधीश के साथ जन निर्धारक भी अभियुक्तों के मामलों पर विचार करते हैं तथा निष्पत्ति देते हैं। सामान्यतः किसी मामले पर विचार एक न्यायाधीश तथा ११ जन निर्धारकों के द्वारा किया जाता है। जन निर्धारकों का न्यायाधीश के समान ही शक्ति प्राप्त होती है और यदि दोनों जन निर्धारकों का मत एक-दूसरे के विपरीत हो तो निष्पत्ति जन निर्धारकों के मत के अनुसार ही होगी।

जन निर्धारकों व निवाचन की प्रणाली न्यायाधीशों व निर्वाचन की प्रणाली व समान है। न्यायाधीशों की भांति जन निर्धारक निवाचित होने के लिए भी मताधिकार प्राप्त नागरिक होने व अनिच्छित अन्य किसी ग्रहता (qualification) की आवश्यकता नहीं है। जन न्यायालय व जन निर्धारक (तथा न्यायाधीश) नागरिकों द्वारा, तथा उच्चतर न्यायालय व जन निर्धारक सोवियतों व नगर निवाचित किए जाते हैं। न्यायाधीशों और जन निर्धारकों में एक मुख्य अंतर यह होता है कि न्यायाधीशों का पद स्थायी होता है वही जन निर्धारक पद में कम से कम लगभग दस दिन काम करते हैं। जन निर्धारक पद के लिए अनेक शक्तियाँ का एक मण्डल (panel) एक साथ निवाचित कर लिया जाता है, और इन्हीं में से जारी जारी से दो व्यक्ति न्यायानय की कार्यवाही में भाग लेते हैं। सोवियत संघ व सर्वोच्च न्यायालय के लिए सर्वोच्च सोवियत २५ जन निर्धारकों का एक मण्डल निवाचित करता है।

जन निर्धारक सामान्य नागरिकों में से ही चुने जाते हैं और इस कारण व अभियुक्तों की कठिनाई को भला भांति समझ सकते हैं। न्यायाधीश जन जीवन से दूर हो जाते हैं, परन्तु जन निर्धारकों के सम्पर्क में यह बात नहीं कही जा सकता। अन्य अनेक देशों में न्यायाधीशों की तथ्य निर्धारण में सहायता करने के लिए जूरी होते हैं, परन्तु उई इतनी विस्तृत शक्ति नहीं प्राप्त होता जितनी जन निर्धारकों को प्राप्त होता है।

सोवियत काल—हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि सोवियत-संघ में अभियुक्तों का अपनी वैयक्तिक प्रतिरक्षा के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। सोवियत न्यायिक संगठन पर विचार आरंभ करने के पूर्व

दा शब्द सोवियत वकीलों के बारे में भी क' देना आवश्यक है। प्रत्येक न्यायालय के क्षेत्र में एक वकीला का मंडल (Collegium) होता है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक वह व्यक्ति हो सकता है जो वकालत करने की ग्रहता रखता हो। वकालत की शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है। जब किसी व्यक्ति या प्रतिगानी को वकील की आवश्यकता होती है तो वह अपने क्षेत्र के वकीलों के मण्डल से या तो स्वयं अपना वकील चुन लेता है या मण्डल से ग्रहने लिए एक वक्तोच नियुक्त करने का अनुरोध करता है। सामान्यतः वकील 'मन्' द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। वकीला को सारा क' ब'ले में जा शुल्क मिलता है वह वकीला का नहीं प्राप्त होता वह मण्डल का प्राप्न होता है। मण्डल प्रति माह वकीला को उनका काय के अनुसार उचित पारिश्रमिक दे देता है। सामान्यतः यह पारिश्रमिक एक कुशल श्रमिक (Skilled workman) के पारिश्रमिक के बराबर ही होता है। मण्डल में अनुशासन बनाए रखने का कार्यमण्डल के प्रसीटियम का सौंपा जाता है।

उपरोक्त प्रणाली अर्य देशों की पद्धति से सबथा भिन्न है। सक्षेप में इसका कारण यही है कि सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट वकीला को सारा 'व्यवस्था से सबद्ध मानते हैं। उन्हें वकील नियुक्त करने का प्रथा को विशेष परिस्थितियों के कारण ही स्वीकार करना पडा। यहा यह उल्लेखनाय है कि सोवियत संघ में वकीला का काय बहुत सीमित होता है, क्याकि वाना प्रतिगानी और साक्षिा से स्वयं न्यायागरी प्रश्न पूछता है और तम्य जमने का प्रयत्न करता है।

न्यायिक संगठन

जन-न्यायालय (People's courts)—सोवियत न्याय व्यवस्था का निम्नतम संगठन सोवियत संघ के जन न्यायालय हैं। डाक्टर ने उह न्यायालय व्यवस्था का विस्तृत आधार कहा है। उनकी काय प्रणाली का प्रास्तासी तथा अन्य अनेक विदेशी पर्यवेक्षकों ने हुत प्रशंसा की है।

प्रत्येक जन न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा दो जन निर्धारक (people's assessors) होते हैं। न्यायाधीश तथा जन निर्धारक दोनों का निर्वाचन जिले

के समस्त नागरिकों द्वारा मजदूरी, प्रत्यक्ष तथा समान मताधिकार के आधार पर शुद्ध मतदान के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीश तथा जन निवारक दोनों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। जन निवारकों का न्यायालय में कार्य करने के लिए जारी जारी से बुलाया जाता है और कोई जन निवारक वर्ष में दस दिन से अधिक कार्य नहीं कर सकता। न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिये जन निवारकों का प्रतिफल दिया जाता है जो कि सा भी दशा में उनकी उतने दिनों की औसत आय से कम नहीं होता। जन न्यायालय में निष्पक्ष बहुमत से किए जाते हैं और जन निवारकों को न्यायाधीश व समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं। न्यायाधीश तथा जन निवारक दोनों को अपने निवारकों को समय समय पर अपने कार्य की प्रार्थना देना आवश्यक है।

जन-न्यायालयों के निम्नतम न्यायालय होने का कारण उन्हें कर्ल प्रारम्भिक क्षमाधिकार ही प्राप्त हैं, अपालीय नहीं। व. यहार और नाटिक दोनों ही प्रकार के मामले सुन सकते हैं तथा उन पर निर्णय दे सकते हैं। यहार-सम्बन्धी (civil) मामलों के क्षेत्र में जन-न्यायालयों का सम्पत्ति, सम्बन्धी विधि, उत्तराधिकार आदि से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने का अधिकार है। नाटिक (criminal) क्षेत्र में उन्हें नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति स्वास्थ्य स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठा के विरुद्ध किए गए अपराधों पर विचार करने का अधिकार है। निवारक विधि के अन्तिम करने करने करने अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने, शासन के विभिन्न अंगों व अंगों तथा अंगों विधियों का पालन न करने आदि के मामलों में जन-न्यायालयों के क्षेत्र में ही आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन-न्यायालयों का क्षमाधिकार अत्यन्त विस्तृत है। अधिकांश यहार तथा नाटिक मामलों पर जन-न्यायालय ही विचार करते तथा निष्पक्ष करते हैं।

जन-न्यायालयों की कार्यवाही की प्रमुख विशेषता यका अनौपचारिकता है। प्र. साम्बिक अनुसार उन कमकरण में सरलता तथा समानता का वातावरण रहता है तथा कानून का सामान्य दैनिक जीवन व पर तथा उसका निरीत समझने की भावना का अभाव रहता है। यह हमें यह प्रकट करता है कि कानून

का क्या बनाया जा सकता है।^१ 'यायाधीशा के कार्य पर निवार प्रकट करते हुए प्रो. लास्की ने लिखा है कि "व न कवल दड ही देत हैं वरन् सामाजिक अयनस्थाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। व जिस मामले पर निवार करते हैं उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाने का पूरा प्रयास करते हैं तथा पूरे मामले का उससे संबद्ध कर के देखते हैं।"^२

प्रदेश क्षेत्रों स्वायत्तशासक क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों के न्यायालय—प्रत्येक प्रदेश, क्षेत्र, स्वायत्तशासक क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र का एक न्यायालय होता है। इन न्यायालयों का नियोजन संबंधित प्रदेश या क्षेत्र की 'भूमिजीवियों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के द्वारा किया जाता है। इन सभी न्यायालयों का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। प्रत्येक न्यायालय में एक सभापति, एक उप सभापति, सदस्य तथा उन निर्धारक होते हैं। इन निर्धारकों का निर्वाचन भी सोवियतों के द्वारा यायाधीशों के समान अवधि के लिए ही किया जाता है। उपरोक्त सभी न्यायालयों में दो विभाग होते हैं—व्यवहार संबंधी मामलों का विभाग तथा दायित्व मामलों का विभाग। ये विभाग क्रमशः व्यवहार तथा दायित्व मामलों की सुनवाई करते हैं।

इन न्यायालयों को प्राथमिक तथा अपीलार्थ दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य की सुरक्षा समाजवादी सम्पत्ति के अपहरण अथवा दुर्व्ययोग से संबंधित मुकदमों की प्राथमिक सुनवाई इन न्यायालयों में हो सकती है। इसी प्रकार के अन्य गम्भीर विषयों से संबंधित मुकदमों की प्राथमिक सुनवाई इन न्यायालयों में हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये सभी न्यायालय जन

^१ There is a simplicity about their work a two phase of equality an absence of that sense of the law as something outside and against normal daily life which gives one a new vision of what the law might be made —Prof Harold J Laski *Law & Justice in Soviet Russia* pp 19-20

^२ They are resolving social misadjustments and not merely inflicting penalties They relate the cases they try to the economic background they can deal with —Laski, *ibid* p 20

न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध की गई प्रतीति पर विचार करते तथा न्याय देते हैं। इनके समक्ष न केवल न्यायी या प्रतिवादी के द्वारा अपील की जा सकती है, बल्कि क्षेत्र के राजपूत अथवा न्यायालय के समाप्ति के अनुष्ठान पर भी ये जन-न्यायालयों के निर्णयों का पुनर्विचार कर सकते हैं।

स्वायत्तशासक गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय—प्रत्येक स्वयत्तशासी गणराज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका निर्वाचन पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वायत्तशासी गणराज्य की सर्वोच्च संविधान के द्वारा किया जाता है। संसदन का दायित्व से यह बहुत कुछ उपरोक्त न्यायालयों के समान हो सकते हैं। इनमें भी न्यायाधीश तथा जन अधिकार दाना कार्य करते हैं। इनका नेत्राधिकार असीमित तथा प्रारम्भिक शक्तों प्रकार का होता है। यह उन मामलों का प्रारम्भिक सुनवाई करते हैं जिन पर निर्णय करने का अधिकार इन्हें विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर भी विचार करते हैं और उन निर्णयों का पुनर्विचार कर सकते हैं।

संघ गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय—संघ गणराज्य का सर्वोच्च न्यायिक अंग उसका सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका न्यायाधीशों तथा जन निर्णायकों का निर्वाचन संघ-गणराज्य का सर्वोच्च संविधान द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है।

संघ-गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय २ क्षेत्राधिकार में प्रारम्भिक तथा असीमित शक्तों ही प्रकार का क्षेत्राधिकार सम्मिलित है। प्रारम्भिक सुनवाई के लिए इसका समस्त क्षेत्र प्रत्यक्ष तथा दायित्व सम्पत्ति शक्तों हैं जिनका असाधारण महत्त्व होता है तथा ये विधि द्वारा स्वयं नेत्राधिकार में प्राप्त जाते हैं। ये संघ-गणराज्य के समस्त न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनते हैं और उनका निर्णय करते हैं। इन्हें संघ-गणराज्य के समस्त न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों का अधीक्षण करने की शक्ति भी दी जाती है। ये संघ गणराज्य के महत्त्वपूर्ण अथवा अनेक समाप्ति के

अनुरोध करने पर निम्न न्यायालयों के निर्णयों को पुनर्विलोकित भी कर सकते हैं।

सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय

सोवियत न्यायिक संगठन के शीर्ष पर अवस्थित सर्वोच्च न्यायालय सोवियत संघ का उच्चतम न्यायालय है। यह सोवियत संघ का एक मात्र संघीय न्यायालय है क्योंकि 'सब' अधीन समस्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करने वाले दोर-न्यायालयों (circuit courts) की भांति कोई अन्य संघीय न्यायालय नहीं हैं। सोवियत संघ के अन्य सभी न्यायालय संघ गणराज्यों, स्वायत्तशासी गणराज्यों, क्षेत्रों आदि से संबंधित हैं।

रचना तथा संगठन—सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोवियत संघ के सर्वोच्च सचिवों के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। सविधान अध्या सन् १९२८ की विधि में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यह समय समय पर परिवर्तित होता रहती है। सन् १९३८ में निर्वाचित न्यायालय में ४५ न्यायाधीश तथा २० जन निधारक (People's assessors) थे। सन् १९४६ में निर्वाचित सर्वोच्च न्यायालय में ६८ न्यायाधीश तथा २५ जन निधारक थे। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया गया है। इस अवधि के पूर्व किसी न्यायाधीश का तभी हटाया जा सकता है जब उसके विरुद्ध सोवियत संघ के महा-वकील (Procurator General) के निनिश्चय तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम की स्वीकृति से दण्ड (crime) प्रपत्रों के लिए मुकदमा चलाया जावे।^१

सर्वोच्च न्यायालय का एक समापति तथा एक उपसमापति होता है। कार्य का सुविधा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का पांच मंडल (collegiums) में विभाजित किया गया है। इन मंडलों के नाम हैं—(१) दण्ड (criminal), (२) जनहानि (civil) (३) सेना (military), (४) रेल परिवहन, तथा (५) जल परिवहन मंडल। इन का मंडल

^१ See Article 18 of the Law on Judiciary (1938)

किंवा मुक्तम् की प्रारम्भिक (original) सुनवाई करता है तो उसमें दा'न निर्धारक तथा एक 'यायाधीश' बैठने हों।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ साविधत सभ के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इससे अतिरिक्त उस कुछ अमान्य-सम्बन्धी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। यह केवल ऐसे मामलों का प्रारम्भिक सुनवाई करता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हों, तथा जिन पर विचार करने का अधिकार इस विधि द्वारा दिया जाता है। यानि उच्च न्यायाधिकारिता से सम्बन्धित अपवाद असाधारण मामलों के मामले ही अपने सम्पूर्ण प्रारम्भिक सुनवाई के लिए आते हैं। इस सब मामलों के बीच ऊपर होने वाले विवादों पर भी प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अपलाय क्षेत्राधिकार—सार्वजनिक सभ के सर्वोच्च न्यायालय को सभ-जनताओं के सर्वोच्च प्राप्ति तथा उस विशेष न्यायाधिका के द्वारा निर्णय मामलों का अमान्य सुनने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय का सभा-मण्डल (military coll group) केनिक न्यायालय के द्वारा निर्णय मामलों का अपीलों की सुनवाई कर सकता है। जिन सभ न्यायालय में किसी अमान्य पर विचार होता है उस सभ जन निर्णय उसका वादवादी में भाग नहीं लेता।

अपलाय सभया अधिकार—उपरोक्त प्रारम्भिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सभ-जन सभ के सर्वोच्च न्यायालय को सभ-जन सभ की न्याय-वर्धना का अधिकार करने का निर्णय शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये सभ-जन सभ के समस्त न्यायालयों का न्यायिक पञ्चाय और अन्तिम के सभ-जन अन्तिम निर्णय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सभा-जन का यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सभ-जन सभ के किसी भी न्यायालय के सम्पूर्ण प्रत्युत्तर किंवा सुनवाई का सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण सभ (Plenum) के सम्पूर्ण प्रत्युत्तर कर सकता है। पूर्ण सभ में न्यायालय के सभी सम्पूर्ण भाग लेते हैं। पूर्ण सभ में सभ-जन सभ के महा-न्यायाधीश का उचित रहना आवश्यक है तथा सभ-जन

शासन का न्याय-मन्त्री भी उपस्थित रह सकता है। न्याय व्यवस्था सनघी विधि के अनुसार न्यायालय के पूरा सत्र का दो मास के अन्दर कम से कम एक सत्र होना आवश्यक है। इस सत्र में उसक विभिन्न मण्डलों के निर्णयों पर न्यायालय के सभापति अथवा महान्यायाधी द्वारा अनुरोध किए जाने की दशा में पुनर्निर्णय किया जाता है तथा प्रधान न्यायालयों को न्यायिक-मदति के सत्र में अनुदेश जारी किए जाते हैं।

सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय का तुलनात्मक स्थिति—
सोवियत संविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय हम उल्लेख कर चुके हैं कि सोवियत संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धान्त का मान्यता नहीं दी गई है। इसी कारण सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का निराचन (interpretation) करने तथा सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियों को उससे प्रतिकूल होने पर अवैध एवं रद्द घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान के निवचन करने का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान हम संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से लगा सकते हैं। अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस द्वारा पारित लगभग अस्सी विधियां तथा राज्य के गवर्नरमण्डलों द्वारा पारित तीन सौ से अधिक विधियों को आंशिक या पूर्ण रूप से अवैध घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित की गई विधियों में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 'न्यू डील (New Deal)' से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधियां भी हैं। भारत के संविधान में भी देश के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का निवचन करने का अधिकार दिया गया है और पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रति सद्विस्त जीवन में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार का अनेक बार प्रयोग किया है। परन्तु सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित किसी विधि को स्पष्टतया संविधान के प्रतिकूल होने पर भी अवैध घोषित नहीं कर सकता। सोवियत संविधान में संविधान का निवचन करने का कार्य सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम को सौंपा गया है न कि सर्वोच्च न्यायालय को।

न्यायालय का एक प्रधान कृत्य नागरिकों के संविधान द्वारा प्रत्याभूतित (Guaranteed) अधिकारों का संरक्षण करना होता है। परन्तु सोवियत

रूप में यदि विधानमण्डल कोई ऐसी विधि पारित करती है तो नागरिका के अधिकारों का अतिक्रमण करती है वो सभी न्यायालय उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता। संविधान में यह भी उपपन्न है कि किसी न्यायादारी (Prosecutor) की अनुमति से किसी नागरिक को गना बनाया जा सकता है।^१ इसी प्रकार के अन्तर्गत सोवियत संघनातिक्रम पुनर्रक्ष नागरिकों का नही गना कर अमरिनिंग में भेज सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा किसी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सावियत सर्वोच्च न्यायालय का नागरिकों के मूलाधिकारों का संरक्षण गना माना जा सकता है।

अतः संविधान में न्यायाधीशों को स्वतन्त्र और केवल विधि के अधीन न्याया गया है, परन्तु हमें इस स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ समझ लेना चाहिए। एक सावियत न्यायाधीश (Judge) के अनुसार 'सामान्य मानकों का पालन करना कर्म की स्वायत्तता का अर्थ शास्त्र की सामान्य नीति का पालन न करना बताना नहीं है। न्यायपालिका सत्य-सत्ता का एक अंग है और इस कारण वह राजनीति में प्रयत्न नहीं कर सकती।'^२ उसी न्यायाधीश ने लिखा है कि यह स्पष्ट ही है कि न्यायाधीशों को स्वतन्त्रता उच्च राजनीतिक अनुदेशों (Political directives) का मानने के कठिन से मुक्त नहीं कर देती। निश्चय ही यह अनुदेश सोवियत विधि के, ता कि संसद के अधिनियमों द्वारा निर्देशित जनता की शक्ति का अभिमुख करता है, कभी अतिक्रमण नहीं कर सकती।^३ न्यायाधीशों का स्वतन्त्रता का यह अर्थ जान लेना चाहिए

^१ See Article 127 of the Soviet Constitution

^२ The independence of Judges means examining concrete cases does not at all include the duty to follow the general policy of the government. The Judiciary is an organ of state power and the state cannot be outside of politics. —Polianky *The Sixth Constitution on the Judiciary & the Prosecutor's Office* p 83

^३ It is self evident that the independence of the Judges does not release them from the duty to obey political directives which of course also cannot go against the Soviet

हा हमें यह याद रखना आवश्यक है कि 'यजहार' में न्यायाधीश पद के लिए यही व्यक्ति निर्वाचित होने हों जा या तो कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य होत हों या तो पार्टी के सदस्य न होने पर भी पार्टी के नेताओं के विश्वासपात्र होत हों और चित्त चारे में यह निश्चय होता है कि वे पार्टी द्वारा प्रतिपादित नीति का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। उस सत्र में यह तथ्य भी पूरा महत्वहीन नहीं है कि सोवियत संघ की सरकार (मंत्रिपरिषद्) का एक सदस्य, न्याय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण मंत्री की कार्यवाही में भाग लेता है और 'याग' लया के प्रशासन का अधीक्षण करता है। इन बातों पर विचार कर हम 'स्टी' परिणाम पर पहुँचते हैं कि सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय कभी भी सरकार की नीति, जो कि वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निश्चित नीति ही होती है, के प्रतिकूल काम पग नहीं उठा सकता।

सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय को न तो उतनी विशद शक्तियाँ ही प्राप्त हैं जितनी संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के सर्वोच्च न्यायालयों को इन देशों के संविधानों के द्वारा प्रदान की गई हैं, और न वह नागरिकों के अधिकारों की पूरा रक्षा करने में ही समर्थ है। उस कन्द्रीय शासन के अन्य अंगों से सर्वथा स्वतंत्र अंग मानने के स्थान पर उनका सहायक अंग मानना ही अधिक उचित होगा।

महान्यायवादी (Procurator General)

सोवियत संविधान में 'याग' व्यवस्था से सम्बन्धित एक उच्चाधिकारी के पद का उल्लेख है जिसे सोवियत संघ का प्रोक््यूरैटर जनरल, अर्थात् महान्यायवादी (Procurator General) कहा गया है। सन् १९४६ के पूर्व इस अधिकारी को 'अटॉर्नी जनरल' (Attorney General) कहते थे। उस वर्ष संविधान में संशोधन कर उसे वर्तमान नाम दिया गया। अन्य देशों के संविधानों में भी उसी समरूप अधिकारी की व्यवस्था की गई है परन्तु सोवियत संघ के मन्त्रिमन्त्रालय तथा अन्य देशों के उसी समरूप अधिकारियों के कृत्या तथा शक्तियों में बहुत अंतर है। सन् १९३३ के पूर्व महान्यायवादी पद संघीय शासन

law that expresses the will of the people the law governed directed by the dictatorship of the proletariat — Ibid p 82

का स्वतंत्र अंग नहीं था वरन् सोनियत सच के सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित था। सन् १९३३ में एक संविधानिक संस्थापना के द्वारा सोनियत सच के महाधायवाणी के पद की स्थापना की गई और इसे सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्र रखा गया। स्थानिक संविधान में भी उसकी इस स्तुत स्थिति को मान्यता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद ११३ में कहा गया है कि 'सोनियत सच के सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा उनके अग्रीन संस्थापना, अधिकारियां तथा नागरिका के विधि का पूरा पालन करने को सर्वोच्च प्रधीक्षण शक्ति सोनियत सच के महाधायवाणी में निहित है।' यह उपर्युक्त महाधायवाणी के पद के महत्त्व का भलाभाति स्पष्ट कर देता है।

नियुक्ति तथा कार्यकाल—सोनियत सच के महाधायवाणी की नियुक्ति कथान सर्वोच्च सोनियत ने द्वारा सात वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। परा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा मन्त्रिपरिषद् का का सर्वोच्च सोनियत ने द्वारा ही नियुक्ति किए जाते हैं। मर्यादाध प्रत्यक्ष पांच तथा बार उप है।

महाधायवाणी के कृत्य तथा शक्तियां—सोनियत सच के महाधायवाणी का मुख्य कृत्य विभिन्न मन्त्रालयों अधिकारियों तथा नागरिका द्वारा विधियों के समुचित रूप में कार्य पालन का अधीक्षण करना है। उक्त सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान अभियोजक (Chief Prosecutor) के रूप में कार्य करता है। महाधायवाणी को यह अधिकार दिया गया है कि वह सोनियत सच के अग्रीन न्यायालय में चलन वाले निम्न मामलों का सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण सच (Plaintiff) के समान उपस्थित कर सकता है। उक्त सच भी कराच न्यायालय के पूर्ण सच में दर्जित रहना आवश्यक है। यदि उक्त सच समझता है कि निम्न न्यायालय द्वारा किया गया कोई निर्णय गलत कठोर या गलत मुद्दा है तो उक्त सर्वोच्च न्यायालय से उसका पुनर्विचार करा करे के लिए अनुमति कर सकता है। यह शासन के विभिन्न विभागों तथा पत्राधिकारियों के कार्य पर भी दृष्टि रखता है जिससे नागरिका के अधिकारों का उपर्युक्त अधिकाधिक आनन्द प्राप्त न हो। महाधायवाणी अवश्य नजरबंदी के मामलों का जांच करता है तथा जनों के प्रशासन का भी देख-भाल करता है। यदि महाधायवाणी का यह विचार हो जाय कि

किसी मामले में अन्याय हुआ है तो वह न्यायालय से उस मामले पर दुबारा विचार करने को कह सकता है।

महान्यायवादी सघ-गणराज्या, स्वायत्तशासक गणराज्या, क्षेत्रों, प्रेशों आदि के न्यायवातियों (Procurators) को पांच सघ की अवधि के लिए नियुक्त करता है। जिलों, नगरों आदि के न्यायवादियों का नियुक्ति सघ गणराज्या के न्यायवादियों के द्वारा का जाती है, परन्तु इन नियुक्तियों पर महान्यायवादी की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये सघ न्यायवादी उसका अधीक्षण में कार्य करते हैं तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य अपने क्षेत्र के न्याय प्रशासन पर दृष्टि रखते हैं तथा गणराज्यों एलिस्, न्यायालयों के कर्मचारियों आदि के कार्यों के सम्बन्ध में महान्यायवादी को सूचना देते हैं। न्यायवातियों को जो भी शक्ति प्राप्त होती है वह महान्यायवादी द्वारा प्रत्यापानित ही होती है।^१

सावियत शासन व्यवस्था में महान्यायवादी तथा उसके विभाग का महत्व—सोवियत सघ के महान्यायवादी का सावियत सघ की सावजनिक सम्पत्ति का अधिकारी सरक्षक तथा ध्वंसामक कार्यवाही करने वाले नागरिकों एवं पत्राधिकारियों का राजकीय शत्रु माना जाता है।^२ सोवियत सघ में अधिकांश सम्पत्ति का समानीकरण कर लिए जाने के कारण उसका सरक्षा का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। न केवल नागरिकों द्वारा हा जाने या अनजाने में सावजनिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाई जा सकती है वरन् सरकारी कर्मचारियों का लापरवाही, असावधानी अथवा अनेतिक आचरण के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति

^१ The theory is that the Procurator General alone bears the prosecutorial power while the other procurators possessing such power only in so far as it is delegated to them by him —Golitsky *The Supreme Soviet of the U S S R and the Organs of Justice* p. 92

^२ The Procurator General is the official guardian of public property and the state in my of graft or sabotage by administrative departments and individuals alike —Harper and Thompson *op cit* p. 236

का पता लगाने और उन्हें दब दिला देने के लिए सभी देशों में गुप्त पुलिस रखी जाती है। अधिकांश देशों में असाधारण महत्व के मामलों के लिए सामान्य न्याय व्यवस्था और अतिरिक्त विशेष व्यवस्था भी हैं, यथा बिना मुकदमा चलाए नजरबंदी का व्यवस्था। परंतु किसी प्रजातान्त्रिक देश में न तो गुप्त पुलिस की कार्यवाहियां ही इतनी अधिक होती हैं जितनी सोवियत सभ में और न विशेष व्यवस्थाओं का इतना व्यापक प्रयोग ही होता है।

सावियत राजनीतिक पुलिस का इतिहास—सावियत राजनीतिक पुलिस का निर्माण सरप्रथम सन् १९१८ में 'चेका (Cheka)' के नाम से हुआ। इसका कार्य क्रांतिप्रेरणी कार्यवाहियां, सावियत राज्य का नष्ट करने के प्रयत्न, तथा छिपे हुए वैयक्तिक व्यापार करने वालों का पता लगाना तथा उन्हें दब देना था। राजनीतिक पुलिस के विशेष कार्यालयों में उपरोक्त अपराधों के आरोप पर गिरफ्तार व्यक्तियों के मुकदमों पर सन्नेप में विचार किया जाता था तथा उन्हें अत्यंत कठोर दण्ड दिया जाता था। आग और निक ने चेका का कार्यवाहियां का उल्लेख करते हुए लिखा है— 'बिना किसी छापाने के इन आयोगों का निर्देशन पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) के सक्रिय सदस्यों को सौंपा जाता था तथा उन्हें किसी व्यक्ति को बंदी बनाने, परीक्षण करने, मुकदमा चलाने, सजा देने का पूर्ण अधिकार था। बहुत ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने शत्रुओं और अथवा सदेहयुक्त शत्रुओं को सीधा गाली से उखाड़ दिया।' ^१ सावियत नेता अपनी राजनीतिक पुलिस को क्रांति की नम्र करवाल (Unshakable punishing word of the Revolution) कहते थे। उस समय राजनीतिक पुलिस ने जो कुछ किया उस के संबंध में यह

The first letters CHEKA stand for the Russian equivalent of the ordinary Commissions to Combat County Revolution, Sabotage and Speculation

^२ The commissions were invariably placed under the direction of active members of the party and had full right to arrest, examine, try, convict, sentence and punish. In many instances they simply executed the orders of the executive expected enemies to be shot —Ogg & Zink op cit p 879

करना ना सकता है कि यह युद्ध तथा राज्य देशों के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न शान्ति में बाधा करना आवश्यक था। परन्तु राजनीतिक पुलिस की कार्यक्षमता यह युद्ध और राज्य हलचल के समान होने के कारण भी गाय गई।

सन् १९२२ में चेका (Cheka) का स्थान गाय (Ogpu) ने ले लिया। उसकी शक्ति का चेका की शक्तियों की तुलना में कुछ भीमता थी। जिस समय सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२८-३२) पर काम आरम्भ हुआ तथा “कुलकों” (Kulaks) का अन्त कर कृषि का सामूहिकरण किया गया उस समय आन्ध्र का शासन में पमाना बंद कर दा गई। शासन का मानों का विरोध करने वालों को राजनीतिक पुलिस बना बना कर नये शिविरों में भेज देती थी जहाँ उन से कठोर परिश्रम कराया जाता था। कृषि के सामूहिकरण का राजनापा होने पर राजनीतिक पुलिस की कार्यक्षमता में कुछ कमी हुई। सन् १९३६ में एक प्रत्यक्ष अंग के रूप में उसका अन्त कर दिया गया और इसे आन्ध्रतरिफ मामलों के मन्त्रालय (Commissariat of Internal Affairs) के अधीन कर दिया गया। उसका नाम प्रत्यक्ष के की (N. K. V. D.) हो गया।

राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में आभा क्या हुई ही है कि एक देश घटना आता जिसने उसकी कार्यक्षमता में बहावक बहुत बढ़ि कर दी। जिसमें १९४४ में कम्युनिस्ट पार्टी — एक प्रमुख नया स्थिति (L. O. P.) का हस्त कर आया। सोवियत शासन ने इस घटना के बाद एक विशाल पुनः संयोजन का हाथ लगा। अन्तर्गत के सभी प्रमुख पराधीनता पर मुख्य बलाघात का प्रथम उद्देश्य राजनीतिक पुलिस के आदेश में न सिर्फ में भेज दिया गया। जिस शक्तियों का यह पदचरम में सम्मिलित शक्ति — संस्था में सन्तुष्ट किया गया उनमें लेनिन के कई प्रमुख साथी तथा के पूर्विक पागल मानव-युद्ध के संस्था भी थे। यह संस्था — प्रथम १९४४ पर यह संस्था का विपुल और वृद्धि किया गया। सन् १९८८ में प्रत्यक्ष में संस्था पर बारसा (L. P. D. S.) में नियुक्त किया गया।

१ The initial letters O G P L stand for the Russian equivalent of the State Political Administration

द्वितीय महायुद्ध के काल में राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में पुनर्प्राप्त वृद्धि हुई। "देशद्रोहियों, 'निदेशों के जासूसों तथा "समाजवादी सम्पत्ति को नष्ट करने वालों" का उसने कोप का भाजन बनना पड़ा। युद्ध की समाप्ति पर राजनीतिक पुलिस की कार्यवाहियों में फिर कमी हुई परन्तु यह विद्यमान रहा। सन् १९४३ में यह कमिसरियत का यह तथा राय-मुरछा नामक दो कमिसरियतों में पारवर्तित कर लिया गया। सन् १९४६ में कमिसरियत का नाम उल्लंघन मंत्रालय (Ministries) कर दिया गया। तब से राजनीतिक पुलिस के दो निभागों का एम वी डी (M V D) और एम जी बी (M G B) कहते हैं। एम वी डी के कमचारी समान पोशाक (Uniform) पहनते हैं जब कि एम जी बी के कमचारी बिना किसी पोशाक के पुत्र रूप से कार्य करते हैं। सन् १९५२ में स्लाविन की मृत्यु के पश्चात् यह मंत्रालय के प्रधान बरिया को देशद्रोह प्रारंभ 'क्रांति विरोधी कार्यों' के लिए प्राणश्रावण दिया गया और उनका स्थान पर नवीन प्रधान मंत्री मालेन्कोव के एक विश्वासपात्र व्यक्ति को नियुक्त किया गया।

राजनीतिक पुलिस के कृत्य तथा शक्तियाँ—राजनीतिक पुलिस का मुख्य काम अभी भी वही है जो सन् १९१७ में उसकी स्थापना के समय था। परन्तु उसकी शक्तियाँ कम हो गई हैं। प्रो. हार्पर और टामसन के कथनानुसार उसे अभी भी 'क्रांति की नग्न करवाले' माना जाता है। विश्वसनीय कार्यवाहियों, देशद्रोहियों, विदेशों के एजेंटों और गुप्तचरों तथा राज्य सम्पत्ति को नष्ट करने या चुराने वालों के समस्त पद्यों का पता लगाना तथा उन्हें निष्फल करना ही इसका प्रधान कृत्य बताया जाता है। यद्यपि उसे सहेय्युक्त व्यक्तियों पर मुकुटमा चढ़ाने का अधिकार नहीं है परन्तु यह उन्हें पापवादी (Persecutor) की आज्ञा से उठा उठा कर अभिशप्ति में भेज सकती है। व्यवहार में ऐसे सभी मामलों पर जिनमें वर्तमान शासन के प्रति निद्रोह या किसी राजनीतिक पक्ष का आभास मिलता है, अभियुक्त सामान्य न्याय व्यवस्था का लाभ उठाने से वंचित रख जाते हैं। ऐसे मामलों

पर समचित्त कायगही करना राजनीतिक पुलिस का कार्य है 'यात्रालया का नहा ।'^१

राजनीतिक पुलिस का दूसरा मुख्य कार्य 'म शिरि' का संचालन करना है । यह कार्य राय मुख्या मालय (M V D) के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । प्रारम्भ में यह शिरि अपराधियों तथा राजनीतिक दलियों का उनसे काम करा कर उन्हें 'सुगम' के लिए स्थापित किए गए थे । 'म शिरि' में प्रदियों के अम से उड़ा उड़ा नगर तथा माध आदि बनाए गए । 'म शिरि' के भद्रियों की सत्ता तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में सोवियत सरकार की आर स फाइ सूचना प्रकाशित नहीं की जाती । इसलिए विभिन्न लेखकों ने विभिन्न कोणों से प्राप्त सरकारी उद्धरणों की हैं । सोवियत विरोधी लेखक इनके भद्रियों का सत्या एक तम दो करो के अन्तर्गत मानते हैं । संयुक्त राष्ट्र का आधिक तथा सामाजिक परिषद द्वारा १९४६ में मांग दैते हुए विविध प्रतिनिधि ने इनका सत्या लगभग एक करो नता थी ।^२ डाकी सख्या के नियम में कुछ निश्चित मताना कल्पित है परन्तु 'तना

प्रचारिका के अनुसार राजनीतिक पुलिस ने रूस नागरिकों को 'म शिरि' में ही भेज सकता है, यन् 'म पर पुन रूप से मुक्तता पना कर अथवा मुक्तता पाने की औपचारिकता के बिना ही प्रणद तक द सकता है । उन्होंने लिखा है "Its ubiquitous agents free from the restraint of law are vested with extra judicial powers which allow them not only to deport citizens suspected of disloyalty to the regime to the penal labour camps that dot the bleak wilderness of Russia's northern and eastern regions, but also to impose death sentences after a trial in camera or without the formality of trial Florensky M T, op cit p 7601 परन्तु अन्त लेखकों के कथन में उन दस कथन की पुष्टि नहीं होता ।

^२ Statement by British delegate Corley Smith as quoted by Florensky

कहा जा सकता है कि यह कई मिलियन (millions) है । यह तथ्य कि सोवियत संघ में जितनी बड़ी सत्ता में नागरिकों को बिना कोई मुकद्दमा चलाए राजनीतिक पुलिस द्वारा संचालित क्रम शिविरों में बंटी रखा जाता है, स्वयं ही राजनीतिक पुलिस के महत्त्व को स्पष्ट कर देता है ।

सहायक पुस्तकों की सूची

(Bibliography)

Buell—A Government in Europe

Bailey V de—Russia and the Soviet Reg

Carr, E. H.—The Bolshevik Revolution (1917-1933) Vol. I

Finer Herman—The Theory and Practice of Modern Government

Florinsky M. T.—The Political System of the U. S. S. R.
in the Governments of Continental Europe edited by James T.
Shotwell

Hunt R. N. C.—Theory and Practice of Communism

Hoppe & Thompson—Government of the Soviet Union

Kapinsky V.—The Social and State Structure of the
U. S. S. R.

Laski Harold J.—Law and Liberty in Soviet Russia

Lenin, V. I.—The State and Revolution

Lenin, V. I.—Selected Works

Marx K.—The Capital

Marx K. & Engels F.—The Communist Party
Manifesto—Selected Works

McBride & Roger

Munro W. B. & A.

Misra R. K.

Ogg F.

Polansky — *The Stalin Constitution on the Judiciary in the Procurator's Office*

Rothstein, Andrew — *A History of Soviet Union*

Stalin J V — *On the Draft Constitution of the U S S R*

Stalin J V, — *Communism*

Stalin J V — *Selected Works*

Sloan Pat — *How the Soviet State is Run*

Sloan Pat — *Russia without Illusions*

Tainin I — *The Stalin Constitution*

Towster, Julian — *The Political Power in the U S S R*
(1941-1944)

Umansky Y — *The Constitutional Rights of Soviet Citizens*

Vyshinsky, A Y — *The Law of the Soviet State*

Vyshinsky A Y — *The Electoral System of the U S S R*

Wobbs Sydney & Battis — *Soviet Communism A New
Crisis to*

Wheeler — *Federal Germany*